खण्ड–496, अंक–1
शुक्रवार, 07 फाल्गुन, शक संवत् 1937
(26 फरवरी, 2016 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

—: 0 :—

(अधिकृत विवरण)

(सोलहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र, 2016)

(खण्ड 496 में 5 अंक हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2016

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे ।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये ।

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ–संख्या
सोलहवीं विधान सभा के सदस्यों की सूची, महामहिम श्री राज्यपाल, मंत्रि–परिषद्, नेता विरोधी दल, उत्तर प्रदेश विधान सभा के पदाधिकारी तथा अधिष्ठाता मण्डल की सूची	1–12
उपस्थित सदस्य	13–18
आगरा में दलित कार्यकर्ता की हत्या से सम्बन्धित नियम–311 की सूचना को सर्वप्रथम लिये जाने की मांग	19–21
प्रश्नोत्तर	21–26
दुनिया में कच्चे तेलों की हुई कमी के अनुरूप हिन्दुस्तान में भी या मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में तेलों के दाम कम किये जाने विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत)	26–28
प्रश्नोत्तर	28–60
मुजफ्फरनगर दंगों के स्टिंग आपरेशन से सम्बन्धित जांच समिति की संस्तुतियों के क्रम में टी0वी टुडे नेटवर्क के पदाधिकारियों द्वारा प्रमुख सचिव, विधान सभा को सदन में उपस्थित होने की समय–सीमा बढ़ाये जाने से सम्बन्धित प्रेषित–पत्र पर सदन का अभिमत	60–69
नियम–301 के अन्तर्गत सूचनाएं	69
जनपद कानपुर महाराजपुर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत श्रीकान्त साहू के घर से मछरीया रोड मजार तक एवं रामचन्द्र अवस्थी पेट्रोल लाइन यशोदा नगर से कर्मपुर गांव सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	69–70
जनपद बहराइच विधान सभा क्षेत्र कैसरगंज विकास खण्ड कैसरगंज के घनी आबादी वाले एक बड़े ग्राम तखता में आवागमन हेतु मार्ग की व्यवस्था न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	70
जनपद फिरोजाबाद में एक आई0टी0आई0 की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	70
जनपद सहारनपुर स्थित कम्पनी बाग का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	71
जनपद बुलन्दशहर में मांट ब्रान्च खण्ड गंगा नहर के उठरावली रजवाहे पर गांव रमानी के पास क्षतिग्रस्त पुल के पुनः निर्माण न होने के कारण उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	71
जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र खजनी एवं धनघटा क्षेत्रान्तर्गत कुवानों नदी पर वनकटा घाट पर आवागमन हेतु पुल न होने से	71–72

विषय **पृष्ठ–संख्या**

उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...

जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रुदौली में विद्युत वितरण खण्ड की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना 72

जनपद मेरठ दक्षिण विधान सभा क्षेत्र की ग्राम फफून्डा से पीपली खेड़ा तक जाने वाले कच्चे मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना 72–73
जनपद वाराणसी विधान सभा क्षेत्र रनिया महाल, तेलियाबाग खुले नाले को ढकने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ... 73
जनपद आगरा के वाटर बाक्स चौराहा से शक्ति सुशील मन्दिर होते हुए बल्केश्वरनाथ महादेव मन्दिर तक की सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना 73
जनपद गाजीपुर के अन्तर्गत एन0एच0–29 पर शहीद श्री जयप्रकाश फिलिंग स्टेशन के सामने श्री अली हुसैन राईनी के घर से श्रीमती सुमन देवी के घर तक के मुख्य मार्ग तक क्षतिग्रस्त मार्ग का नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना 73–74
जनपद हापुड़ में सभी सरकारी भवनों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना 74
जनपद रामपुर के विलासपुर मिलक खानम स्वार मार्ग का चौड़ीकरण एवं सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना 74–75
अग्नि पीड़ित को अहेतुक सहायता दिलवाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना 75
पूर्वांचल के मिनी पी0जी0आई0 के नाम से प्रसिद्ध ओपेक चिकित्सालय कैली में विशेषज्ञ डाक्टरों एवं टेक्नीशियनों की नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना... ... 75–76
जनपद कुशीनगर के तमकुहीराज विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सेवरही ब्लाक में जवही दयाल चैनपट्टी के सामने बूढ़ी गण्डक नदी पर प्लाटून पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ... 76–77
जनपद अलीगढ़ में बरौली विधान सभा क्षेत्र के क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना... 77
जनपद मथुरा में छाता विधान सभा क्षेत्र के क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ... 77–78
जनपद सीतापुर की लहरपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत नानजेड 78

वक्फ की भूमि स्थानीय ग्राम समाज की भूमि में बड़े पैमाने पर राजस्व अभिलेखों में अनियमितता करने वाले लेखपाल/अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ... ...

जनपद सीतापुर के हरगांव विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विकास खण्ड लहरपुर में कतिपय सम्पर्क मार्गों की मरम्मत/रिनीवल कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना 78–79

जनपद सहारनपुर विधान सभा सीट सिकन्दराराऊ के अन्तर्गत ग्राम नगला जलाल से टीकरी खुर्द, कपसिया, ईशेपुर होते हुए बाजिदपुर तक जर्जर सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ... 79

जनपद गोरखपुर विधान सभा क्षेत्र चौरी–चौरा की मुख्य सड़क से ग्राम मीठाबेल होते हुए हरैईया तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना 79–80

जनपद मिर्जापुर विकास खण्ड पहाड़ी के अन्तर्गत ग्राम पंचायत दाती, गौरा राजा (गौरा विशेन) को सम्पर्क मार्ग से जोड़ने हेतु सड़क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना 80

जनपद लखीमपुर के विधान सभा क्षेत्र धौरहरा वि0ख0 रमीया बेहड़ से परौरी मार्ग की पक्की सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना 80–81

जनपद गाजियाबाद के वार्ड–74 में जस्सीपुरा हबीब कम्पाउण्ड के मोड़ पर क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ... 81

जनपद लखनऊ में मलिहाबाद विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत मवईकला आरा मशीन के पास महबूब खेड़ा सरैया फत्तेपुर की सड़क बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ... 81–82

जनपद बरेली के उप निबन्धक कार्यालय बहेड़ी में करोड़ों की भूमि को मात्र 960.00 रुपये स्टाम्प ड्यूटी लेकर प्रकरण का निस्तारण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ... 82

जनपद लखनऊ की डिफेन्स कालोनी नेपालगंज, तेलीबाग, रायबरेली रोड पर तालाब की भूमि को आबादी की भूमि दिखाकर बेचे जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना 82–83

अंसल हाउसिंग एण्ड कन्शट्रेक्शन लि0 के आवंटियों की रजिस्ट्री न होने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना 83–84

जनपद उन्नाव के ग्राम सिकन्दरपुर करन के ग्रामवासियों द्वारा जबरन 84

कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...
जनपद आगरा के अन्तर्गत विकास खण्ड अकोला को तहसील बनाये
जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना 84

जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र की ग्राम सभा दुलहीपुर, सकुर के भट्ठा, सतपोखरी की जल निकासी के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना 85

जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र माधवगढ़ टाउन एरिया में मुंसिफ कोर्ट स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना 85

जनपद बस्ती विधान सभा क्षेत्र बस्ती सदर के कतिपय ग्रामों की जर्जर सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ... 85–86

जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र खेरागढ़ सैंया खेरागढ़ मुख्य मार्ग पर क्षतिग्रस्त पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना 86

राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के संविदा पर कार्यरत वाहन चालक को विनियमित किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना 86

जनपद लखनऊ के नगर निगम के अन्तर्गत एल0डी0ए0 कालोनी सेक्टर–एल–2 में पानी की सप्लाई ठीक से न होने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना 86–87

जनपद शाहजहांपुर में वृद्धावस्था पेंशन, विधवा योजना में की गयी धांधली की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना 87

जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र इगलास करथला नाले पर करथना के निकट पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ... 87

जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र कस्ता में लखीमपुर मैगलगंज मार्ग से परसेहरा खुर्द एवं औरंगाबाद से 26 मील तक की जीर्ण–शीर्ण सड़क को ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ... 88

जनपद महराजगंज की तहसील नौतनवां ग्राम भुन्डी आराजी संख्या–1317 रकबा 0.616 हेक्टेयर तथा 1330 रकबा 0.219 हेक्टेयर पर आरिफ कुरैशी व आशिक कुरैशी द्वारा जबरन कब्जा 88–89

किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा विश्वनाथ के विकास खण्ड लक्ष्मणपुर की निम्नलिखित ग्राम सभाओं में दूषित पेय भू–गर्भजल व अति निम्न जल स्तर से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ... 89

जनपद महोबा में खनिज क्षेत्र के सभी सम्पर्क मार्गों का यथाशीघ्र निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ... 89

विषय	पृष्ठ–संख्या
जनपद हरदोई पूर्व में बनाये गये सभी परीक्षा केन्द्रों में से 20 विद्यालयों को मानक पूर्ण करने के बावजूद परीक्षा केन्द्र न बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	89–90
जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र मोहान के ब्लाक नवाबगंज के अन्तर्गत कतिपय सम्पर्क मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	90
श्री सलिल विश्नोई सदस्य, विधान सभा के साथ दिनांक 15 सितम्बर, 2004 को पुलिस द्वारा किये गये दुर्व्यवहार के प्रकरण पर विशेषाधिकार समिति द्वारा संस्तुति के उपरान्त भी आज तक कोई कार्रवाई न किये जाने विषयक औचित्य का प्रश्न ...	90–92
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड का नवां वार्षिक प्रतिवेदन 2007–2008 (सदन के पटल पर रखा गया)	92
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड का दसवां वार्षिक प्रतिवेदन 2008–2009 (सदन के पटल पर रखा गया)	92
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड का ग्यारहवां वार्षिक प्रतिवेदन 2009–2010 (सदन के पटल पर रखा गया)	92
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड का बारहवां वार्षिक प्रतिवेदन 2010–2011 (सदन के पटल पर रखा गया)	92
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड का तेरहवां वार्षिक प्रतिवेदन 2011–2012 (सदन के पटल पर रखा गया)	93
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड का चौदहवां वार्षिक प्रतिवेदन 2012–2013 (सदन के पटल पर रखा गया)	93
उप लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश का विशेष प्रतिवेदन संख्या–1–2012 (उप लो0आ0) स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित (सदन के पटल पर रखा गया)	93
जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र खेरागढ़ के विकास खण्ड सैंया में कतिपय जर्जर गड्ढेयुक्त सड़कों की मरम्मत कराये जाने विषयक श्री दिनेश रावत आदि निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी) ...	93
जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र खेरागढ़ के विकास खण्ड जगनेर में कतिपय जर्जर गड्ढेयुक्त सड़कों की मरम्मत कराये जाने विषयक श्री राम सिंह सिकरौदिया आदि निवासीगण जनपद	93

आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी) ... ...

विषय **पृष्ठ–संख्या**

जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र खेरागढ़ के विकास खण्ड खेरागढ़ में कतिपय जर्जर गड्ढेयुक्त सड़कों की मरम्मत कराये जाने विषयक श्री मेघराज सोलंकी आदि निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी) ... 94

जनपद लखनऊ के पश्चिम विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कन्हैया माधौपुर वार्ड के फिरदौस कालोनी की कच्ची सड़क व नालियों का जनहित में निर्माण कराये जाने विषयक श्री अनीस हसन आदि निवासीगण जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी) 94

जनपद लखनऊ के पश्चिम विधान सभा क्षेत्र के आलमनगर वार्ड के अन्तर्गत जलालपुर मर्दनखेड़ा की कच्ची सड़क व नालियों का जनहित में निर्माण कराये जाने विषयक श्री जमाल अहमद आदि निवासीगण जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी) 94

जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड सरदार नगर के अन्तर्गत गोरखपुर देवरिया मार्ग पर स्थित डुमरी खुर्द चौराहा से ग्राम सभा शत्रुघनपुर होते हुए लक्ष्मणपुर चौराहे तक की क्षतिग्रस्त सड़क का जनहित में उच्चीकरण एवं चौड़ीकरण कराये जाने विषयक श्री राधेश्याम आदि निवासीगण जनपद गोरखपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी) 94

जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड ब्रह्मपुर के अन्तर्गत राजधानी से नई बाजार जाने के लिये घटुली घाट पर पुल निर्माण कराये जाने विषयक श्री राज बहादुर निषाद आदि निवासीगण जनपद गोरखपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी) ... 94

कार्य–मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत) 95–97

पंचायती राज विभाग का बजट पटल पर प्राप्त न होने सम्बन्धी प्रकरण... 97

कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें 97–104

वित्तीय वर्ष 2016–2017 के आय–व्ययक पर साधारण चर्चा (जारी) ... 104–149

कार्य–मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत) 149

वित्तीय वर्ष 2016–2017 के आय–व्ययक पर साधारण चर्चा... ... 149–166

नियम–51 के अन्तर्गत सूचनाएं 166–168

विषय **पृष्ठ–संख्या**

जनपद बागपत के ग्राम खिंदौड़ा की निवासी सुश्री साक्षी चौहान का दिनांक 30 जनवरी, 2016 को अपहरण होने के उपरान्त दुष्कर्म/हत्या किये जाने के बाद पुलिस द्वारा कोई भी कार्रवाई न किये जाने के सम्बन्ध में श्री लोकेश दीक्षित द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य 168–169

जनपद बलिया की तहसील सिकन्दरपुर में वर्ष 2015–2016 में सूखा एवं ओलावृष्टि से पीड़ित किसानों को मुआवजा राशि दिलाये जाने हेतु धनराशि अवमुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जियाउद्दीन रिजवी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य 169–170

जनपद अम्बेडकर नगर में एस0एम0आई0 रामनगर द्वारा बड़े पैमाने पर की गई अनियमितताओं के सम्बन्ध में श्री भीम प्रसाद सोनकर द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर खाद्य एवं रसद मंत्री का वक्तव्य 170–171

जनपद सन्त कबीर नगर के टेमां सेमरियावां मार्ग का नवीनीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 मो0 अयूब द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य ... 171

जनपद शामली की तहसील शामली अन्तर्गत ग्राम सभा लिलोन में राजकीय बालिका इण्टर कालेज की स्थापना हेतु धन आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में श्री पंकज कुमार मलिक द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर माध्यमिक शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य 172

प्रदेश के अनुसूचित जाति एवं जनजाति व पिछड़ा वर्ग के छात्र–छात्राओं की छात्रावास शुल्क समेत अन्य शुल्कों का भुगतान किये जाने हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में श्री पूरन प्रकाश द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना 172–173

पर समाज कल्याण मंत्री का केवल वक्तव्य ... ...

जनपद मथुरा के कतिपय ग्राम सभाओं स्थित नेशनल हाई–वे–2 व गोवर्धन रोड के दोनों तरफ बसी आबादी से उत्सर्जित जल की समुचित निकासी हेतु गहरे नालों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रदीप माथुर द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर पंचायती राज मंत्री का केवल वक्तव्य 173

जनपद आजमगढ़ के नगर पालिका मुबारकपुर में अधिशासी अधिकारी की नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में श्री शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली द्वारा दी गयी सूचना पर नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य 173

विषय **पृष्ठ–संख्या**

T

जनपद बुलन्दशहर के लोक निर्माण विभाग के प्रान्तीय खण्ड में ठेकेदार की मिलीभगत से सरकारी धन का दुरुपयोग किये जाने के सम्बन्ध में श्री दिलनवाज खां द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य 173–174

जनपद बुलन्दशहर के विकास खण्ड सिकन्द्राबाद के अन्तर्गत गांव सराय घासी व आढ़ा के बीच करों नदी पर पड़ने वाले पुल के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण एवं सिंचाई राज्य मंत्री का केवल वक्तव्य 175

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर में प्राथमिक विद्यालय प्रथम निगोही में कार्यरत रसोइयों को मानदेय दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री रोशन लाल वर्मा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर बेसिक शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य ... 175–176

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोलहवीं विधान सभा के सदस्यों की सूची

1. अंसार अहमद, श्री इलाहाबाद़
2. अखिलेश कुमार सिंह, श्री रायबरेली
3. अखिलेश प्रताप सिंह, श्री देवरिया
4. अगयश राम सरन वर्मा, श्री पीलीभीत
5. अजय, श्री वाराणसी
6. अजय कपूर, श्री कानपुर नगर
7. अजय कुमार, डा0 इलाहाबाद
8. अजय कुमार 'लल्लू', श्री कुशीनगर
9. अजीत कुमार, श्री फर्रुखाबाद
10. अजीमुल हक पहलवान अंसारी, हाजी अम्बेडकर नगर
11. अताउररहमान, श्री बरेली
12. अनिल कुमार, श्री मुजफ्फरनगर
13. अनिल कुमार दोहरे, श्री कन्नौज
14. अनिल वर्मा, श्री उन्नाव
15. अनीसुर्ररहमान, श्री मुरादाबाद
16. अनुग्रह नारायण सिंह, श्री इलाहाबाद
17. अनूप कुमार गुप्ता, श्री सीतापुर
18. अनूप सण्डा, श्री सुल्तानपुर
19. अबरार अहमद, श्री सुल्तानपुर
20. अब्दुल मशहूद खाँ, श्री बलरामपुर
21. अभय नरायन सिंह पटेल, श्री आजमगढ़
22. अभय सिंह, श्री फैजाबाद
23. अभिषेक मिश्र, श्री लखनऊ
24. अमर पाल शर्मा, श्री गाजियाबाद
25. अमित गौरव यादव, श्री एटा
26. अयोध्या प्रसाद पाल, श्री फतेहपुर
27. अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री बाराबंकी
28. अरविन्द सिंह यादव, श्री कन्नौज
29. अराधना मिश्र 'मोना' श्रीमती प्रतापगढ़
30. अरूण कुमार, डा0 बरेली
31. अरूण वर्मा, श्री सुल्तानपुर
32. अरूण कुमारी कोरी, श्रीमती कानपुर नगर
33. अलगू प्रसाद चौहान, श्री सन्तकबीर नगर
34. अली यूसूफ अली, श्री रामपुर
35. अवधेश कुमार सिंह उर्फ मंजू सिंह, श्री गोण्डा
36. अवधेश प्रसाद, श्री फैजाबाद
37. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री लखीमपुर खीरी
38. अविनाश कुशवाहा, श्री सोनभद्र
39. अशफाक अली खां, श्री अमरोहा
40. आदिल शेख, श्री आजमगढ़
41. आनन्द सिंह, कुंवर गोण्डा
42. आनन्द सेन, श्री फैजाबाद
43. आबिद रजा खां, श्री बदायूं
44. आरिफ अनवर हाशमी, श्री बलरामपुर
45. आलमबदी, श्री आजमगढ़
46. आलोक कुमार शाक्य, श्री मैनपुरी
47. आशा किशोर, श्रीमती अमेठी
48. आशीष कुमार यादव, श्री एटा
49. आशीष यादव, श्री बदायूं
50. आशुतोष उपाध्याय, श्री देवरिया
51. आशुतोष टण्डन

---

* mi pquko esa fuokZfprA

(गोपाल जी), श्री लखनऊ
52. आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री बदायूं
53. इकबाल महमूद, श्री संभल
54. इन्दल कुमार, श्री लखनऊ
55. इन्द्रजीत कोरी, श्री कानपुर नगर
56. इन्द्रजीत सरोज, श्री कौशाम्बी
57. इन्द्रपाल सिंह, श्री कानपुर देहात
58. इन्द्राणी देवी, श्रीमती श्रावस्ती
59. इरफान सोलंकी, हाजी कानपुर नगर
60. उत्कर्ष वर्मा मधुर, श्रीलखीमपुर खीरी
61. उदयराज, श्री उन्नाव
62. उदय लाल मौर्या, श्री वाराणसी
63. उपेन्द्र तिवारी, श्री बलिया
64. उमाकान्ती, श्रीमती जालौन
65. उमाशंकर, श्री बलिया
66. उमेश पाण्डेय, श्री मऊ
67. उर्मिला देवी, श्रीमती महोबा
68. ओमकार सिंह, श्री बदायूं
69. ओम कुमार, श्री बिजनौर
70. ओम प्रकाश, श्री गाजीपुर
71. ओम प्रकाश 'बाबा' दुबे, श्री जौनपुर
72. ओम प्रकाश वर्मा, श्री फिरोजाबाद
73. ंकपिल देव अग्रवाल, श्रीमुजफ्फरनगर
74. कमाल अख्तर, श्री अमरोहा
75. कमाल युसुफ मलिक, श्रीसिद्धार्थनगर
76. करतार सिंह भड़ाना, श्रीमुजफ्फरनगर
77. काजिम अली खां
उर्फ नवेद मियां, नवाब रामपुर
78. काली चरन सुमन, श्री आगरा
79. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
80. कृष्ण कुमार ओझा, श्री बहराइच
81. कृष्ण गोपाल पटेल, श्रीलखीमपुर खीरी
82. कृष्णपाल सिंह राजपूत, श्री झांसी
83. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
84. कैलाश चौरसिया, श्री मिर्जापुर
85. कौशल सिंह कुंवर, श्री महराजगंज
86. गंगा सिंह कुशवाहा, श्री कुशीनगर
87. गजराज सिंह, श्री हापुड़
88. गजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
89. गयाचरण दिनकर, श्री बांदा
90. गयादीन अनुरागी, श्री हमीरपुर
91. गायत्री प्रसाद, श्री अमेठी
92. गिरीश चन्द्र उर्फ
गामा पाण्डेय, श्री इलाहाबाद
93. गुटियारी लाल दुवेश, श्री आगरा
94. गुलाब चन्द, श्री जौनपुर
95. गुलाम मौहम्मद, श्री मेरठ
96. गेंदा लाल चौधरी, श्री हाथरस
97. गोमती यादव, श्री लखनऊ
98. गोरख पासवान, श्री बलिया
99. चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री चित्रकूट
100. चन्द्रा रावत, श्रीमती लखनऊ
101. छोटेलाल वर्मा, श्री आगरा
102. जगतम्बा सिंह, श्री मिर्जापुर
103. जगदीश सोनकर, श्री जौनपुर
104. जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
105. जगपाल, श्री सहारनपुर
106. जगराम पासवान, श्री बलरामपुर
107. जन्मेजय सिंह, श्री देवरिया
108. जफर आलम, श्री अलीगढ़
109. जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्रीफर्रुखाबाद
110. जमीर उल्ला खां, श्री अलीगढ़
111. जमील अहमद कास्मी, श्रीमुजफ्फरनगर

* mi pquko esa fuokZfprA

112. जय प्रकाश निषाद, श्री गोरखपुर
113. जय प्रकाश अंचल, श्री बलिया
114. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
115. जाकिर अली, श्री गाजियाबाद
116. जाहीद बेग, श्री
सन्तरविदास नगर (भदोही)
117. जियाउद्दीन रिजवी, श्री बलिया
118. जीतेन्द्र कुमार उर्फ
नन्दू चौधरी, श्री बस्ती
119. ज्योत्सना श्रीवास्तव, श्रीमतीवाराणसी
120. तसलीम, श्री बिजनौर
121. तेज नारायण पाण्डेय उर्फ
पवन पाण्डेय, श्री फैजाबाद
122. तेजपाल सिंह, श्री मथुरा
123. त्रिभुवन राम, श्री वाराणसी
124. त्रिलोकीराम, श्री अलीगढ़
125. दयाशंकर वर्मा, श्री जालौन
126. दलजीत सिंह, श्री बांदा
127. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
128. दिलनवाज खान, श्री बुलन्दशहर
129. दीपक पटेल, श्री इलाहाबाद
130. दीपनारायण सिंह
(दीपक यादव), श्री झांसी
131. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
132. देवनरायन उर्फ
जी0एम0 सिंह, श्री महराजगंज
133. देवेन्द्र अग्रवाल, श्री हाथरस
134. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली
135. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
136. धर्मपाल सिंह, डा0 आगरा
137. धर्मराज, श्री बाराबंकी
138. धर्मसिंह सैनी, डा0 सहारनपुर
139. धर्मेश सिंह तोमर, श्री हापुड़
140. नजीवा खान जीनत, श्रीमतीकासगंज
141. नदीम जावेद, श्री जौनपुर
142. नन्दिता शुक्ल, श्रीमती गोण्डा
143. नरेन्द्र सिंह यादव, श्री फर्रुखाबाद
144. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
145. नवाजिश आलम खान, श्रीमुजफ्फरनगर
146. नवाब जान, श्री मुरादाबाद
147. नागेन्द्र सिंह ''मुन्ना यादव'', श्रीप्रतापगढ़
148. नारद राय, श्री बलिया
149. नाहिद हसन, श्री शामली
150. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
151. नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्रीशाहजहांपुर
152. नूर सलीम राणा, श्री मुजफ्फरनगर
153. पंकज कुमार मलिक, श्री शामली
154. पंकज गुप्ता, श्री उन्नाव
155. परवेज अहमद (टंकी), हाजीइलाहाबाद
156. पारस नाथ यादव, श्री जौनपुर
157. पिंकी सिंह, श्रीमती संभल
158. पीटर फैन्थम, श्री नाम–निर्देशित
159. पीतमराम, श्री पीलीभीत
160. पूजा पाल, श्रीमती इलाहाबाद
161. पूनम सोनकर, श्रीमती चन्दौली
162. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
163. पूर्णमासी देहाती, श्री कुशीनगर
164. प्रदीप चौधरी, श्री सहारनपुर
165. प्रदीप कुमार यादव, श्री औरैया
166. प्रदीप माथुर, श्री मथुरा
167. प्रभूदयाल वाल्मीकि, श्री मेरठ
168. प्रमोद कुमार गुप्ता, श्री औरैया
169. प्रशान्त कुमार सिंह
(राहुल सिंह), श्री इलाहाबाद

170. प्रेम प्रकाश सिंह, श्री देवरिया
171. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
172. फरीद महफूज किदवई, श्री बाराबंकी
173. ''फसीहा मंजर''
''गजाला लारी'', श्रीमती देवरिया
174. फेरन लाल, श्री ललितपुर
175. बंशीधर बौद्ध, श्री बहराइच
176. बंशी सिंह पहाड़िया, श्री बुलन्दशहर
177. बदलू खां, श्री उन्नाव
178. बब्बन सिंह चौहान, श्री चन्दौली
179. बाबू खां, श्री हरदोई
180. बाबूलाल, श्री गोण्डा
181. बावन सिंह, श्री गोण्डा
182. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमतीबुलन्दशहर
183. बृज लाल सोनकर, श्री आजमगढ़
184. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
185. बृजेश कुमार, श्री हरदोई
186. बेचई सरोज, श्री आजमगढ़
187. बैजनाथ, श्री मऊ
188. ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
189. भगवत सरन गंगवार, श्री बरेली
190. भगवती प्रसाद, श्री अलीगढ़
191. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
192. भाई लाल कोल, श्री मिर्जापुर
193. भीम प्रसाद सोनकर, श्रीअम्बेडकरनगर
194. मदन गोपाल वर्मा, श्री फतेहपुर
195. मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
196. मदन सिंह उर्फ सन्तोष, श्री औरैया
197. मधुबाला, श्रीमती
सन्त रविदास नगर (भदोही)
198. मनबोध, श्री देवरिया
199. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
200. मनीष रावत, श्री सीतापुर
201. मनोज कुमार, श्री चन्दौली
202. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
203. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
204. ममतेश शाक्य, श्री कासगंज
205. महबूब अली, श्री अमरोहा
206. महावीर सिंह, कुं0 हरदोई
207. महावीर सिंह राणा, श्री सहारनपुर
208. महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा आगरा
209. महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ
झीन बाबू, श्री सीतापुर
210. महेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी
211. माइकल चन्द्रा, श्री अमरोहा
212. माता प्रसाद पाण्डेय, श्रीसिद्धार्थनगर
213. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
214. मानपाल सिंह, श्री कासगंज
215. मविया अली, श्री सहारनपुर
216. मुकुट बिहारी वर्मा, श्री बहराइच
217. मुकेश शर्मा, श्री बुलन्दशहर
218. मुकेश श्रीवास्तव उर्फ
ज्ञानेन्द्र प्रताप, श्री बहराइच
219. मुख्तार अंसारी, श्री मऊ
220. मुनीन्द्र शुक्ला, श्री कानपुर नगर
221. मुसर्रत अली बिट्टन, श्री बदायूं
222. मुहम्मद गाजी, श्री बिजनौर
223. मुहम्मद रमजान, श्री श्रावस्ती
224. मूलचन्द्र चौहान, ठा0 बिजनौर
225. मो0 अयूब, डा0 सन्तकबीर नगर
226. मो0 आसिफ, श्री फतेहपुर
227. मो0 आसिफ जाफरी, सी0ए0कौशाम्बी
228. मौहम्मद इकबाल, श्री बिजनौर
229. मो0 जासमीर अंसारी, श्री सीतापुर
230. मो0 मुस्लिम, श्री अमेठी
231. मो0 रेहान, श्री लखनऊ
232. मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
233. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद

---

* mi pquko esa fuokZfprA

234. मौ0 अलीम खां, श्री बुलन्दशहर
235. मौ0 इरफान, श्री मुरादाबाद
236. मौहम्मद युसुफ अंसारी, श्री मुरादाबाद
237. यासर शाह, श्री बहराइच
238. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
239. योगेन्द्रपाल सिंह, श्री कानपुर देहात
240. योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया', श्री गोण्डा
241. रघुनन्दन सिंह भदौरिया, श्रीकानपुर नगर
242. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
243. रघुराज सिंह शाक्य, श्री इटावा
244. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
245. रणजीत सुमन, श्री एटा
246. रमेश चन्द बिन्द, डा0 मिर्जापुर
247. रमेश चन्द्र दुबे, श्री सोनभद्र
248. रमेश प्रसाद कुशवाहा, श्री ललितपुर
249. रविदास मेहरोत्रा, श्री लखनऊ
250. रविन्द्र कुमार मोल्हू, श्री सहारनपुर
251. रवीन्द्र जायसवाल, श्री वाराणसी
252. रविन्द्र भडाना, श्री मेरठ
253. रवि शर्मा, श्री झांसी
254. रश्मि आर्य, डा0 झांसी
255. राकेश कुमार, श्री अलीगढ़
256. आर0 के0 वर्मा, डा0 प्रतापगढ़
257. राकेश प्रताप सिंह, श्री अमेठी
258. राकेश बाबू, श्री फिरोजाबाद
259. राजकिशोर सिंह, श्री बस्ती
260. राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्रीमैनपुरी
261. राजकुमार रावत, श्री मथुरा
262. राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज, श्री महोबा
263. राजबली जैसल, श्री इलाहाबाद
264. राजमती, श्रीमती गोरखपुर
265. राजीव गुम्बर, श्री सहारनपुर
266. राजीव कुमार सिंह, श्री बाराबंकी
267. राजेन्द्र, श्री गोरखपुर
268. राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
269. राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
270. राजेश यादव, श्री शाहजहांपुर
271. राजेश्वरी, श्रीमती हरदोई
272. राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0गोरखपुर
273. राधेलाल रावत, श्री उन्नाव
274. राधे श्याम, श्री अमेठी
275. राधेश्याम सिंह, श्री कुशीनगर
276. राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
277. राम करन आर्य, श्री बस्ती
278. रामखिलाड़ी सिंह यादव, श्री संभल
279. रामगोपाल, श्री बाराबंकी
280. राम गोविन्द, श्री बलिया
281. रामचन्द्र चौधरी, श्री सुल्तानपुर
282. रामचन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
283. रामपाल यादव, श्री सीतापुर
284. रामपाल राजवंशी, श्री सीतापुर
285. राम प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
286. राम मगन, श्री बाराबंकी
287. राममूर्ति वर्मा, श्री अम्बेडकर नगर
288. राममूर्ती सिंह वर्मा, श्री शाहजहांपुर
289. रामलाल अकेला, श्री रायबरेली
290. रामवीर उपाध्याय, श्री हाथरस
291. रामवीर सिंह, श्री फिरोजाबाद
292. रामशरन, श्री लखीमपुर खीरी
293. राम सिंह, श्री प्रतापगढ़
294. रामस्वरूप सिंह, श्री कानपुर देहात
295. रामहेत भारती, श्री सीतापुर
296. रामेश्वर सिंह यादव, श्री एटा
297. रियाज अहमद, श्री पीलीभीत
298. रीता बहुगुणा जोशी, प्रो0 लखनऊ
299. रुचिवीरा, श्रीमती बिजनौर
300. रूबी प्रसाद, श्रीमती सोनभद्र
301. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
302. लक्ष्मीकान्त उर्फ पप्पू निषाद, श्री सन्तकबीर नगर
303. लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0 मेरठ

304. लक्ष्मी गौतम, श्रीमती संभल
305. ललितेश पति त्रिपाठी, श्री मिर्जापुर
306. लालमुन्नी सिंह, श्रीमती सिद्धार्थनगर
307. लोकेन्द्र सिंह, श्री बिजनौर
308. लोकेश दीक्षित, श्री बागपत
309. वकार अहमद शाह, डा0 बहराइच
310. वसीम अहमद, श्री आजमगढ़
311. वहाब चौधरी, श्री गाजियाबाद
312. वाचस्पति, श्री कौशाम्बी
313. विक्रम सिंह, श्री फतेहपुर
314. विजमा यादव, श्रीमती इलाहाबाद
315. विजय कुमार पासवान, श्रीसिद्धार्थनगर
316. विजय मिश्र, श्री
सन्त रविदास नगर (भदोही)
317. विजय कुमार, डा0 गोरखपुर
318. विजय कुमार दूबे, श्री कुशीनगर
319. विजय कुमार मिश्र, श्री गाजीपुर
320. विजय बहादुर पाल, श्री कन्नौज
321. विजय बहादुर यादव, श्री गोरखपुर
322. विजय सिंह, श्री रामपुर
323. विजय सिंह पुत्र प्रेम सिंह, श्रीफर्रुखाबाद
324. विनय तिवारी, श्री लखीमपुर खीरी
325. विनोद तिवारी, श्री महराजगंज
326. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
327. विनोद कुमार उर्फ
पण्डित सिंह, श्री गोण्डा
328. विमला बाथम, श्रीमती गौतमबुद्धनगर
329. विवेक कुमार सिंह, श्री बांदा
330. विशम्भर सिंह, श्री बांदा
331. वीरपाल राठी, श्री बागपत
332. वीर सिंह, श्री चित्रकूट
333. वीरेन्द्र सिंह, श्री बरेली
334. वीरेश यादव, श्री अलीगढ़
335. वेदराम भाटी, श्री गौतमबुद्ध नगर
336. शंखलाल मांझी, श्री अम्बेडकरनगर
337. शकुन्तला देवी, सुश्री शाहजहांपुर
338. शमशेर बहादुर उर्फ
शेरू भैय्या, श्री लखीमपुर खीरी
339. शमीमुल हक, श्री मुरादाबाद
340. शहजिल इस्लाम, श्री बरेली
341. शाकिर अली, श्री देवरिया
342. शारदा प्रताप शुक्ला, श्री लखनऊ
343. शाह आलम उर्फ
गुड्डु जमाली, श्री आजमगढ़
344. शाहिद मंजूर, श्री मेरठ
345. शिव कुमार बेरिया, श्रीकानपुर देहात
346. शिव चरन प्रजापति, श्री हमीरपुर
347. शिव पाल सिंह यादव, श्री इटावा
348. शिव प्रताप यादव, डा0 बलरामपुर
349. शिवाकान्त ओझा, प्रो0 प्रतापगढ़
350. शिवेन्द्र सिंह उर्फ
शिव बाबू, श्री महाराजगंज
351. शेर बहादुर, श्री अम्बेडकरनगर
352. शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री जौनपुर
353. श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्रीवाराणसी
354. श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
355. श्याम बहादुर सिंह यादव, श्रीआजमगढ़
356. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
357. श्रद्धा यादव, श्रीमती जौनपुर
358. श्रीभगवान शर्मा, श्री बुलन्दशहर
359. संगीत सिंह सोम, श्री मेरठ
360. संग्राम यादव, डा0 आजमगढ़
361. संजय कपूर, श्री रामपुर
362. संजय प्रताप जयसवाल, श्री बस्ती
363. सईद अहमद, श्री इलाहाबाद
364. सचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री जौनपुर
365. सतवीर सिंह गुर्जर, श्रीगौतमबुद्ध नगर

366. सतीश कुमार निगम 'एडवोकेट', श्री कानपुर नगर
367. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
368. सत्यदेव पचौरी, श्री कानपुर नगर
369. सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री मेरठ
370. सत्यवीर मुन्ना, श्री इलाहाबाद
371. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
372. सन्तराम कुशवाहा, श्री जालौन
373. सन्तोष पाण्डेय, श्री सुल्तानपुर
374. सलिल विश्नोई, श्री कानपुर नगर
375. सिनोद कुमार शाक्य (दीपू), श्रीबदायूं
376. सिबगतुल्ला अंसारी, श्री गाजीपुर
377. सियाराम सागर, डा0 बरेली
378. सीमा, श्रीमती जौनपुर
379. सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री फतेहपुर
380. सुखदेवी वर्मा, श्रीमती इटावा
381. सुदामा प्रसाद, श्री महराजगंज
382. सुदेश शर्मा, श्री गाजियाबाद
383. सुधाकर, श्री मऊ
384. सुधीर कुमार, श्री उन्नाव
385. सुनील कुमार सिंह यादव, श्रीसोनभद्र
386. सुनील कुमार लाला, श्रीलखीमपुर खीरी
387. सुब्बा राम, श्री गाजीपुर
388. सुभाष पासी, श्री गाजीपुर
389. सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री रायबरेली
390. सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी
391. सुरेश राणा, श्री शामली
392. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
393. सुरेश बंसल, श्री गाजियाबाद
394. सुल्तान बेग, श्री बरेली
395. सुशील सिंह, श्री चन्दौली
396. सूरज पाल सिंह, श्री आगरा
397. सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमतीगाजीपुर
398. सोबरन सिंह यादव, श्री मैनपुरी
399. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री कुशीनगर
400. हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री लखीमपुर खीरी
401. हरिओउम् यादव, श्री फिरोजाबाद
402. हेमराज वर्मा, श्री पीलीभीत
403. हेमलता चौधरी, श्रीमती बागपत
404. 'रिक्त गाजीपुर

'श्री कैलाश निर्वाचन क्षेत्र संख्या–376 जंगीपुर, जिला गाजीपुर की दिनांक 09 फरवरी, 2016 के अपराह्न में हुई मृत्यु के फलस्वरूप।

महामहिम राज्यपाल
श्री राम नाईक
मंत्रि–परिषद्

क्रमांक	नाम	कार्य विभाग (पोर्टफोलियो)
1	2	3
1	श्री अखिलेश यादव मुख्य मंत्री	सामान्य प्रशासन, सचिवालय प्रशासन, गृह, गोपन, सतर्कता, नियुक्ति, कार्मिक, सूचना, निर्वाचन, वित्त, संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन (व्यापार कर), न्याय, विधायी, नियोजन, प्रोटोकाल, नागरिक उड्डयन, राज्य सम्पत्ति, आबकारी, मद्यनिषेध, ऊर्जा, चिकित्सा शिक्षा, औद्योगिक विकास, जन्तु उद्यान, आवास एवं शहरी नियोजन, नगर भूमि, गन्ना विकास, चीनी मिलें, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय, प्रशासनिक सुधार, पर्यावरण, इलेक्ट्रानिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी, कार्यक्रम कार्यान्वयन, राष्ट्रीय एकीकरण, आयुष, अवस्थापना, समन्वय, भाषा, कृषि विदेश व्यापार, कृषि निर्यात, कृषि विपणन, वाह्य सहायतित परियोजना, समग्र ग्राम्य विकास, बाल विकास एवं पुष्टाहार, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य।
2	श्री मो0 आजम खाँ	संसदीय कार्य, मुस्लिम वक्फ, नगर विकास, जल सम्पूर्ति, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, शहरी समग्र विकास, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज।
3	श्री शिवपाल सिंह यादव	लोक निर्माण, सिंचाई एवं जल संसाधन, बाढ़ नियंत्रण, सहकारिता, भूमि विकास, परती भूमि विकास विभाग, राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन।
4	श्री अहमद हसन	बेसिक शिक्षा
5	श्री अवधेश प्रसाद	होमगार्ड्स, प्रान्तीय रक्षक दल
6	श्री ओम प्रकाश सिंह	पर्यटन
7	श्री पारस नाथ यादव	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा
8	श्री रामगोविन्द चौधरी	समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण, सैनिक कल्याण।
9	श्री दुर्गा प्रसाद यादव	वन

10	श्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी	खादी एवं ग्रामोद्योग
11	श्री राजकिशोर सिंह	लघु सिंचाई, पशुधन तथा पंचायती राज।

क्रमांक	नाम	कार्य विभाग (पोर्टफोलियो)
1	2	3
12	श्री राजेन्द्र चौधरी	राजनैतिक पेंशन
13	श्री राममूर्ति वर्मा	दुग्ध विकास
14	श्री रघुराज प्रताप सिंह ''राजा भइया''	स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क, पंजीयन, नागरिक सुरक्षा।
15	श्री गायत्री प्रसाद प्रजापति	भू–तत्व एवं खनिकर्म
16	श्री इकबाल महमूद	खाद्य एवं औषधि प्रशासन
17	श्री महबूब अली	रेशम एवं वस्त्रोद्योग, अर्थ एवं संख्या व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास।
18	श्री शाहिद मंजूर	श्रम एवं सेवायोजन
19	श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'	ग्राम्य विकास
20	श्री कमाल अख्तर	खाद्य एवं रसद
21	श्री विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह	कृषि (कृषि विदेश व्यापार, कृषि निर्यात एवं कृषि विपणन को छोड़कर), कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान।
22	श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया	कारागार
23	श्री साहब सिंह सैनी	पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास
24	श्री बलराम यादव	माध्यमिक शिक्षा
25	श्री नारद राय	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

1	श्रीमती अरूण कुमारी कोरी	संस्कृति
2	श्री विजय कुमार मिश्र	धर्मार्थ कार्य
3	श्री रियाज अहमद	मत्स्य एवं सार्वजनिक उद्यम
4	श्री फरीद महफूज किदवई	प्राविधिक शिक्षा
5	श्री मूल चन्द्र चौहान	उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण
6	श्री राम सकल गूर्जर	खेल एवं युवा कल्याण
7	श्री नितिन अग्रवाल	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन
8	श्री यासर शाह	परिवहन

9	श्री मदन चौहान	मनोरंजन कर
10	श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा	महिला कल्याण
11	श्री रविदास मेहरोत्रा	परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण।
12	श्री शारदा प्रताप शुक्ला	उच्च शिक्षा

राज्य मंत्री

क्रमांक	नाम	कार्य विभाग (पोर्टफोलियो)
1	2	3
1	श्री वसीम अहमद	बाल विकास, पुष्टाहार, बेसिक शिक्षा एवं ऊर्जा
2	डा0 शिव प्रताप यादव	जन्तु उद्यान, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
3	श्री राजीव कुमार सिंह	कृषि, (कृषि विदेश व्यापार, कृषि निर्यात एवं कृषि विपणन को छोड़कर), कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान एवं धर्मार्थ कार्य।
4	श्री अभिषेक मिश्रा	व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास
5	श्री नरेन्द्र वर्मा	समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण व सैनिक कल्याण।
6	श्री सुरेन्द्र सिंह पटेल	लोक निर्माण एवं सिंचाई
7	श्री मानपाल सिंह	परिवहन
8	श्री शंखलाल मांझी	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण।
9	श्री कैलाश चौरसिया	बाल विकास एवं पुष्टाहार व बेसिक शिक्षा।
10	श्री रामपाल राजवंशी	कारागार
11	श्री रामकरन आर्य	वाह्य सहायतित परियोजना, समग्र ग्राम विकास, खेल एवं युवा कल्याण, आबकारी।
12	श्री जगदीश सोनकर	जल संसाधन एवं परती भूमि विकास।
13	श्री राममूर्ती सिंह वर्मा	पिछड़ा वर्ग कल्याण
14	श्री विजय बहादुर पाल	माध्यमिक शिक्षा
15	श्री राधेश्याम सिंह	कृषि, (कृषि विदेश व्यापार, कृषि निर्यात एवं कृषि विपणन को छोड़कर), कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान तथा चिकित्सा शिक्षा

16	श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'	नियोजन एवं ऊर्जा
17	श्री ओमकार सिंह यादव	ग्राम्य विकास
18	श्री तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय	वन

क्रमांक	नाम	कार्य विभाग (पोर्टफोलियो)
1	2	3
19	श्री सुधीर कुमार रावत	सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
20	श्री हेमराज वर्मा	खाद्य तथा रसद
21	श्री लक्ष्मीकान्त उर्फ पप्पू निषाद	खाद्य तथा रसद
22	श्री वंशीधर बौद्ध	समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण व सैनिक कल्याण

नेता विरोधी दल
श्री स्वामी प्रसाद मौर्य

उत्तर प्रदेश विधान सभा के पदाधिकारी तथा अधिष्ठाता मण्डल

अध्यक्ष

श्री माता प्रसाद पाण्डेय

उपाध्यक्ष

रिक्त

प्रमुख सचिव
श्री प्रदीप कुमार दुबे

अधिष्ठाता मण्डल (2015–2016)

1–श्री अनूप सण्डा, सदस्य, विधान सभा (सुल्तानपुर)
2–श्री शाकिर अली, सदस्य, विधान सभा (देवरिया)
3–श्री उदय राज, सदस्य, विधान सभा (उन्नाव)
4–श्रीमती आशा किशोर, सदस्य, विधान सभा (रायबरेली)
5–डा0 धर्म सिंह सैनी, सदस्य, विधान सभा (सहारनपुर)
6–श्री राजबली जैसल, सदस्य, विधान सभा (इलाहाबाद)
7–डा0 राधामोहन दास अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा (गोरखपुर)
8–श्री अनुग्रह नारायण सिंह, सदस्य, विधान सभा (इलाहाबाद)
9–रिक्त।
10–रिक्त।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोलहवीं विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 26 फरवरी, 2016 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य–280

1. अंसार अहमद, श्री इलाहाबाद
2. अखिलेश प्रताप सिंह, श्री देवरिया
3. अगयश राम सरन वर्मा, श्री पीलीभीत
4. अजय कुमार, डा0 इलाहाबाद
5. अजय कुमार 'लल्लू', श्री कुशीनगर
6. अजीत कुमार, श्री फर्रुखाबाद
7. अजीमुल हक पहलवान अंसारी, हाजी अम्बेडकर नगर
8. अताउररहमान, श्री बरेली
9. अनिल वर्मा, श्री उन्नाव
10. अनीसुर्ररहमान, श्री मुरादाबाद
11. अनूप कुमार गुप्ता, श्री सीतापुर
12. अब्दुल मशहूद खाँ, श्री बलरामपुर
13. अभय नरायन सिंह पटेल, श्री आजमगढ़
14. अभय सिंह, श्री फैजाबाद
15. अभिषेक मिश्र, श्री लखनऊ
16. अमित गौरव यादव, श्री एटा
17. अयोध्या प्रसाद पाल, श्री फतेहपुर
18. अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री बाराबंकी
19. अरविन्द सिंह यादव, श्री कन्नौज
20. अराधना मिश्र 'मोना' श्रीमती प्रतापगढ़
21. अरूण कुमारी कोरी, श्रीमती कानपुर नगर
22. अली यूसूफ अली, श्री रामपुर
23. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री लखीमपुर खीरी
24. अविनाश कुशवाहा, श्री सोनभद्र
25. अशफाक अली खां, श्री अमरोहा
26. आदिल शेख, श्री आजमगढ़
27. आनन्द सिंह, कुंवर गोण्डा
28. आनन्द सेन, श्री फैजाबाद
29. आबिद रजा खां, श्री बदायूं
30. आरिफ अनवर हाशमी, श्री बलरामपुर
31. आलमबदी, श्री आजमगढ़
32. आलोक कुमार शाक्य, श्री मैनपुरी
33. आशा किशोर, श्रीमती अमेठी
34. आशीष कुमार यादव, श्री एटा
35. आशुतोष टण्डन (गोपाल जी), श्री लखनऊ
36. आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री बदायूं
37. इकबाल महमूद, श्री संभल
38. इन्दल कुमार, श्री लखनऊ
39. इन्द्रजीत कोरी, श्री कानपुर नगर
40. इन्द्रजीत सरोज, श्री कौशाम्बी
41. इन्द्रपाल सिंह, श्री कानपुर देहात

---

* mi pquko esa fuokZfprA

42. इन्द्राणी देवी, श्रीमती श्रावस्ती
43. इरफान सोलंकी, हाजी कानपुर नगर
44. उदयराज, श्री उन्नाव
45. उपेन्द्र तिवारी, श्री बलिया
46. उमाकान्ती, श्रीमती जालौन
47. उमाशंकर, श्री बलिया
48. उमेश पाण्डेय, श्री मऊ
49. उर्मिला देवी, श्रीमती महोबा
50. ओम प्रकाश वर्मा, श्री फिरोजाबाद
51. कपिल देव अग्रवाल, श्री मुजफ्फरनगर
52. काली चरन सुमन, श्री आगरा
53. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
54. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
55. कौशल सिंह कुंवर, श्री महराजगंज
56. गजराज सिंह, श्री हापुड़
57. गजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
58. गयादीन अनुरागी, श्री हमीरपुर
59. गायत्री प्रसाद, श्री अमेठी
60. गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय, श्री इलाहाबाद
61. गुलाब चन्द, श्री जौनपुर
62. गुलाम मौहम्मद, श्री मेरठ
63. गोमती यादव, श्री लखनऊ
64. चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री चित्रकूट
65. चन्द्रा रावत, श्रीमती लखनऊ
66. छोटेलाल वर्मा, श्री आगरा
67. जगतम्बा सिंह, श्री मिर्जापुर
68. जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
69. जगराम पासवान, श्री बलरामपुर
70. जन्मेजय सिंह, श्री देवरिया
71. जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री फर्रुखाबाद
72. जमीर उल्ला खां, श्री अलीगढ़
73. जय प्रकाश निषाद, श्री गोरखपुर
74. जय प्रकाश अंचल, श्री बलिया
75. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
76. जाकिर अली, श्री गाजियाबाद
77. जाहीद बेग, श्री सन्तरविदास नगर (भदोही)
78. जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री बस्ती
79. ज्योत्सना श्रीवास्तव, श्रीमती वाराणसी
80. तसलीम, श्री बिजनौर
81. तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय, श्री फैजाबाद
82. तेजपाल सिंह, श्री मथुरा
83. त्रिभुवन राम, श्री वाराणसी
84. त्रिलोकीराम, श्री अलीगढ़
85. दयाशंकर वर्मा, श्री जालौन
86. दलजीत सिंह, श्री बांदा
87. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
88. दिलनवाज खान, श्री बुलन्दशहर
89. दीपक पटेल, श्री इलाहाबाद
90. दीपनारायण सिंह (दीपक यादव), श्री झांसी
91. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
92. देवेन्द्र अग्रवाल, श्री हाथरस
93. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली
94. धर्मराज, श्री बाराबंकी
95. धर्मेश सिंह तोमर, श्री हापुड़
96. नजीवा खान जीनत, श्रीमती कासगंज
97. नदीम जावेद, श्री जौनपुर

* mi pquko esa fuokZfprA

98. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
99. नागेन्द्र सिंह ''मुन्ना यादव'', श्री प्रतापगढ़
100. नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्री शाहजहांपुर
101. नूर सलीम राणा, श्री मुजफ्फरनगर
102. पंकज कुमार मलिक, श्री शामली
103. पंकज गुप्ता, श्री उन्नाव
104. परवेज अहमद (टंकी), हाजी इलाहाबाद
105. पिंकी सिंह, श्रीमती संभल
106. पीतमराम, श्री पीलीभीत
107. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
108. पूर्णमासी देहाती, श्री कुशीनगर
109. प्रदीप कुमार यादव, श्री औरैया
110. प्रदीप माथुर, श्री मथुरा
111. प्रभूदयाल वाल्मीकि, श्री मेरठ
112. प्रमोद कुमार गुप्ता, श्री औरैया
113. प्रशान्त कुमार सिंह (राहुल सिंह), श्री इलाहाबाद
114. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
115. ''फसीहा मंजर'' ''गजाला लारी'', श्रीमती देवरिया
116. फेरन लाल, श्री ललितपुर
117. बंशीधर बौद्ध, श्री बहराइच
118. बदलू खां, श्री उन्नाव
119. बब्बन सिंह चौहान, श्री चन्दौली
120. बाबूलाल, श्री गोण्डा
121. बावन सिंह, श्री गोण्डा
122. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमती बुलन्दशहर
123. बृज लाल सोनकर, श्री आजमगढ़
124. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
125. बृजेश कुमार, श्री हरदोई
126. बेचई सरोज, श्री आजमगढ़
127. बैजनाथ, श्री मऊ
128. भगवत सरन गंगवार, श्री बरेली
129. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
130. भीम प्रसाद सोनकर, श्री अम्बेडकरनगर
131. मदन गोपाल वर्मा, श्री फतेहपुर
132. मदन सिंह उर्फ सन्तोष, श्री औरैया
133. मधुबाला, श्रीमती सन्त रविदास नगर (भदोही)
134. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
135. मनीष रावत, श्री सीतापुर
136. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
137. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
138. ममतेश शाक्य, श्री कासगंज
139. महावीर सिंह, कुं0 हरदोई
140. महावीर सिंह राणा, श्री सहारनपुर
141. महेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी
142. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
143. मानपाल सिंह, श्री कासगंज
144. मविया अली, श्री सहारनपुर
145. मुकुट बिहारी वर्मा, श्री बहराइच
146. मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप, श्री बहराइच
147. मुख्तार अंसारी, श्री मऊ
148. मुसर्रत अली बिट्टन, श्री बदायूं
149. मो0 अयूब, डा0 सन्तकबीर नगर
150. मो0 आसिफ, श्री फतेहपुर
151. मौहम्मद इकबाल, श्री बिजनौर
152. मो0 जासमीर अंसारी, श्री सीतापुर
153. मो0 मुस्लिम, श्री अमेठी

---

* mi pquko esa fuokZfprA

154.मो0 रेहान, श्री लखनऊ
155.मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
156.मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
157.मौ0 इरफान, श्री मुरादाबाद
158.मौहम्मद युसुफ अंसारी, श्री मुरादाबाद
159.यासर शाह, श्री बहराइच
160.योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
161.योगेन्द्रपाल सिंह, श्री कानपुर देहात
162.योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया', श्री गोण्डा
163. रघुनन्दन सिंह भदौरिया, श्री कानपुर नगर
164.रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
165.रघुराज सिंह शाक्य, श्री इटावा
166.रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
167.रणजीत सुमन, श्री एटा
168.रमेश चन्द बिन्द, डा0 मिर्जापुर
169.रविदास मेहरोत्रा, श्री लखनऊ
170.रवीन्द्र जायसवाल, श्री वाराणसी
171.रविन्द्र भडाना, श्री मेरठ
172.आर0 के0 वर्मा, डा0 प्रतापगढ़
173.राकेश प्रताप सिंह, श्री अमेठी
174.राजकिशोर सिंह, श्री बस्ती
175.राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्री मैनपुरी
176.राजकुमार रावत, श्री मथुरा
177.राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज, श्री महोबा
178.राजबली जैसल, श्री इलाहाबाद
179.राजमती, श्रीमती गोरखपुर
180.राजीव गुम्बर, श्री सहारनपुर
181.राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
182.राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
183.राजेश्वरी, श्रीमती हरदोई
184.राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0 गोरखपुर
185.राधेलाल रावत, श्री उन्नाव
186.राधे श्याम, श्री अमेठी
187.राधेश्याम सिंह, श्री कुशीनगर
188.राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
189.राम करन आर्य, श्री बस्ती
190.रामगोपाल, श्री बाराबंकी
191.रामचन्द्र चौधरी, श्री सुल्तानपुर
192.रामचन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
193.रामपाल यादव, श्री सीतापुर
194.रामपाल राजवंशी, श्री सीतापुर
195.राममूर्ति वर्मा, श्री अम्बेडकर नगर
196.रामलाल अकेला, श्री रायबरेली
197.रामवीर उपाध्याय, श्री हाथरस
198.रामवीर सिंह, श्री फिरोजाबाद
199.राम सिंह, श्री प्रतापगढ़
200.रामहेत भारती, श्री सीतापुर
201.रामेश्वर सिंह यादव, श्री एटा
202.रीता बहुगुणा जोशी, प्रो0 लखनऊ
203.रुचिवीरा, श्रीमती बिजनौर
204.रूबी प्रसाद, श्रीमती सोनभद्र
205.रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
206.लक्ष्मी गौतम, श्रीमती संभल
207.ललितेश पति त्रिपाठी, श्री मिर्जापुर
208.लालमुन्नी सिंह, श्रीमती सिद्धार्थनगर
209.लोकेन्द्र सिंह, श्री बिजनौर
210.लोकेश दीक्षित, श्री बागपत
211.वसीम अहमद, श्री आजमगढ़
212.वहाब चौधरी, श्री गाजियाबाद
213.वाचस्पति, श्री कौशाम्बी
214.विजमा यादव, श्रीमती इलाहाबाद
215.विजय कुमार पासवान, श्री सिद्धार्थनगर
216.विजय कुमार, डा0 गोरखपुर
217.विजय बहादुर पाल, श्री कन्नौज

218.विजय बहादुर यादव, श्री गोरखपुर
219.विनय तिवारी, श्री लखीमपुर खीरी
220.विनोद तिवारी, श्री महराजगंज
221.विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
222.विमला बाथम, श्रीमती गौतमबुद्धनगर
223.विशम्भर सिंह, श्री बांदा
224.वीरपाल राठी, श्री बागपत
225.वीर सिंह, श्री चित्रकूट
226.वेदराम भाटी, श्री गौतमबुद्ध नगर
227.शकुन्तला देवी, सुश्री शाहजहांपुर
228.शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या, श्री लखीमपुर खीरी
229.शमीमुल हक, श्री मुरादाबाद
230.शहजिल इस्लाम, श्री बरेली
231.शाकिर अली, श्री देवरिया
232.शारदा प्रताप शुक्ला, श्री लखनऊ
233.शाह आलम उर्फ गुड्डु जमाली, श्री आजमगढ़
234.शाहिद मंजूर, श्री मेरठ
235.शिव कुमार बेरिया, श्रीकानपुर देहात
236.शिव चरन प्रजापति, श्री हमीरपुर
237.शिव पाल सिंह यादव, श्री इटावा
238.शिव प्रताप यादव, डा0 बलरामपुर
239.शिवाकान्त ओझा, प्रो0 प्रतापगढ़
240.शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री महाराजगंज
241.शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री जौनपुर
242.श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्री वाराणसी
243.श्याम बहादुर सिंह यादव, श्री आजमगढ़
244.श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
245.श्रद्धा यादव, श्रीमती जौनपुर
246.संग्राम यादव, डा0 आजमगढ़
247.संजय कपूर, श्री रामपुर
248.संजय प्रताप जयसवाल, श्री बस्ती
249.सचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री जौनपुर
250.सतीश कुमार निगम 'एडवोकेट', श्री कानपुर नगर
251.सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
252.सत्यदेव पचौरी, श्री कानपुर नगर
253.सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री मेरठ
254.सत्यवीर मुन्ना, श्री इलाहाबाद
255.सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
256.सन्तराम कुशवाहा, श्री जालौन
257.सलिल विश्नोई, श्री कानपुर नगर
258.सिनोद कुमार शाक्य (दीपू), श्री बदायूं
259.सिबगतुल्ला अंसारी, श्री गाजीपुर
260.सीमा, श्रीमती जौनपुर
261.सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री फतेहपुर
262.सुखदेवी वर्मा, श्रीमती इटावा
263.सुदामा प्रसाद, श्री महराजगंज
264.सुदेश शर्मा, श्री गाजियाबाद
265.सुधाकर, श्री मऊ
266.सुधीर कुमार, श्री उन्नाव
267.सुनील कुमार लाला, श्री लखीमपुर खीरी
268.सुब्बा राम, श्री गाजीपुर
269.सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री रायबरेली
270.सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी
271.सुरेश राणा, श्री शामली

272.सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
273.सुरेश बंसल, श्री गाजियाबाद
274.सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमती गाजीपुर
275.सोबरन सिंह यादव, श्री मैनपुरी
276.स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री कुशीनगर
277.हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री लखीमपुर खीरी
278.हरिओउम् यादव, श्री फिरोजाबाद
279.हेमराज वर्मा, श्री पीलीभीत
280.हेमलता चौधरी, श्रीमती बागपत

नोट :–बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री अहमद हसन) तथा माध्यमिक शिक्षा मंत्री श्री बलराम यादव भी सदन में उपस्थित थे।

ख1ण्00, आगरा में दलित कार्यकर्ता की हत्या से सम्बन्धित नियम–311 की सूचना को सर्वप्रथम लिये जाने की मांग

(भारतीय जनता पार्टी के अनेक सदस्यगण सदन के वेल में आकर अपनी–अपनी बात कहने लगे और सरकार विरोधी नारे लगाने लगे जिससे घोर व्यवधान की स्थिति उत्पन्न हो गई।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल (सदन के वेल से)–

माननीय अध्यक्ष महोदय, 7.00 बजे हत्या की घोषणा की गई और 10.00 बजे उस आदमी की हत्या कर दी गई, दिन–दहाड़े बाजार में घेर करके।

श्री रवीन्द्र जायसवाल (सदन के वेल से)–

मान्यवर, बी0एच0यू0 के छात्र राजेश यादव की बहन को छेड़ा गया, वह एफ0आई0आर0 कराने गया, पुलिस ने एफ0आई0आर0 नहीं किया, बाद में उसकी हत्या कर दी गई।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग अपना–अपना स्थान ग्रहण करें और शान्तिपूर्वक सदन की कार्यवाही चलने दें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मानीय अध्यक्ष जी, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले एक व्यक्ति की हत्या की गई, पूरा प्रदेश में मान्यवर, कानून–व्यवस्था पर कोई नियंत्रण नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

आप नियमों में अपनी सूचना दें, नियम–56 में इसे लायें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, हमने नियम–311 में नोटिस दिया है।

श्री अध्यक्ष–

चलिये हमने नियम–56 में मान लिया है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, ऐसा है, आखिरकार यह चुनाव की वजह से हत्या की गई, दो दिन पहले हत्या की सुपारी दी गई और सबुह 7.00 बजे पूरे क्षेत्र को मालूम था कि इसकी हत्या हो जायेगी। मान्यवर, चाहे आगरा हो, चाहे बनारस हो, चाहे प्रतापगढ़ हो, चाहे पीलीभीत हो, पूरे प्रदेश में जंगल राज कायम है, कानून–व्यवस्था पर कोई नियंत्रण नहीं है। घटनायें रुक नहीं रही हैं, मान्यवर आखिरकार वह कौन सा दिन आयेगा मान्यवर, जब इन घटनाओं पर रोक लगेगी।

श्री अध्यक्ष–

इसे आपने नियम–311 में दिया है, लेकिन नियम–56 में आप इस पर बोलियेगा, यहां सदन के वेल में एकत्रित होकर सदन की कार्यवाही में व्यवधान क्यों उत्पन्न कर रहे हैं। डा0 साहब आप इन लोगों को लेकर अपने स्थान पर चलिये, आप नियम जानते हैं, तो नियम–56 में आप बोलियेगा, चलिये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, आखिरकार हम यह पूछना चाहते हैं सरकार से कि इस प्रकार की घटनाओं पर कोई नियंत्रण नहीं हो रहा है, पूरे प्रदेश में इस प्रकार की घटनायें हो रही हैं, आज फिर से एक सिपाही मारा गया, एक प्रतापगढ़ में मारा गया, एक पीलीभीत में मारा गया।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग सदन की कार्यवाही क्यों बाधित कर रहे हैं, नियम–56 में जब आयेगा, तब बोलियेगा, चलिये अपना–अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, आपके माध्यम से हम सरकार से यह जरूर चाहते हैं कि इन घटनाओं पर नियंत्रण कैसे और कब तक लगेगा।

श्री अध्यक्ष–

आप अपना सुझाव नियम–56 जब लिया जायेगा, तब उसमें दीजिएगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, एक दलित जाति का व्यक्ति आगरा में जिस प्रकार सरे बाजार दिन दहाड़े, सर के पास गोली रख कर पांच लोगों ने उसे गोलियों से भून दिया। इन घटनाओं को आखिरकार कब तक बर्दाश्त किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग अपने स्थान पर चलें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, मेरी मांग यह है कि सदन के तमाम नियमों को निलम्बित करके इस पर सबसे पहले चर्चा कराई जाय।

श्री अध्यक्ष–

आपकी नोटिस को नियम–56 में मान लिया गया है, नियम–56 जब लिया जायेगा, तब इस पर बोलियेगा।

(सदन के वेल में उपस्थित सदस्यगण सरकार विरोधी नारे लगाते रहे)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग अपने स्थान पर चलें, अगर आप सदन नहीं चलने देना चाहते हैं, तो साफ बता दें स्पष्ट कि सदन नहीं चलने देंगे। यह सोलहवीं विधान सभा का आखिरी

बजट सत्र है, अब कोई ऐसा काम हम नहीं करना चाहते हैं जो आपके भी अनुरूप न हो और मेरे भी अनुरूप न हो, इसलिए मेरा निवेदन है आप लोग अपने स्थान पर जायें। जब आप लोगों को नियम–56 में बोलने का मौका दिया जा रहा है, तो अभी क्यों हल्ला मचा रहे हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, नियम–311 में हमें सुना जाय।

श्री अध्यक्ष–

आपने अपनी बात कह ली, तो नियम–56 का महत्व भी खत्म कर देंगे, जब आप सब अभी कह डाल रहे हैं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

चलिए, अब यह पांच लोग इतना कर रहे हैं, इतने लोग बैठे हैं। दस लोग मिल करके पूरे विधान सभा को बाधित कर रहे हैं। आप तो कम से कम पढ़े–लिखे हो।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, नियम–56 को सबसे पहले ले लीजिए।

श्री अध्यक्ष–

अब यही मैं पहले कह रहा हूं, इतना हल्ला क्यों किया। आप मानते हो लेकिन हल्ला करके, हम तो पहले से कह रहे थे नियम–56 में ले लेंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, लेकिन सबसे पहले ले लीजिए।

श्री अध्यक्ष–

अच्छा, चलिए। अब जाइए न, नेता बुला रहे हैं। जाइए।

(वेल में आए हुए भारतीय जनता पार्टी के सदस्य अपने–अपने आसन पर वापस चले गए)

[11.06, प्रश्नोत्तर

नत्थी (क)

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में खाद्य पदार्थों के बढ़ते हुए मूल्यों पर अंकुश लगाने हेतु सरकार की योजना की जानकारी

'01–श्री नदीम जावेद

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में खाद्य पदार्थों के बढ़ते हुए मूल्यों पर अंकुश लगाने हेतु कोई योजना सरकार ने बनाई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री (श्री हेमराज वर्मा)–

जी हां।

1–राज्य स्तर पर खाद्यायुक्त की अध्यक्षता में, मण्डल स्तर पर मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में तथा जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में ''मूल्य नियंत्रण प्रकोष्ठ'' स्थापित किया गया है जिसकी समय–समय पर बैठक आयोजित कर आवश्यक वस्तुओं की मूल्य वृद्धि की समीक्षा की जाती है।

2–दालों पर संग्रह सीमा लागू की गयी है।

3–प्रदेश/भारत सरकार द्वारा दाल एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं के बाजार भाव की निरन्तर समीक्षा की जाती है।

4–जमाखोरी व कालाबाजारी के विरुद्ध जिलाधिकारियों द्वारा कार्यवाही की जाती है।

5–रिटेल आउटलेट खुलवाकर उचित मूल्य पर उपभोक्ताओं को दालों का वितरण किया जाता है।

6–कर्मचारी कल्याण निगम के माध्यम से 5000 कुन्तल अरहर की दाल का उठान किया गया है, जिसकी प्रोसेसिंग कराने के उपरान्त रु0 120 प्रति किलो की दर से कर्मचारी कल्याण निगम के विभिन्न डिपो के माध्यम से अरहर की दाल का वितरण उपभोक्ताओं में कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री नदीम जावेद–

मान्यवर, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे अनुपूरक पूछने का अवसर दिया। 2015 के जो आंकड़े हैं, वह इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि जो मंहगाई की दर है, वह लगभग 64 प्रतिशत तक बढ़ी है। राज्य सरकार के आंकड़ों के अनुसार जो फसलों की तबाही हुई है, वह 33 प्रतिशत है। लेकिन एक और स्टडी है, 'सेंटर फॉर साइंस एण्ड इनवायरमेण्ट' की, यह एक बड़ी संस्था है, उसके आंकड़ों के अनुसार लगभग 78 प्रतिशत फसल की तबाही हुई है। अध्यक्ष जी, डीजल पर जो वैट है, वह उत्तर प्रदेश में 9.7 प्रतिशत है, पेट्रोल पर 7.2 है, और जो कच्चा तेल आता है, उस पर किसी राज्य में वैट नहीं लगता है, केवल उत्तर प्रदेश में 5 प्रतिशत अधिक लगता है। अध्यक्ष जी, मेरा जो मूल प्रश्न है, वह यह है कि एक अलग तरह की परिस्थिति इस वर्ष, इस राज्य के अन्दर उत्पन्न होने वाली है। राज्य सरकार ने जो जवाब दिया है, वह बहुत ही जनरल जवाब है और इसमें कोई स्पेसिफिक बात नहीं है। रियल चैलेन्ज यह है कि जो मंहगाई इस वर्ष बढ़ेगी, चूंकि जो मांग है और जो पैदावार है उस पर एक बहुत भारी अंतर है, तो इसको किस प्रकार से राज्य सरकार पूरा करेगी और पूरा करने के साथ–साथ मंहगाई पर नियन्त्रण किस प्रकार से रखेगी ?

श्री हेमराज वर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे माननीय सदस्य जी का जो प्रश्न था, उसका पूरा जवाब तो दे दिया गया है और इसमें आवश्यक वस्तुओं के मूल्य पर नियंत्रण रखने की

जो बात है, इसके सम्बन्ध में शासन के पत्रांक : 565/29–7–15–ड–20/2015, दिनांक 21 दिसम्बर, 2015 द्वारा राज्य स्तर पर आयुक्त, खाद्य रसद विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ मण्डल स्तर पर मण्डलायुक्त एवं जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में मूल्य अनुश्रवण प्रकोष्ठ का गठन किया गया है।

प्रदेश में आगरा, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, हापुड़ एवं झांसी की मण्डियों से थोक एवं फुटकर बाजार भाव प्राप्त कर उक्त प्रकोष्ठ द्वारा अनुश्रवण एवं समीक्षा किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य रूप से आवश्यक वस्तुओं में गेहूं, चावल, दालों, खाद्य तेल, आलू, प्याज एवं टमाटर पर विशेष ध्यान केन्द्रित किये जा रहे है। जमाखोरी एवं कालाबाजारी के विरुद्ध अभियान हेतु प्रदेश के जिलाधिकारियों को दालों, आलू, प्याज की उपलब्धता तथा बाजार भाव में निगरानी रखने, जमाखोरी एवं कालाबाजारी पर प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम द्वारा रिटेल आउटलेट खुलवा कर गरीब बस्तियों में उचित दर पर दालें, आलू एवं प्याज का वितरण कराने तथा थोक विक्रेताओं के साथ बैठक कर अन्य स्थान पर भी आउटलेट खुलवा कर वितरण कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। दालों की स्टाक सीमा की अधिसूचना दिनांक 19–11–2015 द्वारा उत्तर प्रदेश अनुसूचित वस्तु व्यापारी (लाइसेंस देने और अपसंचय पर निर्बन्धन) (92वां संशोधन) आदेश, 2015 के माध्यम से संशोधन कर दालों पर स्टाक सीमा दिनांक 30 सितम्बर, 2016 तक लागू रहने की अधिसूचना जारी की जा चुकी है। उक्त तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत दालों के सम्बन्ध में प्रवर्तन की कार्रवाई भी की जा रही है जिसके सफल परिणाम प्राप्त हुए हैं। उक्त के अतिरिक्त खाद्य आयुक्त कार्यालय द्वारा दालों की जमाखोरी एवं कालाबाजारी पर निगरानी रखने तथा मूल्य एवं आवक की निरन्तर समीक्षा करते हुए प्रतिदिन की गई कार्यवाही की सूचना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में सभी अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

मान्यवर, किसी भी वस्तु का दाम डिमाण्ड और सप्लाई से तय होता है। कालाबाजारी तो तब हो जब चीज उपलब्ध हो। सरकार ने तीन दिन पूर्व इस सदन में स्वयं स्वीकार किया है कि दाल का उत्पादन आज से दो साल पहले 23 लाख टन होता था जो घट करके 14 लाख टन हो गया। आपने भी सुना, हम लोगों ने भी सुना तो जब सरकार स्वयं यह मानती है कि दाल का उत्पादन घट गया। घट गया तो चीजें महंगी हो गईं और सरकार को इस मूल्य पर नियंत्रण करना था तो सरकार को अन्य प्रान्तों से दाल मंगवा करके उत्तर प्रदेश में उपलब्ध कराना चाहिए था। मैं मा0 मंत्री जी से सिर्फ यही जानना चाहता हूं कि जब सरकार के पास इस बात के आंकड़े थे कि दाल का उत्पादन कम हो गया, दाल की कमी हो गई, दाल का मूल्य बढ़ जाएगा तो सरकार ने अन्य प्रान्तों से कितनी दाल मंगवा करके, इस प्रान्त में आयात करके नागरिकों को उपलब्ध कराने का प्रयास किया।

श्री अध्यक्ष–

लिखा तो है कि कल्याण निगम से 5000 कुन्टल मंगवाई है।

श्री हेमराज वर्मा–

मा0 अध्यक्ष जी, जहां तक दालों की पैदावार की बात है तो पिछले वर्ष मौसम में अचानक ऐसी तब्दीली आई जिससे दाल ही नहीं अन्य फसलें भी चौपट हो गईं। अचानक जब तैयार फसलें बर्बाद हो गईं तो यह भी एक समस्या रही। कालाबाजारी और ज्यादा स्टॉक करने वाली यह भी एक समस्या रही। इसके सम्बन्ध में कालाबाजारी को रोकने के लिए स्टॉक लिमिट निर्धारित की गई और स्टॉक लिमिट के साथ–साथ हमने भारत सरकार से अब तक 5000 कुन्टल दाल, अनमिल दाल ली गई, खरीदी गई और उसके बाद में उसको वितरित भी किया गया है। इसके साथ–साथ हमने कालाबाजारी को रोकने के लिए स्टॉक लिमिट निर्धारित की है जिसमें फुटकर विक्रेताओं को 50 कुन्टल, थोक विक्रेताओं को 1500 कुन्टल और कमीशन एजेण्ट को 1500 कुन्टल है। अगर कहीं पर कोई इससे अधिक स्टॉक रखता है तो उसके खिलाफ सीधी–सीधी कार्यवाही की जाती है। इस तरह के निर्देश दिए गए हैं।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

मान्यवर, बुन्देलखण्ड की जो हालत है और जिस प्रकार से वहां 99 प्रतिशत दलहन की फसलें नष्ट हो गई हैं तो दाल की उपलब्धता और कम होने वाली है। मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि दाल की सम्भावित कमी को देखते हुए सरकार ने क्या एडवांस में व्यवस्था की है कि दाल का दाम फिर न बढ़ने पाए।

श्री अध्यक्ष–

मा0 मंत्री जी, क्या आपने कोई योजना बनाई है ?

श्री हेमराज वर्मा–

मान्यवर, इस वर्ष तो मौसम लगभग ठीक है और किसानों ने दालों की फसलें लगाई हैं। निश्चित तौर पर सब ठीक–ठाक रहा तो पर्याप्त मात्रा में हम लोगों को दालें किसानों द्वारा उपलब्ध हो जायेंगी और उसके बाद भी कहीं पर कोई जरूरत पड़ती है, भारत सरकार से हम लोग इसको खरीदेंगे।

श्री नदीम जावेद–

माननीय अध्यक्ष जी, दाल पर तो बात हो गई लेकिन दाल के साथ–साथ जो दूसरी फसलें हैं वह भी काफी खराब हालत में हैं। उत्तर प्रदेश आलू के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर बंगाल है और जो आलू की फसल है। उसकी भी तकरीबन 15 से 20 प्रतिशत कम उसकी पैदावार हो रही है तो दाल के साथ आलू और जो दूसरी आवश्यक चीजें हैं उसको भी क्या जैसे राज्य की सरकार ने जवाब दिया है कि रिटेल आउटलेट खुलवा कर उचित मूल्य पर उपभोक्ताओं को दालों का वितरण किया जाता है या किया जायेगा तो क्या यह जो दूसरी जरूरी चीजें हैं, वह आम लोगों तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार इस तरह की व्यवस्था करेगी।

श्री अध्यक्ष–

यह कह रहे हैं कि जिस तरह से दाल की व्यवस्था कर रहे हैं, इसी तरह से आलू का भी करेंगे। लेकिन आलू तो सरप्लस रहता है, तमाम बाजार में बिक रहा है।

श्री नदीम जावेद–

माननीय अध्यक्ष जी, इस बार का जो डाटा है और अनुमान है उसके हिसाब से पूछ रहा हूं। मैं आलू के साथ–साथ जो दूसरी आवश्यक वस्तुएं हैं, उसके बारे में भी माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, अब अगला सवाल लेते हैं।

नत्थी (ख)

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में डीजल की कीमतों में भारी कटौती के कारण परिवहन विभाग के अन्तर्गत चलने वाली बसों तथा अनुबन्धित बसों का किराया कम किये जाने की मांग

'01–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डीजल की कीमतों में भारी कटौती के कारण सरकार परिवहन विभाग के अन्तर्गत चलने वाली बसों तथा अनुबन्धित बसों का किराया उसी अनुपात में कम किये जाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री यासर शाह)–

जी हां।

परिवहन निगम के कार्मिकों के वेतन भत्तों एवं डीजल के मूल्यों में वृद्धि/कमी के दृष्टिगत प्रत्येक वर्ष जनवरी एवं जुलाई में किराया वृद्धि/कमी पर विचार करने हेतु उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना दिनांक 07–11–2012 द्वारा सूत्र निर्धारित किया गया है। शासन द्वारा निर्धारित सूत्र के अनुसार वेतन भत्तों में वृद्धि और डीजल के मूल्यों में हुयी कमी के अनुसार उ0प्र0 परिवहन निगम द्वारा संचालित निगम एवं अनुबंधित बस सेवाओं के यात्री किराये में दिनांक 28–11–2014 से 01 पैसा प्रति यात्री प्रति कि0मी0 कमी भी की गयी है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, पिछले लगभग दो वर्षों में मान्यवर, डीजल के मूल्य में 15 रुपये से 17 रुपये की कमी आई है। मान्यवर, मैंने स्पेसिफिक प्रश्न पूछा था कि जो परिवहन विभाग के लिए अनुबन्धित बसें हैं, परिवहन विभाग क्या अपना किराया कम करेंगे। मान्यवर, अगर इसका औसत लगाये कि एक बस एक दिन में एक हजार किलोमीटर चलती है और उसका एवरेज 5 किलोमीटर प्रति लीटर का है, इस हिसाब से 3 रुपये प्रति किलोमीटर, प्रति यात्री की दर से कमी आई और सरकार ने इसमें कमी की है मात्र एक पैसा प्रति किलोमीटर प्रति व्यक्ति। अर्थात् आप अगर दिन में एक हजार किलोमीटर चलें तो मात्र दस रुपये का फर्क पड़ता है एक बस पर जो कमी की है, और सरकार को 3.00 रुपये प्रति किलोमीटर प्रति व्यक्ति मिलता है। कहां 3.00 रुपये और

कहां 1 पैसा तो 2 रुपये 99 पैसे प्रति व्यक्ति प्रति किलोमीटर सरकार की जेब में जा रहा है, इसलिए मैंने पूछा क्योंकि कोई कामर्शियल स्टेज के ऊपर सरकारें नहीं चलती हैं, जन कल्याण के लिए सरकार चलती है कि जनता को ज्यादा से ज्यादा राहत मिले। सरकार भले ही घाटे में रहे लेकिन उसे जनता को राहत देना चाहिए तो मेरे प्रश्न पूछने का आशय यह था कि क्या माननीय मंत्री जी, इस पर विचार करेंगे कि जिस अनुपात में डीजल के मूल्य में कमी आई है उसके अनुपात में अगर न सही तो कम से कम 50 परसेन्ट, 60 परसेन्ट तक यात्रियों को राहत देंगे मेरा आशय यह था और मैंने स्पेसिफिक रूप से यह पूछा है।

श्री यासर शाह–

माननीय अध्यक्ष जी, सब प्रभु की लीला है। अगर एब्सल्यूट डीजल के दामों से रेल किराया, बस किराया केवल तेल के दामों से, अगर वह कम हो जाए तो जाहिर है खन्ना साहब, बहुत सीनियर मेम्बर हैं।

(सत्तापक्ष के एक सदस्य ने कहा कि वह औसत प्रभु को समझाइये।)

श्री अध्यक्ष–

आप मंत्री जी को जवाब देने दीजिए।

श्री यासर शाह–

मान्यवर, 11 रुपये 72 पैसे का जो डीजल इस वक्त बिकना चाहिए वह 46 रुपये में बिक रहा है, किसकी जेब में वह प्राफिट जा रहा है, किसकी जेब में नहीं जा रहा है यह कोई जानता नहीं है। जाहिर है जिन लोगों ने सरकार बनाई वह बड़ी–बड़ी तेल कम्पनियां भी चलाते हैं तो प्रॉफिट उसमें जा रहा होगा यह प्रभु की लीला है डीजल के दाम पर अगर रेल किराया और बस किराया कम हो जाये तो कोई बात ही नहीं और भी भत्ते होते हैं, मंहगाई भत्ता होता है, तन्ख्वाहें देनी होती हैं, मेन्टिनेन्स होता है, रेल किराया या अगर स्पेसिफिकली रोडवेज की बात करें तो वह तो मान्यवर कल हमने देख ही लिया कि रेल किराया कितना कम हुआ है अगर परिवहन विभाग की बात करें तो परिवहन विभाग में जो किराया तय होता है वह डीजल या फ्यूल कास्ट उसके अलावा जो हमारे अन्य भत्ते होते हैं जैसे टी0ए0/डी0ए0 या मंहगाई भत्ते जो हम अपने इम्प्लाइज को देते हैं उन सबको साथ में लेकर तब घटाया या बढ़ाया जाता है और इस समय जो एक पैसे की कमी प्रति व्यक्ति प्रति किलोमीटर की गयी है वह कमी सही है और जैसे–जैसे केन्द्र सरकार हमारे पर और मेहरबान होगी तेल के दामों में और कमी कर देंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर यह खुद 17 से 19 प्रतिशत टैक्स ले रहे हैं और हमको लांछन कर रहे हैं।

दुनिया में कच्चे तेलों में हुई कमी के अनुरूप हिन्दुस्तान में भी या मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में भी तेलों के दाम कम किये जाने विषयक प्रस्ताव

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

यदि सदन सहमत हो तो अभी क्योंकि नेता भाजपा ने यह कहा कि जन कल्याण के लिए सरकारें होती है तो सरकारों से मुराद राज्य सरकार नहीं केन्द्र सरकार भी होगी, मेरा ऐसा मानना है। अगर सदन सहमत हो तो इतिहास में इतनी गिरावट तेल में और क्रूड आयल की कीमत में नहीं हुई जितनी इस वक्त मे हुई है पूरी दुनिया में बहुत मन्दी आई है और भारत को उसका ऐतिहासिक लाभ हुआ है। अगर सदन सहमत हो तो एक रैजूल्यूशन यहां से पास किया जाये और भारत सरकार से यह आग्रह किया जाये कि जितनी कीमत कम हुई है किसानों की भलाई के लिए उतनी ही कीमत कम कर दी जाये ताकि प्रदेशों में भी डीजल की कीमत को कम किया जा सके। अगर भारतीय जनता पार्टी इससे असहमत है तो वह सदन का बहिर्गमन कर सकते हैं वर्ना मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी को भी सहमत होना चाहिए। क्योंकि सरकारें जन कल्याण के लिए होती हैं और किसान की कमर टूट गयी है इस कीमत से और क्योंकि सीधा फायदा इससे किसान को ही होता है। जिस तरह पूरी दुनिया में तेल की कीमत कम हुई है भारत भी कम कीमत अदा कर रहा है उसी अनुपात में डीजल की हम पेट्रोल की नहीं कह रहे, डीजल की कीमत कम कर दी जाये, अगर सदन सहमत हो।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष महोदय जी, यद्यपि कि संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो यहां पर प्रस्ताव रखा उसको देखते हुए मैं केवल यह अनुरोध करना चाहता हूं यह सही है कि विश्व बाजार में जब 200/250 रुपये प्रति बैरल कच्चा तेल था नहीं, 150 डालर प्रति बैरल था तो उस समय जो पेट्रोल और डीजल के रेट थे वर्तमान मे विश्व बाजार में 30 डालर के भी नीचे आ गया तो उसका मतलब है कि इस तुलना में तो आज 20 रुपये लीटर डीजल होना चाहिए और पेट्रोल 25 रुपये प्रति लीटर होना चाहिए इस अनुपात में तो स्वाभाविक रूप से कुल मिलाकर समानुपाती जिस अनुपात में विश्व बाजार में रेट घटे हैं कच्चे तेल के उसके सापेक्ष इस देश में भी डीजल और पेट्रोल के दाम घटने चाहिए थे लेकिन वह नहीं घटे तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं यह देश की जनता पर, प्रदेश की जनता पर एक अतिरिक्त बड़ा बोझ गलत नीतियों के चलते पड़ रहा है। तो यद्यपि कि इस पर तो उत्तर प्रदेश सरकार को बहुत पहले पहल करनी चाहिए थी कि भारत सरकार से मिल बैठकर बात करती और यह अनुरोध उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से उत्तर प्रदेश सरकार का एक लिखित प्रस्ताव गया होता और इस पर बैठक भी हुई होती लेकिन देर से आये दुरुस्त आये, अक्ल आज आई तो भी उसका स्वागत है लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, पहली बार संसदीय कार्य मंत्री जी एक अच्छा प्रस्ताव लाये हैं तो हम समझते हैं कि इसको सर्वसम्मति से पास होना ही चाहिए। (मेजों की थपथपाहट)

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, जो विषय केन्द्र सरकार से संबंधित है इनके लोग केन्द्र सरकार से अनुरोध करें वह फैसला करेंगे। इस सरकार के सामने दो विकल्प हैं, एक तो विकल्प यह है कि इसके ऊपर पैसे कम करे और दूसरा विकल्प यह है कि बोरिया बिस्तर बांधकर घर चले जायें इस्तीफा दे करके, इनके बस का कुछ है नहीं सरकार वरकार

चलाना, यह घर चले जायें बोरिया बिस्तर बांध के। हर बात के लिए, हम यहां की बात कर रहे हैं इस प्रदेश की बात कर रहे हैं जो इनके विभाग से संबंधित है उसकी बात कर रहे हैं और हर बात के लिए गेंद पाले में केन्द्र के, इनके बसका कुछ भी नहीं है, हर बात के लिए रोना हाय रे मम्मी, हाय रे मेरे पेट में दर्द हो रहा है, हाय रे मम्मी मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मान्यवर, ये बोरिया बिस्तर बांधकर घर चले जायें।

श्री मोहम्मद आजम खां–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं क्षमा चाहूंगा, मैं तो चाहता हूं आज फिर माफी मांग लूं आपसे, कल भी माफी मांगी थी मैंने। इसमें तो आप इतने भावुक बेकार हो रहे हैं, न भावुक होने की जरूरत है, न गुस्सा करने की जरूरत है यह तो एक जनकल्याण की बात है उत्तर प्रदेश के पास कोई ऐसा तेल का कुंआ नहीं है कि उत्तर प्रदेश अपना तेल निकाले और अपनी गाड़ियों में डाले क्योंकि भारत सरकार का कुछ चीजों पर कन्ट्रोल रहता है वह कन्ट्रोल है और क्योंकि लग रहा है पूरे सदन की सहमति है तो उसमें एक ऐसा रेज्युल्यूशन अगर चला जायेगा हो सकता है भारत सरकार आपके रेज्युल्यूशन के बाद विचार करे और पूरे देश का भला हो जाय। पूरे देश के किसानों का भला अगर उत्तर प्रदेश विधान सभा के एक रेज्युल्यूशन से होता है तो मैं समझता हूं 4 साल की गुजरी हुई सरकार की एक बड़ी उपलब्धी होगी।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, इनके बस की बात नहीं है, इनको इस्तीफा देने के अलावा हर बार यह रोना केन्द्र का रोते हैं। यह डीजल पर 2 रुपये 99 पैसे प्रति व्यक्ति प्रति किमी ज्यादा ले रहे हैं। हम एक जस्टीफाइड बात कर रहे हैं उसके ऊपर जवाब देने के बजाय इधर–उधर घूमते हैं। अटकाऊ और घुमाऊ जवाब है इनका इसलिए हम और हमारा दल इस सरकार के रवैये के प्रति सदन का बहिष्कार करता है।

(श्री सुरेश कुमार खन्ना अपने दल के साथ सदन का बहिष्कार कर चले गये)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष महोदय जी, जब संसदीय कार्य मंत्री जी का यह प्रस्ताव आया है तो यह प्रस्ताव संसदीय कार्य मंत्री का प्रदेश सरकार का है प्रस्ताव, तो इसको केवल हवा में न उड़ा दिया जाय इस पर गम्भीरता से विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

तो आगे जीरो आवर में इसको पारित करा दीजिए, प्रश्न प्रहर खत्म हो जाय, जीरो आवर में पारित करा दीजिए।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

नहीं, नहीं मान्यवर, जब इसी प्रश्न पर यह प्रसंग अभी आया है तो अभी पास करा दें।

श्री अध्यक्ष–

तो इसे अभी पास करा दें।

प्रश्न यह है कि यह विधान सभा केन्द्र सरकार से सिफारिश करती है कि दुनिया के पैमाने पर जो डीजल के दाम, कच्चे तेलों के दाम कम हुए हैं उसी के अनुरूप हिन्दुस्तान में भी या मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में भी तेलों के दाम कम कर दिये जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

प्रश्नोत्तर क्रमागत

प्रदेश में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग द्वारा जनपद बाराबंकी, आगरा, इलाहाबाद तथा वाराणसी में मारे गये छापों के जांच परिणामों की मांग विषयक

'02–श्री अनुग्रह नारायण सिंह तथा श्री सुरेश राणा–

क्या खाद्य एवं औषधि प्रशासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा वर्ष 2015–16 में जून, 2015 तक कराई गई जांच में कितने प्रतिष्ठानों के जांच के लिये भेजे गये नमूनों में गुणवत्ताहीनता एवं मिलावट की शिकायतें मिली हैं ? क्या सरकार बाराबंकी, आगरा, इलाहाबाद तथा वाराणसी में मारे गये छापों में नमूनों की जांच के परिणाम आदि का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खाद्य एवं औषधि प्रशासन मंत्री (श्री इकबाल महमूद)–

वित्तीय वर्ष 2015–16 में जून, 2015 तक प्रदेश में खाद्य पदार्थों के संदर्भ में कृत प्रवर्तन कार्यवाही में कुल 4143 नमूनें जांच हेतु संग्रहीत किये गये एवं उक्त अवधि में जांचे गये नमूनों में 181 नमूने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये गये हैं। इसी प्रकार आलोच्य अवधि में कुल 1572 औषधि नमूने, जांच एवं विश्लेषण हेतु संग्रहीत किये गये और इस अवधि में विश्लेषित 173 नमूने औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अन्तर्गत निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये गये हैं।

जनपद बाराबंकी, आगरा, इलाहाबाद तथा वाराणसी में मारे गये छापों में नमूनों की जांच के परिणाम के सम्बन्ध में स्थिति निम्नवत् है :–

क्र0सं0	जनपद	नमूने	मानक के अनुसार नहीं पाये गये नमूने
1	बाराबंकी	66	32
2	आगरा	97	45
3	इलाहाबाद	81	27
4	वाराणसी	83	26

इसी प्रकार उक्त जनपदों के औषधि के नमूनों के जांच के परिणाम के सम्बन्ध में स्थिति निम्नवत् है :–

क्र0सं0	जनपद	नमूने	मानक के अनुसार नहीं पाये गये नमूने
1	बाराबंकी	06	02
2	आगरा	41	00
3	इलाहाबाद	17	01
4	वाराणसी	06	01

उपरोक्तानुसार।

प्रश्नोत्तर (क्रमागत)

श्री सुरेश राणा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि इस बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पर आपने मुझे अनुपूरक करने का मौका दिया। मान्यवर, वैसे तो पिछले दो वर्षों से यहां पर एक लाइन सब सवालों के जवाब में सुपरहिट थी कि वित्तीय संसाधनों पर आधारित है।

जो भी प्रश्न हम लोग यहां पर पूछते थे उसमें बस एक ही जवाब आता था कि वित्तीय संसाधनों पर आधारित है और अब पिछले डेढ़ वर्षों से यहां सदन में एक लाइन और बड़े जोरों से चल रही है कि कोई भी सवाल पूछा जाये तो कहा जाता है कि केन्द्र सरकार जवाब देगी, कोई सवाल पूछा जाये कि कहा जाता है कि यह केन्द्र सरकार की जवाबदेही है। यह दो वाक्य इस सदन के सुपरहिट वाक्य हैं यानि कि सारा का सारा मामला दूसरों की ओर घुमा देना।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य, कृपया आप इस सवाल से संबंधित प्रश्न पूछिये।

श्री सुरेश राणा–

माननीय अध्यक्ष जी, हम तो आपकी कृपा चाहते हैं। सारा मामला सरकार द्वारा अपनी जिम्मेदारी से भाग जाने का है। लगातार पिछले चार साल से इस विषय पर चर्चा हो रही है और खुद सरकार ने माना है कि 4143 जो जांच के नमूने लिये गये उनमें से 181 नमूनों में पाया गया कि गड़बड़ थी। औषधि में 1572 नमूने लिये गये और इनमें से 173 में माना कि गड़बड़ थी। तो यह तो सरकार मान ही रही है कि चाहे औषधि हो और चाहे खाद्य पदार्थ हो इनमें भारी मिलावट प्रदेश के अंदर चल रही है। दूसरी बात, इनकी जो संख्या का अनुपात है वह इस ओर इशारा करता है कि कहीं न कहीं जांच में निश्चित रूप से लापरवाही है। कहां संख्या–4143 और कहां 181, मेरा आपके माध्यम से सरकार से सीधे–सीधे दो सवाल हैं। एक है कि मिलावट के बाद क्या कार्रवाई सरकार ने की और मिलावट न हो सरकार ऐसा वातावरण प्रदेश के अंदर तैयार करे। मैं निवेदन करता हूं कि प्रदेश में कोई मिलावट न हो इसके लिए कोई अच्छा वातावरण तैयार करने की शुरुआत क्या प्रदेश सरकार के द्वारा कोई कार्य योजना तैयार होगी और दूसरा प्रश्न कि जो परिणाम आने की समयावधि है, इस समयावधि को घटा करके कोई और कार्य योजना मिलावट रोकने की बनायेगी। माननीय मंत्री जी से यह मेरे दो सवाल हैं।

श्री इकबाल महमूद–

माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश के अंदर इस सरकार ने इस संबंध में जितनी कार्रवाई की हैं और जितने छापे मारे हैं इससे पहले कभी भी इतनी कार्रवाई नहीं हुई है। चार जिलों के संबंध में माननीय सदस्य ने मालूमात हासिल किया है। बाराबंकी में 19 छापे मारकर 66 नमूने लिये गये हैं, जिसमें से 32 नमूने मानक के अनुरूप नहीं पाये गये है और कार्रवाई चल रही है। इन नमूनों को लेने और छापे मारने के बाद हमने कार्रवाई की है, कुछ ए0डी0एम0 के यहां मुकदमे चल रहे हैं, कुछ सी0जे0एम0 के यहां चल रहे हैं और उन पर कार्रवाई की गयी है और जुर्माने भी किये गये हैं । कमी कोई नहीं की जा रही है और न की जायेगी।

श्री सुरेश राणा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैनें कहा था कि प्रदेश के अंदर एक ऐसा माहौल तैयार हो जो मिलावट की ओर न जाय। तो इसके लिये सरकार कोई कार्य योजना तैयार कर रही है यह मेरा पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि जो यह समयावधि है इस समयावधि में परिवर्तन करने का कोई काम सरकार करेगी। चूँकि 3100–4100 नमूने लिये गये हैं और

181 में दोष पाया गया तो संख्या का अनुपात ही बता रहा है तो क्या उसकी प्रक्रिया में सुधार करेंगे, यह कोई आरोप–प्रत्यारोप का विषय नहीं है।

श्री इकबाल महमूद–

हम तो कार्रवाई पूरी कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो वह हमें दे दीजिये, हम उस पर अमल करेंगे।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है।

श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या–

अध्यक्ष जी, आज हम लोगों के स्वास्थ्य के प्रति, बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य में यह मिलावटखोरी चाहे औषधि की हो या खाद्य पदार्थों की हो, बड़ा बुरा असर डाल रही है। जैसा कि अन्य देशों में इसमें बहुत अधिक सजा का प्रावधान है हमारे देश में और प्रदेश में ऐसे मामलों में बहुत कम सजा का प्रावधान है और वह लोग पैरवी करके छूट जाते हैं। मेरा आपके माध्यम से सरकार से सीधा प्रश्न है कि जो मिलावटखोरी करते हैं जो इसके दोषी पाये जायें, उनके विरुद्व सरकार कोई कठोर सजा का प्रावधान करने पर विचार करेगी ?

श्री इकबाल महमूद–

मान्यवर, इसके लिये नियम बने हुये हैं और जो नियम विरुद्व काम कर रहे हैं, उनको सजा दी जा रही है। 10 लाख रुपये जुर्माने की सजा देने का हक ए0डी0एम0 को है और आजीवन कारावास तक की सजा इसमें हो सकती है।

श्री अध्यक्ष–

अब आगे बढ़ते हैं। यह अभी जो प्रश्न रखा गया था मेरे से हिन्दुस्तान शब्द निकला था। मौर्य जी का सुझाव है कि उसके स्थान पर भारत अथवा देश रखा जाय तो जो हिन्दुस्तान कहा गया था, उसे देश रख दिया जाय।

प्रदेश में प्रत्येक सरकारी सस्ते गल्ले (राशन की दुकान) पर डोर स्टेप डिलीवरी कराने विषयक

'03.श्री मनीष असीजा–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्रत्येक सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान (राशन की दुकान) पर डोर स्टेप डिलीवरी सुनिश्चित कराने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हेमराज वर्मा–

जी हां।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत प्रदेश में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान पर डोर स्टेप डिलीवरी लागू किया जाना प्रस्तावित है।

अतिशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री मनीष असीजा–

मेरा इस प्रश्न को पूछने का जो उद्देश्य है माननीय अध्यक्ष जी कि लगभग 16 करोड़ लोग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत कवरेज में आयेंगे। यह सदन

इस बात से अवगत रहे कि प्रदेश में सबसे अधिक लोगों के दरवाजे तक पहुंचने वाली यह जनकल्याणकारी ऐसी योजना है जिसमें पात्र व्यक्तियों को दो रुपये किलो गेहूं और तीन रुपये किलो चावल मिलेगा। माननीय अध्यक्ष जी, मेरे इस प्रश्न का यह हेतु है और हम सब जानते हैं कि एफ0सी0आई0 के गोदामों से ब्लाक गोदाम तक जब खाद्यान्न चलता है और ब्लाक से कोटेदार के दरवाजे तक पहुंचता है तो इसमें बहुत बड़ी लीकेज होती है और बहुत बड़ा भ्रष्टाचार होता है और करोड़ो–अरबों रुपया ऐसे लोगों की जेब में चला जाता है जो कालाबाजारी हैं और उन लोगों का हक मारा जाता है जो गरीब हैं, जिसको इसकी आवश्यकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय और एन0एफ0एस0ए0 जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है उन दोनों में यह स्पष्ट इंगित है कि इस लीकेज को जो एफ0सी0आई0 के गोदाम से ब्लाक गोदाम तक होती है, रोकने के लिये डोर स्टेप डिलीवरी होना आवश्यक है। मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि डिलीवरी लागू किया जाना प्रस्तावित है। मेरा प्रश्न है कि क्या अभी किन्हीं स्थानों पर डोर स्टेप डिलीवरी लागू है ?

श्री हेमराज वर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाया जाय और जो खाद्य वस्तुयें अनुमन्य हैं वह हर उपभोक्ता तक आसानी से पहुंचे कहीं पर कोई गड़बड़ी न हो इस उद्देश्य से एक पारदर्शी व्यवस्था शुरू की गई है और अभी इस सम्बन्ध में जो डोर स्टेप डिलीवरी लागू करने के सम्बन्ध में अभी 14 जनवरी, 2016 को आदेश लागू कर दिये गये हैं और इसके अन्तर्गत जो भी हैण्डलिंग एवं परिवहन, जो ठेकेदारी करना चाहते हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया चल रही है जैसे ही वह प्रक्रिया सम्पन्न हो जायेगी उसके बाद शीघ्र ही केन्द्र कॉल किये जायेंगे उसके बाद उसका कार्य शरू हो जायेगा, बड़ी तेजी से इस पर काम चल रहा है।

श्री मनीष असीजा–

सरकार के 2013–14 के बजट में यह उल्लिखित है कि 19 जनपदों के नगरीय क्षेत्रों में डोर स्टेप डिलीवरी इस वक्त कार्यरत है तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह कार्यरत है।

श्री अध्यक्ष–

आपने तो बताया कि प्रक्रिया चल रही है रजिस्ट्रेशन हो रहा है वह जब हो जायेगा तब चालू हो जायेगा, अब नगरीय क्षेत्रों का आप पूछ रहे हैं।

श्री हेमराज वर्मा–

मा0 अध्यक्ष जी, इसमें प्रक्रिया चल रही है और शीघ्र ही इस पर हम लोग काम कर लेंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मा0 सदस्य द्वारा पूछा गया कि 19 जिलों में यह प्रक्रिया चल रही है और आप बता रहे हैं कि वह प्रस्तावित है। एक तरफ इसी सदन में यह कहा गया था और आप कह रहे हैं कि प्रक्रिया चल रही है तो दोनों में से एक बात सही हो सकती है।

श्री अध्यक्ष–

जो वह कह रहे हैं उसे सुनिये, अब हम कैसे कहें कि वह क्या कह देंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, जो प्रक्रिया 19 जिलों में चालू की गई थी क्या वह प्रक्रिया खत्म कर दी गई है।

श्री मनीष असीजा–

मेरा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष–

आपका तो हर प्रश्न महत्वपूर्ण होता है, ऐसा हम नहीं मानते कि आपका प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं है।

श्री मनीष असीजा–

यह मेरा प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह राजनीति से ऊपर उठकर है।

श्री अध्यक्ष–

आपका तो डोर टू डोर पहुंचाने का है ना कि गांव में दुकानदार के घर पर, अभी एक गोदाम में जाता था मार्केटिंग का इंस्पेक्टर होता था वहां से दुकानदार लाद करके अपने घर ले जाते थे, जांच होती थी कि पहुंचा कि नहीं पहुंचा, वहीं वह बांटते थे। अब यह प्रस्ताव कर रहे हैं कि हमने प्रक्रिया चालू कर दी है, टेण्डर–वेण्डर है, वह गांव में ले जा करके जहां–जहां भी होगा, वहां उनके घर पर पहुंचायेंगे, अभी तो प्रस्ताव कर रहे हैं। आप 2013–14 का सवाल बता रहे हैं पता नहीं कि उनके पास जवाब है या नहीं है। आप दूसरा सवाल पूछिये ना।

श्री मनीष असीजा–

2011–12 में सरकार ने यह कबूल किया है कि वह 19 जिलों में डोर स्टेप डिलीवरी कर रही है, यह सरकार की ही सूचना है, सरकार का बजट है। मैं दूसरा प्रश्न पूछ ले रहा हूं पिछले चार सालों से सरकार का यह उत्तर है कि वह 19 जिलों के नगरीय क्षेत्र में डोर स्टेप डिलीवरी कर रही है और अभी आपने बताया है कि 14 जनवरी को नया आदेश हुआ है मैं उसका स्वागत करता हूं पर मैं एक बात पूछना चाहता हूं लगभग जैसा मेरे साथियों ने कहा हर बात पर केन्द्र की तरफ बात को उछाल देना उसके पहले मैं अपनी बात डाल दूं तो मान्यवर, यह तो शत–प्रतिशत केन्द्र अनुदानित योजना है और यह पूरी स्टडी है जेनड्रेज नाम के अर्थशास्त्री एन0एस0एस0ओ0 नेशनल सेन्ट्रल सर्वे आर्गेनाइजेशन और एफ0सी0आई0 कोटे के उठान पर यह स्टडी है कि 58 प्रतिशत उत्तर प्रदेश में सरकारी खाद्यान्न की लीकेज है। पिछले चार साल से केन्द्र के द्वारा 100 प्रतिशत अनुदानित योजना में 58–60 प्रतिशत की लीकेज यह सरकार स्वीकार कर रही है और डोर स्टेप डिलीवरी जो मा0 सर्वोच्च न्यायालय के 14 सितम्बर, 2011 के आदेशों पर सरकार ने हलफनामा दाखिल किया हुआ है, मैं सदन में जिम्मेदारी से कहता हूं कि हम डोर स्टेप डिलिवरी लागू करेंगे और यह चार साल में लागू नहीं कर पाये।

श्री अध्यक्ष–

वह कर रहे हैं।

श्री मनीष असीजा–

मान्यवर, 100 प्रतिशत केन्द्र अनुदानित योजना में 58 प्रतिशत की लीकेज है, अगर यह डोर स्टेप डिलीवरी लागू हो जाए, ट्रकों पर जी0पी0एस0 सिस्टम लग जाए, ट्रकों पर विशेष चिन्हीकरण हो जाए, उनके मार्ग तय हो जाएं कि कहीं एफ0सी0आई0 के गोदाम से ब्लॉक गोदाम की जगह। वह सीधे बार्डर के पास ट्रक अगर जायेगा तो उसको रोकने के लिए यह कार्रवाई होनी थी जो केन्द्र सरकार की 100 प्रतिशत अनुदानित योजना है उसमें राज्य सरकार 04 साल में अब तक कुछ न कर सकी। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि डोर स्टेप डिलीवरी को आप कब तक लागू कर देंगे, कोई तिथि बतायेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

असीजा जी, मंत्री जी ने बताया था कि प्रक्रिया चल रही है तो उसके बाद लागू करेंगे। अब तारांकित प्रश्न संख्या–05 सतीश महाना जी।

श्री मनीष असीजा–

अध्यक्ष जी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं मंत्री जी ये तो बतायें कि कब तक लागू करा देंगे?

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, जैसे ही भा0ज0पा0 की सरकारें जो राज्यों में है, जैसे ही वो लागू कर देंगी, हम भी विचार कर लेंगे।

श्री मनीष असीजा–

मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को अवगत कराना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में यह योजना लागू है।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मैं सभी राज्यों में जहां आपकी सरकारें हैं उनकी बात कर रहा हूं।

अध्यक्ष–

असीजा जी, अब बैठिये।

श्री मनीष असीजा–

माननीय अध्यक्ष जी, सरकार हर बात केन्द्र सरकार पर टाल दें रही है। 60 प्रतिशत अनाज गरीबों का लीक हो रहा है, सरकार उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। यह कम से कम पूरे सदन की जानकारी में आना चाहिए कि डोर–स्टेप–डिलीवरी लागू करने से आप भाग रहे हैं। बिहार में जहॉ 80–90 प्रतिशत की लीकेज थी वहॉ आज 22 प्रतिशत हो गयी है। प्रदेश सरकार इसमें गम्भीरता नहीं दिखा रही है।

श्री अध्यक्ष–

असीजा जी, अब भाषण मत करिये, बैठिये।

प्रदेश में विद्युत की बढ़ती मांग को दृष्टिगत रखते हुये कोयला, जल, विद्युत के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक स्रोतों से विद्युत उत्पादन की कोई योजना सरकार द्वारा बनाये जाने विषयक

'04.श्री सतीश महाना–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विद्युत की बढ़ती मांग की दृष्टिगत रखते हुये कोयला (थर्मल) जल विद्युत (हाइड्रो) के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक

स्रोतों से विद्युत उत्पादन की कोई योजना सरकार द्वारा बनाई गई है ? यदि हां, तो उक्त योजना का प्रारूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री विजय बहादुर पाल)–

जी हां।

उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों पर आधारित विद्युत उत्पादन की निम्नलिखित योजनायें हैं :

1–सौर ऊर्जा :–

प्रदेश सरकार द्वारा सौर ऊर्जा ग्रिड कनेक्टेड तथा रूफटॉप विद्युत उत्पादन हेतु निम्नांकित नीतियां प्रख्यापित की गयी हैं।

क–सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन के लिये प्रदेश सरकार द्वारा सौर ऊर्जा नीति–2013 प्रख्यापित की गयी है।

ख–भवनों की छतों पर सोलर पावर प्लाण्ट स्थापित कर विद्युत उत्पादन हेतु रूफटॉप सोलर फोटोवौल्टाईक प्लाण्ट नीति–2014 प्रख्यापित की गयी है।

2–पवन ऊर्जा :–

प्रदेश में पवन ऊर्जा के विद्युत उत्पादन की सम्भावनाओं के दृष्टिगत नेशनल इन्स्टी्टयूट आफ विण्ड इनर्जी (भारत सरकार) के दिशा निर्देशानुसार पवन ऊर्जा की सम्भाव्यता वाले 05 जनपदों (शाहजहांपुर, लखीमपुर, गोण्डा, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर) में 80 मी0 ऊँचाई पर विण्ड रिर्सोस असेसमेन्ट कार्य किया जा रहा है।

3–बायोमास :–

चीनी मिलों में बगास पर आधारित को जनरेशन विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के अलावा नॉन–बगास परियोजनाओं के साथ–साथ इण्डस्ट्रियल वेस्ट पर आधारित परियोजनायें निजी क्षेत्र में भारत सरकार की योजना के अन्तर्गत स्थापित करायी जा रही हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सतीश महाना–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से दो छोटी–छोटी बातें पूछना चाहता हूं। क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह जो इन्होंने सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और बायोमास ये तीन जो इन्होंने वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत बताये हैं इनमें से कितनी ऊर्जा का प्रोडक्शन वर्तमान में उत्तर प्रदेश में हो रहा है और उसको बढ़ाने का क्या लक्ष्य निर्धारित किया है ?

श्री विजय बहादुर पाल–

मान्यवर, सौर ऊर्जा नीति, 2013 के अंतर्गत 500 मेगावाट क्षमता लक्षित है। उक्त के सापेक्ष 500 मेगावाट क्षमता की परियोजनाओं का आवंटन विकासकर्ताओं को निविदा के माध्यम से किया जा चुका है। उक्त स्थापित 90 मेगावाट की सौर ग्रिड संयोजित परियोजनाओं में से 10 मेगावाट क्षमता की परियोजना ग्राम कहरहरिकला जनपद–महोबा में, 10 मेगावाट की क्षमता की परियोजना ग्राम मऊरानीपुर जनपद

ललितपुर में, 10–10 मेगावाट क्षमता की परियोजना ग्राम अमरपुर जनपद ललितपुर में और 50 मेगावाट क्षमता की परियोजना ग्राम कालपी जनपद–जालौन में स्थापित की गयी है। जहां तक लक्षित 500 मेगावाट क्षमता से अधिक लक्ष्य निर्धारित करने का प्रश्न है इस सम्बन्ध में सौर ऊर्जा नीति, 2013 में निर्धारित 500 मेगावाट लक्ष्य की पूर्ति एवं उत्पादन होने के बाद विचार किया जायेगा।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, आपसे तीनों में पूछा था एक सौर ऊर्जा, दूसरा पवन ऊर्जा और तीसरा बायोमास का अगर तीनों का बता देंगें तो फिर एक साथ पूछूंगा नहीं तो फिर अलग अलग आप बताओगे और आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। आप बता तो नहीं पाओगे। तो पहले आप उस हिसाब से उत्तर दे दें।

श्री अध्यक्ष–

अरे वह विद्वान हैं।

श्री विजय बहादुर पाल–

विपक्ष की शानदार भूमिका निभाने वाले माननीय महाना जी आप बड़े वाणीवीर हैं। मैं इस बात को इस रूप में कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी अडिग हैं, अदम्य हैं और उनकी इस योजना की घोषणा के बारे में आप एक, एक शब्द, एक एक वाक्यांश और एक एक वाक्य अगर आप कृपापूर्वक सुन लेंगे कम शब्दों में, तो आप सहमत हो जायेंगें। उत्तर प्रदेश हैज प्रोमिसिंग पोटेन्शियल फार पावर जनरेशन बेस्ड ऑन सोलर इनर्जी इबन्डेन्ट सन–शाइन अवलेबिल थ्रोआउट द इयर कैन बी हार्नेस्ड फार इलेक्ट्रीसिटी जेनरेशन (सत्ता पक्ष की तरफ से मेजें थपथपाने पर शोर) इन दिस कानटेक्स्ट वी आर डिटरमाइन्ड टू क्रियट ए कन्डूसिव इनवायरमेन्ट टू इनकोरेज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन सेटिंग अप सोलर बेस्ड पावर प्लाण्ट इन द स्टेट।

श्री अध्यक्ष–

अरे इसका हिन्दी कर दीजिये।

श्री विजय बहादुर पाल–

आपने कहा कि अकेली सौर ऊर्जा की बात बताकर पवन ऊर्जा और उन पर कुछ कहने के लिये है उन पर क्रियान्वयन के लिये प्रयास चल रहा है और जब प्रयास और क्रियान्वयन के लिये प्रक्रिया पूरी हो जायेगी तो मान्यवर, तो आपको यह पूछने की आवश्यकता नहीं रहेगी और न हमें उत्तर देने की।

श्री अध्यक्ष–

अभी क्रियान्वयन नहीं हुआ, हो जायेगा तो पता चल जायेगा।

श्री सतीश महाना–

माननीय अध्यक्ष जी,.

श्री अध्यक्ष–

अब क्या है।

श्री सतीश महाना–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने आपसे पहले निवेदन किया था। मेरा निवेदन सुन लीजिये कृपापूर्वक। मान्यवर, पढ़ने के लिये बोला। मान्यवर, एक छोटी सी बात। मान्यवर, कालेज में हम लोग चुनाव लड़ते थे। हमारा एक साथी था हमने उसको कहा कि चुनाव में खड़े हो जाओ। उसने कहा कि हमको भाषण देना नहीं आता। मैंने कहा पढ़कर बोल देना। वह जैसे ही पढ़कर बोलना शुरू हुआ तो जैसे ही उसने पहली लाइन, उसने कहा कि मैं अभी बैठा–बैठा सोच रहा था। यह भी लिखकर लाया था कि मैं बैठा बैठा सोच रहा था तो हमने सोचा पहली लाइन पढ़ नहीं पायेगा तो हमने वैसे ही शोर मचाना शुरू कर दिया जैसे इन्होंने अभी यहां पर मचाया कि किसी को पता ही न चले कि बोल क्या रहे हैं। पढ़कर भी क्या बोल रहे हैं। (शोर)

श्री अध्यक्ष–

आप सवाल करिये ना। अरे आप लोग शांत रहें।

श्री सतीश महाना–

माननीय अध्यक्ष जी, बोल लेने दीजिये, तब बोलूं।

श्री अध्यक्ष–

नहीं आप प्रश्न करिये। अब इसमें बहुत ज्यादा प्रश्न रह नहीं गया है।

श्री सतीश महाना–

माननीय अध्यक्ष जी कभी कभी, कभी कभी नहीं अधिकांशतः समय पर उधर से यह जवाब आता है कि आपकी सरकार वहां क्या कर रही है।

श्री अध्यक्ष–

इसमें तो नहीं आया, इसमें क्यों बोल रहे हैं आप। आप सवाल पूछिये।

श्री सतीश महाना–

इसके पहले वाले में आया था। माननीय अध्यक्ष जी, राजस्थान इस समय लगभग 21000 मेगावाट सौर ऊर्जा प्रोड्यूस कर रहा है। मध्य प्रदेश 950 मेगावाट कर रहा है। ऐसे ही तमिलनाडु और गुजरात जैसे स्टेट कर रहे हैं। सरकार का यह उत्तर आया कि अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। यह आप ही ने बताया।

श्री अध्यक्ष–

लक्ष्य तो बताया है।

श्री सतीश महाना–

यही बताया ना कि अभी कुछ भी नहीं कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

कर रहे हैं अभी उत्पादन। यह कहां कहा कि नहीं कर रहे हैं। आप अपनी तरफ से जोड़ते हैं। जो पूछना हो वह पूछिये।

श्री सतीश महाना–

अच्छा मान्यवर, मैं पूछ रहा हूं। जो सरकार अभी कुछ नहीं कर रही जो इन्होंने कहा कि अभी हम कुछ नहीं कर रहे।

श्री अध्यक्ष–

क्यों नहीं वो तो कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं। आप फिर अपनी तरफ से जोड़ रहे हैं।

श्री सतीश महाना–

जो सरकार कह रही हैं कि अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

आप फिर उसी पर आ गये।

श्री सतीश महाना–

जब आप बोलना शुरू हो जाते हैं तो मेरी बोलने की हिम्मत नहीं होती है।

श्री अध्यक्ष–

जब वह कह रहे हैं कि मैं यह कर रहा हूं और आप कह रहे हैं कि सरकार कह रही है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो उनकी बात को आप कन्ट्राडिक्ट इस तरह से कर रहे हैं। आप सवाल करिये ना।

श्री सतीश महाना–

जो सरकार कह रही है कि हम कुछ करेंगे जिन्होंने अभी तक कुछ किया नहीं है। यह वाली बात तो ठीक है न मान्यवर। (हंसी) जो कुछ कर रहे हैं और जिन्होंने अभी तक कुछ किया नहीं है इसका मतलब यह सौर ऊर्जा वैकल्पिक ऊर्जा के बारे में गम्भीर नहीं हैं। जो कुछ नहीं किया और जो कर रहे हैं। (हंसी)

श्री अध्यक्ष–

आप तो वहीं घूम घूम कर जा रहे हैं। आगे बढ़ नहीं रहे हैं।

श्री विजय बहादुर पाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे बड़ा खेद है कि माननीय महाना जी को मैं अपनी बात ठीक से नहीं समझा पाया। विकास का होता है सूचकांक/बिजली की किल्ल्त नहीं रहेगी। प्रदेश में बिजली का होगा अधिक उत्पादन। अगले पांच वर्षों में बिजली का उत्पादन 11,000 मेगावाट से 21,000 मेगावाट किया जाना है। इसके ऊपर लगभग साठ हजार करोड़ से अधिक पॉच वर्षों में (शोर) तय किया जाना है। बिजली योजनाओं के ऊपर बात कर रहे थे कृपया ध्यान से सुन लीजिए महाना जी, अन्य बिजली योजनाओं सौर ऊर्जा आदि योजनाओं पर उत्तर प्रदेश सरकार का व्यय पिछले वर्ष की तुलना में दोगुना कर दिया गया है।

(मेजें थपथपाई गईं)

कई ग्राम स्ट्रीट लाईट सौर ऊर्जा से संचालित हो रहे हैं।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

मान्यवर, मेरे दो सवाल हैं एक तो ऊर्जा नीति के तहत प्रदेश जितनी भी बिजली का उपयोग करता है उसका पांच प्रतिशत इस प्रदेश को सौर ऊर्जा के माध्यम से प्राप्त करना है। सरकार 11000 मेगावाट का दावा करती है और 90 मेगावाट सौर ऊर्जा से उत्पादन करती है माननीय मंत्री जी जानकारी नहीं दे पा रहे हैं लेकिन 90 मेगावाट होता है, 11000 हजार का उपयोग होता है इस हिसाब से 550 मेगावाट कम से कम

प्रयोग इस वर्ष होना चाहिए। सरकार अपने इस लक्ष्य को कब प्राप्त कर लेगी। क्योंकि नियामक आयोग ने इस बात की इनको नोटिस दी हुई है। दूसरी बात सरकार ने तीन दिनों पहले यह बताया इसी सदन में कि सौर ऊर्जा का जो प्रति यूनिट मूल्य है वह 10 रुपये 28 पैसे पड़ता है और यह बहुत मंहगी पड़ती है। क्या सरकार कोई ऐसी योजना बना रही है जिससे कि सौर ऊर्जा का यह उत्पादित मूल्य कम किया जा सके।

श्री विजय बहादुर पाल–

डाक्टर साहब यह पता नहीं कहां से अपनी सही जानकारी ले आए। (हंसी) 90 मेगावाट क्षमता की परियोजनाओं से उत्पादित विद्युत को यू0पी0पी0सी0एल0 द्वारा 8 रुपया 44 पैसा और प्रति यूनिट 9 रुपया 33 पैसा। जो यह नोटिस की बात कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार को बहुत सी नोटिसें दी जा रही हैं। लेकिन इन्हें कितनी नोटिसें इस प्रदेश की जागरुक जनता द्वारा दी जा रही हैं उसका यह कभी ध्यान नहीं देते है। आपको तो नोटिसें केन्द्र सरकार के नेता दे रहे हैं आपको मटियामेट कोई नहीं करना चाहता। आपके केन्द्रीय सरकार के नेता आपकी गरिमा गिरा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी ने जवाब दिया कि 8 रुपया कुछ पैसा है। आपका कहना है मंत्री जी क्या आप इसको कम करने पर विचार करेंगे इसका लागत मूल्य कम हो यही आपका मुख्य सवाल है।

श्री विजय बहादुर पाल–

सरकार अपने उत्तर प्रदेश के निवासियों, किसानों और विद्युत उपभोक्ताओं के लिए जनकल्याण के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। जो भी उनके हित में हो सकता है वह किया जाएगा।

श्री सतीश महाना–

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को प्रणाम करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि इस प्रश्न को प्रश्न एवं संदर्भ समिति को संदर्भित करने का कष्ट करें।

प्रदेश में निर्मल भारत अभियान के तहत वर्ष 2013–2014 एवं 2014–2015 का लक्ष्य पूरा हुआ था नहीं एवं पूरा होने में कितना समय लगेगा।

'05.श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में निर्मल भारत अभियान के तहत वर्ष 2013–2014 एवं 2014–2015 का लक्ष्य पूरा कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो सरकार उक्त लक्ष्य की शत–प्रतिशत पूर्ण कराने हेतु कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पंचायती राज मंत्री (श्री राजकिशोर सिंह)–

जी नहीं।

जी हां।

वित्तीय वर्ष 2013–14 में लक्षित 8,90,881 के सापेक्ष 7,89,092 शौचालयों का निर्माण कराते हुये अवशेष 1,01,789 शौचालयों को वित्तीय वर्ष 2014–15 में सम्मिलित करते हुये कुल लक्षित 10,92,896 के सापेक्ष 5,15,440 शौचालयों का निर्माण कराया जा चुका है। अवशेष 5,77,456 को चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 की कार्य योजना में सम्मिलित कर निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रदेश के लिये बहुत गम्भीर चिन्ता का विषय है कि आज प्रदेश में तमाम पिछड़े क्षेत्र, तमाम वह जनपद, जिन लोगों के घरों में आज भी शौचालय नहीं है वह शौचालय न होने के कारण अभी भी शौच करने खेतों में और तमाम जगहों पर जाने का काम करते है। अध्यक्ष महोदय इन्होंने जो जवाब दिया है उसमें यह दर्शाया है कि 2015–16 में लक्ष्य जो इन्होंने लिया है 10,92,896 के सापेक्ष 5,15,440 शौचालयों का निर्माण कराया जा चुका है और 577,456 को चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 की कार्ययोजना में सम्मिलित कर निर्माण कार्य पूर्ण कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश में लगभग डेढ़ करोड़ शौचालय बनाने का लक्ष्य है। डेढ़ करोड़ लोगों के घरों में आज भी शौचालय नहीं है। अब तक मात्र 40 लाख से भी कम शौचालय बने हैं। प्रदेश के पूर्वांचल के तमाम जनपदों में चाहें वह कुशीनगर हो, महाराजगंज हो, देवरिया, सिद्धार्थनगर, बस्ती, बलिया हो आप देख रहे हैं कि आज भी यहां लोगों के घरों में शौचालय नहीं है और उनको बाहर जाना पड़ता है। खुले आसमान के नीचे शौच करना पड़ता है।

श्री अध्यक्ष–

सवाल पूछें।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

जिससे तमाम बीमारियां होती हैं। अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम को पूर्ण करने के लिए माननीय मंत्री जी ने क्या लक्ष्य रखा है ? क्या मंत्री जी यह बताएंगे कि उक्त कार्यक्रम को पूर्ण करने के लिए कितने धन की आवश्यकता है। केन्द्र का कितना अंशदान है और कितना धन प्राप्त हुआ है।

श्री अध्यक्ष–

शौचालय पर कितना पूछेंगे सड़क पर पूछते।

श्री राजकिशोर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी माननीय लल्लू जी ने केन्द्र और राज्य का अंश पूछा है इसमें 60–40 का रेशियो होता है। 60 प्रतिशत केन्द्र का अंश और 40 प्रतिशत राज्य का अंश होता है। दूसरा इसमें इन्होंने कहा कि अब तक कितने आवास का निर्माण कराया गया आपको जानकारी नहीं है अब तक करीब 18 लाख के करीब शौचालय का निर्माण कराया जा चुका है और एक सर्वे होता है बेसलाइन सर्वे हमने कराया है पूरे उत्तर प्रदेश

में लगभग 2 करोड़ 40 लाख ऐसे परिवार हैं जहां शौचालय नहीं है। इसको 2019 तक भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की यह कार्य योजना है कि 2019 तक पूरे उत्तर प्रदेश में हर घर में शौचालय की व्यवस्था करा दी जाए। 2019 तक पूरे उत्तर प्रदेश में हर घर में शौचालय का निर्माण करा दिया जाएगा।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

मेरा एक प्रश्न और है।

श्री अध्यक्ष–

लल्लू जी शौचालय पर कितना पूछेंगे।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

अध्यक्ष महोदय अन्तिम सवाल है। जो शौचालय दिया जाता है अभी भी गांव में प्रधान और सेक्रेट्री के खाते में सीधा पैसा जाता है। जो लाभार्थी है उसके खाते में सीधा पैसा नहीं दिया जाता है। अभी भी अगर यह देखा जाए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कुछ गांवों को ही चिन्हित किया जाता है जो बहुत खास टाइप के लोग होते हैं उन्हीं का चयन होता है। सभी के लिए व्यवस्था नहीं की जाती है। अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा क्या लाभार्थियों के खाते में सीधे पैसा भेजने की कोई व्यवस्था सरकार द्वारा कराई जाएगी यह मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं।

श्री राजकिशोर सिंह–

अध्यक्ष जी इसको हम दिखवा लेंगे अगर कोई दिक्कत नहीं आती है तो सीधे भिजवा देंगे। इसमें 12 हजार रुपया है कुछ वहां पर मनरेगा से अलग से ग्राम प्रधान द्वारा व्यवस्था की जाती है लेबर कंपोनेंट इसमें मनरेगा से भी किया जाता है क्योंकि 12 हजार में शौचालय नहीं बन सकता है। कुछ बड़े लोग भी हैं वह भी शौचालय लेते हैं आप कह रहे हैं कि एक जिले में एक गांव में कुछ लोगों को दिया जाता है आप बताइए आपके गांव में भी देख लेंगे। अगर यह कहेंगे तो हम लल्लू जी के अगल–बगल में इनके परिवार में बनवा देंगे।

श्री दलवीर सिंह–

अध्यक्ष जी आपके माध्यम से केवल एक प्रश्न पूछना चाहता हूं यह जो 12 हजार रुपए दिए जा रहे हैं।

सरकार की तरफ से जो 12000 रूपये दिये जा रहे हैं यह बहुत अच्छा कदम है।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 मंत्री जी ने अभी जो जवाब दिया है वह मेरे विचार से उचित नहीं है। इन्होंने कहा कि अगल–बगल के घरों में बनवा देंगे, इसका क्या मतलब है ?

श्री अध्यक्ष–

मा0 मंत्री जी का कहने का आशय यह था कि जहां कहीं भी शौचालय नहीं बने होगें तो वहां पर बनवा दिये जायेंगे।

(सदस्य, श्री अजय कुमार 'लल्लू' अपने स्थान पर खड़े रहकर बोलने का प्रयास करते रहे)

श्री अध्यक्ष–

मा0 लल्लू जी, अब आप बैठ जाईये, विवाद मत उत्पन्न कीजिये। आपने अपना प्रश्न पूछ लिया है।

श्री राजकिशोर सिंह–

मा0 अध्यक्ष जी, जो व्यक्ति अपने घर के अगल–बगल स्वच्छता अभियान के तहत काम नहीं कर सकता, जो अपने गांव का विकास नहीं कर सकता, जो अपने परिवार का विकास अच्छे तरीके से नहीं कर सकता, उसको इस सदन से इस्तीफा देकर चले जाना चाहिये। इसलिये मैं कहना चाहता हूं आप बता दीजिये, आदरणीय मुलायम सिंह जी हमारे आदरणीय नेता हैं।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कई सदस्यों द्वारा अपने–अपने स्थानों पर खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

लल्लू जी, आपके सभी प्रश्नों का उत्तर आ गया है, अब आप बैठ जाईये। जोशी जी, आप भी बैठ जाईये।

श्री दलवीर सिंह–

मा0 अध्यक्ष जी, यह जो 12000 रूपये की व्यवस्था सरकार की तरफ से शौचालय निर्माण के लिये की जा रही है। गांवों में शौचालय के निर्माण के लिये लोग बहुत जागरूक हैं, लेकिन यह जो 12000 रुपये शौचालय निर्माण हेतु दिये जा रहे हैं बहुत अपर्याप्त हैं। लोग गांवों में शौचालय बनाने के लिये बहुत ही जागरूक हैं, बहुत इच्छुक हैं और बहुत ही उत्साहित हैं। यह बहुत अच्छी योजना है, लेकिन गांवों में इससे भी बढ़िया शौचालय बनाने के लिये लोग तैयार हैं। मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यदि 12000 रुपये के अतिरिक्त लाभार्थी अपनी जेब से पैसा लगाकर उस शौचालय को और बढ़िया ढंग से बनवाना चाहे तो क्या सरकार उसे अतिरिक्त धन लगाने की इजाजत देगी ?

श्री राजकिशोर सिंह–

मा0 अध्यक्ष जी, 12000 रुपये की जो सरकारी व्यवस्था है, उसके अतिरिक्त यदि कोई भी लाभार्थी पैसा लगाना चाहे तो सरकार की तरफ से इस पर कोई रोक नहीं है।

(इस मध्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कई सदस्य अपने–अपने स्थानों पर खड़े होकर बोलने का प्रयास करते रहे)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग उसे अभी जीरो आवर में व्यवस्था के प्रश्न पर उठाइयेगा, अभी प्रश्न हो जाने दीजिये। आप लोग प्रश्नकाल ही नहीं होने दे रहे हैं। आप लोग बैठ जाईये।

प्रदेश की विभिन्न जेलों में वर्ष 2012 से 10–11–2015 तक जेलों में हुई मौतों की संख्या एवं सरकार द्वारा क्या कार्रवाई हुई

'06.डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की विभिन्न जेलों में वर्ष 2012 से 10–11–2015 तक कितनी मौते हुई है तथा इन मौतों के सन्दर्भ में सरकार ने अब तक क्या–क्या कार्रवाई की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कारागार मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया)–

प्रदेश की कारागारों में निरुद्ध बंदियों में से कुल 1363 बंदियों की मृत्यु वर्ष 2012 से दिनांक 10–11–2015 के मध्य हुई है। प्रत्येक बंदी के मृत्यु के प्रकरण में निम्नवत् कार्रवाई की गयी है :–

1–कारागार स्तर से प्रत्येक बंदी मृत्यु की सूचना तत्काल रेडियोग्राम/फैक्स द्वारा मा0 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली/राज्य मानवाधिकार आयोग, उत्तर प्रदेश को दी गयी।

2–प्रत्येक मृतक बंदी का पोस्टमार्टम चिकित्सकों के पैनल द्वारा कराया जाता है तथा पोस्टमार्टम की विडियोग्राफी करायी गयी।

3–प्रत्येक बंदी की मृत्यु की पंचनामा रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, वीडियो कैसेट एवं सुसंगत अभिलेख मा0 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली को भेजे गये।

4–प्रत्येक बंदी के मृत्यु प्रकरण की न्यायिक जांच कराई गयी।

5–बंदी मृत्यु के प्रकरणों में न्यायिक जांच रिपोर्ट की संस्तुति एवं मा0 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निर्देशानुसार कार्रवाई की जाती है। उपरोक्त प्रकरणों में से 833 प्रकरणों की न्यायिक जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट में 150 कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई की संस्तुति की गयी। मा0 आयोग द्वारा मृतक बंदियों के आश्रितों को अन्तरिम राहत दिये जाने की संस्तुति के अनुपालन में धनराशि रु0 77,00,000/– (रु0 सतहत्तर लाख) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य अपने स्थान पर खड़े होकर बोलने का प्रयास कर रहे थे)

(व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग बैठिए, जीरो ऑवर में व्यवस्था के प्रश्न में इसे उठाना, प्रश्न हो जाने दीजिए। आप लोग तो प्रश्न ही नहीं होने देते हैं।

माननीय कारागार मंत्री जी, उत्तर पढ़े।

(माननीय कारागार मंत्री ने उत्तर पढ़ना प्रारम्भ किया लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य लगातार बोलते रहे)

आप लोग नहीं मानेंगे ?

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य अपनी बात कहते हुए वेल में आ गए)

श्री अध्यक्ष–

आपका तो पूरा उत्तर आ गया है, क्या जरूरी है जिद करने की ? यह गलत बात है। आप रोज इस तरह का बवाल करते हैं, आप लोगों की आदत बन गयी है, बड़े नेताओं को दिखाने के लिए कि मैंने असेम्बली जाम कर दी। आपके पूरे प्रश्न का उत्तर आ गया तो क्या वजह है ऐसा करने की ? अगर कोई शिकायत है तो जब जीरो ऑवर आयेगा, तब उठाइयेगा।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

मान्यवर, मेरा बहुत गंभीर सवाल है। पूरे प्रदेश की जनता से जुड़ा हुआ सवाल है। मंत्री जी शौचालयों से जुड़े इस सवाल पर बिल्कुल भी गंभीर नहीं हैं। जो शब्द मंत्री जी ने कहे हैं, वे शब्द वापस लेने पड़ेंगे, नहीं तो मैं यहीं बैठूंगा। मैं तो एक गंभीर सवाल लाया था।

श्री अध्यक्ष–

हां, हम जानते हैं, आप बहुत गंभीर सवाल लाए हैं, यहीं बैठना है तो बैठिए।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कई सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री अध्यक्ष–

अब हो गया, चला गया दिल्ली संदेश कि आप लोग असेम्बली जाम कर रहे हैं। आप लोग अपने स्थान पर चलिए। जब हम कह रहे हैं कि जब जीरो ऑवर आयेगा, तब अपनी बात कहिएगा।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

अध्यक्ष जी, मर्यादा का सवाल है।

श्री अध्यक्ष–

हम आपकी मर्यादा खूब समझते हैं। जब मैं कह रहा हूं कि जब जीरो ऑवर आयेगा तब आप उस बात को व्यवस्था के नाम पर उठाइगा, मैं सुनूंगा, अभी सवाल आ जाने दीजिए।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य वेल से अपने–अपने स्थानों पर चले गए)

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी, उत्तर पढ़िए।

(माननीय कारागार मंत्री ने उत्तर पढ़ा)

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल–

अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी का मैंने इस सवाल के माध्यम से पूरे सदन से परिचय करा दिया, यह पहला जवाब है, इनका। तीन प्रश्न छोटे–छोटे हमारे हैं। एक तो है कि 150 कर्मियों के विरूद्ध कार्यवाई की संस्तुति जांच रिपोर्ट में की गयी। अब सवाल यह है कि जांच रिपोर्ट में तो संस्तुति मिल गयी, लेकिन मैंने पूछा था कि सरकार ने क्या कार्रवाई की ? क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जेल परिसर के अन्दर इस प्रकार की जघन्य हत्याओं में लिप्त अपराधी पुलिस कर्मियों के विरूद्ध अगर कार्यवाई की संस्तुति की गयी है, पिछले तीन सालों से तो सरकार ने उस रिपोर्ट के आधार पर अभी तक कार्यवाई क्या की है ? नम्बर–दो यह जो मौते हुई अध्यक्ष महोदय 1363 यह छोटी–मोटी मौतें नही हैं, उत्तर प्रदेश की जेलों में पिछले तीन सालों में 1363 लोगों ने

अपना जीवन खो दिया है, इसके पहले के अगर तीन साल का आंकड़ा निकाला जाय तो यह कुल मिलाकार के 972 था, इस पार्टी के कार्यकाल में जेल में मरने वालों की संख्या 972 से बढ़कर के 1363 हो गई है, मैं सरकार से यह जानना चहता हूं कि यह जो मौतें बढ़ रही हैं जेल के अन्दर, समाजवादी पार्टी की सरकार के कार्यकाल में, क्या सरकार इन मौतों की जांच के लिए, आखिर यह क्यों बढ़ रही हैं, एक–एक मौत को आप मानवाधिकार में भेजते हैं, वह तो एक अलग विषय है, मेरा पूछना यह है कि आखिर मौतें बढ़ रही हैं, सरकार को जानना चाहिए कि आखिर क्यों बढ़ रही हैं, क्या सरकार इस सन्दर्भ में कोई जांच आयोग बैठाने की और उसकी रिपोर्ट पर ऐसी व्यवस्था करने की कि यह मौतें न हो पायें, कोई कार्रवाई करेगी।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया–

माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश की जेलों में चिकित्सा की सहूलियत हैं, थोड़ी कमी है, जब से मैंने जिम्मेदारी सम्भाली है, मैंने एक नया रास्ता निकाला है। 90 हजार के लगभग बंदी हैं, बंदियों में कुछ लोगों के अन्दर आकर छोटी–छोटी बीमारियां बढ़ती हैं, कुछ बाहर होती हैं, मैं 15 दिन के अन्दर–अन्दर एक नई योजना लागू कर रहा हूं, मैंने चिकित्सा विभाग से रिक्वेस्ट की हमारे पास डाक्टर्स की कमी है, अभी 3500 बंदी रक्षक की कमी है, हम भर्ती कर रहे हैं, डाक्टरों की भी भर्ती कर रहे हैं, तो मैंने कहा उतनी देर जितनी देर हम भर्ती नहीं कर लेते, हर जनपद से जिला चिकित्साधिकारी हर हफ्ते में दो डाक्टर एक जेल में और दे दें अपने से और उससे क्या होगा कि चार हफ्तों में 08 डाक्टर और एक जेल को देख सकेंगे, यह कर रहे हैं। 90 हजार बंदियों में से अभी आपने कहा कि पहले 900 लोगों के हो चुके थे, मेरी समाजवादी पार्टी सरकार के आने के बाद 400 का आंकड़ा इन्होंने दिया तो आज मैं आपसे पूछता हूँ कि मौत पर तो डाक्टर, वैद्य और बड़े–बड़े हकीम भी काबू नहीं पा सके, मृत्यु किसी के हाथ में नहीं है मगर हमारे दोष से नहीं हुई, हमने अभी और दवाई का प्रबन्ध किया है, चिकित्सा का प्रबन्ध किया है और हम तेजी से कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जेलों में जिसको भी कोई तकलीफ है, वह दूर की जाय चिकित्सा के लिहाज से।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल–

मा0 अध्यक्ष जी, मंत्री जी यह कह रहे हैं कि 400 मौतें इनके कार्यकाल में बढ़ गईं, ऊपर वाले ने करा दीं, मौत किसी के हाथ में नहीं ऊपर वाले ने करा दीं और साथ में यह भी कह रहे हैं कि अब जब यह मंत्री बने हैं तो व्यवस्था कुछ सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, इसके पहले गड़बड़ थी, इन्होंने अपने पहले के मा0 मंत्रियों और सरकार पर एक टिप्पणी भी कर दी, एक–एक जेल का निरीक्षण हो चुका अध्यक्ष जी और यह सारी कमियां पीने के पानी से लेकर खाने से लेकर सब स्थापित दर्ज हो चुके, मैं जानना यह चाहता हूं कि सरकार यह जो बढ़ी हुई समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में मौतें हैं, इनको संज्ञान में लेगी, गम्भीरता से लेगी, इनकी जांच करायेगी, इनके पीछे के कारणों को समझने और हम लोगों को बताने का काम करेगी, बस इतना सा सवाल है, मा0 अध्यक्ष जी।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया–

माननीय अध्यक्ष जी, एक तो लांछन लगाना, चलते–चलते बात को बाजार में, ये इन मित्रों को मुबारक हो, मैं ऐसा नही हूं, मैंने केन्द्र में भी प्रश्नों के उत्तर दिये हैं, यहां

भी मोहब्बत से और सच्चाई से और बाहर देख रहे लोगों से डर कर कि कहीं पांच सेकेण्ड भी बरबाद तो नहीं हो रहा लोगों का वक्त। आप जानकारी कर लेना रामूवालिया के शब्द में कभी ताना और चलते–चलते किसी को आंख देना ऐसी आदत नहीं है। एक साध्वी तो उखड़ सकती है, मैं 40 वर्ष से राजनीति में हूं, और लांछनों से बच कर रहा हूं। किसी के द्वारा लांछन लगाया ही नहीं गया। कोई मेरे ऊपर एक बाल्टी भर लगा दे, आगे आ जाये। अब हम करना क्या चाहते हैं।

(सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया–

आप सुनिए तो, बिल्कुल हर मृत्यु की न्यायिक जांच होती है। अगर तो आपको किसी न्यायिक जांच पर आपत्ति है तो आप मुझे लिख कर दीजिए जो विधान की विधि के अनुसार हल होगा मैं करूंगा लेकिन मौतों की गिनती पर, आज मैं अपने पूर्वज मंत्रियों को प्रणाम करता हूं उन्होंने एक रत्तीभर भी कोई अवहेलना नहीं की।

श्री अध्यक्ष–

बस बैठिए। अब प्रश्नों का समय समाप्त। ¥अभी लल्लू रूक जाओ जरा। अरे रूको न। स्टिंग आपरेशन वाला खत्म हो जाये, बैठिए न। रुकिए, अब इसके बाद कहिएगा।

प्रदेश में सभी नागरिकों को मुफ्त इलाज कराने की सुविधा उपलब्ध कराने की नीति के अन्तर्गत गुर्दे एवं हृदय रोगों के मुफ्त उपचार की व्यवस्था

'07–डा0 अरुण कुमार–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सभी नागरिकों को मुफ्त इलाज कराने की सुविधा उपलब्ध कराने की नीति के अन्तर्गत कैन्सर, गुर्दे एवं हृदय रोगों के उपचार की व्यवस्था है ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे रोगियों को संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इन्स्टीट्यूट एवं डा0 राम मनोहर लोहिया मेडिकल इन्स्टीट्यूट में भी उक्त मुफ्त चिकित्सा सुविधा दिलाने का प्रबन्ध करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव)–

उत्तर प्रदेश में असाध्य रोगों के निःशुल्क उपचार हेतु नियमावली, 2013 (यथा संशोधित) के अन्तर्गत असाध्य रोगों (कैंसर, हृदय रोग, लीवर, किडनी एवं मौसमी महामारी) से पीड़ित मरीज जिन्हें चिकित्सालय में भर्ती कर उपचार की आवश्यकता हो, को निःशुल्क उपचार की सुविधा उ0प्र0 के राजकीय मेडिकल कालेजों/किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ/डा0 राम मनोहर लोहिया इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लखनऊ/उ0प्र0 ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान सैफई, इटावा/संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ में अनुमन्य है।

असाध्य रोग नियमावली के अन्तर्गत लाभार्थियों की श्रेणी में बी0पी0एल0 कार्ड धारकों एवं बी0पी0एल0 सूची के सदस्यों के साथ–साथ सवा तीन एकड़ तक की जोत

---

† rkjkafdr ç'u la0&6 N mijkUr ç'uksa dk le; lekIr gqvkA

के कृषक अथवा जिनकी आय रु0 35,000.00 (रुपये पैंतीस हजार मात्र) वार्षिक से कम हो एवं सेवारत राज्य कर्मचारी सम्मिलित है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य सरकार द्वारा राशन कार्ड बनाने के लिये प्राइवेट कम्पनियों को टेन्डर दिये जाने एवं प्राइवेट कम्पनियों द्वारा जारी राशन कार्ड में भारी खामियों के बाद मेसर्स आरकेड नामक कम्पनी को ब्लैकलिस्टेड किये जाने की जानकारी

'08–श्री नदीम जावेद–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सरकार राशन कार्ड बनाने के लिये प्राइवेट कम्पनियों को टेन्डर देती है ? यदि हां, तो क्या इन प्राइवेट कम्पनियों द्वारा जारी राशन कार्ड में भारी खामियां पाये जाने के कारण मेसर्स आरकेड नामक कम्पनी को ब्लैकलिस्टेड किया गया है ? यदि हां, तो राशन कार्ड बनाने जैसे महत्वपूर्ण कार्य में सुधार एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य कराये जाने के लिए सरकार की क्या कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री कमाल अख्तर)–

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के एण्ड–टू एण्ड कम्प्यूटरीकरण के अन्तर्गत नये राशन कार्डों के ऑनलाइन मुद्रण एवं निर्गमन के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–3575/29–6–2013–109 सा/2013, दिनांक 01 अक्टूबर, 2013 में दिये गये निर्देशों के क्रम में ऑनलाइन राशन कार्डों के मुद्रण व निर्गमन कराये जाने की प्रक्रिया निर्धारित की गयी है। उक्त शासनादेश के अन्तर्गत जिलाधिकारी वेण्डर्स/एजेन्सियों के माध्यम से यह कार्य जिलों में विकेन्द्रीकृत व्यवस्था से कराना सुनिश्चित करेंगे।

जिला पूर्ति अधिकारी, लखनऊ की आख्यानुसार मेसर्स आरकेड नामक कम्पनी के विरुद्ध दिनांक 10 सितम्बर, 2015 को थाना हजरतगंज में एफ0आई0आर0 दर्ज करायी गयी है।

जी हां। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत चयनित पात्र गृहस्थियों को ऑनलाइन फीड किये गये डाटा का प्रिन्ट आउट उपलब्ध कराकर उसमें संशोधित त्रुटियों को ठीक कराये जाने का कार्य चल रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

'09–डा0 धर्मपाल सिंह–

ख्8वें मंगलवार के ता0प्र0सं0–07 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

प्रदेश में गरीब मेघावी छात्र/छात्रायें जो अर्थिक कठिनाई के कारण एम0बी0बी0एस0 की पढ़ाई करने में असमर्थ रहते हैं, को किन्हीं शर्तों पर एम0बी0बी0एस0 की मुफ्त शिक्षा प्रदान करने विषयक

'10–श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गरीब मेधावी छात्र/छात्रायें जो आर्थिक कठिनाई के कारण एम0बी0बी0एस0 की पढ़ाई करने में असमर्थ रहते हैं, को किन्हीं शर्तों पर एम0बी0बी0एस0 की मुफ्त शिक्षा प्रदान करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

प्रदेश के राजकीय मेडिकल कालेजों/किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ/उ0प्र0 ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान सैफई, इटावा में एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम में अध्ययनरत छात्रों से बहुत ही साधारण शुल्क लिया जाता है, जिसमें आरक्षित श्रेणी के छात्रों की ट्यूशन फीस (शिक्षण शुल्क) सामान्य वर्ग के छात्रों से ली जाने वाली ट्यूशन फीस की आधी होती है।

एम0बी0बी0एस0 में अध्ययनरत आरक्षित श्रेणी के छात्रों (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग) द्वारा जमा किये जाने वाले शुल्क की प्रतिपूर्ति भी प्रदेश के समाज कल्याण विभाग द्वारा कर दी जाती है। उक्त के अतिरिक्त आरक्षित श्रेणी के छात्रों को समाज कल्याण विभाग द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान किये जाने की व्यवस्था है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश की ग्राम पंचायतों में एक–2 सेक्रेटरी के अधीन 10 से 12 ग्राम सभाएं होने से कार्याधिक्य होने के कारण हो रही निवासियों की असुविधा हेतु सरकार द्वारा उक्त सेक्रेटरियों का कार्य क्षेत्र छोटा किये जाने की मांग

'11–श्री संजय प्रताप जयसवाल–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की ग्राम पंचायतों में एक–एक सेक्रेटरी के अधीन 10 से 12 ग्राम सभाएं होने से कार्याधिक्य होने के कारण सम्बन्धित ग्राम सभाओं के निवासियों को असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सेक्रेटरियों का कार्य क्षेत्र छोटा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजकिशोर सिंह–

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

प्रदेश के जनपद मुख्यालयों पर प्रस्तावित नये बस अड्डों के निर्माण कार्य शुरू कराये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

01–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के कितने जनपद मुख्यालयों पर नये बस अड्डे बनने प्रस्तावित हैं तथा इनका निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि शाहजहांपुर जनपद में बरेली मोड़ पर सैटेलाइट बस अड्डा प्रस्तावित है ? यदि हां, तो इसका निर्माण कब प्रारम्भ होगा ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री यासर शाह–

प्रदेश के 22 जनपद मुख्यालयों पर नये बस अड्डे बनाने प्रस्तावित है। इनका निर्माण वर्ष 2017 तक पूर्ण करा दिया जायेगा।

शाहजहांपुर जनपद में बरेली मोड़ पर सैटेलाइट बस अड्डा बनाने के लिए परिवहन निगम का कोई प्रस्ताव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

शाहजहांपुर में पूर्व से ही परिवहन निगम का बस स्टेशन निर्मित है। अतः सैटेलाइट बस स्टेशन बनाये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

जनपद इलाहाबाद स्थित स्वरूप रानी अस्पताल के खुले प्रांगण में एकत्रित कूड़े की व्यवस्था की मांग

02–श्री दीपक पटेल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद स्थित स्वरूप रानी अस्पताल के खुले प्रांगण में कूड़ा एकत्र किये जाने से डाक्टरों, मरीजों तथा आस–पास रहने वालों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तथा आस–पास के लोग बीमार हो रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार अस्पताल में कूड़ा स्टोर न बनाकर कहीं और कूड़ा स्टोर बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं। जनपद इलाहाबाद स्थित स्वरूपरानी अस्पताल की प्रतिदिन सफाई कर्मियों द्वारा सफाई करने के उपरान्त कूड़े को एकत्रित कर अस्पताल परिसर के पिछले हिस्से में एक किनारे ऐसे स्थल पर रखा जाता है, जहां न तो कोई आवास है और न ही डाक्टरों एवं मरीजों का आना–जाना रहता है। अतः संक्रमण की संभावना नहीं है। उक्त कूड़े को नगर निगम द्वारा सप्ताह में दो बार उठवा लिया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड नियामताबाद के ग्राम सभाओं के पंचायत चुनाव 2015 के मतदाता सूची में नाम हटाने के सम्बन्ध में विवरण की मांग

03–श्री बब्बन सिंह चौहान–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड नियामताबाद के ग्राम सभाओं के पंचायत चुनाव 2015 के मतदाता सूची में पुनरीक्षण के नाम पर 35ः मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से काटा गया है, के विरुद्ध प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 24–11–2015, पत्र सं0–ख–5–एन–321920 जिलाधिकारी, जनपद चन्दौली को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजकिशोर सिंह–

जी हां।

जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय), चन्दौली के पत्र दिनांक 09–02–2016 द्वारा अवगत कराया गया है कि राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा निर्गत अधिसूचना दिनांक 17–05–2015 के क्रम में मतदाता

सूची का वृहद पुनरीक्षण कराया गया जिसके दौरान 01–06–2015 से 13–07–2015 तक बी0एल0ओ0 द्वारा घर–घर जाकर गणना और सर्वेक्षण कार्य किया गया। उक्त अवधि में बी0एल0ओ0 द्वारा छूटे हुए नामों का परिवर्धन, त्रुटिपूर्ण नामों का संशोधन एवं अपात्र नामों का विलोपन किया गया। किसी पात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची से विलोपित नहीं किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर विधान सभा क्षेत्र तिलहर के कतिपय कच्चे गड्ढायुक्त मार्ग के निर्माण की मांग

04–श्री रोशन लाल वर्मा–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–शाहजहांपुर, विधान सभा क्षेत्र–तिलहर, विकास खण्ड–निगोही में बरैचा से बुढानपुर तक रेलवे स्टेशन निगोही से कटैया उसमानपुर तक एवं बिलसण्डा रोड पर ईशापुर से बहादुरपुर तक के मार्ग कच्चे गड्ढायुक्त, ऊबड़–खाबड़ होने के कारण जनता को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्गों का निर्माण/मरम्मत कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजकिशोर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

05–श्री रोशन लाल वर्मा–

ख्4थे बुधवार के अता0प्र0सं0–187 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

06–श्री भगवान सिंह कुशवाहा–

ख्3सरे बुधवार के अता0प्र0सं0–200 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

07–श्री भगवान सिंह कुशवाहा–

ख्3सरे बुधवार के अता0प्र0सं0–199 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

जनपद बस्ती में पंचायत चुनाव के दौरान खरीदी गई सोलर लाइट की जांच सम्बन्धी विषयक

08–श्री संजय प्रताप जयसवाल–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती में पंचायत चुनाव के दौरान नियम विरुद्ध चीन निर्मित सोलर लाइट बिना निविदा कराये खरीदने की उच्च स्तरीय जांच तथा दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 22 दिसम्बर, 2015 प्रमुख सचिव, पंचायती राज, उ0प्र0 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजकिशोर सिंह–

जी हां।

पत्र दिनांक 07 जनवरी, 2016 द्वारा जिलाधिकारी, बस्ती से आख्या मांगी गयी। जिलाधिकारी द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 30 जनवरी, 2016 के अनुसार शिकायत को निराधार एवं तथ्यहीन पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत सम्पर्क मार्ग को पिचमार्ग में परिवर्तित करने सम्बन्धी विषयक

09–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के विशेश्वरगंज पुरैना सम्पर्क मार्ग से परशुरामपुरवा गांव में राम किशोर गोस्वामी के घर तक सम्पर्क मार्ग को पिचमार्ग में परिवर्तित कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर मुख्य मंत्री सचिवालय में दर्ज कम्प्यूटर संख्या–पी0जी0 10682358, पत्र संख्या–सीएम/वि0को0/एम0/पी0जी0 10682358/2015, दिनांक 02–09–2015 निदेशक, पंचायती राज को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजकिशोर सिंह–

जी हां।

धनाभाव के कारण निर्माण कार्य कराया जाना संभव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

10–श्री दीपक पटेल–

ख्4थे मंगलवार के अता0प्र0सं0–102 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

सरकारी मेडिकल कालेजों में शिक्षारत विद्यार्थियों से फीस सम्बन्धित जानकारी के सम्बन्ध में विवरण

11–डा0 अरुण कुमार–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र ख–5 नं0–032531, दिनांक 14–08–2015 जो सरकारी मेडिकल कालेजों में शिक्षारत विद्यार्थियों से फीस सम्बन्धित जानकारी के सम्बन्ध में था, प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग उ0प्र0 लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

शासनादेश दिनांक 20–08–2010 द्वारा चिकित्सा शिक्षा (एलोपैथी) में स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों का शुल्क निर्धारित किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है :––

(क) स्नातक पाठ्यक्रम

1–शिक्षण शुल्क	रु0 18000/– प्रतिवर्ष
2–अन्य शुल्क	रु0 4000/– प्रतिवर्ष
3–विकास शुल्क	रु0 2000/–प्रतिवर्ष
4–प्रवेश शुल्क	रु0 2000/– केवल प्रवेश के समय
5–काशन मनी	

(रिफण्डेबुल)	रु0 10000/– केवल प्रवेश के समय
6–छात्रावास शुल्क	
सिंगल सीटेड	रु0 300/– प्रतिमाह
डबल सीटेड	रु0 200/– प्रतिमाह
ट्रिपल सीटेड/अधिक	रु0 100/– प्रतिमाह
7–विद्युत उपभोग	रु0 200/– प्रतिमाह
(ख) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम	
1–शिक्षण शुल्क	रु0 24000/– प्रतिवर्ष
2–अन्य शुल्क	रु0 4000/– प्रतिवर्ष
3–विकास शुल्क	रु0 2000/– प्रतिवर्ष
4–प्रवेश शुल्क	रु0 2000/– केवल प्रवेश के समय
5–काशन मनी	रु0 10000/– केवल प्रवेश के समय
(रिफण्डेबुल)	
6–छात्रावास शुल्क	निःशुल्क
7–विद्युत उपभोग	रु0 500/– प्रतिमाह

आरक्षित श्रेणी के छात्रों के ट्यूशन फीस (शिक्षण शुल्क) सामान्य वर्ग के छात्रों से ली जाने वाली ट्यूशन फीस (शिक्षण शुल्क) की आधी (50 प्रतिशत) होगी।

स्नातक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत आरक्षित श्रेणी के छात्रों (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग) द्वारा जमा किये जाने वाले शुल्क की प्रतिपूर्ति भी प्रदेश के समाज कल्याण विभाग द्वारा कर दी जाती है, साथ ही आरक्षित श्रेणी के छात्रों को समाज कल्याण विभाग द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान किये जाने की भी व्यवस्था है।

जनपद फैजाबाद के विकास खण्ड मवई में बैठकों के द्वारा की गई स्वीकृत परियोजनाओं के पूर्ण होने के सम्बन्ध में विवरण

12–श्री रामचन्द्र यादव–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–फैजाबाद के विकास खण्ड मवई में क्षेत्र पंचायत की वर्ष 2012 से जनवरी, 2016 तक कुल कितनी बैठकें हुईं तथा बैठकों में पारित राज्य वित्त आयोग 13वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर स्वीकृत परियोजनाओं में कितनी परियोजनाओं का कार्य पूर्ण हो गया है तथा कितनी अधूरी हैं ? क्या सरकार अधूरी योजनाओं को निश्चित समय सीमा में पूर्ण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजकिशोर सिंह–

जनपद फैजाबाद के विकास खण्ड मवई में क्षेत्र पंचायत की वर्ष 2012 से जनवरी, 2016 तक कुल 03 बैठकें हुई है। बैठक में पारित संस्तुति के सापेक्ष उपलब्ध धनराशि के आधार पर राज्य वित्त आयोग में स्वीकृत 91 परियोजनाओं के सापेक्ष 55 एवं 13वें वित्त में 74 परियोजनाओं के सापेक्ष 27 का कार्य पूर्ण हो गया है।

शेष स्वीकृत कार्य धनराशि उपलब्ध होने पर कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

सरकार को राशन की दुकानों से उपभोक्ताओं के खाद्यान्न आवंटन करने में कम वजन/तौल करने सम्बन्धी जानकारी एवं खाद्यान्न राशन सामग्री पैकेट में प्रदान करने के सम्बन्ध में जानकारी

13–श्री मनीष असीजा–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को राशन की दुकानों से उपभोक्ताओं को खाद्यान्न आवंटन करने में कम वजन/तौल करने सम्बन्धी शिकायतों की जानकारी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त को रोकने के सम्बन्ध में उपभोक्ताओं को खाद्यान्न राशन सामग्री पैकेट में प्रदान करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कमाल अख्तर–

राशन की दुकानों से उपभोक्ताओं को खाद्यान्न आवंटन करने में कम वजन/तौल करने सम्बन्धी शिकायतों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाती है। प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की गुणवत्ता को उच्चीकृत करने की दृष्टि से त्रिस्तरीय चेकिंग व्यवस्था लागू है, जिसके अन्तर्गत प्रवर्तन कार्रवाई की जाती है। प्रवर्तन कार्रवाई के अन्तर्गत माह अप्रैल, 2015 से जनवरी, 2016 तक 32629 छापे/निरीक्षण किये गये, जिसके अन्तर्गत 507 एफ0आई0आर0 दर्ज करायी गयी है। इसके अतिरिक्त 2859 उचित दर दुकानों को निलम्बित, 1551 उचित दर दुकानों को निरस्त किया गया, रु0 222.92 लाख की प्रतिभूति की राशि जब्त की गयी एवं रु0 954.49 लाख की आवश्यक वस्तुएं जब्त की गयी है।

राशन की दुकानों से उपभोक्ताओं को खाद्यान्न/राशन सामग्री पैकेट में प्रदान करने की व्यवस्था वर्तमान में नहीं हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान में शासन की ऐसी कोई नीति नहीं है।

प्रदेश में कार्यरत घरेलू कामगारों को अन्य राज्यों की भांति श्रमिक श्रेणी में लाने एवं उनकी न्यूनतम मजदूरी निर्धारित किये जाने विषयक

14–श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या–

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री को सम्बोधित मा0 नेता विरोधी दल, विधान सभा, उ0प्र0 का पत्र संख्या–66/ने0वि0द0/2016, दिनांक 12–01–2016, जो प्रदेश में कार्यरत घरेलू कामगारों को अन्य राज्यों की तरह श्रमिकों की श्रेणी में लाने एवं उनकी न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (श्री शाहिद मंजूर)–

जी हां।

घरेलू कामगारों के सम्बन्ध में न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण किये जाने हेतु न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की अनुसूची–1 के अन्तर्गत सम्मिलित किये जाने हेतु अग्रेतर कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के पयागपुर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत झाला तरहर के आवागमन को सुलभ करवाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर की गई कार्रवाई की जानकारी

15–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के ग्राम पंचायत झाला तरहर में आवागमन को सुलभ बनाने हेतु मार्ग को आर0सी0सी0 कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर मुख्य मंत्री सचिवालय में दर्ज कम्प्यूटर संख्या–पी0जी0–10694071, पत्र संख्या–सी0एम0 / वि0को0 / एम0 / पी0जी0–10694071 / 2015, दिनांक 30–09–2015 जिलाधिकारी, बहराइच को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजकिशोर सिंह–

जी हां।

धनाभाव के कारण कार्रवाई नहीं की जा सकी। जिला विकास अधिकारी, बहाइच के पत्र दिनांक 04–01–2016 द्वारा मा0 सदस्य को उक्त स्थिति से सूचित किया जा चुका है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र के ग्राम पं0 बनघुसरा में मार्ग को खड़न्जा कराये जाने प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 30–09–2015 पर गई कार्रवाई की जानकारी

16–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के ग्राम पं0 बनघुसरा में मार्ग को खड़न्जा कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर मुख्य मंत्री सचिवालय में दर्ज कम्प्यूटर संख्या–पी0जी0–10694085 पत्र संख्या–सी0एम0 / वि0को0 / एम0 / पी0जी0–10694085 / 2015, दिनांक 30–09–2015 जिलाधिकारी, बहराइच को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजकिशोर सिंह–

जी हां।

जिलाधिकारी, बहराइच द्वारा प्रश्नगत पत्र में उल्लिखित प्रकरण के सम्बन्ध में आवश्यक कार्रवाई हेतु खण्ड विकास अधिकारी, विशेश्वरगंज, बहराइच को निर्देशित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर में सरकारी सस्ते गल्ले के स्वीकृत दुकानों की जानकारी विषयक

17–श्री नदीम जावेद–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–जौनपुर में सरकारी सस्ते गल्ले की स्वीकृत दुकानों में से वर्तमान समय में कितनी दुकानें चल रही हैं तथा

कितनी निलम्बित हैं ? क्या यह सही है कि बहुत से कोटेदारों की मृत्यु होने के उपरान्त भी उसी के नाम से चल रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर आवश्यक कार्रवाई करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कमाल अख्तर–

वर्तमान समय में जनपद जौनपुर में उचित दर की कुल 2002 दुकानें कार्यरत हैं, जिसके सापेक्ष 18 दुकानें निलम्बित चल रही हैं। इन निलम्बित दुकानों का निकटस्थ उचित दर विक्रेता के यहां सम्बद्धीकरण करके उठान/वितरण पर्यपेक्षणीय अधिकारी की उपस्थिति में कराया जा रहा है।

जी नहीं। जनपद में मृतक कोटेदार के नाम से कोई भी उचित दर की दुकान संचालित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के विकास खण्ड–सरगंज के कतिपय मार्गों के निर्माण कराये जाने विषयक

18–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर में वि0ख0–सरगंज के अन्तर्गत ग्राम पंचायत कचनापुर, सगारपुर से पिच मार्ग टेढ़वा अल्पी मिश्र तक लगभग 600 मीटर पिच मार्ग पर गैप है और रोड का निर्माण नहीं हुआ है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा इसका निर्माण कार्य कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजकिशोर सिंह–

जी हां।

धनाभाव के कारण निर्माण कार्य कराया जाना सम्भव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 में निर्दिष्ट जिला, ब्लाक एवं उचित दर की दुकानों के स्तर पर सतर्कता समितियों के गठन की मांग

19–श्री मनीष असीजा–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता एवं जवाब देही हेतु आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन किये गये सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2001 में निर्दिष्ट जिला ब्लाक एवं उचित दर की दुकानों (राशन दुकानों) के स्तर पर सर्तकता समितियों का गठन किया गया है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो उक्त समितियों का गठन कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री कमाल अख्तर–

भारत सरकार, उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के जी0एस0आर0–630(ई), दिनांक 31 अगस्त, 2001 के

क्रम में उत्तर प्रदेश अनुसूचित वस्तु वितरण आदेश, 2004 निर्गत किया गया है, जिसके प्रस्तर–21 ख्3(1), में प्राविधान किया गया है कि ''सक्षम प्राधिकारी उचित मूल्य की दुकान के स्तर पर सतर्कता समितियों/प्रशासनिक समिति (ग्राम सभा स्तरीय) का गठन सुनिश्चित करेगा, जोकि उचित मूल्य की दुकान के कार्य का अनुश्रवण करेगी''। शासनादेश दिनांक 19–07–2006 द्वारा दुकान स्तर पर गठित विभागीय/प्रशासनिक/सतर्कता समितियों को भंग करते हुए उनका कार्य एवं दायित्व पंचायती राज विभाग द्वारा गठित प्रशासनिक समिति को पूर्ण रूप से सौंप दिया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर में प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 9–9–2015 में उल्लिखित सम्पर्क मार्ग को पिच में परिवर्तित कराये जाने विषयक पत्र पर कार्रवाई की मांग

20–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के पत्र में उल्लिखित सम्पर्क मार्ग को पिच मार्ग में परिवर्तित कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर मुख्य मंत्री सचिवालय में दर्ज कम्प्यूटर संख्या–पी0जी0–10684960, पत्र संख्या–सी0एम0/वि0को0/एम0/पी0जी0–10684960/2015, दिनांक 09–09–2015 प्रमुख सचिव, पंचायती राज को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजकिशोर सिंह–

जी हां।

धनाभाव के कारण कार्रवाई नहीं की जा सकी।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बहराइच के ग्राम पंचायत बिराहिमपुर बेल्हौरा के 01 मार्ग का डामरीकरण/सी0सी0 कराये जाने प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 16–8–15 पर की गई कार्रवाई विषयक

21–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के ग्राम पंचायत बिराहिमपुर बेल्हौरा के 01 मार्ग का डामरीकरण/सी0सी0 कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर मुख्य मंत्री सचिवालय में दर्ज कम्प्यूटर संख्या–पी0जी0–10688539, पत्र संख्या–सी0एम0/वि0को0/एम0/पी0जी0–10688539/2015, दिनांक 16–09–2015 प्रमुख सचिव, पंचायती राज को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजकिशोर सिंह–

जी हां।

धनाभाव के कारण कार्रवाई नहीं की जा सकी।

उपरोक्तानुसार।

जनपद मुगलसराय के ग्राम सभा चौरहट में कतिपय स्थलों पर जल निकासी हेतु 500 मीटर नाले निर्माण कराये जाने विषयक

22–श्री बब्बन सिंह चौहान–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के ग्राम सभा–चौरहट, वि0ख0–नियामताबाद में पीरू सविृद, नई बस्ती में डा0 नुमानी के घर से पूरब तरफ जल निकासी के लिये 500 मीटर नाला निर्माण करवाना अति आवश्यक है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त नाला निर्माण करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजकिशोर सिंह–

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम पंचायत के पास पर्याप्त धनराशि उपलब्ध नहीं होने के कारण कार्य कराया जाना सम्भव नहीं है।

जनपद इलाहाबाद के ग्रामीण क्षेत्रों में भी नगर निगम की भांति अधिक घनी आबादी वाली ग्राम सभाओं में सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था कराये जाने विषयक

23–श्री दीपक पटेल–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–इलाहाबाद के नगर निगम क्षेत्र में स्थापित सार्वजनिक शौचालय की तरह ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक घनी आबादी वाले ग्राम सभाओं में सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था का लाभ ग्रामीणों तक पहुंचायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजकिशोर सिंह–

जी हां।

जनपद इलाहाबाद में स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत वार्षिक कार्य योजना 2015–16 में 50 सामुदायिक स्वच्छता परिसर प्रस्तावित किये गये हैं। सामुदायिक स्वच्छता परिसर हेतु धनराशि प्राप्त होने पर घनी आबादी वाले ग्राम सभाओं में सार्वजनिक शौचालय का लाभ ग्रामीणों को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत बुलन्दशहर श्री प्रदीप कुमार के विरुद्ध पुल निर्माण में की गई अनियमितताओं की जांच सी0बी0आई0 से कराये जाने विषयक

24–श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या वर्तमान में अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत बुलन्दशहर तथा तत्कालीन जिला पंचायत कुशीनगर प्रदीप कुमार के विरुद्ध एक पुल निर्माण की जांच में दोषी पाये जाने पर सी0बी0आई0 द्वारा

उनके विरुद्ध अभियोजन दर्ज कराने की अनुमति शासन ने नहीं दिया है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री राजकिशोर सिंह–

जी हां।

सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा श्री प्रदीप कुमार के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृत करने का औचित्य नहीं पाया गया।

25–श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव–

ख्दिनांक 25–02–2016 को अता0प्र0सं0–22 द्वारा उत्तरित,

जनपद बलिया की आयुर्वेद डिस्पेंसरियों हेतु सरकारी भवन उपलब्ध करवाये जाने विषयक

26–श्री जय प्रकाश अंचल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार जनपद–बलिया में आयुर्वेद की डिस्पेंसरियां वर्तमान समय में किराये के भवनों में हैं, कितने सरकारी भवनों में संचालित हैं ? क्या सरकार किराये के भवनों में संचालित डिस्पेंसरियों को उनके लिये सरकारी भवन बनाकर संचालित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जनपद बलिया में 35 आयुर्वेदिक डिस्पेंसरियां किराये के भवनों में एवं 15 आयुर्वेदिक डिस्पेंसरियां सरकारी भवनों में संचालित हैं।

जिला अनुश्रवण समिति से अनुमोदित निर्माण के प्रस्ताव के सापेक्ष उपलब्ध परिव्यय एवं बजट की उपलब्धता के आधार पर चिकित्सालयों के भवनों का निर्माण कराया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद के विकास खण्ड रूदौली के ग्राम पंचायत फिरोजपुर मखदूमी के प्रधान पद के निर्वाचन में की गई अनियमितता की जांच करवाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 29–12–2015 पर की गई कार्रवाई की जानकारी

27–श्री रामचन्द्र यादव–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–फैजाबाद के विकास खण्ड रूदौली के ग्राम पंचायत फिरोजपुर मखदूमी के प्रधान पद के निर्वाचन में की गयी अनियमितता की जांच कराकर निर्वाचन निरस्त करने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर मुख्य मंत्री कार्यालय के कम्प्यूटर में दर्ज पत्र संख्या–सी0एम0/वि0को0/एम0/पी0जी0–10721579/15, दिनांक 29–12–2015 द्वारा निदेशक, पंचायती राज को आदेश दिये गये थे ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्रवाई की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजकिशोर सिंह–

जी हां।

प्रश्नगत पत्र प्रधान पद के निर्वाचन की मतगणना घोषित होने के उपरान्त प्राप्त होने के कारण जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी, फैजाबाद अथवा निदेशक,

पंचायती राज के स्तर से कोई कार्यवाही करने की अधिकारिता नहीं रह जाती है, क्योंकि संयुक्त प्रान्त, पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा–12(ग) में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार शिकायत सक्षम प्राधिकारी को निश्चित समय के भीतर प्राप्त होनी चाहिए, फिर भी निदेशक, पंचायती राज के पत्र दिनांक 22–2–2016 द्वारा शिकायतकर्ता को नियमानुसार वाद सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट/एस0डी0एम0 के न्यायालय में योजित करने का सुझाव दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया की निलम्बित की गई सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों को बहाल करवाने विषयक

28–श्री जय प्रकाश अंचल–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र बैरिया जनपद–बलिया में सरकारी सस्ते गल्ले की निलम्बित दुकानों को सरकार बहाल करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कमाल अख्तर–

विधान सभा बैरिया अन्तर्गत विकास खण्ड–मुरलीछपरा के ग्राम पंचायत–मुरलीछपरा की 04 दुकानें क्रमशः जनार्दन सिंह–केन्द्र दोकटी, रंग सिंह–केन्द्र दोकटी, नूरजहां–केन्द्र विशुनपुरा, मदन यादव–केन्द्र नवानगर की दुकान नायब तहसीलदार बैरिया व पूर्ति निरीक्षक बैरिया की जांच आख्या के आधार पर उप जिलाधिकारी, बैरिया द्वारा दिनांक 13 जनवरी, 2016 को निलम्बित की गयी है। उप जिलाधिकारी, बैरिया द्वारा उक्त निलम्बन आदेश में विक्रेताओं को उनके ऊपर लगाये गये आरोप के सम्बन्ध में साक्ष्य सहित स्पष्टीकरण उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। उचित दर विक्रेताओं द्वारा अपना स्पष्टीकरण उप जिलाधिकारी, बैरिया को प्रस्तुत कर दिया गया है।

दुकानों को बहाल/निरस्त करने का निर्णय उप जिलाधिकारी, बैरिया के यहां लम्बित है।

उक्तानुसार।

जनपद बुलन्दशहर में स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत ब्लाक खुर्जा तथा लाड अरनिया में निर्माण कराये गये शौचालयों की जानकारी

29–श्री बंशी सिंह पहाड़िया–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत जनपद–बुलन्दशहर के ब्लाक खुर्जा तथा लाड अरनिया में कितने शौचालयों का निर्माण कराया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजकिशोर सिंह–

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत जनपद–बुलन्दशहर के ब्लाक–खुर्जा में 1436 शौचालयों तथा लाड अरनिया में 467 शौचालयों का निर्माण कराया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में निजी वाहनों पर गलत तरीके से लाल व नीली बत्ती लगाने पर दण्ड प्राविधानित करने की मांग

30–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में लाल बत्ती व नीली बत्ती किन–किन राजनेताओं/अधिकारियों की सरकारी गाड़ियों पर अनुमन्य हैं ? क्या जो लोग अपनी निजी गाड़ियों पर अनाधिकृत रूप से लाल या नीली बत्ती लगाते हैं, के लिये क्या दण्ड प्राविधानित है ? क्या गलत तरीके से प्रयुक्त बत्तियों को रोकने के लिये इसके दण्ड को बढ़ाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यासर शाह–

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या–4/352/तीस–4–2014–8(1)/13, दिनांक 10–03–2014 व अधिसूचना संख्या–544/तीस–4–2014–8(1)/13, दिनांक 22–08–2014 में उल्लिखित राजनेताओं/अधिकारियों को लाल बत्ती प्रयोग करने की अनुज्ञा प्रदान की गयी है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या–6/354/तीस–4–2014–8(1)/13, दिनांक 10–03–2014 में उल्लिखित अधिकारियों को नीली बत्ती के प्रयोग करने की अनुज्ञा प्रदान की गयी है।

मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–177 के अन्तर्गत गाड़ियों पर अनधिकृत रूप से लाल या नीली बत्ती प्रयोग करने वाले व्यक्तियों के लिये प्रथम बार अपराध के लिये जुर्माने से, जो एक सौ रुपये तक का हो सकेगा और किसी द्वितीय या पश्चात्वर्ती अपराध के लिये, जुर्माने से जो तीन सौ रुपये तक का हो सकेगा दण्डनीय होगा।

केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम केन्द्र सरकार का है। उक्त अधिनियम में राज्य सरकार को किसी भी दण्ड को बढ़ाने का कोई प्राविधान नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गोरखपुर के बड़हलगंज में राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज के निर्माण को पूरा करवाने हेतु समय–सीमा निर्धारित करने की मांग

31–श्री राजेश त्रिपाठी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जनपद के बड़हलगंज (खड़ेसरी) में राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज का निर्माण विगत 5 वर्षों से चल रहा है ? यदि हां, तो उक्त निर्माण कार्य पूरा किये जाने की कोई समय–सीमा है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

जी नहीं। निर्माण कार्य का पुनरीक्षित आगणन नियमानुसार परीक्षणाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

32–श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या–

ख4थे बुधवार के अता0प्र0सं0–186 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

जनपद कानपुर नगर में मिलावटी खाद्य पदार्थों को बेचने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने की मांग

33–श्री अजय कपूर–

क्या खाद्य एवं औषधि प्रशासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–कानपुर नगर में खुले आम बिक रहे मिलावटी खाद्य पदार्थों के कारण नागरिकों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है और उन्हें भंयकर बीमारियां हो रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार मिलावट करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि इसके लिये दोषियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इकबाल महमूद–

जी नहीं। ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में कतिपय वर्षों में जिन एजेन्सियों द्वारा कम गेंहू की खरीद की गई है उनके विरुद्ध कार्रवाई की मांग

34–डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2012–13, 2013–14, 2014–15 तथा 2015–16 में गेहूं की खरीद लक्ष्य के सापेक्ष कम की गयी है ? यदि हां, तो किन–किन एजेन्सियों द्वारा कम की गयी है ? यदि हां, तो कम खरीद की जिम्मेदारी तय करके दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कमाल अख्तर–

रबी विपणन वर्ष 2012–13 के अन्तर्गत प्रदेश का कुल लक्ष्य 42.00 लाख मी0 टन था, जिसके सापेक्ष 50.62 लाख मी0 टन की खरीद की गयी, जो लक्ष्य का 120.54 प्रतिशत है।

रबी विपणन वर्ष 2013–14 के अन्तर्गत प्रदेश का कुल लक्ष्य 60.00 लाख मी0 टन था, जिसके सापेक्ष 6.8 लाख मी0 टन की खरीद की गयी, जो लक्ष्य का 11.38 प्रतिशत है।

रबी विपणन वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत प्रदेश का कुल लक्ष्य 45.00 लाख मी0 टन था, जिसके सापेक्ष 6.2 लाख मी0 टन की खरीद की गयी, जो लक्ष्य का 13.96 प्रतिशत है।

रबी विपणन वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत प्रदेश का कुल लक्ष्य 30.00 लाख मी0 टन था, जिसके सापेक्ष 22.67 लाख मी0 टन की खरीद की गयी, जो लक्ष्य का 75.57 प्रतिशत है।

रबी विपणन वर्ष 2012–13 में आवश्यक वस्तु निगम, नैफेड, एन0सी0सी0एफ0 तथा भारतीय खाद्य निगम, 2013–14 में खाद्य विभाग, पी0सी0एफ0, यू0पी0 एग्रो, यू0पी0एस0एस0, एस0एफ0सी0, कर्मचारी कल्याण निगम, नैफेड, एन0सी0सी0एफ0 एवं भारतीय खाद्य निगम तथा रबी विपणन वर्ष 2014–15 में खाद्य विभाग, पी0सी0एफ0, यू0पी0 एग्रो, यू0पी0एस0एस0, एस0एफ0सी0, कर्मचारी कल्याण निगम, एन0सी0सी0एफ0 एवं भारतीय खाद्य निगम, रबी विपणन वर्ष 2015–16 में पी0सी0एफ0, यू0पी0 एग्रो, यू0पी0एस0एस0, एस0एफ0सी0, कर्मचारी कल्याण निगम, एन0सी0सी0एफ0, पंजीकृत सहकारी समितियों नैफेड एवं भारतीय खाद्य निगम द्वारा लक्ष्य से कम खरीद की गयी। इन वर्षों में प्रदेश को प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ा, जिसके कारण गेहूं की उपज कम हुई तथा प्रदेश के किसानों के पास अपना गेहूं न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचने का पर्याप्त गेहूं की अनुपलब्धता थी। अतः क्रय एजेन्सियों द्वारा लक्ष्य से कम खरीद की गयी। वर्णित परिस्थितियों में कार्रवाई किया जाना उचित नहीं था।

प्रश्न नहीं उठता।

समस्या का कारण प्राकृतिक आपदायें थीं।

भारत सरकार की योजनान्तर्गत जनपद फिरोजाबाद के जिला चिकित्सालय को उच्चीकृत करते हुए मेडिकल कालेज बनाये जाने हेतु चयनित भूमि चिकित्सा शिक्षा विभाग को हस्तान्तरित करने की मांग

35–श्री मनीष असीजा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार की योजनान्तर्गत पांच जिला चिकित्सालयों (फिरोजाबाद, फैजाबाद, बहराइच, बस्ती एवं शाहजहांपुर) को उच्चीकृत करते हुए मेडिकल कालेज बनाये जाने के सम्बन्ध में उ0 प्र0 सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को भेजे गये प्रस्ताव में फिरोजाबाद मेडिकल कालेज हेतु चयनित भूमि को चिकित्सा शिक्षा विभाग को हस्तगत किये जाने सम्बन्धी पत्र भेजे गये हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार को जानकारी है कि बिना भूमि की उपलब्धता के उक्त प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा मेडिकल कालेज हेतु धनावंटन नहीं किया जा सकेगा ? यदि हां, तो क्या सरकार फिरोजाबाद मेडिकल कालेज हेतु चयनित भूमि को तत्काल चिकित्सा शिक्षा विभाग को हस्तान्तरित करने हेतु आवश्यक पत्र केन्द्र सरकार को प्रेषित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

जी हां।

जनपद फिरोजाबाद के जिला चिकित्सालय को भारत सरकार की योजना के अन्तर्गत उच्चीकृत किये जाने हेतु माध्यमिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 की भूमि चिन्हित कर ली गयी है। चिन्हित भूमि को चिकित्सा शिक्षा विभाग को हस्तान्तरित किये जाने की कार्रवाई राज्य सरकार द्वारा की जा रही है। भूमि हस्तान्तरण हेतु केन्द्र सरकार को पत्र प्रेषित किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में वर्तमान वर्ष 2016 में ईंट भट्ठों के संचालन में रायल्टी शुल्क में की गई वृद्धि को कम करने की मांग

36–श्री रामचन्द्र यादव–

क्या भू–तत्व एवं खनिकर्म मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने प्रदेश में वर्तमान वर्ष 2016 में रायल्टी शुल्क में 120 गुना की वृद्धि के कारण ईंट भट्ठों के संचालन में कठिनाई हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त को कम करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

भू–तत्व एवं खनिकर्म मंत्री (श्री गायत्री प्रसाद प्रजापति)–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियमावली, 1963 के नियम–21 के प्राविधानों के अनुसार रायल्टी की दरें 03 वर्ष से पहले पुनरीक्षित नहीं की जा सकती हैं। इसके पूर्व 02 नवम्बर, 2012 में रायल्टी की दरें बढ़ायी गयी थी। वर्ष 2012 से दिसम्बर, 2015 तक रायल्टी की दरें यथावत रही हैं। वर्तमान में ईंट बनाने की मिट्टी हेतु रायल्टी दर रु0 54.00 प्रति हजार, बनी ईट निर्धारित की गयी है।

जनपद फिरोजाबाद में वर्ष 2015–16 में मिलावटी दूध में पकड़े गये दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग

37–श्री मनीष असीजा–

क्या खाद्य एवं औषधि प्रशासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में वर्ष 2015–16 में मिलावटी दूध के कितने मामले पकड़े गये तथा इसके लिये दोषियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इकबाल महमूद–

वित्तीय वर्ष 2015–16 में जनवरी, 2016 तक जनपद में दूध के सम्बन्ध में 45 निरीक्षण किये गये, 28 छापे डालकर 28 नमूने संग्रहीत किये गये हैं। इस अवधि में जांचोपरान्त 09 नमूने मानकों के अनुरूप नहीं पाये गये हैं। उक्त के सम्बन्ध में 07 वाद न्याय निर्णायक अधिकारी के न्यायालय में दायर किये जा चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

ख12.21, मुजफ्फरनगर दंगों के स्टिंग आपरेशन से सम्बन्धित जांच समिति की संस्तुतियों के क्रम में टी0वी0 टुडे ने वर्क के पदाधिकारियों द्वारा प्रमुख सचिव, विधान सभा को सदन में उपस्थित होने की समय–सीमा बढ़ाये जाने से सम्बन्धित प्रेषित–पत्र पर सदन का अभिमत

श्री अध्यक्ष–

मुजफ्फरनगर दंगों के स्टिंग आपरेशन से संबंधी जांच समिति की संस्तुतियों के क्रम में टी0वी0 टुडे नेटवर्क के पदाधिकारियों को सदन में आज उपस्थित होने के निर्देश

दिए गए थे। उनकी ओर से एक पत्र प्रमुख सचिव को प्राप्त हुआ है। प्रमुख सचिव इस पत्र को सदन के समक्ष पढ़कर सदन को अवगत करायेंगे। प्रमुख सचिव सदन के समक्ष रखें।

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, आप द्वारा प्रेषित पत्र संख्या–42/वी0एस0/लेजिस्लेचर/157/एस0, 2013 जिस पर 23–02–2016 की तारीख अंकित है। हमें 24–02–16 को शाम 7.00 बजे प्राप्त हुआ। जिसमें लिखा है कि हम सम्माननीय विधान सभा और माननीय विधान सभा अध्यक्ष का पूरा सम्मान करते हैं। साथ ही हम यह निवेदन करना चाहते हैं कि इस नोटिस पर जवाब देने के लिए हमें बहुत कम समय दिया गया है। हम इस बात के लिए आपसे क्षमा चाहते हैं कि यह व्यावहारिक रूप से संभव नहीं हो पा रहा है कि हम 26–02–2016 को सम्माननीय विधान सभा के समक्ष उपस्थित हो पाएं। इसके अलावा हमें कमेटी की उस जांच रिपोर्ट और संस्तुतियों की पूरी प्रति भी प्राप्त नहीं हुई है। हम सम्माननीय विधान सभा के समक्ष अपने केस में अपना पक्ष रखने के लिए निवेदन करते हैं कि हमें रिपोर्ट की प्रति प्राप्त करायी जाये और विधान सभा में पेश होने के लिए हमें कोई दूसरी तारीख दी जाये ताकि हमें सम्माननीय विधान सभा के समक्ष अपनी बात रखने के लिए थोड़ा और वक्त मिल जाये। श्रीमती पद्मा जोशी और श्री दीपक शर्मा, टी0वी0 टुडे नेटवर्क लिमिटेड में फिलहाल कार्यरत नहीं हैं क्योंकि यह नोटिस उनके निमित्त भी प्राप्त हुआ है अतः हम उनसे सम्पर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। हम यह पूरी ईमानदारी के साथ कहना चाहते हैं कि माननीय विधान सभा अध्यक्ष और सम्माननीय विधान सभा का हम पूरा सम्मान करते हैं। हमारी पूरी इच्छा है कि हम सम्माननीय विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत हों। हम सिर्फ इसलिए आपसे वक्त मांग रहे हैं ताकि रिपोर्ट और उसकी संस्तुतियों को हम ठीक से अध्ययन कर सकें और आपके सहयोग से अपनी बात सही ढंग से पेश कर सकें। हम आपसे आशा करते हैं कि हमारे इस निवेदन पर कृपापूर्वक विचार करते हुए आप हमें अपना पक्ष रखने के लिए थोड़ा वक्त और देंगे।

भवदीय, डा0 पुनीत जैन, ग्रुप हेड लीगल एण्ड कम्पलायनसेंस टी0वी0 टुडे नेटवर्क।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता विरोधी दल इस पर आप अपने विचार रखें।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

माननीय अध्यक्ष जी, यह संस्तुति 16 फरवरी को इस सदन में प्रस्तुत हुई थी और आज 26 फरवरी है। बीच में दस दिन का अन्तराल था। यद्यपि कि प्रस्तुत होने के लिए इनके पास पर्याप्त समय था और इसके बावजूद सदन में न आना और पत्र भेजना यह किसी न किसी बहाने की ओर इंगित करता है। चूंकि सदन एक तरफा कार्रवाई करने के पक्ष में भी नहीं है इसलिए नैसर्गिक न्याय का तकाजा है कि जब सभी प्रकार के उच्च संवैधानिक और न्यायिक प्रतिष्ठान यानी न्यायपालिकाएं भी निवेदन पर समय देती हैं तो एक अवसर हमें इन्हें देना चाहिए और साथ ही साथ यदि यह पत्र हाथोंहाथ आया हो तो इसकी भी स्थिति को प्रमुख सचिव जी स्पष्ट करेंगे। अगर पत्र हाथोंहाथ

आया है तो उसी वक्त उनको जांच सम्बन्धी जो प्रतिवेदन है उसको भी हस्तगत कर देना चाहिए और अन्तिम निर्देश के साथ जो भी तिथि आज आपके द्वारा सुनिश्चित की जाती है। हर हालत में उस तिथि पर उनकी उपस्थिति अनिवार्य हो और उसमें भी यदि कहीं आना–कानी, बहानेबाजी या चिट्ठी के माध्यम से समय मांगने की बात आती है तो उसके बाद वारण्ट इश्यू करके उनको यहां तलब किया जाए लेकिन जो सदन की मंशा है जिस तरीके से, मनमाने तरीके से कट ऐण्ड पेस्ट के माध्यम से स्टिंग को तैयार कर किसी की भी छवि को खराब करने का जो घिनौना खेल खेला गया है, किसी भी हालत में उनको इसकी गलती का एहसास होना चाहिए इसलिए एक अवसर प्रदान करने के बाद जैसा कि चर्चा के दौरान मैंने विस्तार से इस पर अपनी बातें रखीं उसको भी ध्यान में रखते हुए कि कई दोषों में ये लोग वांछित हैं इसलिए उसके अनुरूप इनको कड़ी से कड़ी सजा भी अवश्य मिलनी चाहिए।

(सदन में मेजों की थपथपाहट)

मान्यवर, इसलिए इसमें मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि नैसर्गिक न्याय के आधार पर इनको एक अवसर प्रदान करें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, इस जांच समिति के गठन, प्रक्रिया और सुनवाई से भारतीय जनता पार्टी पहले ही अपने आपको अलग कर चुकी है।

श्री प्रदीप माथुर–

मा0 अध्यक्ष जी, मुजफ्फरनगर में हुए दंगे में किए गए स्टिंग ऑपरेशन से सम्बन्धित जांच समिति में आज समय दिया गया था और ये आज उपस्थित नहीं हुए। 10 दिन का समय काफी होता है तो मैं समझता हूं कि यह एक टैक्टिक है, एक तरीका है समय आगे बढ़ाने का। उन्होंने बाई हैण्ड लेटर मा0 प्रमुख सचिव को भेजा है। न्याय प्रक्रिया यह कहती है कि एक बार जब समय मांगा जाता है या डेट मांगी जाती है कोर्ट में तो कोर्ट भी उस पर विचार करती है कि समय दे दिया जाए परन्तु एक ही बार समय दिया जाए और इस पर टालमटोली नहीं होनी चाहिए। यह विधायिका की अस्मिता का मामला है और जो कुछ भी हुआ वह बड़ी निन्दनीय और खेदजनक इन्होंने व्यवस्था करी थी जिससे कि हम सब लोग शर्मसार हुए। इसमें एक डेट दे दीजिए और उसके बाद कोई डेट देने की जरूरत नहीं है।

श्री दलवीर सिंह–

मा0 अध्यक्ष जी, मैं नेता प्रतिपक्ष के सुझावों से पूर्ण रूप से सहमत हूं और अपने आप को सम्बद्ध करता हूं क्योंकि ये मा0 विधायकों का प्रश्न है और मा0 विधायकों से जुड़ा हुआ प्रश्न है। इस पर कार्यवाही तो गम्भीरता से अवश्य होनी चाहिए। अगर इस जैसी घटना पर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर क्या हाल होगा हम सब लोगों का तो मैं चाहूंगा कि समय की जब उन्होंने मांग की है तो समय उन्हें दे दिया जाए लेकिन टाइम बाउण्ड करके उन्हें अगली तारीख में निश्चित आने के लिए कोई प्राविधान जो भी नियमानुसार होता हो उस पर आप निर्णय करें।

(डा0 मो0 अयूब के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

डा0 साहब आप रुकिये आप नेता नहीं हैं, बैठें न, नेताओं से बात होती है।

डा0 मो0 अयूब–

माननीय अध्यक्ष जी, 24 को ये लेटर मिला है। मेरा आपसे यह अनुरोध है कि इसको स्पेशल मैसेन्जर से भेजा जाए, ताकि भेजने में कोई देरी न हो और सारे डाक्यूमेंट के साथ भेजा जाए।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि यह वाकया मेरी जात से ताल्लुक रखता है और मैं जैसा भी हूं यह सदन भी जानता है और साफ–सुथरी जिन्दगी गुजारने वाले लोग भी जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो मत अपना रखा और जो राष्ट्रवाद की परिभाषा इस वक्त पूरे देश में बहस में है। मान्यवर, राष्ट्रवाद एक ऐसा शब्द है जिससे पूरे राष्ट्र को एक किया गया। ''ए कॉनसेप्ट ऑफ वननेस'' कुछ बुनियादी सवाल लोकतंत्र के ऐसे हैं जिनपर बहस होने ही नहीं दी गई और नतीजा यह हुआ कि लोकतंत्र, संविधान और व्यवस्था के असल मायनों को आजाद हिन्दुस्तान समझ ही नहीं सका और अगर समझना चाहता था तो हमारी राजनैतिक खुदगर्जियां उन पर इतनी हावी आ गईं कि हमने नये–नये तरीके से उस परिभाषा को लज्जित किया, अपमानित किया और लोगों को समझने नहीं दिया। राष्ट्रवाद 1947 के बाद का कोई शब्द नहीं है। ''द कॉनसेप्ट ऑफ वाननेस'' उस वक्त था जब हिन्दुस्तानियों ने यह फैसला किया कि यह देश हमारा है और हमें अंग्रेजों को देश से बाहर कर देना है, उस वक्त हुआ था राष्ट्रवाद का पहला कॉनसेप्ट, पहला तसव्वुर उसी वक्त आया था हिन्दुस्तानियों के जेहन में, वे चाहे हिन्दू हो, मुसलमान हो, सिख हो और इसाई हो उन सब ने मिलकर राष्ट्रवाद पर एक मजबूत लड़ाई लड़ी थी और 1947 में देश आजाद हुआ था। आज जो लोग राष्ट्रवाद को अपने ढंग से पेश करना चाहते हैं, उनके अपने राजनैतिक मकासिद हो सकते हैं लेकिन राष्ट्रवाद का वह मतलब नहीं है जो आज बहस में है। मुझे बहुत तकलीफ हुई उस दिन जब भारतीय जनता पार्टी जो कि उस वक्त कि हां ये सब गलत हुआ है। यह अलग बात है कि आपने अपने सदस्य को नहीं भेजा कमेटी में, लेकिन अगर आप उस दिन की प्रोसीडिंग्स देखेंगे तो आप पूरे सदन के साथ थे, लेकिन आपने अपने पक्ष को अपने ढंग से रखा इसलिए इसमें आप उत्तेजित न हों, जो सच है वह भी सुनना चाहिए। मुजफ्फरनगर के दंगों का पूरा प्लान और पूरी भूमिका और इस स्टिंग आपरेशन को जो मेरा नहीं है। ये स्टिंग मेरा नहीं था, ये उस दरोगा का हो सकता है, लेकिन इसे नाम दिया गया मेरे स्टिंग का ताकि मुझे ज्यादा से ज्यादा बदनाम किया जा सके, इसलिए कि मैं खुद कहता हूं कि मैं मजबूत इरादों का आदमी हूं। मुझे अगर कोई गलत कहता है तो गलत साबित करे। मेरे लिए मान्यवर, यह कुर्सी बेशक सम्मान की है लेकिन यह मेरी मजबूरी नहीं है, मंत्री रहना या विधान सभा का सदस्य रहना मेरी मजबूरी नहीं है। इस सदन के सम्मान से ज्यादा नहीं है, इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता

पार्टी के उस अमल को छोड़कर अगर इस सदन का एक व्यक्ति भी, क्योंकि यह सवाल तन्हा मेरा नहीं है, यह सबके सम्मान का सवाल है। मैं तो बच गया लेकिन हो सकता है कि कोई कमजोर साथी न बच सके। इसलिए आज मैं पूरे सदन में बड़ी ईमानदारी के साथ कहता हूं कि अगर एक सदस्य को भी अपने पुराने फैसले से इत्तेफाक नहीं है तो यह मेरा त्याग–पत्र है। मैं आज अपना मंत्रि–मण्डल से इस्तीफा लेकर आया हूं, अगर एक सदस्य को भी इत्तेफाक नहीं है, तो मैं इस सदन का कम से कम मंत्री की हैसियत में रहने का अधिकार नहीं रखता। बहुत–बहुत, शुक्रिया।

श्री दलवीर सिंह–

शायद ही सदन का कोई ऐसा सदस्य हो।

श्री अध्यक्ष

त्याग–पत्र की कोई जरूरत नहीं है, सब आपसे इत्तेफाक रखते हैं।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

माननीय अध्यक्ष जी, जो संसदीय कार्य मंत्री जी की अपनी अन्तर्वेदना, पीड़ा सदन पटल पर आई, यह एक स्वाभाविक है। किसी की छवि को जो एक लम्बे संघर्ष के तहत ईमानदारी से इस ऊंचाई तक लाया हो, क्षण भर में किसी की साजिश से तथ्यहीन, झूठे आरोपों के बिना पर, उसके व्यक्तित्व का मानमर्दन किया जाये तो यह पीड़ा किसी की भी हो सकती है, जिसके साथ यह घटना घटती है और मान्यवर, इसीलिए जब यह प्रकरण स्टिंग आपरेशन पहली बार सदन में आया था तो मैंने ही आपसे निवेदन कर इस बात का प्रस्ताव रखा था कि इसकी विधिवत आपके द्वारा बनाई गयी कमेटी से जांच होनी चाहिए और उस पर सारे सदन की सहमति रही, आपने सबकी सहमति लेकर कमेटी का गठन किया और कमेटी ने अपनी जांच रिपोर्ट भी दी। जांच रिपोर्ट में संसदीय कार्य मंत्री जी श्री आजम खां पूर्णतः निर्दोश साबित हुए, स्टिंग आपरेशन तथ्यहीन और झूठा पाया गया इसीलिए आपने इस स्टिंग आपरेशन के द्वारा जो भी यहां घटनाक्रम हुआ उसके सम्बन्ध मे आपने जांच समिति की जो कमेटी रिपोर्ट बनाई थी, उस रिपोर्ट के परिप्रेक्ष्य में, जो भी दोषी हुए उनको चिन्हित कर आज यहां सदन में प्रस्तुत होने का निर्देश दिया था और उनका पत्र आया जिसमे उन्होंने आपसे, और समय लेने का अनुरोध किया। मान्यवर, समय तो आपकी कृपा पर निर्भर है कि कौन सी तिथि निश्चित करेंगें, उनकी उपस्थिति भी होनी चाहिए यह भी सुनिश्चित करेगी और साथ ही साथ यहां पर मै जो नहीं कहना चाहता था आपकी पीड़ा को देखने के बाद वह कहना पड़ रहा है, जब पूरा का पूरा सदन इस मुद्दे पर एक मत है तो एक बड़ी राजनीतिक पार्टी को इस सदन की राय से अपने को विरत रखना यह बात कहीं समझ मे नही आ रही और कहीं इस घटना से यह प्रतीत होता है कि स्टिंग आपरेशन की रिपोर्ट आने के बाद एक राजनीतिक दल उससे अपनी असहमति जताते हुए हर गतिविधियों से बाहर रखता है तो यह क्या संदेश देना चाहते हैं कि स्टिंग आपरेशन भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर किया गया था (मेजों की थपथपाहट) मान्यवर, अगर स्टिंग आपरेशन इनके इशारों पर नहीं किया गया था तो स्टिंग आपरेशन करने वाले जो जांच समिति के

माध्यम से गलत पाये गये हैं, झूठे पाये गये हैं, दोषी पाये गये है, विभिन्न धाराओं मे अपराधी साबित हुए हैं, ऐसे लोगों को बचाने का काम भारतीय जनता पार्टी क्यों कर रही है? मान्यवर, यह भी बहस और चर्चा का विषय बनाती है चूंकि आज ऐसे मुद्दे जिस पर पूरा सदन एक मत होता है, सत्ता और विपक्ष की जो सीमा होती है उसको तोड़कर जब किसी बात पर आम राय आती है, मुद्दे पर बात होती है तो ऐसे मुद्दे पर एक बड़े राजनीतिक पार्टी को उससे अपने को अलग रखना कहीं न कहीं शक की सुई इनकी ओर ले जाने का काम करती है। मन्यवर, हम समझते हैं ऐसे मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी का जो कृत्य है वह निन्दनीय है और साथ ही साथ आज ऐसे मौके पर जो साम्प्रदायिक शक्ति होने का आरोप लगाया जाता है, साम्प्रदायिक दंगे भड़काने के आरोप लगाये जाते हैं। साम्प्रदायिकता का जहर घोलने का आरोप लगाया जाता है वह सारे के सारे आरोप भारतीय जनता पार्टी के कृत्य से साबित हो रहे हैं। इसलिए मैं आपसे, आज जब सदन किसी एक बिन्दु पर आम राय और आम सहमत है तो भारतीय जनता पार्टी के इस कृत्य की मैं घोर निन्दा भी करता हूं और साथ ही साथ इस पर प्रभावी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए जो भी स्टिंग आपरेशन के दोषी हैं वह किसी भी हालत में बचने नहीं चाहिए उनको सजा जरूर देनी चाहिए यह माननीय पीठ को तय करना है। (शोर)

श्री अध्यक्ष–

उन्हें अपना पक्ष रखने दीजिए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, नेता विरोधी दल ने जो आरोप सदन में लगाये हैं हम उसका पूरी तरीके से खण्डन करते हैं। (शोर)

(श्री सुदेश शर्मा और भारतीय जनता पार्टी के अनेक सदस्य सदन के वेल में आ गये जिससे सदन में घोर व्यवधान पैदा हो गया।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री सुदेश शर्मा (सदन के वेल से)–

मान्यवर, जो भी आरोप आजम खां साहब पर लगाये गये हैं, उस पर मैं बोलना चाहता हूं, इस्तीफा आजम साहब को नहीं इनको देना चाहिए।

(सदन के वेल में आये हुए भारतीय जनता पार्टी के सदस्य ''सपा–बसपा–कांग्रेस आई, चोर–चोर मौसेरे भाई'' तथा ''मक्खनबाजी नहीं चलेगी, चापलूसी नहीं चलेगी'' के नारे लगाते रहे जिससे सदन में घोर व्यवधान बना रहा।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, नेता विरोधी दल के इस वक्तव्य की हम घोर निन्दा करते हैं जो भी आरोप उन्होंने लगाये हैं हम पूरी तरह से उसका खण्डन करते हैं।

श्री अध्यक्ष–

उन्होंने आरोप लगाये आपने खण्डन कर दिया बात खत्म हो गयी, अब चलिये, नारा लगाने से कुछ नहीं होगा।

(ब0स0पा0 के कुछ सदस्य अपनी–अपनी सीटो से उठकर आगे आ गये और ख ग ग ग , के नारे लगाने लगे।)

श्री अध्यक्ष–

चलिये, आप लोग अपनी–अपनी सीटों पर जायें। आप लोग अपनी–अपनी सीटों पर चलिये। यह जो प्रतिवेदन है यह उनको दिला दिया गया था, मैं अपना फैसला सुनाता हूं।

न्यायहित में यह उपयुक्त प्रतीत होता है कि इनको अनुरोध के अनुसार समय प्रदान कर दिया जाए। सभी दोषी पदाधिकारियों को इस आशय के निर्देश दिये जाएं कि वह दिनांक 4 मार्च, 2016 को अपराह्न 12.30 बजे सदन में उपस्थित होंगे। समिति की जांच के प्रतिवेदन की प्रतियां पुनः प्राप्त करा दी जाएं। यह अपेक्षा की जाती है कि सदन के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(सदस्यों द्वारा नारा लगाते रहने से सदन में व्यवधान बना रहा)

मैं 15 मिनट के लिए सदन को स्थगित करता हूं।

(घोर व्यवधान के कारण श्री अध्यक्ष ने 12 बजकर 43 मिनट पर सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिये स्थगित कर दी।)

(12 बजकर 58 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 15 मिनट के लिये और बढ़ा दिया।)

(1 बजकर 13 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

(सदन की बैठक पुनः प्रारम्भ होने पर)

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्य सदन के वेल में मौजूद थे)

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, जिस समय माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बोल रहे थे, हमने पूरी शान्ति से उनको सुना। जिस समय नेता विरोधी दल बोले, हमने उनकी बात को भी सुना। अब हमारी बात भी पूरी शान्ति से सुनी जानी चाहिये। आपने हमको बोलने को कहा तो सदन अव्यवस्थित हो गया।

श्री अध्यक्ष–

मैंने तो कहा कि सब लोग शान्त रहिये। हमारी तरफ से तो कोई कमी नहीं रही, मैंने तो स्वयं आपको बोलने का मौका दिया।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्य सदन के वेल से नारा लगाने लगे 'सपा–बसपा, कांग्रेस आई–चोर–चोर मौसेरे भाई')

श्री अध्यक्ष–

आपने अपनी बात कह ली अब आप अपनी सीटों पर जायें। उन्होंने आरोप लगाया, आपने खण्डन कर दिया। अब बात खत्म हो गयी, अब चलिये। यह नारा लगाने से कुछ नहीं होगा।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्य सदन के वेल से नारा लगाते रहे 'सपा–बसपा, कांग्रेस आई– चोर–चोर मौसेरे भाई')।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग अपनी–अपनी सीटों पर जायें ।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्य अपने स्थानों पर चले गये)

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं चार बातें सीधे–सीधे कहना चाहता हूं। नेता विरोधी दल ने एक आरोप लगाया हम उसका पूरी तरह खण्डन करते हैं और उनके वक्तव्य की हम घोर निन्दा भी करते हैं। मान्यवर, यह भारतीय जनता पार्टी न होती और भारतीय जनता पार्टी के श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी न होते तो बहुजन समाज पार्टी भी न होती। यह अहसानफरामोशी है कि तीन बार जिसके माध्यम से इन्होंने सरकार बनाई उसी को किसी न किसी तरह अनर्गल तरीके से लांछित करना और वह भी केवल वोटों की खातिर लांछित करना, ऐसे आपके वक्तव्य की हम निन्दा करते हैं। मान्यवर, दूसरी बात, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी चले गये मा0 मुख्य मंत्री जी ने उनको मंत्री बनाया है सदन ने नहीं बनाया है। आज सदन के सामने जिस प्रकार से अपना प्रस्तुतीकरण किया गया, मान्यवर, हमने तो सीधे–सीधे यह बात कही थी कि इस स्टिंग ऑपरेशन की जो स्थिति बनी, उसकी जो कमेटी बनी, हम उसकी प्रक्रिया से, उसके गठन से, सुनवाई से, कार्यवाही से एवं संस्तुतियों से अपने आपको अलग कर चुके हैं, उस पर असहमति व्यक्त कर चुके हैं। क्योंकि इस स्टिंग ऑपरेशन कमेटी के गठन की जो प्रक्रिया हुई हम उससे सहमत नहीं थे। मान्यवर, अभी तक इस सदन की प्रक्रिया यही रही कि मा0 अध्यक्ष सभी दलों के नेताओं से नाम मांगते हैं और दलीय नेताओं से नाम मांगने के आधार पर ही वह समिति का गठन करते हैं। मान्यवर, यह समिति जिन उद्देश्यों से बनी, वह केवल इसलिए बनी थी कि केवल एक व्यक्ति विशेष को निर्दोष साबित किया जाए।

श्री अध्यक्ष–

आपका कहना सही नहीं है, समिति जो बनी थी उसमें आपसे नाम मांगा गया था और आपके मनीष असीजा जी उसमें थे और आपने उन्हें वापस कराया, मैंने नाम मांगा था कि आप किसी का नाम दीजिए आपने नाम नहीं दिया तो इसमें मेरा क्या दोष है। आप आरोप गलत लगा रहे हैं, हर समय आपको अवसर दिया गया था।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मा0 अध्यक्ष जी, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, पहले मेरी पूरी बात आ जाए।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्य सदन के वेल में आकर नारेबाजी करने लगे)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मैं इस बात को मानता हूं, मैंने नाम मांगा इन्होंने नहीं दिया, जब अपने से मैंने नॉमिनेट कर दिया तो उनको वापस बुला लिया, यह कहना कि हमें नहीं पूछा गया यह गलत है, यह आरोप निराधार है, मैं इसको निराधार बताता हूं। चलिये, छोड़िये आप बैठिये, नहीं करना है तो छोड़ो। पहले आप अपने सदस्यों को बुला लीजिए तब बोलियेगा और अपनी बात को जल्दी खत्म कीजिएगा।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्य सदन के वेल से अपने आसन पर चले गये)

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, मैं दो बातें और कहना चाहता हूं कि मुजफ्फरनगर में जो कुछ भी हुआ वह प्रशासनिक फेल्योर था। मान्यवर, दोषी लोगों को छोड़ना और रात में डी0एम0, एस0पी0 का ट्रांसफर करना, यह प्रशासनिक फेल्योर था। भारतीय जनता पार्टी का या उसके किसी कार्यकर्ता का इससे दूर–दूर तक कोई सम्बन्ध नहीं था। मान्यवर, हमारे दो सदस्यों को रासुका में निरुद्ध किया गया और आप हाईकोर्ट के जजमेंट को देख लें उन लोगों को कहीं दोषी नहीं पाया गया लेकिन उन लोगों को 60 दिनों तक रासुका में निरुद्ध किया गया। मान्यवर, किसी प्रकार का कोई दोष नहीं था और यह कह देना और किसी पार्टी पर लांछन लगाने की जितनी निन्दा की जाए, हम उसकी निन्दा करते हैं। मान्यवर, हम एक अपील और करना चाहते हैं, यह सपा और बसपा की केवल मुस्लिम वोटों की लड़ाई है।

(कई सदस्यों के जोर–जोर से बोलने पर व्यवधान)

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

इसमें भारतीय जनता पार्टी का कहीं से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, आपने अपनी बात कह ली, अब हम आगे बढ़ते हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, जो इस्तीफा सदन के सामने दिया गया वह एक प्रकार का नाटक है, इस सदन ने किसी को मंत्री नहीं बनाया, इस सदन को यह अधिकार नहीं है कि वह किसी को मंत्री बनाये, यह अधिकार मुख्य मंत्री जी का है, अगर इस्तीफा देना है तो मा0 मुख्य मंत्री जी के सामने दें।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, आप बैठिये, अब आपकी बात आ चुकी है, अब ज्यादा न कहिये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, स्टिंग ऑपरेशन की रिपोर्ट आ गयी लेकिन हमारे सदस्य सलिल विश्नोई हैं, उनके मामले को 11 साल हो गये विशेषाधिकार समिति में गये लेकिन रिपोर्ट नहीं आयी।

श्री अध्यक्ष–

आज वह है, जो आपने दिया है उसे मैंने लिया है।

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा भी है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, एक व्यवस्था का प्रश्न है। जब कोई विषय आपके आदेश से यहां पर प्रस्तुत किया जाता है और सदन की सहमति से और आपके निर्देश से अंतिम कोई निर्णय लिया जाता है तो उस निर्णय को यह कहना कि किसी व्यक्ति को बचाने की नीयत से स्टिंग ऑपरेशन पर जांच कमेटी बिठायी गयी थी, यह न केवल गलत है बल्कि पूरे सदन की अवमानना है और पीठ की भी अवमानना है। (ब0स0पा0 के सदस्यों की तरफ से शेम, शेम की आवाजें आयीं) मान्यवर, पूरे सदन के साथ–साथ पीठ को भी कटघरे में खड़ा करने का इन्होंने दुःसाहस किया है। माननीय अध्यक्ष जी, यहां पर पूरे स्टिंग ऑपरेशन में शुरू से लेकर आज तक चर्चा के दौरान हिन्दू और मुस्लिम को आपस में बांटने का शब्द कभी किसी पार्टी, दल या सदस्य के द्वारा प्रयोग नहीं किया गया था। पहली बार मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण के लिए इस पर बहस हो रही है, ये आरोप लगाना इनकी फिरकापरस्ती वाली मानसिकता को जाहिर करती है। जिस तरीके से साम्प्रदायिक सौहार्द का कत्लेआम कर, हिन्दू–मुसलमानों को दंगे की भेंट चढ़ाकर, हिन्दू–मुसलमानों की लाश और खून–खराबे पर सत्ता हथियाना चाहते हैं। एक बार इनके मंसूबे कामयाब हो गये, एक बार इनके मंसूबे भले कामयाब हो गये हों लेकिन उत्तर प्रदेश में इनकी दाल नहीं गलने वाली है और इसीलिए खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे। जब देख रहे हैं कि आज खटिया खड़ी बिस्तरा गोल होता नजर आ रहा है, दिल्ली और बिहार में सूपड़ा साफ हो गया, अब उत्तर प्रदेश में भी सूपड़ा साफ होने के लक्षण दिखायी पड़ रहे हैं तो ऐसी खिसियाहट में पीठ पर भी आरोप लगा रहे हैं, सदन को भी लांछित करने का काम कर रहे हैं और अपनी बिगड़ी मानसिकता का भी परिचय देते हुए मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण की बात कर रहे हैं। हम समझते हैं कि ऐसी आपत्तिजनक जो इन्होंने यहां पर बात रखी है, अपनी बात के माध्यम से जो पीठ को इन्होंने लांछित किया है इसके लिए सार्वजनिक रूप से खन्ना जी को खेद व्यक्त करना चाहिए। जिस तरीके से इन्होंने पीठ को कटघरे में खड़ा कर दिया कि एक व्यक्ति विशेष को बचाने की नीयत से पीठ ने स्टिंग ऑपरेशन समिति के गठन करने का निर्देश दिया। यह मान्यवर, कितनी घटिया किस्म की बात है कि अपने बचाव के लिए पूरे पीठ को लांछित करने का काम कर रहे हैं, सदन को भी लांछित करने का काम कर रहे हैं इस पर इन्हें सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए।

'श्री प्रदीप माथुर–

माननीय अध्यक्ष जी, जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी ने लोकतांत्रिक परम्पराओं की धज्जियां उड़ायी हैं वह बड़ी शर्मनाक घटना है, आज स्थिति यह है कि स्टिंग ऑपरेशन के संदर्भ में जब पूरी विधान सभा एकमत थी, इन लोगों ने बहिष्कार किया, जिस तरह से पीठ के ऊपर उंगली उठायी तो ये अपने गिरेबान में झांकने वाली बात है कि ये देशभक्त हैं या छद्म देशभक्त ? स्थिति यह हो गयी है कि इन्होंने

---

* oDrk us Hkk"k.k dk iquohZ{k.k ugha fd;kA

छोटे–छोटे मामलों में पूरे प्रदेश में अराजकता फैला रखी है, ये वोटों का ध्रुवीकरण कराकर फिर से जो सत्ता में आने के सपने देख रहे हैं वे अब पूरे होने वाले नहीं हैं। जिस तरह से इन्होंने मा0 आजम खां साहब के मुद्दे को लेकर, ये खाली आजम खां साहब का मामला नहीं है, यह हर विधायक की अस्मिता का मामला है। जिस तरीके से स्टिंग ऑपरेशन किया जाता है, जिस तरीके से झूठा इंगित किया जाता है, तो मान्यवर, आपने स्टिंग ऑपरेशन जांच समिति बिठायी बिल्कुल सही बिठायी। फिर इसके बाद आपने सर्वदलीय बैठक में पूछकर आपने नाम रखे, जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नाम नहीं दिया तब आपने मनीष असीजा जी का नाम रखा, तो खन्ना जी ने उसे विद्ड्रा कर लिया। मुझे तो यह लगता है कि स्टिंग ऑपरेशन जो हुआ इन्होंने ही कराया है और इसीलिये बार–बार बहिष्कार कर रहे हैं। यह बहिष्कार इसीलिये कर रहे हैं कि टेलीविजन वाले कहीं कैमरा इनकी तरफ न घुमा दें, यह न कहें कि परदे के पीछे कौन है ? परदे के पीछे भाजपा है। यह दंगा पार्टी है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अब आप बैठिये।

श्री प्रदीप माथुर–

इन्होंने दंगे कराये यह सत्ता में आ गये। अब यह सत्ता में आने वाले नहीं हैं, जिस तरह से दिल्ली और बिहार में इनका सूपड़ा साफ हुआ उत्तर प्रदेश में भी इनका सूपड़ा साफ हो जायेगा। मान्यवर, यह लोग असाम्प्रदायिक लोग हैं, यह दंगा कराने वाले लोग हैं, यह माहौल बिगाड़ने वाले लोग हैं।

श्री अध्यक्ष–

इस तरह से आरोप–प्रत्यारोप करते रहेंगे तो कार्यवाही आगे कैसे चलेगी। आप बैठिये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, पीठ का पूरा सम्मान है। पीठ का पूरा सम्मान रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, जिस तरह से पीठ को कठघरे में खड़ा किया गया उसको कार्यवाही से निकाल दिया जाय। मान्यवर, पीठ का पूरा सम्मान है।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है।

श्री प्रदीप माथुर–

मान्यवर, यह खेद मांगें।

श्री अध्यक्ष–

बैठिये हो गया। अब नहीं अब हो गया।

ख01.28, नियम–301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 26–2–2016 को नियम–301 के अन्तर्गत कुल 45 सूचनायें प्राप्त हुईं। पहली सूचना श्री मुकुट बिहारी की जनपद बहराइच विधान सभा क्षेत्र कैसरगंज विकास खण्ड कैसरगंज के घनी आबादी वाले एक बड़े ग्राम तखता के आवामगन हेतु

मार्ग की व्यवस्था न होने के उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। श्री जगन प्रसाद गर्ग की जनपद आगरा के वाटर बाक्स चौराहा से शक्ति सुशील मंदिर होते हुए बल्केश्वर नाथ महादेव मन्दिर तक की सड़क के निर्माण...

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, मेरी एक व्यवस्था सुन लीजिये।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

माननीय अध्यक्ष जी, आज के बाद दिनांक 4,5,6 मार्च को सदन का अधिवेशन होगा और दिनांक 5 व 6 में कोई सूचनाएं नहीं ली जायेंगी और 8 मार्च अंतिम दिन होगा तो आज के बाद एक हफ्ते के लिये आप उठ भी रहे हैं 4 तारीख तक के लिये उठ रहे हैं तो मान्यवर, आज जितनी सूचनाएं हैं सब ले लीजिये मान्यवर, बड़ी कृपा होगी।

श्री सतीश महाना–

अध्यक्ष जी, हमारा यह निवेदन है कि आपने कार्य–मंत्रणा में यह तय किया आगे के जो विधान सभा की कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिशें हैं, उसमें आपने तय किया कि 4, 5, 6 व 8 को 301 की सूचना न ली जायं तो मान्यवर, जब आगे आपने चार दिन 301 की सूचना नहीं लेनी है तो 301 की सूचना के निमित्त यह आखिरी दिन है तो सब सूचनाएं ले लें।

श्री अध्यक्ष–

तो सब ले लिया जाय यही ना। ठीक है, सब ले लिया जाय।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, नियम–301 की सभी सूचनाएं ले लें।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है चलिये।

(सभी स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं)

जनपद कानपुर महाराजपुर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत श्रीकान्त साहू के घर से मछरीया रोड मजार तक एवं रामचन्द्र अवस्थी पेट्रोल लाइन यशोदा नगर से कर्मपुर गांव सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सतीस महाना–

ख्महोदय,

कानपुर महाराजपुर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत एम–257 यशोदा नगर श्री कान्त साहू के घर से मछरीया रोड मजार तक तथा एन–122 राम चन्द्र अवस्थी पेट्रोल लाइन यशोदा नगर से कर्मपुर गांव सम्पर्क का निर्माण कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है। मार्ग के क्षतिग्रस्त होने के कारण आवागमन प्रभावित है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर उपरोक्त मार्गों का निर्माण कराये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।,

जनपद बहराइच विधान सभा क्षेत्र कैसरगंज विकास खण्ड कैसरगंज के घनी आबादी वाले एक बड़े ग्राम तखला में आवागमन हेतु मार्ग की व्यवस्था न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

---

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

श्री मुकुट बिहारी वर्मा–

ख्महोदय,

विधान सभा क्षेत्र कैसरगंज जनपद बहराइच के विकास खण्ड कैसरगंज अन्तर्गत एक बहुत बड़ी आबादी का घनी बस्ती का ग्राम तखता है जिसके निवासीगण मार्ग के अभाव में आवागमन की सुविधा से वंचित है। कैसरगंज से गोड़हिया जाने वाले पक्के रोड से तखता ग्राम तक जाने वाली नहर की पटरी जो सिंचाई विभाग की है इस पर खड़ंजा या पक्का मार्ग बना दिया जाय जो नहर की भी सुरक्षा हो जायेगा और गांव वालों को आवागमन की सुविधा प्राप्त हो जायेगी। काफी समय इस नहर की पटरी के पक्के निर्माण की मांग की जा रही है परन्तु अभी कोई कार्रवाई न होने से जनता में निराशा व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उक्त नहर की पटरी को खड़ंजा/डामरीकृत किये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।,

जनपद फिरोजाबाद में एफ0आई0आर0 की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मनीष असीजा–

ख्महोदय,

नगर फिरोजाबाद में कांच की चूड़ी, ग्लास वेयर, किचन वेयर, झाड़ फानूस, साइंटिफिक उत्पाद, कांच के जार बोतलें, कांच के खिलौने, लालटेन की चिमनी, बल्ब सेल आदि अनेकों प्रकार के उत्पादों का निर्माण होता है। फिरोजाबाद के उत्पाद देश भर की आपूर्ति के साथ–साथ बड़े पैमाने पर विदेशों में भी निर्यात किये जा रहे हैं।

महोदय, लगभग 100 वर्षों से भी पुराना कांच का उद्योग नगर फिरोजाबाद की आर्थिक रीड़ के साथ–साथ एक सांस्कृतिक विरासत भी है और इस सांस्कृतिक विरासत की आत्मा है, पूरे फिरोजाबाद के लाखों की संख्या के गरीब, मेहनतकश, मजदूर।

फिरोजाबाद मुख्यालय में कांच उद्योग से सम्बन्धित प्रशिक्षण की दृष्टि से राजकीय आई0टी0आई0 की स्थापना किये जाने की मांग मेरे द्वारा कई वर्षों से की जा रही है। आई0टी0आई0 से प्रशिक्षण प्राप्त कर नगर के हजारों–लाखों बेरोजगार युवक तकनीकी रूप से दक्ष होकर रोजगार प्राप्ति के अवसर प्राप्त कर सकेंगे। जिससे उनके जीवन स्तर में भी सुधार आयेगा एवं कांच उद्योग को भी एक नई दिशा मिल सकेगी।

अतः लोक महत्व का अविलम्बनीय विषय है। अतः सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए फिरोजाबाद नगर मुख्यालय पर एक राजकीय आई0टी0आई0 की स्थापना किये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद सहारनपुर स्थित कम्पनी बाग का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजीव गुम्बर–

ख्महोदय,

---

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

सहारनपुर नगर के बीच में कम्पनी बाग बना हुआ है। उपरोक्त बाग में प्रतिदिन हजारों लोग अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए घूमने आते हैं जिसमें बहुत बड़ी संख्या में स्त्री, बुजुर्ग व बच्चे भी शामिल रहते हैं। उपरोक्त बाग में सुविधायें न के बराबर हैं, वहां पर लाइट की समुचित व्यवस्था नहीं है, सड़के भी क्षतिग्रस्त हैं और बच्चों के खेलने हेतु झूले भी पर्याप्त मात्रा में नहीं हैं। कम्पनी बाग के अतिरिक्त सहारनपुर में कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जिसमें जाकर लोग उसका लाभ उठा सकें। शौचालय भी काफी दूर है जिस कारण बुजुर्गो व महिलाओं को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। मण्डलायुक्त सहारनपुर द्वारा भी इस बाग के सौन्दर्यीकरण हेतु एक कमेटी बनाई गयी है जिसकी कोई भी बैठक अधिकारियों द्वारा नहीं बुलाई गयी है। कम्पनी बाग के पास पर्याप्त मात्रा में सौन्दर्यीकरण व सुविधाओं हेतु धन है परन्तु निर्माण कार्य व सौन्दर्यीकरण न होने से जनमानस में निराशा एवं आक्रोश है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कम्पनी बाग का सौन्दर्यीकरण कराये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।,

जनपद बुलन्दशहर में मांट ब्रान्च खण्ड गंगा नहर के उठरावली रजवाहे पर गांव रमानी के पास क्षतिग्रस्त पुल के पुनः निर्माण न होने कारण उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी–

ख्महोदय,

मेरे विधान सभा के अन्तर्गत मांट ब्रान्च खण्ड गंगा नहर से निकलने वाले उठरावली रजवाहे पर गांव रमानी के पास पड़ने वाला पुल वर्षो से क्षतिग्रस्त है। इस पुल से होकर गांव बैलाना, बुर्ज, रमानी, चौकी, ख्वाजपुर आदि अनेक गांवों के लोग गुजरते है। गांव वालों में अनेक बार चन्दा करके पुल की मरम्मत कराई है। लेकिन यह पूरी तरह ठीक होने स्थिति में नहीं है। अगर पुल का पुर्न निर्माण नहीं कराया गया तो कभी गम्भीर दुर्घटना हो सकती है जिसमें मानव हानि भी हो सकती है। जनहित में उक्त पुल का पुनः निर्माण अति आवश्यक है।

अतः नियम–301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई की मांग करती हूं।,

जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र खजनी एवं धनघटा क्षेत्रान्तर्गत कुवानों नदी पर बनकटा घाट पर आवागमन हेतु पुल न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सन्त प्रसाद–

ख्महोदय,

जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र खजनी तथा जनपद संतकबीर नगर की विधान सभा क्षेत्र धनघटा के मध्य कुवानों नदी बहती है। संतकबीर नगर जिला के धनघटा विधान सभा क्षेत्र के लोगो को व्यवसायिक, शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य की दृष्टि से लोगों का आना–जाना जनपद गोरखपुर मुख्यालय पर होता रहता है। संतकबीर नगर जनपद के दक्षिण भाग में कोई अच्छा स्वास्थ्य केन्द्र न होने के कारण अक्सर लोग गोरखपुर मेडिकल कालेज का सहयोग लेते हैं परन्तु दुर्भाग्य है कि आजादी के इतने

दिन बाद भी बनकटा घाट कुवानों नदी पर पक्का पुल नहीं बन सका। जिससे दोनों विधान सभा के लोगों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इस घाट पर पुल बन जाने से लाखों लोगों को आवागमन का मार्ग सुगम हो जायेगा।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कुवानों नदी पर पक्का पुल बनाये जाने हेतु वक्तव्य की मांग करता हूं।,

जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रूदौली के विद्युत वितरण खण्ड की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम चन्द्र यादव–

ख्महोदय,

जनपद फैजाबाद विधान सभा क्षेत्र रूदौली अन्तर्गत जनहित में विद्युत वितरण खण्ड की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में क्षेत्रवासियों द्वारा एक दसक से मांग की जा रही है। इस क्षेत्र में एक नगर पालिका दो विकास खण्ड लगभग 5 लाख की आबादी है। कामर्शियल उपभोक्ताओं की संख्या लगभग 5 हजार है निजी नलकूप चलाने वाले किसानों की एवं सामान्य विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या लगभग 15 हजार है। वर्तमान समय में 424 बस्तियों का ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य चल रहा है जिससे उपभोक्ताओं की संख्या बढ़कर 30 हजार तक पहुंचने की सम्भावना है। क्षेत्र के किसानों व अन्य उपभोक्ताओं को नये कनेक्शन लेने के लिए व विद्युत सम्बन्धित समस्याओं के निदान के लिए जिला मुख्यालय फैजाबाद 60 कि0मी0 की दूरी तय करना पड़ता है। जिसके कारण आम उपभोक्ताओं का समय बर्बाद होता है वहीं दूसरी तरफ किराये में इस माह लाखों रुपये खर्च करना पड़ता है। इस समस्या के समाधान के लिए विद्युत वितरण खण्ड रूदौली की स्थापना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए रूदौली में विद्युत वितरण खण्ड की स्थापना कराये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।,

जनपद मेरठ दक्षिण विधान सभा क्षेत्र की ग्राम फफून्डा से पीपली खेड़ा तक जाने वाले कच्चे मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रविन्द्र भड़ाना–

ख्महोदय,

मेरठ दक्षिण विधान सभा क्षेत्र की ग्राम फफून्डा से 69 नं0 सरकारी ट्यूबवेल से होकर पीपली खेड़ा जाने वाला मार्ग कच्चा है। जिसके कारण मार्ग अत्यधिक खराब रहता है और आवागमन में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। कच्चा मार्ग होने के कारण जगह–जगह गड्ढ़े होने से आये दिन दुर्घटनायें भी होती रहती हैं। जनहित में उक्त मार्ग का डामरीकरण कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है। इस सम्बन्ध में जिला स्तर पर प्रयास भी किया गया परन्तु कोई कार्रवाई न होने से जनमानस में हताशा एवं निराशा व्याप्त है।

---

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उपरोक्त मार्ग का डामरीकरण कराये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।,

जनपद वाराणसी विधान सभा क्षेत्र रनिया महाल, तेलियाबाग खुले नाले को ढ़कने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रवीन्द्र जायसवाल–

ख्महोदय,

वाराणसी उत्तरी विधान सभा क्षेत्र के रनिया महाल, तेलियाबाग में खुला नाला बहता है। इस नाले के दोनों तरफ घनी आबादी रहती है। इस नाले को ढ़कने की मांग बहुत दिनों से हो रही है। जिस पर नगर निगम ने अवस्थापना निधि से नाले को ढ़कने का टेंडर भी किया लेकिन ठेकेदार व नगर निगम के कर्मचारी उस नाले को नहीं ढ़के और उसका भुगतान भी ले लिया। जनहित में मेरी मांग है के खुले नाले को तत्काल ढ़कवाया जाय और बिना कार्य किये भुगतान लेने वाले दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई किया जाय।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए अविलम्ब कार्रवाई की मांग करता हूं।,

जनपद आगरा के वाटर बक्स चौराहा से शक्ति सुशील मन्दिर होते हुए बल्केश्वर नाथ महादेव मन्दिर तक की सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जगन प्रसाद गर्ग–

ख्महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आगरा के वाटर बक्स चौराहा से शक्ति सुशील मन्दिर होते हुये बल्केश्वर नाथ महादेव मन्दिर तक की सड़क के निर्माण की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

वाटर बक्स चौराहा से शक्ति सुशील मन्दिर होते हुये बल्केश्वर नाथ महादेव मन्दिर तक की सड़क काफी गड्ढ़ा युक्त व जर्जर हो गयी है इसका निर्माण विगत 04 वर्षों से नहीं हुआ है। यहां से हजारों की संख्या में वाहन निकलते हैं तथा सभी वाहनों का निकलना मुश्किल हो गया है। इस कारण क्षेत्र की जनता में भारी रोष है। जनहित में इस गड्ढ़ा युक्त व जर्जर सड़क का निर्माण कराने की अति आवश्यकता है।

अतः मैं लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार से उक्त महत्वपूर्ण सड़क के निर्माण कराने की मांग करता हूं।,

जनपद गाजीपुर के अन्तर्गत एन0एच0–29 पर शहीद श्री जयप्रकाश फिलिंग स्टेशन के सामने श्री अली हुसैन राईनी के घर से श्रीमती सुमन देवी के घर तक के मुख्य मार्ग का नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम कुमार रावत–

रू महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान जनपद गाजीपुर के अन्तर्गत छण्भ्.29 पर शहीद श्री जयप्रकाश फिलिंग स्टेशन/पेट्रोल पम्प के सामने श्री

---

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

अली हुसैन राईनी के घर से श्रीमती सुमन देवी के घर तक के मुख्य मार्ग तक क्षतिग्रस्त जर्जर मार्ग की ओर ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उक्त मार्ग शहरी क्षेत्र का एक प्रमुख मार्ग है, जिसपर प्रतिदिन स्थानीय निवासियों का आवागमन रहता है जो अत्यन्त ही जर्जर एवं क्षतिग्रस्त है, जिसमें बड़े–बड़े गढ्ढ़े बने हुए हैं, जिसमें आये दिन दुर्घटनायें होती रहती हैं। स्थानीय निवासियों को आवागमन में अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

अतः सदन के माध्यम से उक्त मार्ग की मरम्मत/नवनिर्माण कराये जाने हेतु शासन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं।,

जनपद हापुड़ में सभी सरकारी भवनों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गजराज सिंह–

ख्महोदय, जनहित के प्रकरण पर अवगत कराना है कि जपद हापुड़ गाजियाबाद से विभाजित होकर 04 वर्ष पूर्व नया जिला सृजित हुआ था। हापुड़ मुख्यालय पर लगभग सभी सरकारी कार्यालय किराये पर और सरकारी भवनों में चल रहे हैं जो अपर्याप्त है। प्रशासन को इन भवनों में कार्य चलाना मुश्किल हो रहा है। जिला प्रशासन ने कलेक्ट्रेट, न्यायालय तथा अन्य सभी विभागों के भवनों के निर्माण के लिए भूमि आवंटित कराकर प्रस्ताव सरकार को भेज दिए हैं जो काफी समय से शासन स्तर पर विचाराधीन है। सरकारी भवन न होने से कार्य प्रभावित हो रहे हैं। अतः इस लोक महत्व एवं जनहित के कार्यों के लिए शासन से भवन निर्माण के लिए अविलम्बनीय धन आवंटित किया जाना अति आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए नवसृजित जनपद–हापुड़ के सभी सरकारी भवनों के निर्माण के लिए सरकार से धन आवंटित कराने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।,

जनपद रामपुर के विलासपुर मिलक खानम स्वार मार्ग का चौड़ीकरण एवं सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संजय कपूर–

ख्महोदय,

मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान जनपद रामपुर का विलासपुर मिलक खानम स्वार मार्ग जो कि चौड़ीकरण व सुन्दरीकरण के पूर्ण न होने से उत्पन्न स्थिति को ओर आकर्षित कराना चाहता हूं। यह मार्ग दो तहसीलों को जोड़ने वाला एक प्रमुख मार्ग है। यह मार्ग अत्यन्त जीर्ण–शीर्ण अवस्था में है इसकी चौड़ीकरण सुन्दरीकरण की स्वीकृति शासन द्वारा कई वर्ष पूर्व दी जा चुकी है। इस मार्ग पर लगभग आधा कार्य पूर्ण हो चुका है मगर जो भाग अपूर्ण है उसमें कि0मी0 2 से लेकर 07 तक की स्थिति अत्यन्त दयनीय है जिस पर निरन्तर दुर्घटनायें हो रही हैं जिससे जान व माल नुकसान हो रहा है तथा शासन द्वारा 27 मई, 2015 को रु0 05 करोड़ आवंटित भी किया

---

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

है, मगर जिले के लोक निर्माण अधिकारियों की गैर जिम्मेदारी की वजह से इस पर टेण्डर नहीं हो पाने के कारण जनता को बहुत बड़ी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है, जिससे जनता में भारी रोष व नाराजगी व्याप्त है। जनहित में उपरोक्त मार्ग का अविलम्ब चौड़ीकरण व सुन्दरीकरण किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। यदि यह कार्य जिले के लोक निर्माण के अधिकारियों की लापरवाही की वजह से नहीं होता है तो कभी भी कोई अप्रिय घटना घटित हो सकती है जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी विभाग की होगी।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त प्रकरण पर शीघ्र कार्रवाई की मांग करता हूं।,

अग्नि पीड़ितों को अहैतुक सहायता दिलवाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अन्सार अहमद–

ख्महोदय,

मैं आपका ध्यान प्रदेश के अग्नि पीड़ितों को दी जाने वाली अहैतुक सहायता आपदा राहत विषयक प्रकरण जो राजधानी लखनऊ में दिनांक 13 अप्रैल, 2013 को आकांक्षा गारमेण्ट दुकान नम्बर यू0जी0एफ0–7, आरोही प्लाजा, पत्रकारपुरम्, गोमतीनगर, लखनऊ में रात्रि में अचानक बिजली की शार्ट सर्किट से आग लग जाने के कारण दुकान में रखे कपड़ों, फर्नीचर, नकदी रुपये आदि जिसकी कीमत लगभग रुपये दस लाख थी, जलकर खाक हो गयी, की तरफ ले जाना चाहता हूं।

मुख्य मंत्री आपदा राहत कोष से आर्थिक क्षतिपूर्ति दिये जाने हेतु प्रार्थना–पत्र मुख्य मंत्री कार्यालय अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को दिनांक 05 जून, 2015 को सम्पत्ति के नुकसान के विवरण सहित दिया गया था।

प्रार्थना–पत्र को पत्र संख्या 186/मु0मं0का0–5/2015, दिनांक 25 जून, 2015 द्वारा जिलाधिकारी, लखनऊ को अपनी आख्या/संस्तुति शासनादेश संख्या–अ–/1175/मु0मं0का0–4–5/ 2003, दिनांक 12 दिसम्बर, 2003 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराये जाने का निर्देश दिया गया था।

जिलाधिकारी, लखनऊ कार्यालय ने दिनांक 10–07–2015 को रजिस्टर्ड डाक द्वारा विवरण सहित आख्या मुख्य मंत्री कार्यालय अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन को भेजी जा चुकी है, परन्तु दुर्भाग्य का विषय है कि अग्निपीड़ित को अभी तक अहैतुक सहायता नहीं प्रदान की गयी है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के उक्त प्रश्न का सदन/सरकार के संज्ञान में लाकर तत्काल कार्रवाई एवं अहैतुक सहायता दिये जाने की मैं मांग करता हूं।,

पूर्वांचल के मिनी पी0जी0आई0 के नाम पर प्रसिद्ध ओपेक चिकित्सालय कैली में विशेषज्ञ डाक्टरों एवं टेक्नीशियनों की नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संजय प्रताप जायवाल–

---

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

ख्महोदय,

अवगत कराना है कि पूर्वांचल के मिनी पी0जी0आई0 के नाम से प्रसिद्ध ओपेक चिकित्सालय कैली का अस्तित्व संकट में है। कैली गांव में दो दशक पूर्व खाड़ी देशों के मदद से अत्याधुनिक अस्पताल के निर्माण की आधारशिला रखी गयी जिसमें लगभग 70 करोड़ रुपये की लागत से अस्पताल भवन वर्ष 1977 में बनकर तैयार हुई। अस्तित्व के संकट को देखते हुए सरकार ने अस्पताल को नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड आफ हेल्थ सर्विस नामक संस्था को सौंप दिया मगर आज भी अस्पताल की दशा जस की तस है। यहां आधा दर्जन ऐसे विभाग हैं जहां गम्भीर रोगों के इलाज की व्यवस्था की गयी थी लेकिन विशेषज्ञ डाक्टरों के अभाव में कक्ष में ताला लटक रहा है। दूर दराज से आने वाले मरीजों को गोरखपुर या लखनऊ के अस्पतालों में रेफर कर दिया जा रहा है। अस्पताल की स्थिति के बारे में पत्राचार करने के बावजूद कोई नतीजा नहीं निकला। करोड़ों रुपये की मशीने ठप्प पड़ी हैं। शुरूआत में अस्पताल के लिए भारी भरकम चिकित्सकों व पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती की गयी। इसके बाद यहां आसपास जिलों के अलावा पड़ोसी देश नेपाल व बिहार प्रदेश के मरीजों की लाइन लग गयी। संसाधनों का लाभ भी मरीजों को मिलने लगा। लगभग 06 वर्ष अस्पताल बड़े ही अच्छे तरीके से चला मगर शासन की स्थानान्तरण की नीति के चलते यहां पर तैनात अधिकांश चिकित्सकों का स्थानान्तरण हो गया। इसके बाद ओपेक चिकित्सालय की स्थिति दिन व दिन खराब होती चली गयी। पहले नेफ्रालोजी विभाग पर ताला लगा, इसके बाद हृदय रोग विभाग, डाक्टरों के स्थानान्तरण के कारण बन्द हो गया। ओपेक चिकित्सालय कैली में 03 वर्ष से पैथालोजिस्ट की नियुक्ति नहीं हुई हैं। ऐसे में विशेष जांच मसलन लीपिड प्रोफाइल, हिमोटालाजोजी, फुल बायोकमेस्ट्री व सिरोलाजी बन्द है, डायलेसिस यूनिट, टीएमटी यूनिट, ईसीजी यूनिट, इन्डोस्कोपी यूनिट, आइसीसीयू पर 12 वर्षों से ताला लटक रहा है। अस्पताल में अत्याधुनिक मशीनें तो मौजूद हैं लेकिन उसे संचालित करने वाले विशेषज्ञ नहीं है। ऐसे में सरकार से आग्रह है कि अस्पताल की स्थिति का संज्ञान में लेकर ओपेक चिकित्सालय कैली में विशेषज्ञ डाक्टरों व टेक्निीशियन की नियुक्ति किया जाना जनहित में अति आवश्यक है। प्रकरण लोक महत्व का है।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त प्रकरण पर शीघ्र कार्रवाई की मांग करता हूं।,

जनपद कुशीनगर के तमकुहीराज विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सेवरही ब्लाक में जवही दयाल चैन पट्टी के सामने बूढ़ी गण्डक नदी पर प्लाटून पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

ख्महोदय, लोक महत्व में अविलम्बनीय एवं तात्कालीन विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र तमकुहीराज के ब्लाक–सेवरही अन्तर्गत जवही दयाल चैनपट्टी के सामने बुढ़ी गण्डक नदी है। इस क्षेत्र की जनता जो कृषि पर आधारित है, के लगभग 50 गांवों के लोगों को कृषि कार्य हेतु

प्रतिदिन बुढ़ी गण्डक नदी पार करना पड़ता है, जिसके लिए नाव एकमात्र साधन है। यहां अक्सर दुर्घटना होती रहती है तथा जान–माल का खतरा बना रहता है। इसके समीप नेपाल सीमा है। यदि बुढ़ी गण्डक नदी पर प्लाटून पुल सरकार द्वारा बना दिया जाय तो नेपाल की सीमा कुशीनगर से जुड़ने से काफी सारे विकास की रास्ते भी खुलेंगे तथा बौद्ध भिक्षुओं को सुगम एवं अल्पदूरी का एक मार्ग मिल जाएगा। इसी प्रकार मेरे विधानसभा क्षेत्र तमकुहीराज में ही नवलपुर बिहर–राज्य तथा उत्तर प्रदेश के विकास खण्ड दुदही, बरवापट्टी के मध्य बहती है। नदी के दोनों धाराओं के बीच टापू पर लगभग 30 हजार एकड़ भूमि उत्तर प्रदेश के किसानों की है। इस क्षेत्र जनता जो कृषि पर आधारित है जिनको कृषि कार्य हेतु प्रतिदिन बुढ़ी गण्डक नदी पार करना पड़ता है तथा जिसके लिए नाव एक मात्र साधन है। नदी पर करने में अक्सर दुर्घटना होती रहती है तथा जान–माल का नुकान होता रहता है। यहां की जनता में उपरोक्त कठिनाइयों के कारण काफी रोष व्याप्त है। इसलिए जनपद–कुशीनगर के तमकुहीराज विधान सभा क्षेत्र में उपरोक्त दोनों स्थानों 1–जवही दयाल चैनपट्टी के सामने बुढ़ी गण्डक नदी पर प्लाटून पुल तथा 2–वि0ख0–दुदही के बरवापट्टी एवं बिहार राज्य के नवलपुर के बीच में बह रही बुढ़ी गण्डक नदी के बीच में प्लाटून पुल बनाया जाना जनहित में अति आवश्यक है। प्रकरण लोकमहत्व का है।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त प्रकरण पर शीघ्र कार्रवाई की मांग करता हूं।

जनपद अलीगढ़ में बरौली विधान सभा क्षेत्र के क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दलवीर सिंह–

ख्महोदय,

जनपद–अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र बरौली निम्नलिखित सड़कें अति क्षतिग्रस्त हैं। जनहित में निम्न मार्गों की मरम्मत अति आवश्यक है :––

1–तालानगरी से किड़ारा सम्पर्क मार्ग।

2–तालानगरी से किड़ारा सम्पर्क मार्ग।

3–तालानगरी से कोड़रा सम्पर्क मार्ग।

4–हरदुआगंज कासिमपुर मार्ग से भीमगढ़ी मार्ग।

5–हरदुआगंज कासिमपुर मार्ग से जारौठी सम्पर्क मार्ग।

6–हरदुआगंज रेलवे स्टेशन से ग्राम साथा मार्ग।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त मार्गों की मरम्मत कराये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद मथुरा में छाता विधान सभा क्षेत्र के क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री तेजपाल सिंह–

---

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

ख्महोदय, जनपद–मथुरा के विधान सभा क्षेत्र छाता निम्नलिखित सड़कें अति क्षतिग्रस्त है। जनहित में निम्न मार्गों की मरम्मत अति आवश्यक है :––

1–चौमुहा से तरौली मार्ग।

2–एन0एच0–2 छटीकरा से परखमगुजर–दलौता–काचरोठ बेहटा–शेरगढ़ तक।

3–अकबरपुर शेरगढ़ कि0मी0–9 (नौगांव आबादी भाग)।

4–खायरा से धरमपुरा मार्ग।

5–कोसी नन्दगांव मार्ग से धरमनगर मार्ग।

6–कोसी शाहपुर से नगला हसनपुर मार्ग।

7–शाहपुर से ऐच वाया सिरौली (हरियाणा सीमा तक)।

8–लालपुर से होटल (हरियाणा सीमा तक)।

9–उमराला से होडल (हरियाणा सीमा तक)।

10–छाता से बहरावली।

11–मुख्य सड़क कोसी बठैन कला–बठैन खुर्द–हुलवाना–कामर–लालपुर आदि से कोटवन एन0एच0–2 तक।

12–कोसी शाहपुर मार्ग से धानौता होते हुए रूपनगर उझानी आदि बसई तक।

13–गोबर्धन छाता मार्ग।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त मार्गों की मरम्मत कराये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद सीतापुर के लहरपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत नानजडे वक्फ की भूमि स्थानीय ग्राम समाज की भूमि में बड़े पैमाने पर राजस्व अभिलेखों में अनियमितता करने वाले लेखपाल/अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मो0 जासमीर अन्सारी–

ख्महोदय,

आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

जिला–सीतापुर की मेरी विधान सभा क्षेत्र कस्बा लहरपुर के अन्तर्गत नानजडे वक्फ की भूमि एवं स्थानीय ग्राम समाज की भूमि एवं कई तालाब स्थित हैं। उक्त भूमि पर मोहल्ला काजी टोला, मोहल्ला बेहटी, मोहल्ला अम्बरसराय, मोहल्ला लोखरीयापुर, मोहल्ला मगोलपुर आदि स्थित है। उक्त क्षेत्र का स्थानीय लेखपाल कमलेश तिवारी द्वारा लोगों से अवैध वसूली करके वक्फ भूमि ग्राम समाज की भूमि एवं तालाबों को पटवाकर अवैध तरीकों से कब्जा करवा कर बेड़े पैमाने पर रजिस्ट्री करायी जा रही है। लोगों द्वारा स्थानीय लेखपाल की मिली–भगत वक्फ की भूमि, स्थानीय ग्राम समाज की भूमि एवं तालाबों पर जबरन कब्जा कर आवास बनाये जा रहे हैं। जिससे क्षेत्रीय जनता को अत्यधिक परेशानी हो रही है। जबकि मा0 उच्चतम न्यायालय का आदेश है कि 1972 के राजस्व अभिलेखों में दर्ज तालाबों को उन्हें मूल रूप में विकसित किया जाए, परन्तु उक्त भ्रष्टाचारी लेखपाल द्वारा बड़े पैमाने पर राजस्व अभिलेखों में अनियमिततायें एवं बड़े पैमाने पर अवैध वसूली करते हुए वक्फ की भूमि, ग्राम समाज की भूमि एवं तालाबों पर गलत

---

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

तरीके से लोगों को आवंटित कर कब्जा कराया जा रहा है। क्षेत्रीय जनता द्वारा वक्फ की भूमि, स्थानीय ग्राम समाज की भूमि एवं तालाबों पर किये गये अवैध कब्जे को खाली कराते हुए दोषी लेखपाल/अधिकारियों के विरुद्ध कठोर दण्डात्मक कार्रवाई किये जाने हेतु स्थानीय उच्च अधिकारियों एवं शासन से अनुरोध किया गया है, परन्तु अभी तक उक्त ग्राम समाज की भूमि एवं तालाबों को उनके मूल स्वरूप में नहीं किया गया और न ही दोषी लेखपाल एवं अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गयी। जिससे क्षेत्रीय जनता में अत्यधिक आक्रोश व्याप्त है। अतः मैं सदन के माध्यम से भ्रष्टाचारी लेखपाल के विरुद्ध कार्रवाई किये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद सीतापुर के हरगांव विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विकास खण्ड लहरपुर के कतिपय सम्पर्क मार्गों की मरम्मत/रिनीवल कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रामहेत भारती–

ख्महोदय,

आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

निर्वाचन क्षेत्र 147, हरगांव के विकास खण्ड लहरपुर के अन्तर्गत लहरपुर तम्बौर रोड से अकैचनपुर टम्पा तथा विकास खण्ड–परसेण्डी के फर्रकपुर पुल से राम विलास पुरवा होते हुए ढोलई कला फत्तेपुर मातिनपुर सम्पर्क मार्ग अत्यन्त क्षतिग्रस्त हो गये हैं, रोड की ऊपर की पर्त उखड़कर खड्ढ़े हो गये हैं, जिस कारण क्षेत्रवासियों को रोडों पर चलना मुश्किल हो गया है। गन्ने का सीजन चल रहा है, गन्ना किसान अपनी गन्ने की ट्रालियों, डनलप बैलगाड़ियों को ले जाते वक्त हर समय जोखिम में रहता है। जिससे क्षेत्र के लोगों को काफी परेशानी व असुविधा होने के साथ–साथ आक्रोश भी है।

अतएव मैं सदन के माध्यम से सरकार से ब्लाक–लहरपुर के अन्तर्गत अकैचनपुर टम्पा तथा ब्लाक–परसेण्डी के अन्तर्गत फर्रकपुर पुल से रामविलासपुरवा, ढोलई कला होते हुए फत्तेपुर मातिनपुर सम्पर्क मार्गों की मरम्मत/रिनीवल कराये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद सहारनपुर विधान सभा सीट सिकन्दराराऊ के अन्तर्गत ग्राम नगला जलाल से टीकरी खुर्द कपसिया, ईशेपुर होते हुए बाजिदपुर तक जर्जर सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रामवीर उपाध्याय–

ख्महोदय,

कृपया आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि जिला–हाथरस के मेरे विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराराऊ के अन्तर्गत ग्राम नगला जलाल से टीकरी खुर्द, कपसिया, ईशोपुर होते हुए बाजिदपुर मार्ग तक (ल0 लगभग 11 कि0मी0) सड़क अत्यधिक जर्जर/पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त अवस्था में है। उक्त सड़क पर लगभग बीस ग्राम पंचायत पड़ती हैं। उक्त क्षतिग्रस्त सड़क से हजारों की संख्या में लोगों का आवागमन होता है। क्षतिग्रस्त सड़क

---

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

होने से आये दिन राहगीरों के साथ मार्ग दुर्घटनायें हो रही हैं। क्षेत्रीय जनता द्वारा क्षतिग्रस्त सड़क के निर्माण कराये जाने हेतु कई बार उच्च अधिकारियों एवं शासन से अनुरोध किया जा चुका है। मेरे द्वारा स्वयं भी कई बार सरकार से क्षतिग्रस्त सड़क के निर्माण हेतु अनुरोध किया गया, परन्तु अभी तक उक्त क्षतिग्रस्त सड़क के निर्माण हेतु कोई भी प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही है। जिसमें क्षेत्रीय जनता में अत्याधिक रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद गोरखपुर विधान सभा क्षेत्र चौरी–चौरा की मुख्य सड़क से ग्राम मीठाबेल होते हुए हरैइया तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जय प्रकाश निषाद–

ख्महोदय, आपके माध्यम से मैं इस सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

जिला गोरखपुर के मेरे विधान सभा क्षेत्र चौरी–चौरा के ब्लाक सरदार नगर तथा ब्लाक ब्रह्मपुर के अन्तर्गत चौरी–चौरा (गोरखपुर से देवरिया जाने वाली सड़क) मुख्य सड़क से ग्राम मीठाबेल होते हुए हरैइया तक प्रधान मंत्री योजना के तहत सड़क बनायी जानी थी। उक्त सड़क का पूर्ण निर्माण नहीं कराया गया, बीच में ही सड़क निर्माण कार्य को रोक दिया गया है। जितनी सड़क का निर्माण कार्य कराया गया है उसमें मानक के अनरूप निर्माण कार्य नहीं कराया गया है और स्थानीय अधिकारियों की सांठ–गांठ के कारण ठेकेदारों को भुगतान भी करा दिया गया है। सड़क का सही ढंग से एवं पूर्ण निर्माण नहीं किये जाने से क्षेत्रीय जनता को आवागमन में अत्यधिक परेशानियां हो रही हैं। क्षेत्रीय जनता के साथ आये दिन दुर्घटनायें हो रही है। क्षेत्रीय जनता द्वारा उक्त सड़क को मानक के अनुसार बनाये जाने एवं सड़क का पूर्ण निर्माण कराये जाने हेतु स्थानीय उच्च अधिकारियों एवं शासन से अनुरोध किया गया, परन्तु अभी तक उक्त सड़क का पूर्ण निर्माण नहीं कराया गया और दोषी लोगों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं किये जाने से क्षेत्रीय जनता में अत्यधिक रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतएव आपके माध्यम से सरकार से जनहित में **चौरी–चौरा (गोरखपुर से देवरिया जाने वाली सड़क) मुख्य सड़क से ग्राम मीठाबेल होते हुए हरैइया तक की सड़क का पूर्ण निर्माण कराये जाने** की मांग करता हूं तथा दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए।,

जनपद मिर्जापुर, विकास खण्ड–पहाड़ी के अन्तर्गत ग्राम पंचायत दांती, गौरा राजा (गौरा विशेन) को सम्पर्क मार्ग से जोड़ने हेतु सड़क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 रमेश चन्द्र बिन्द–

[महोदय, आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

जिला–मिर्जापुर के विकास खण्ड–पहाड़ी के अन्तर्गत ग्राम पंचायत दांती व ग्राम पंचायत गौरा राजा (गौरा विशेन) स्थित है, जोकि चारों तरफ से जंगल से घिरा हुआ है, उक्त ग्राम पंचायतों में जाने हेतु कोई भी सम्पर्क मार्ग नहीं बना हुआ है। उक्त ग्राम पंचायतों में जाने हेतु क्षेत्रीय ग्रामवासियों को जंगल के ऊबड़–खाबड़ रास्तों से आना–जाना पड़ता है। जिससे क्षेत्रीय जनता एवं ग्रामवासियों को आवागमन में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रीय जनता द्वारा कई बार स्थानीय उच्च अधिकारियों एवं शासन से उक्त ग्राम पंचायतों को सम्पर्क मार्ग से जोड़े जाने हेतु सड़क निर्माण करने हेतु अनुरोध किया गया है, परन्तु अभी तक सड़क निर्माण हेतु शासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। जिससे क्षेत्रीय जनता में अत्यधिक रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतएव आपके माध्यम से सरकार से जनहित में **मिर्जापुर के विकास खण्ड–पहाड़ी के अन्तर्गत ग्राम पंचायत दांती व ग्राम पंचायत गौरा राजा (गौरा विशेन) को सम्पर्क मार्ग से जोड़े जाने हेतु** सड़क का निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद लखीमपुर के विधान सभा क्षेत्र धौरहरा, वि0ख0 रमिया बेहड़ से परौरी मार्ग की पक्की सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या–

[महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि मेरे जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र धौरहरा में वि0 ख0 रमिया बेहड़ के अन्तर्गत रमिया बेहड़ से परौरी मार्ग पर गन्ना विभाग द्वारा निर्मित पक्की सड़क अत्यन्त जीर्ण–शीर्ण अवस्था में होने के कारण आये दिन दुर्घटनायें होती रहती हैं। यहां की क्षेत्रीय जनता एवं हजारों लोगों को आने–जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जिससे सरकार के प्रति क्षेत्रीय जनता में काफी रोष एवं जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त ग्राम रमिया बेहड़ से परौरी पक्की सड़क का मरम्मतीकरण/पुनर्निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद गाजियाबाद के वार्ड 74 में जस्सीपुरा हबीब कम्पाउण्ड के मोड़ पर क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश बंसल–

ख्महोदय,

मेरी विधान सभा क्षेत्र गाजियाबाद के वार्ड नम्बर–74 में एक मुख्य सड़क जो जस्सीपुरा से हबीब कम्पाउण्ड के मोड़ तक जाती है, पूर्णतयः क्षतिग्रस्त है। यह एक

---

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

मुख्य सड़क है, जिसमें काफी संख्या में लोगों/वाहनों का आवागमन रहता है, इस सड़क पर जगह–जगह गड्ढे हो चुके हैं व बरसात के दिनों में गन्दा पानी भरा रहता है जिसके कारण यहां के निवासियों को बड़ी असुविधा है व गम्भीर बीमारी फैलने का भी भय रहता है।

अतः जनहित में, जिस सड़क पर चलना भी दूभर है, की मरम्मत कराये जाने का अनुरोध करता हूं।

मैं सदन के माध्यम से इस अविलम्बनीय व लोक महत्व के प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित कराये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद लखनऊ के मलिहाबाद विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत मवईकला आरा मशीन के पास महबूब खेड़ा सरैया फतेहपुर की सड़क बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री इन्दल कुमार–

ख्महोदय,

मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र मलिहाबाद जनपद लखनऊ के अन्तर्गत मलिहाबाद में मवईकला आरा मशीन से महबूब खेड़ा फतेहपुर वाया दिलक खेड़ा सम्पर्क मार्ग (10 नं0–1 से 600 एम0एम0ह्यूम पाइप पुलिया सहित) का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में मेरे द्वारा पत्र दिया गया था, जिसके सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग अनुभाग–14 उ0प्र0 शासन, लखनऊ में लम्बित पड़ी हुई है। उक्त के सम्बन्ध में कार्य कराया जाना जनहित में आवश्यक है। उपरोक्त सम्पर्क मार्ग अत्यन्त जर्जर हालत में हैं जर्जर होने के कारण आम जनता को आने–जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मवईकला आरा मशीन से महबूब खेड़ा सरैया तिलक खेड़ा होते हुए फतेहपुर सड़क लम्बाई लगभग 5 कि0मी0 नव निर्माण सड़क बनवाये जाने हेतु जनता द्वारा बार–बार मांग की जा रही है। जनहित की समस्या को देखते हुए उक्त कार्य कराया जाना आवश्यक है। जनमानस से जुड़ा हुआ प्रश्न है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए मवई कला आरा मशीन के पास महबूब खेड़ा/सरैया तिलक खेड़ा होते हुए फतेहपुर तक की सड़क जनहित में बनवाये जाने की मांग सरकार से करता हूं।,

जनपद बरेली के उप निबन्धक कार्यालय बहेड़ी में करोड़ों की भूमि को मात्र 960.00 रुपये स्टाम्प ड्यूटी लेकर प्रकरण का निस्तारण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रोकश प्रताप सिंह–

[महोदय,

मैं आपका ध्यान जनपद बरेली के उप निबन्धक कार्यालय बहेड़ी जनपद बरेली ने दिनांक 18–05–2015 को पुस्तक संख्या–1 खण्ड 3790 के क्रमांक : 241 से 258 क्रम संख्या–4915 पर पंजीकृत किया है जोकि चन्द्र प्रकाश के गाटा संख्या–159 से 170 तक

176, 182 व 200 को साथ मिला कर उसका सेल सर्टिफिकेट में रु0 960.00 दर्ज किया गया जबकि इसमें क्रेता व विक्रेता उपस्थित नहीं हैं, करोड़ों की भूमि को मात्र रु0 960. 00 स्टाम्प ड्यूटी लेकर प्रकरण का निस्तारण किया जा सकता है इस पर प्रश्न चिन्ह लगता है, जांच का विषय है।

अतः इस लोक महत्व के प्रश्न को सदन में उठाने हेतु आपकी अनुमति चाहता हूं ताकि इसकी एक उच्च स्तरीय जांच हो सके।,

जनपद लखनऊ की डिफेन्स कालोनी नेपालगंज, तेलीबाग, रायबरेली रोड पर तालाब की भूमि को आबादी की भूमि दिखा कर बेचे जाने के सम्बन्ध नियम–301 अन्तर्गत सूचना

श्री उदय राज–

[महोदय,

मैं आपका ध्यान डिफेन्स कालोनी नेपालगंज, तेलीबाग, रायबरेली रोड, लखनऊ से लगे तालाब की तरफ ले जाना चाहता हूं जिसका खसरा नं0–57 व 58 को खसरा नं0–60 से बदल कर आबादी की भूमि को तालाब व तालाब की भूमि को आबादी दर्शा कर नगर निगम के लेखपाल, कानूनगो, तहसीलदार व एस0डी0एम0 द्वारा भू–माफिया को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से तालाब को निरन्तर पाट कर प्लाटिंग कर बेचा जा रहा है जिससे पानी की निकासी की समस्या निरन्तर बढ़ती जा रही है एवं वहां के निवासियों में अत्यधिक रोष व्याप्त है।

राजस्व विभाग के नम्बरों में खसरा नं0–57 व 58 तालाब अलग स्थान पर है व खसरा नं0–60 भूमि अलग स्थान पर है किन्तु नगर निगम के नक्से में वह स्थान बदलकर 12 बीघा 15 बिस्वा तालाब को पाटकर करोड़ों रु0 का लाभ अर्जित किया जा रहा है व बन्दर बांट चल रही है।

नगर निगम द्वारा दिनांक 19 मार्च, 2015 को विधान सभा में नियम–301 के अन्तर्गत उठाये गये प्रकरण पर तालाब की भूमि पर 12 बीघा 19 विस्वा में से 8 बीघा 4 विस्वा भूमि पर अवैध कब्जा दर्शाया गया है।

जिसमें खसरा नं0–57 तालाब की भूमि पर 75 व खसरा नं0–58 पर 88 अर्थात् कुल 163 कब्जेदार तालाब भूमि पर दर्शाया गया है। जिसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

मैं यह जानना चाहता हूं कि उक्त 163 अवैध कब्जेदार कौन–कौन हैं उनके नाम, पते, मकान नं0 क्या–2 हैं तथा उन्हें अभी तक नोटिस क्यों नहीं भेजी गयी यदि भेजी गयी तो कब–कब तथा उस नोटिस में क्या–क्या अंकित है कहीं भू–माफिया को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से नोटिस में विलम्ब किया जा रहा है ताकि पूरा तालाब पाट कर वे बिक जायें उसमें मकान बन जाये तब नोटिस भेजी जाये और प्रकरण कानूनी प्रक्रिया में फंस कर रह जाये।

उक्त खसरा नं0 की भूमि का एग्रीमेंट किसने व किसके साथ किया गया है प्लाट की रजिस्ट्री किसके द्वारा की जा रही है उसका पूरा विवरण क्या है ?

---

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

तालाब के उस पार स्व0 श्री शमशेर सिंह की भूमि का कुल रकबा कितना था उन्होंने तो अपने कार्यकाल मे उक्त ढाई बीघा भूमि बेच दी थी वर्तमान में उनके दो पुत्र जो सेना में कार्यरत हैं तो किस भूमि को और कैसे बेच रहे हैं। डिफेन्स कालोनी से उनका सुन्दर मकान भू–माफिया द्वारा बना कर दिया गया है व वो ही तालाब भूमि की रजिस्ट्री भी कर रहे हैं। ऐसा मुझे ज्ञात हुआ है। उक्त समस्त प्रकरण की एक उच्च स्तरीय जांच नगर निगम व राजस्व विभाग की टीम गठित कर कराना नितान्त आवश्यक है। ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके व वास्तविकता सामने आये तब तक तालाब को पाटना व भूमि को बेचने पर रोक लगाई जाये।

लोक महत्व के इस प्रश्न पर नगर निगम व राजस्व विभाग की संयुक्त टीम से जांच कराने हेतु इसे नियम–301 में उठाने हेतु आपकी स्वीकृति चाहता हूं।,

अंसल हाउसिंग एण्ड कान्सट्रेक्शन लि0 के आवांटियों को रजिस्ट्री न होने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी–

ख्महोदय,

मैं आपका ध्यान अंसल हाउसिंग एण्ड कान्सट्रेक्शन लि0, लखनऊ की तरफ ले जाना चाहता हूं जहां 'अंसल आंगन योजना' ई0डब्लू0एस0, अशियाना, कानपुर रोड में 591 आवंटियों को वर्ष 2009 में आवंटित आवास की आज तक रजिस्ट्री नहीं करायी गयी है। आवंटी आवंटित भू–खण्ड की रजिस्ट्री हेतु दर–दर भटक रहे हैं जबकि भू–खण्ड की रजिस्ट्री लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ को करनी है।

उक्त में श्री प्रदीप शर्मा को आवंटित मकान संख्या–786, सेक्टर 'एम'–1, आशियाना, कानपुर रोड, लखनऊ को वर्ष 2009 में आवंटित हुआ था जिसकी पूर्ण धनराशि आवंटी द्वारा जमा की जा चुकी है एवं श्री शर्मा व अन्य आवंटियों लगभग एक वर्ष से आवंटित भू–खण्डों में निवास भी कर रहे हैं।

अंसल हाउसिंग एण्ड कन्स्ट्रेक्शन लि0, लखनऊ को लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा 1200 आवासों को बनाने व बेचने का अधिकार प्रदान किया गया था। अंसल हाउसिंग एण्ड कन्स्ट्रेक्शन लि0, लखनऊ द्वारा 591 आवासों को आवंटित कर धनराशि प्राप्त कर ली गयी थी परन्तु रजिस्ट्री लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ करनी थी किन्तु लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ भू–खण्डों की रजिस्ट्री करने से इन्कार कर रहा है।

उक्त के संदर्भ में सूचना का अधिकार के तहत अपील आर0टी0आई0–194/8–3–15–122 (सूचना)/15, दिनांक 22–12–2015 (आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3) दिनांक 25–3–2015 द्वारा उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ को पुनः अनुस्मरण कराया गया किन्तु लगभग एक वर्ष पश्चात् भी सम्बन्धित को अभी तक कोई भी सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

---

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

अतः मैं चाहता हूं कि उक्त 591 आवंटियों को रजिस्ट्री लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा न करने की जांच कराने व उपरोक्त आवंटियों के उपरोक्त प्रकरण का निस्तारण यथाशीघ्र कराते हुये इसे नियम–301 में उठाने हेतु आपकी अनुज्ञा चाहता हूं।,

जनपद उन्नाव के ग्राम सिकन्दरपुर करन के ग्रामवासियों द्वारा जबरन कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शिवचरण प्रजापति–

ख्महोदय,

मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए अवगत कराना चाहता हूं कि ग्राम सिकन्दरपुर (कर्ण), तहसील–सदर, जनपद–उन्नाव में श्री प्रेम नरायण तिवारी एवं लक्ष्मीकान्त द्वारा ग्राम समाज एवं गंगा कृष्ण पुत्र जयशंकर की भूमि गाटा संख्या–1499 रकबा–304 की जमीन पर जबरन कब्जा करने के कारण पूरे गांव में जबरदस्त असन्तोष एवं विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हो गयी है इन असामाजिक तत्वों द्वारा गांव में आतंकित कर जबरन कब्जा किया जा रहा है गांव में तनाव की स्थिति व्याप्त है किसी भी समय कोई अप्रिय घटना हो सकती है।

इस लोक महत्व के विषय पर अन्यत्र कार्रवाई कर जांच किये जाने हेतु सदन में वक्तव्य की मांग करता हूं।,

जनपद आगरा के अन्तर्गत विकास खण्ड अकोला को तहसील बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री काली चरण सुमन–

ख्महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि जनपद–आगरा, 90 आगरा ग्रामीण क्षेत्र अन्तर्गत विकास खण्ड–अकोला आबादी एवं क्षेत्रफल के अनुपात में बहुत बड़ा है इसके अन्तर्गत आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र का क्षेत्रफल आता है तथा फतेहपुर सीकरी विधान सभा क्षेत्र का क्षेत्रफल आता है। उक्त क्षेत्रों के लोग अपनी समस्याओं को लेकर आगरा सदर तहसील के अन्तर्गत जाते हैं जोकि आगरा सदर तहसील बहुत बड़ी तहसील है। आगरा सदर तहसील के अन्तर्गत पूरा शहर है तथा ग्रामीण अंचल है। ग्रामीण अंचल के लोगों को आने–जाने में बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा एवं समय की बर्बादी होती है। अतः वि0ख0–अकोला को तहसील बनाने के लिए समय–समय पर किसान, मजदूर एवं सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न स्तरों पर जन आन्दोलनों द्वारा तहसील बनाये जाने की मांग की जा रही है। तहसील न बनने से क्षेत्रीय जनता का सरकार के प्रति भारी जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनहित में आगरा जनपद के अन्तर्गत वि0ख0–अकोला को तहसील बनवाये जाने की कार्रवाई की मांग करता हूं।,

---

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र की ग्राम सभा दुलहीपुर, सकुर के भट्ठा, सतपोखरी की जल निकासी के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बब्बन सिंह चौहान–

ख्महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि जनपद–चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय विकास खण्ड–नियामताबाद के ग्राम सभा–दुलहीपुर, सकुर के भट्ठा, सतपोखरी ग्राम सभाओं में जल निकासी की व्यवस्था न होने से बस्तियों में जलभराव बना रहता है, वहीं लोगों के घरों में गंदा पानी घुसने के कारण खतरनाक बीमारियों का उत्पन्न होना स्वाभाविक है। उक्त गांवों में जल निकासी की व्यवस्था न होने के कारण कुछ लोगों के मकान भी ध्वस्त हो गये। जिसके कारण कई बड़ी घटनाएं घट चुकी है जिसमें कई लोग की जानें भी चली गई है। उक्त ग्राम सभाओं में जल निकासी न होने के कारण क्षेत्रीय जनता में सरकार के प्रति भारी रोष–जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त ग्राम सभाओं में जल निकासी की व्यवस्था कराये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र माधवगढ़ टाउन एरिया में मुंसिफ कोर्ट स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अप्तर्गत सूचना

श्री सन्त राम कुशवाहा–

[महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र माधौगढ़ में लगभग 20 वर्ष पहले माधौगढ़ टाउन एरिया में तहसील की व्यवस्था किया गया माधौगढ़ तहसील लगभाग 5 लाख आबादी का इलाका है लेकिन यहां मुन्सिफ कोर्ट की स्थापना अभी तक नहीं हो पायी है। माधौगढ़ तहसील के लोगों को लगभग 50 कि0मी0 दूरी तय करके अपने मुकदमें के निस्तारण हेतु जालौन आना–जाना पड़ता है। जिससे क्षेत्रीय जनता व किसानों को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मेरे द्वारा कई बार पत्राचार के माध्यम से लिखित एवं मौखिक रूप में शासन एवं प्रशासन को अवगत कराया गया लेकिन अभी तक प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई न होने से क्षेत्रीय किसानों में सरकार के प्रति क्षेत्रीय एवं किसानों में रोष एवं जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय एवं तत्कालीन विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त विधान सभा क्षेत्र के माधौगढ़ टाउन एरिया में मुन्सिफ कोर्ट स्थापित कराये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद बस्ती विधान सभा क्षेत्र बस्ती सदर के कतिपय ग्रामों की जर्जर सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी–

[महोदय,

अवगत कराना है जनपद–बस्ती के विधान सभा क्षेत्र 310, बस्ती सदर के अन्तर्गत आने वाले ग्राम–मुण्डेरवा, रामपुर मार्ग पर बढ़ाया चौराहे से धौरहरा, गोचना तक सड़क की बहुत ही जर्जर हालत है एवं सड़क में बहुत बड़े–बड़े गड्ढे हैं, जिसके कारण

---

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

वहां के निवासियों को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जिसके कारण आवागमन बाधित रहता है एवं सड़क दुर्घटनायें होती रहती हैं, जिससे क्षेत्रीय जनता का सरकार के प्रति भारी जनाक्रोश है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए जनहित में उक्त सड़क का निर्माण कार्य यथाशीघ्र कराये जाने की कार्रवाई की मांग करता हूं।,

जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र खेरागढ़ सैंया–खेरागढ़ मुख्य मार्ग पर क्षतिग्रस्त पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री भगवान सिंह कुशवाहा–

[महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र खेरागढ़ में वि0ख0 खेरागढ़ के अन्तर्गत सैंया–खेरागढ़ मुख्य मार्ग से भाकर के गांव के लिए सड़क मार्ग के बीच में पुलिया क्षतिग्रस्त होने के कारण गांव भाकर का मुख्य मार्ग अवरुद्ध हो गया है। जिससे क्षेत्रीय जनता को आवागमन में काफी कठिनाइयों का सामना करता पड़ता है। जिससे सरकार के प्रति क्षेत्रीय जनता में काफी रोष एवं जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त मार्ग पर क्षतिग्रस्त पुलिया का निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं।,

राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के संविदा पर कार्यरत वाहन चालक को विनियमित किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री चन्द्रभान सिंह पटेल–

[महोदय,

अवगत कराना चाहूंगा कि जनपद–लखनऊ में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, उ0प्र0 तृतीय तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ के आदेश संख्या–8330/रा0पि0व0आ0/2002, दिनांक 01–08–2002 से वाहन चालक के रिक्त पद पर विभागीय संविदा के रूप में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, उ0प्र0 में कार्यरत है। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की लखनऊ बेंच द्वारा पारित आदेश सं0–4190/2014 को अवधेश कुमार सिंह की दयनीय स्थिति को देखते हुए राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, उ0प्र0 को सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए न्यूनतम वेतनमान दिये जाने का निर्देश दिया गया है किन्तु विभाग द्वारा चालक के रिक्त पद पर न तो नियमित नियुक्ति की जा रही है और न ही न्यूनतम वेतनमान दिया जा रहा है। शासन द्वारा चालक के रिक्त पद हेतु प्रति वर्ष बजट/धनराशि आवंटित किया जाता है किन्तु विनियमितीकरण न होने से कर्मचारी के पूरे परिवार की हालत बहुत ही दयनीय हो गयी है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कर्मचारी के हित में कार्यवाही कराये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद लखनऊ के नगर निगम के अन्तर्गत एल0डी0ए0 कालोनी सेक्टर एल–2 में पानी की सप्लाई ठीक से न होने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राधेश्याम जायसवाल–

---

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

[महोदय,

मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। सेक्टर एल–2 एल0डी0ए0 कालोनी, लखनऊ के आवास संख्या–2/255 से आवास संख्या–2/455 तक व अन्य आवासों में पानी की सप्लाई जल संस्थान द्वारा किया जाता है, परन्तु उक्त सप्लाई पानी की टंकी के माध्यम से न करते हुए सीधे ट्यूबवेल से किया जा रहा है। चूंकि पानी का पाइप बीस वर्ष पहले तीन इंच का पड़ा है इसलिए जगह–जगह टूट जाता है। यही नहीं नाम मात्र थोड़े समय के लिए धीमी गति से पानी की सप्लाई की जा रही है जो बगैर टुल्लू चलाये पानी घरों में नहीं आता है। जिससे कालोनीवासियों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है, आये दिन शिकायतें जल संस्थान के अभियन्ताओं से की जाती हैं परन्तु जल संस्थान के अभियन्ता कुछ सुनने को तैयार नहीं हैं। जिससे वहां के रहने वाले लोगों में रोष की भावना उत्पन्न हो रही है। तत्काल जनहित में चार इंच की पाइप नयी डाली जाय और पानी की सप्लाई सीधे पानी की टंकी के माध्यम से सुचारु रूप से समय पर करायी जाय।

अतः इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए समस्या का समाधान किये जाने एवं दोषियों के विरुद्ध लापरवाही बरतने के आरोप में दण्डित किये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद शाहजहांपुर में वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन योजना में की गयी धांधली की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रोशन लाल वर्मा–

ख्महोदय,

आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

जनपद–शाहजहांपुर के मेरे विधान सभा क्षेत्र–133, तिलहर के अन्तर्गत गरीब एवं असहाय पात्र लोगों को दी जा रही वृद्धावस्था पेंशन एवं विधवा पेंशन आदि को बन्द कर दिया गया है। क्षेत्रीय दलालों द्वारा अवैध तरीके से धन वसूली करके गलत ढंग से सक्षम लोगों को वृद्धावस्था पेंशन एवं विधवा पेंशन आदि सुविधाओं का लाभ दिलाया जा रहा है। क्षेत्रीय जनता ने पात्र लोगों को पूर्व में दी जा रही वृद्धा पेंशन एवं विधवा पेंशन आदि का लाभ दिलाये जाने का स्थानीय प्रशासन एवं उच्च अधिकारियों से कई बार अनुरोध किया परन्तु अभी तक उक्त पात्र गरीब, असहाय लोगों को वृद्धा पेंशन एवं विधवा पेंशन का लाभ नहीं दिया जा रहा है। जिससे क्षेत्रीय जनता में अत्यधिक रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतएव आपके माध्यम से सरकार से विधान सभा क्षेत्र तिलहर के पात्र गरीब, असहाय पात्र लोगों को वृद्धावस्था पेंशन एवं विधवा पेंशन आदि की सुविधायें दिलाये जाने की मांग करता हूं।,

---

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र इगलास करथला नाले पर करथला के निकट पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री त्रिलोकी राम–

[महोदय,

मेरे विधान सभा क्षेत्र इगलास, जनपद अलीगढ़ के अन्तर्गत करथला नाले पर ग्राम करथना के निकट पुल न होने के कारण ग्रामीण व स्कूली बच्चे सीमेंट का खम्भा डालकर उससे नाला पार करते है। नाला पार करते समय स्कूली बच्चे नाले में गिर चुके है। यह जनहित का प्रकरण है। नाले पर पुल के निर्माण न होने के कारण ग्रामीणों में काफी आक्रोश है।

अतः मैं जनहित में उक्त पुल का निर्माण कराये जाने की मांग करता हूँ।,

जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र कस्ता में लखीमपुर–मैगलगंज मार्ग से परसेहरा खुर्द एवं औरंगाबाद से 26 मील तक एक जीर्ण–शीर्ण सड़क को ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में

नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुनील कुमार लाला–

[मान्यवर,

मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान जनपद लखीमपुर खीरी के अपने विधान सभा क्षेत्र कस्ता की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ मेरे विधान सभा क्षेत्र कस्ता के अन्तर्गत आने वाली मण्डी समिति की सड़कें लखीमपुर–मैगलगंज मार्ग से अछनिया से पहाड़ा तक, बेहजम नीमगांव मार्ग से परसेहरा होते हुये परसेहरा खुर्द तक एव औरंगाबाद से छब्बीस मील तक की सड़कें अत्यन्त जीर्ण–शीर्ण अवस्था में है आये दिन यहाँ पर स्कूल गाड़ियाँ, ट्रकें एवं टैम्पों पलट रही है कई लोग घायल हो गये है। मान्यवर, यहाँ पर जान–माल का खतरा बना हुआ है। यहाँ के लोग काफी आक्रोषित एवं भयभीत है।

अतएव उक्त अविलम्बनीय विषय पर उपरोक्त क्षतिग्रस्त मार्गों के नवीनीकरण हेतु मैं सदन के माध्यम से कार्रवाई की मांग करता हूँ।,

जनपद महराजगंज को तहसील नौतनवां ग्राम भुन्डी अराजी नं0–1317 रकबा 0.616 हे0 तथा 1330 रकबा 0.219 हेक्टेयर पर आरिफ कुरैशी व आशिक कुरैशी द्वारा जबरन कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कुंवर कौशल सिंह–

[महोदय,

लोक महत्व के विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुये अवगत कराना है कि वार्ड नं0 16, बहादुर शाह नगर राजस्व ग्राम–भुन्डी, तहसील–नौतनवां, जनपद–महराजगंज के सविता देवी पत्नी सुबास वर्मा जोकि समाजवादी पार्टी से सभासद भी हैं। ग्राम भुन्डी, तहसील–नौतनवां, जनपद महराजगंज में स्थित अराजी नं0 1317 रकबा 0.616 हे0 तथा 1330 रकबा 0.219 हेक्टेयर हैं। जो वर्षो से ग्राम सभा तथा वार्ड

---

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

के लोग उक्त भूमि पर खलिहान के रूप में उपयोग करते है। उक्त भूमि पर जमींनदारी अभी खत्म नहीं हुई है। इसलिये ग्राम सभा भुन्डी क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले जमीनदार भी खलिहान की भूमि को खाली कराने के लिये उप जिलाधिकारी नौतनवां तथा जिलाधिकारी, महराजगंज को प्रार्थना–पत्र दिया है। उक्त ग्राम सभा की खलिहान के रूप में स्थित अराजी नं0–1317 रकबा 0.616 हे0 तथा 1330 रकबा 0.219 हे0 भूमि माफिया तथा दबंग किस्म के लोग आरिफ कुरैशी व आशिक कुरैशी पुत्र हवीबुल्लाह कुरैशी अपने तथा अपने परिवार के नाम गलत ढंग से दर्ज कराकर, उक्त भूमि पर दबंगयी के बल पर निर्माण कार्य कराया जा रहा हैं। इसके विरोध में श्री सुबास वर्मा 02–02–2016 से 09–02–2016 तक आमरण अनशन पर बैठे थे। प्रशासन के आश्वासन पर तहसीलदार अनशन को समाप्त कराकर एक लिखित आश्वासन दिनांक 09–02–2016 को दिया कि जांच पड़ताल कराकर उक्त भूमि को खाली करा दिया जायेगा। किन्तु आज तक प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गयी। यह प्रकरण जनहित एवं लोक महत्व का है।

अतः अविलम्बनीय एवं लोकमहत्व के विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुये शीघ्र कार्यवाही की मांग करता हूँ।,

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र विश्वनाथ विकास खण्ड लक्ष्मणपुर को निम्नलिखित ग्राम सभाओं में दूषित भू–गर्भ पेयजल व अति निम्न स्तर से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 आर0 के0 वर्मा–

[महोदय,

जनपद प्रतापगढ़ की विकास–लक्ष्मणपुर की ग्राम सभाओं देवापुर सकली, रावतपुर जूड़ापुर धनसारी, नरायनपुर, नौबस्ता, सरियापुर, रेडी, गजराही, काक्षा पूरनपुर खजूर, रामपुर खजूर, सरवाजपुर हरिहरपुर कैलहा, मकई, डोमीपुर, दौलतपुर, बलीपुर परसन, कोड़रामादूपुर देवली, लीलापुर सिन्धौर हण्डौर, बरापुर भीख डाड़ी आदि ग्राम सभाओं के पेय भू–गर्भ जल में फ्लोराइड जैसे हानिकारक तत्वों की अधिकता है और भू–गर्भ पेयजल का स्वाद अत्यधिक खारा है जिससे इण्डिया मार्का–2 हैण्डपम्प के बोर आदि की लोहे की पाइप अल्प समय में ही जंग लगकर खराब हो जाती है जिससे क्षेत्रवासियों में स्वास्थ्य की खराबी और घोर पेयजल संकट की समस्या व्याप्त हो गई है जिसके कारण क्षेत्रवासियों में आक्रोश व्याप्त है।

अतः सादर अनुरोध है कि जनहित को ध्यान में रखते हुये उपरोक्त ग्राम सभाओं में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करते हुये सदन में वक्तव्य की मांग करता हूँ।,

जनपद महोबा में खनिज क्षेत्र के सभी सम्पर्क मार्गों का यथाशीघ्र निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राज नारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज–

[महोदय,

कृपया अवगत कराना चाहूंगा कि महोबा जनपद में अत्यधिक पत्थर खादाने होने के कारण भारी यातायात से ग्राम काली पहाड़ी, गंज, घरौंद, मकरबई, डहर्रा, पहरा, खरका, डडहट, दहरा, घरौन, गहरा, काजी बम्हौरी इत्यादि ग्रामों के सम्पर्क माग्र पूर्णतः ध्वस्त हो चुके है, लोगों का पैदल चलना भी मुश्किल है, प्रायः ग्रामीणों का पत्थर व्यापारियों व वाहन मालिकों से झगड़ा होता है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुये उपरोक्त सभी सड़कों का निर्माण कराये जाने की मांग करता हूँ।,

जनपद हरदोई पूर्व में बनाये गये सभी परीक्षा केन्द्रों में से विद्यालयों को मानक पूर्ण करने के बावजूद परीक्षा केन्द्र न बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बृजेश कुमार–

[महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि जनपद–हरदोई में वर्ष 2014–15 में 300 परीक्षा केन्द्र बनाये गये थे। वर्ष 2015–16 में केवल 280 विद्यालयों को परीक्षा केन्द्र बनाया गया है। छोड़े गये 20 विद्यालय शासन द्वारा निर्धारित सभी मानकों की औपचारिकताओं को पूर्ण करते हैं। छोड़े गये विद्यालयों को परीक्षा केन्द्र बनाये जाने हेतु स्थानीय छात्र–छात्राओं एवं अभिभावकों द्वारा स्थानीय प्रशासन से अनुरोध किया परन्तु उक्त विद्यालय को परीक्षा केन्द्र न बनाये जाने से क्षेत्रीय छात्र–छात्राओं एवं अभिभावकों में सरकार के प्रति भारी रोष एवं जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुये कार्रवाई की मांग करता हूँ।,

जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र मोहान के ब्लाक नवाबगंज के अन्तर्गत कतिपय सम्पर्क मार्गों का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राधेलाल रावत–

[महोदये,

संज्ञान में लाना चाहूंगा कि जनपद–उन्नाव के मेरे विधान सभा क्षेत्र 164, मोहान के ब्लाक–नवाबगंज के अन्तर्गत सोहरामऊ से गोरिन्दा मार्ग तक, बल्ला फार्म से कटेहल मार्ग तक, अजगैन से बीर सिंह मार्ग तक, ब्लाक–हसनगंज के अन्तर्गत नवई से मदनापुर तक निर्माणाधीन सम्पर्क मार्ग, ब्लाक–औरास के अन्तर्गत शाहपुर तोदा से बयारी गाँव तक सम्पर्क मार्ग तक की सड़क अत्यधिक क्षतिग्रस्त अवस्था में है, उक्त सड़कें पूरी तरह से टूट कर उसमें बड़े–बड़े गड्ढे बन चुके हैं। उक्त सड़कों से लगभग सैकड़ों ग्रामों के निवासियों का आवागमन होता है। उक्त सड़कें क्षतिग्रस्त होने के कारण राहगीरों के साथ आये दिन मार्ग दुर्घटनायें हो रही हैं। उक्त क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत/जीर्णोद्धार हेतु क्षेत्रीय जनता द्वारा स्थानीय उच्च अधिकारियों एवं प्रशासन से कई बार अनुरोध किया

---

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

गया है परन्तु अभी तक शासन द्वारा उपरोक्त सड़कों के निर्माण हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। आवागमन में बाघा उत्पन्न होने के कारण क्षेत्रीय जनता में अत्यधिक जनाक्रोश व्याप्त है।

अत इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराये जाने की मांग करता हूं।,

[01.30, श्री सलिल विश्नोई सदस्य विधान सभा के साथ दिनांक 15 सितम्बर, 2004 को पुलिस द्वारा किये गये दुर्व्यवहार के प्रकरण पर विशेषाधिकार समिति द्वारा संस्तुति के उपरान्त भी आज तक कोई कार्रवाई न किये जाने विषयक औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

अब यह 300 का है। 300 में तीन सूचनायें आई थीं। इसमें सुरेश कुमार खन्ना जी की सुनी जायेगी और दो नहीं सुनी जायेगी।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सलिल विश्नोई जो इस विधान सभा के सम्मानित सदस्य है वर्ष 2002 से वर्ष 2007 तक भी वह चौदहवीं विधान सभा के सदस्य थे। मान्यवर, वह दिनांक 15 सितम्बर, 2004 को एक ज्ञापन देने जा रहे थे और उस ज्ञापन देने के दौरान मान्यवर, पुलिस पार्टी के द्वारा उस पर हमला किया गया। एक शान्तिपूर्ण तरीके से वह जा रहे थे उस पर हमला किया गया मान्यवर। उनको अपमानजक टिप्पणियाँ, अभद्र टिप्पणियाँ भी उनके खिलाफ की गई। मान्यवर, वह प्रकरण माननीय विशेषाधिकार समिति को आपके माध्यम से, इस पीठ के माध्यम से सुपुर्द किया गया था और उस विशेषाधिकार समिति की सिफारिश जुलाई के आखिरी हफ्ते में मान्यवर, 2005 में इस सदन में प्रतिवेदन के रूप में प्रस्तुत की गई। मान्यवर, आज लगभग 11 वर्ष हो गये और इन 11 वर्षों में मान्यवर, डिले डिफीट द जस्टिस यह एक सूक्ति है कि अगर किसी न्याय में देरी हो तो वह भी एक अन्याय की श्रेणी में गिना जाता है। मान्यवर, हम आपसे विनम्रतापूर्वक आग्रह करते है कि एक लम्बा अन्तराल हो गया मान्यवर। जो लोग आरोपी थे, जिन लोगों के खिलाफ समिति ने संस्तुति की कि इनको दोषी करार दिया जाता है और सदन को इस बात के लिए कहा था कि सदन उसमें दंड निर्धारित करेगा। इसमें इतना अंतराल हो गया मान्यवर, हमारा आपसे सिर्फ यह आग्रह है कि इसमें तत्काल जो दोषी हैं उनको बुलाकर, जो दोषी हैं, उनको बुलाकर दंड का निर्धारण कर दें ताकि इनको मान्यवर, न्याय मिल सके।

श्री अध्यक्ष–

माननीय खन्ना जी, जब मैं पिछले टर्म में 2007 में स्पीकर था, तब यह प्रकरण कानपुर वाला मेरे सामने आया था और मैंने ही इसको विशेषाधिकार समिति को संदर्भित किया था और संदर्भित रिपोर्ट पर डेट भी तय हो गई थी और वह अधिकारी जिन्हें दंडित होना था वह आए भी थे लेकिन उस दिन किन्हीं परिस्थितियों में सदन में यह बात बन नहीं पाई, वह पेश नहीं हो पाए, इसके बाद यह मामला दब गया फिर पांच–छः साल इधर बीत गए आप कह रहे हैं कार्य–मंत्रणा में बात कर लेते, वह पेंडिग है और

यह मेरे समय का ही केस है उसमें फिर हम डेट तय करके उनको भी तलब करेंगे। बात करेंगे। कार्य–मंत्रणा में बात करेंगे।

श्री सलिल विश्नोई–

श्रीमन् यह खेद का विषय है।

श्री अध्यक्ष–

इसमें मेरा दोष नहीं है मैंने उसको तलब किया वह आकर बैठा था आप ही लोगों का दोष था उस दिन और कोई कारण नहीं था मैंने तो उस दिन उसको बुलाया था। वह तलब हुआ था आपके लोग ही इधर–उधर हो गए तो मैं क्या करूं।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

मान्यवर, हम सब लोग यहां प्रदेश की जनता का आदर सम्मान करने आए हैं और प्रदेश की समस्याओं पर हम सवाल उठाते हैं सरकार के मंत्रीगण जवाब देते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज बड़ी विचित्र स्थिति हुई जब मैंने प्रदेश से संदर्भित, शौचालय से संदर्भित समस्याओं को, निर्मल भारत अभियान से संबंधित समस्या को आपके समक्ष सदन में उठाया। माननीय अध्यक्ष जी, आप कार्यवाही उठाकर देख लीजिए माननीय मंत्री जी का यह जवाब आया कि आप अपने परिवार में अगल–बगल में बता दीजिए मैं वहां पर शौचालय बनवा दूंगा। मान्यवर, हम यहां किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं आए हैं हम सेवा के भाव से आए हैं और इस तरह का आरोप किसी व्यक्ति पर लगाना बड़ा निन्दनीय है, टिप्पणी है, मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, फिर इन्होंने यह कहा कि जो शौचालय अपने घर में न बनवाए, बगल में न बनवाए, गांव में न बनवाए, ऐसे लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए, मान्यवर मैं यहां किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं आया हूं। मैं आया हूं अपने क्षेत्र की आशा आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, मैं पिछड़े क्षेत्र की समस्या को उठाने के लिए इस विधान सभा में आया हूं तो मैं आपके माध्यम से यह मांग करना चाहता हूं कि इस पर माननीय मंत्री जी को खेद प्रकट करना चाहिए सार्वजनिक रूप से इस बात के लिये और उनको अपने शब्द वापस लेने चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

देखिए, माननीय मंत्री जी का यह आशय नहीं होगा कि वह आपके सम्मान के खिलाफ बोलें, परिवार का मायने घर होता है, गांव में जब पूछा जाता है कि इस गांव में कितने घर हैं तो लोग पूछते हैं कि कितने परिवार हैं। परिवार मायने घर, और अगर आपके मकान के अलग–बगल नहीं शौचालय है तो उन्होंने पूछा होगा यह उनका उद्देश्य रहा होगा अब रही बात इस्तीफा देकर चले आएं इस बारे में आप हमें लिखकर दो ना, लिखकर दोगे तो हम पूछेंगे मंत्री जी से, लिखकर दो।

लघु सिंचाई, पशुधन तथा पंचायती राज मंत्री (श्री राजकिशोर सिंह)–

मान्यवर, इनको हर्ट करने की मेरी कोई मंशा नहीं थी अगर इनको तकलीफ है तो वह सब आप कार्यवाही से निकाल दीजिए।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है बैठिए बात खत्म हो गई।

[01-35] उ0 प्र0 पावर कार्पोरेशन लिमिटेड का नवां वार्षिक प्रतिवेदन, 2007–2008[*]

नियोजन एवं ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई')–

माननीय अध्यक्ष महोदय आपकी अनुमति से उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड के नवां वार्षिक प्रतिवेदन 2007–2008 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा–619ए की उपधारा (3) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड का दसवां वार्षिक प्रतिवेदन 2008–2009

नियोजन एवं ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई')–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड के दसवां वार्षिक प्रतिवेदन 2008–2009 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा–619ए की उपधारा (3) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूँ।

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड का ग्यारहवां वार्षिक प्रतिवेदन 2009–2010

नियोजन एवं ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई')–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड के ग्यारहवां वार्षिक प्रतिवेदन 2009–2010 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा–619ए की उपधारा (3) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूँ।

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड का बारहवां वार्षिक प्रतिवेदन 2010–2011

नियोजन एवं ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई')–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड के बारहवां वार्षिक प्रतिवेदन 2010–2011 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा–619ए की उपधारा (3) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूँ।

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड का तेरहवां वार्षिक प्रतिवेदन 2011–2012

नियोजन एवं ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई')–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड के तेरहवां वार्षिक प्रतिवेदन 2011–2012 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा–619ए की उपधारा (3) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूँ।

उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड का चौदहवां वार्षिक प्रतिवेदन 2012–2013

नियोजन एवं ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई')–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड के चौदहवां वार्षिक प्रतिवेदन 2012–2013 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा–619ए की उपधारा (3) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूँ।

उप लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या–1–2012 (उप लो0 आ0)
(स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित)

---

† Nkik ugha x;k gSA

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उप लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या–1–2012 (उप लो0 आ0) (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) को उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त एवं उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा–12 की उपधारा (7) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–10 इसमें कुछ नहीं है। अब मद संख्या–11।

[01-35] जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र खेरागढ़ के विकास खण्ड सैंया में कतिपय जर्जर गड्ढेयुक्त सड़कों की मरम्मत कराये जाने विषयक श्री दिनेश रावत आदि निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका४

श्री भगवान सिंह, कुशवाहा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र खेरागढ़ के विकास खण्ड सैंया में कतिपय जर्जर गड्ढेयुक्त सड़कों की मरम्मत कराये जाने विषयक श्री दिनेश रावत व श्री कमल सिंह कुशवाहा निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूँ।

जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र खेरागढ़ के विकास खण्ड जगनेर में कतिपय जर्जर गड्ढेयुक्त सड़कों की मरम्मत कराये जाने विषयक श्री रामसिंह सिकरौदिया आदि निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री भगवान सिंह, कुशवाहा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र खेरागढ़ के विकास खण्ड जगनेर में कतिपय जर्जर गड्ढेयुक्त सड़कों की मरम्मत कराये जाने विषयक श्री रामसिंह सिकरौदिया आदि निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूँ।

जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र खेरागढ़ के विकास खण्ड खेरागढ़ में कतिपय जर्जर गड्ढेयुक्त सड़कों की मरम्मत कराये जाने विषयक श्री मेघराज सोलंकी आदि निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री भगवान सिंह, कुशवाहा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र खेरागढ़ के विकास खण्ड खेरागढ़ में कतिपय जर्जर गड्ढेयुक्त सड़कों की मरम्मत कराये जाने विषयक श्री मेघराज सोलंकी व श्री नरेन्द्र सिकरवार निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूँ।

जनपद लखनऊ के पश्चिम विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कन्हैया माधौपुर वार्ड के फिरदौस कालोनी की कच्ची सड़क व नालियों का जनहित में निर्माण कराये जाने विषयक श्री अनीस हसन द्वारा निवासीगण जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री मो0 रेहान–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद लखनऊ के पश्चिम विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कन्हैया माधौपुर वार्ड के फिरदौस कालोनी की कच्ची सड़क व नालियों का जनहित में निर्माण कराये जाने विषयक श्री अनीस हसन व श्री मो0 अकील सिद्दीकी निवासीगण जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूँ।

जनपद लखनऊ के पश्चिम विधान सभा क्षेत्र के आलमनगर वार्ड के अन्तर्गत जलालपुर मर्दनखेड़ा की कच्ची सड़क व नालियों का जनहित में निर्माण कराये जाने विषयक श्री जमाल अहमद द्वारा निवासीगण जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री मो0 रेहान–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद लखनऊ के पश्चिम विधान सभा क्षेत्र के आलमनगर वार्ड के अन्तर्गत जलालपुर मर्दनखेड़ा की कच्ची सड़क व नालियों का जनहित में निर्माण कराये जाने विषयक श्री जमाल अहमद व श्री प्रेम यादव निवासीगण जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूँ।

जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड सरदार नगर के अन्तर्गत गोरखपुर–देवरिया मार्ग पर स्थित डुमरी खुर्द चौराहा से ग्राम सभा शत्रुघनपुर होते हुए लक्ष्मणपुर चौराहे तक की क्षतिग्रस्त सड़क का जनहित में उच्चीकरण एवं चौड़ीकरण कराये जाने विषयक श्री राधेश्याम आदि निवासीगण जनपद गोरखपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री जय प्रकाश निषाद–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड सरदार नगर के अन्तर्गत गोरखपुर–देवरिया मार्ग पर स्थित डुमरी खुर्द चौराहा से ग्राम सभा शत्रुघनपुर होते हुए लक्ष्मणपुर चौराहे तक की क्षतिग्रस्त सड़क का जनहित में उच्चीकरण एवं चौड़ीकरण कराये जाने विषयक श्री राधेश्याम व अन्य निवासीगण जनपद गोरखपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूँ।

जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड ब्रम्हपुर के अन्तर्गत राजधानी से नई बाजार जाने के लिये घटुली घाट पर पुल निर्माण कराये जाने विषयक श्री राज बहादुर निषाद आदि निवासीगण जनपद गोरखपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री जय प्रकाश निषाद–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड ब्रम्हपुर के अन्तर्गत राजधानी से नई बाजार जाने के लिये घटुली घाट पर पुल निर्माण कराये जाने विषयक श्री राज बहादुर निषाद व अन्य निवासीगण जनपद गोरखपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूँ।

[01-38] कार्य–मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–14 में कुछ नहीं है अब मद संख्या–15। उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य–मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 25 फरवरी, 2016 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 26 फरवरी, 2016 से दिनांक 11 मार्च, 2016 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिशें की हैं :–

1–दिनांक 04 मार्च, 2016 को सदन में पुरःस्थापित उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2016 पर विचार एवं उसके पारण सम्बन्धी मदें ली जायं।

2–दिनांक 04, 05, 06 व 08 मार्च, 2016 को नियम–300, 301 तथा 56 के अन्तर्गत सूचनायें न ली जायं।

3–दिनांक 08 मार्च, 2016 को, दिनांक 04 मार्च, 2016 के लिये निर्धारित अनुदान संख्या–80, 81 व 83 तथा 06 मार्च, 2016 के लिये निर्धारित अनुदान संख्या–92 की मांगों पर विचार एवं मतदान की मदें ली जायं।

4–तद्नुसार दिनांक 26 फरवरी, 2016 से दिनांक 11 मार्च, 2016 तक के उपवेषनों का कार्यक्रम निम्नवत् रखा जाय :–

फरवरी, 2016

26 शुक्रवार	वित्तीय वर्ष 2016–2017 के आय–व्ययक पर साधारण चर्चा।
27 शनिवार 28 रविवार 29 सोमवार **मार्च, 2016** 01 मंगलवार 02 बुधवार 03 गुरुवार	बैठक नहीं होगी।
04 शुक्रवार	1–वित्तीय वर्ष 2016–2017 के आय–व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान। 2–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2016 पर विचार एवं उसका पारण।
मार्च, 2016 05 शनिवार 06 रविवार	वित्तीय वर्ष 2016–2017 के आय–व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।
07 सोमवार (महाशिवरात्रि का अवकाश)	बैठक नहीं होगी।
मार्च, 2016 08 मंगलवार	1–वित्तीय वर्ष 2016–2017 के आय–व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान। 2–**3.00 बजे अपराह्न** उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2016 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण। 3–माननीय डा0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी, सदस्य विधान सभा द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं एक–एक घण्टे की चर्चाधीन

निम्नलिखित सूचनाओं पर अग्रेतर चर्चा :–

(क) पूर्वान्चल सहित प्रदेश के जनपदों में दिमागी बुखार न फैले इसकी आवश्यक व्यवस्था तथा रोगग्रस्त हो जाने पर बच्चों को तत्काल प्रभावी चिकित्सा व्यवस्था के माध्यम से जीवन रक्षा करने के संबंध में।

(ख) प्रदेश की जलवायु पर ग्लोबल वार्मिंग के कुप्रभाव पड़ने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

4–श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, माननीय नेता विरोधी दल व अन्य, श्री प्रदीप माथुर व अन्य तथा श्री सुरेश कुमार खन्ना एवं डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल, सदस्यगण, विधान सभा द्वारा नियम–56 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं माननीय अध्यक्ष विधान सभा द्वारा नियम–52 में परिवर्तित निम्नलिखित सूचना पर एक घण्टे की चर्चा :–

बुन्देलखण्ड के सभी जनपदों में सूखे की समस्या से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

5–श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, माननीय नेता विरोधी दल व अन्य तथा श्री प्रदीप माथुर व अन्य सदस्यगण, विधान सभा द्वारा नियम–56 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं माननीय अध्यक्ष विधान सभा द्वारा नियम–52 में परिवर्तित निम्नलिखित सूचना पर दो घण्टे की चर्चा :–

प्रदेश में विद्युत आपूर्ति की समस्या का निराकरण न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

09 बुधवार
10 गुरुवार
11 शुक्रवार
} बैठक नहीं होगी।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मा0 अध्यक्ष जी, इसमें एक टाइपिंग मिस्टेक हो गयी है। कार्य–मंत्रणा समिति की बैठक में नियम–56 की सूचनाएं 4, 5, 6 और 8 तारीख को लिये जाने का तय हुआ था।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

मा0 अध्यक्ष जी, कार्य–मंत्रणा में यह तय हुआ था कि नियम–56 की सूचनाएं आगे के सभी उपवेशनों में ली जायेंगी, क्योंकि शनिवार और इतवार को पूर्व से ही कोई प्रश्न नहीं लगे हैं, इसलिये उस दिन प्रश्नकाल नहीं होगा। यदि प्रश्नकाल नहीं होगा तो सीधे–सीधे नियम–56 की सूचनाओं को लेने के बाद सीधे बजट पर चर्चा होगी, यह कल तय हुआ था।

श्री अध्यक्ष–

हम मिनट्स देख लेंगे और सुधार कर देंगे।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, क्योंकि यूनेनिमस होना है लिहाजा मा0 नेता विरोधी दल और मा0 नेता भारतीय जनता पार्टी के सुझाव को मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गयी है तथा संशोधन सहित सहमत है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव जो मा0 संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है तथा जो संशोधन सहित है से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

पंचायती राज विभाग का बजट साहित्य पटल पर प्राप्त न होने सम्बन्धी प्रकरण

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–16 कुछ नहीं है।

श्री काली चरन सुमन–

मान्यवर, पंचायती राज विभाग का बजट अभी तक पटल पर नहीं आया है जबकि यह शुरू में ही लगा हुआ है।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसको देख लेंगे।

[01-44] कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 26–2–2016 को नियम–56 के अन्तर्गत कुल 17 सूचनायें प्राप्त हुईं, जिनमें शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनायें चयनित की गईं। प्रथम दो सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जा सकता है।

पहली सूचना श्री दलवीर सिंह की प्रदेश में पैथोलाजी लैबों व अल्ट्रा साउण्ड सेन्टरों द्वारा मनमानी फीस वसूलने व अनाधिकृत रूप से संचालित लैबों द्वारा सही जांच न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है।

दूसरी सूचना श्री मनीष असीजा की जनपद फिरोजाबाद के नगर निगम फिरोजाबाद अन्तर्गत स्वकर प्रणाली से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

तीसरी सूचना श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री त्रिभुवन राम, श्री अली युसुफ अली, श्री लोकेश दीक्षित, श्रीमती पूजा पाल, श्रीमती रजनी तिवारी, श्री इन्द्रपाल सिंह, श्री ममतेश शाक्य, श्री अयोध्या प्रसाद पाल, श्री राजेन्द्र, श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री मो0 आसिफ, श्री

मो0 इकबाल, श्री रविन्द्र कुमार मोल्हू, श्री ओम कुमार, श्री भगवान सिंह कुशवाहा, डा0 विजय कुमार, श्री इन्द्रजीत सरोज एवं श्री जय प्रकाश निषाद की लखनऊ एवं नोएडा में ब0स0पा0 शासनकाल में निर्मित पार्कों, उद्यान, स्मारक आदि के रखरखाव न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है।

चौथी सूचना श्री अगयश राम सरन वर्मा की नियामक प्राधिकारी, इलाहाबाद द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा, 2013 की परीक्षा के उपरान्त नियुक्तियां न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है।

पांचवीं सूचना डा0 आर0के0 वर्मा की प्रदेश में चल रही राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजनान्तर्गत बी0पी0एल0 परिवारों के स्मार्ट कार्ड धारकों का योजना से सम्बद्ध अस्पतालों के द्वारा इलाज न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें अस्वीकृत की गयीं, श्री अजय कुमार 'लल्लू', श्री संजय प्रताप जयसवाल, श्री सतीश महाना, श्री गेंदालाल चौधरी, डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल, श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री जय प्रकाश निषाद, श्री बब्बन सिंह चौहान, श्री राम प्रसाद चौधरी, श्री जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री प्रदीप माथुर, श्री बंशी सिंह पहाड़िया, श्री गयादीन अनुरागी, श्री राधे श्याम, श्री ललितेशपति त्रिपाठी, श्रीमती अराधना मिश्रा 'मोना', श्री रोशन लाल वर्मा एवं श्री रामचन्द्र यादव।

नियम–311 की दो सूचनाएं थीं जिनको मैंने नियम–56 में ले लिया है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने कृपापूर्वक इस बात का आश्वासन दिया था कि हमें अवसर देंगे।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, आप बोल लीजिए, ज्यादा समय नहीं लीजिएगा। आज 3.00 बजे तक सभी को जाना है, इसलिए 5–7 लोग जो बोलने वाले हैं, जल्दी–जल्दी उनको बुलवा करके बन्द कर देंगे।

'श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, यह विशेष रूप से आगरा महानगर की एक घटना है और बहुत ही हृदय विदारक घटना है। कल सुबह लगभग 11.00 बजे आगरा का जो व्यस्ततम् बाजार है, मन्टोला, उसमें विश्व हिन्दू परिषद् के उपाध्यक्ष, श्री अरूण माहौर, जो कोरी समाज से आते हैं, कल दिन के 11.00 बजे 05 लागों ने उनकी निर्मम हत्या कर दी और मान्यवर, हत्या का कारण यह बताया जाता है, जिन लोगों के ऊपर आरोप लगाया गया है हत्या का, उन लोगों ने 2 दिन पहले भी इनको धमकी दी थी और सुबह 7.00 बजे से यह बात हवा में तैर रही थी कि आज इनकी हत्या हो जायेगी। मान्यवर, यह अपने आप में बहुत ही गंभीर मामला है कि एक तरफ तो सरकार लगातार

---

*oDrk us Hkk"k.k dk iquohZ{k.k ugha fd;kA

कानून–व्यवस्था को सुधारने का दावा करती है और दूसरी तरफ लगातार प्रदेश में हत्याओं का सिलसिला बढ़ रहा है और खास तौर से डे–लाइट में, व्यस्ततम् बाजार में, इस प्रकार से अपराधियों के इतने हौसले बुलन्द हैं कि उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि उन्हें कितने दिन जेल में रहना पड़ेगा, उन्हें इस बात की भी परवाह नहीं है कि उनकी जमानत होगी कि नहीं होगी ? इसलिए मान्यवर, यह अपने आप में बहुत गंभीर घटना है और घटना का कारण यह बताया जाता है कि जो अरूण माहौर थे, दलित समाज के व्यक्ति थे, 40–45 साल की जिसकी उम्र थी, जिसके दो नाबालिक बच्चे हैं, उसकी विधवा पत्नी है, हत्या का कारण यह बताया जाता है कि जो लोग गोकशी करते थे, उन लोगों का यह विरोध करते थे, उनके नाजायज कामों के खिलाफ आन्दोलन करते थे, उसके खिलाफ उसने आवाज उठायी थी। इसलिए मान्यवर, उसको चुनौती देकर दिनदहाड़े उसकी हत्या कर दी गयी। मान्यवर, उसके पीछे वृद्ध माता–पिता भी हैं और उसका पूरा परिवार अनाथ हो गया है। उसके परिवार के सामने रोजी–रोटी का भी बहुत बड़ा संकट है, उसके परिवार के सामने पूरी तरीके से मान्यवर, अंधेरा है। मान्यवर, हम आपके माध्यम से सरकार से यह मांग करते हैं कि सरकार कम से कम एक सरकारी नौकरी उसकी पत्नी को देने का आश्वासन दे और उसके परिवार के भरण–पोषण के लिए, आगे के जीवन–यापन के लिए कम से कम 50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता करें क्योंकि मान्यवर, आदमी के जाने के बाद सिर्फ पैसा ही एक मात्र ऐसा सहारा रह जाता है, जिसके आधार पर वह आगे की जिन्दगी जी सकता है।

मान्यवर, दूसरी घटना, परसों रात प्रतापगढ़ में हुई और एक घटना पीलीभीत में भी हुई। एक स्थान पर पुलिस का होमगार्ड, महादेव प्रसाद मिश्रा, वह मारे गए और मान्यवर, ताज्जुब तब होता है कि उस थाने के बाहर बमबारी की गई। यह मानिकपुर थाना है प्रतापगढ़ में, वहां पर बाकायदा 10–15 बम फेंके गए और उसके बाद सार्वजनिक रूप से 6–7 हमलावरों ने एक संतरी की मान्यवर, हत्या कर दी।

मान्यवर, पीलीभीत में भी एक एस0सी0 की हत्या कर दी गई। तो मान्यवर, यह तीनों–चारों घटनायें ऐसी हैं जो ह्रदय विदारक हैं और सरकार के कानून–व्यवस्था के दावों की पोल खोलती हैं। मान्यवर, मैं अपनी बात पर फिर से बल देता हूं कि जो मृतक हैं, उन्हें आर्थिक सहायता दी जाये। मान्यवर, आगरा के अरूण माहौर के परिवार को आर्थिक सहायता और उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी देने के लिए आप सरकार को निर्देश दे दें कि कम से कम उसके जीवन–यापन के लिए यह व्यवस्था करवा दें।

मान्यवर, इस बात के आप निर्देश दे दें सरकार को कि कम से कम उसके जीवन–यापन के लिए यह व्यवस्था करवा दें और दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई हो, दोषी पकड़े जायं और इससे एक संदेश भी देना चाहिए मान्यवर कि कम से कम यह सरकार दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने वाली है। मान्यवर, हम मांग करते हैं कि सदन की सारी कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा करा ली जाय।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, सरकार यह संदेश बराबर देती रहती है और सख्त कार्यवाही होती है, आगे भी होगी, इसमें न परेशान होने की जरूरत है और न ही यह सोचने की कोई गुंजाइश है कि सरकार इसमें कोई रियायत करेगी, बहुत निन्दनीय घटना है मान्यवर, मुकदमा संख्या–08/2016, धारा–147, 148, 149, 302, 323, 504, 506 व 325 एस0सी0 ऐक्ट की भी धारा इस पर लगाई गई है। इसमें क्योंकि नामजद मुल्जिमान भागे हुए हैं, उनके यहां बराबर दबिशों का सिलसिला जारी है, जल्द ही गिरफ्तारी हो जायेगी, हो सकता है गिरफ्तारी हो रही हो, हो चुकी हो या हो जाय। मुख्य मंत्री जी द्वारा 10 लाख रुपया मान्यवर इसमें सहायता बतौर दिया गया है और 05 लाख रुपया समाज कल्याण विभाग से दिया गया है और भी किसी सहायता की अगर जरूरत होगी तो सरकार उस पर विचार करेगी।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, सहायता की राशि को बढ़वा दें, क्योंकि मरने के बाद आदमी के सिर्फ यही रह जाता है कि उसका जीवन यापन कैसे हो, उसके दो बच्चे हैं विधवा पत्नी है। मान्यवर, यह सहायता पर्याप्त नहीं है, इसको बढ़ाया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है अब आप बैठ जाइये।

श्री प्रदीप माथुर–

माननीय अध्यक्ष जी, 24 फरवरी, 2016 की सांय काल की घटना है हजरतगंज, जहां गांधी प्रतिमा के नीचे पार्क के पास रोहित वेमुला के आत्महत्या तथा दिल्ली में जे0एन0यू0 की घटना के परिप्रेक्ष्य में छात्रों का एक समूह धरना दे रहा था और वह धरना देते हुए छात्र जब अपना मूक प्रदर्शन कर रहे थे गांधीवादी तरीके से तब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने उनकी इतनी बुरी तरह से पिटाई की कि पूछिये मत। मा0 अध्यक्ष जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां पर आये लाठी–डण्डों से उनको पीटा और उसके बाद उनके पास तिरंगा झण्डा था, उसे भी छीना और फाड़ दिया और तिरंगे झण्डे का अपमान किया और छात्रों को घायल कर दिया, पुलिस मूक दर्शक की तरह उन्हें देखती रही और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मान्यवर, यह प्रत्यक्षदर्शी मामला है, इस तरह से प्रदेश में माहौल बिगाड़ा जा रहा है, जगह–जगह छोटी–छोटी बातों को लेकर शिक्षा में फांसीवादी और साम्प्रदायिकता को फैलाया जा रहा है, इसी तरह लखनऊ विश्वविद्यालय में इस तरह की घटना हुई, गोरखपुर विश्वविद्यालय में घटना हुई।

श्री अध्यक्ष–

आप सिर्फ इसकी ग्राह्यता पर बोलिये।

श्री प्रदीप माथुर–

इसमें दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाय और मान्यवर मैं मांग करता हूं कि सदन की सारी कार्यवाही रोक कर के इस पर चर्चा करा ली जाय।

श्री अध्यक्ष–

अब आप बैठ जाइये। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी इसको दिखवा लीजिएगा।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, आपने भी अधूरी सूचना दी है, दरअसल वह ऐसे लोग थे जिन्होंने यह विरोध प्रदर्शन किया, उनके साथ तो ऐसा होना ही चाहिए था। मान्यवर, वैसे तो कानून हाथ में लेना बुरी बात है, मगर जो मानसिकता पनप रही है और जैसा मैंने कहा कि राष्ट्रवाद के मतलब लोगों ने कुछ ऐसे निकाल लिये हैं कि आर0एस0एस0 हेडक्वार्टर से जो राष्ट्रवाद समझाया जायेगा, वही राष्ट्रवाद होगा और जिन्हें वह सर्टिफिकेट देंगे वही राष्ट्रवादी होंगे, बड़ी अफसोसनाक घटना है मान्यवर, इस पर कार्रवाई होगी।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है चलिये, अब मा0 असीजा जी।

'श्री मनीष असीजा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं फिरोजाबाद नगर के नागरिकों का करारोपण के नाम पर जो उत्पीड़न हो रहा है, उस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, फिरोजाबाद एक औद्योगिक शहर है और वहां मिली–जुली आबादी है। 4 अगस्त, 2014 से यह नगर पालिका से नगर निगम बना। उसके बाद से नगर निगम के कर विभाग के द्वारा एक सोचे–समझे तरीके के साथ नगर के विभिन्न आवासीय संपत्ति स्वामियों के ऊपर अनाप–शनाप टैक्स के नोटिस दिए जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इनकी सीधी–सच्ची प्रैक्टिस है कि किसी के यहां जाते हैं, उसको एक लाख, दो लाख रुपये का नोटिस देते हैं। यह चार–छः लोगों के ग्रुप बनाकर जाते हैं जिससे कि भवन स्वामी पूरी तरह से घबरा जाए और उनके सामने सौदेबाजी कर दे और उनकी गलत मंशा पूरी कर दे। माननीय अध्यक्ष जी, ऐसे मामले सामान्यतः आरोप–प्रत्यारोप की प्रवृत्ति से भी लगाये जाते हैं और कई बार यह वास्तविकता भी है। तो मैं इस सदन के सामने पूरी जिम्मेदारी से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हैं, मेरे पास विशेष मामले हैं, उनकी एक पत्रावली है और नोटिस भी है। मैं इसे माननीय मंत्री जी को सौंप दूंगा। इसमें एक और प्रमुख बात है कि नगर निगम बनने से पहले नगर पालिका परिषद् फिरोजाबाद में पिछले बीस–तीस वर्षों से न्यूनतम किराया दर की पद्धति से करारोपण हो रहा था। हाउस टैक्स और वाटर टैक्स लग रहा था। अचानक से 2011–12 और 2012–13 के साल में यह कैपिटल टैक्स के आधार पर टैक्स चार्ज किया गया। इसकी स्थिति यह हो गयी कि जिस भवन स्वामी के पास 43 सौ रुपये वार्षिक कर था उसको 5 लाख 76 हजार कर दिया गया। जिसका 29 सौ पच्चीस था उसका 4 लाख 73 हजार 6 सौ 80 कर दिया। जिसका 13 सौ पचास था उसका 2 लाख 69 हजार 8 सौ तीस कर दिया। यह तो हलचल मच गयी। सुपरसीड थी, वह कुछ समय के लिए जो प्रशासक थे उनके पास जिम्मेवारी आ गयी। तो उन्होंने जैसा राजा का व्यवहार होता है, वैसा किया। सीधे–सीधे उसको 50 प्रतिशत कम भी कर दिया गया। मेरा जहां तक स्थानीय निकाय का अनुभव है कि इस प्रकार आधा किसी को माफ करने का कोई

---

*oDrk us Hkk"k.k dk iquohZ{k.k ugha fd;kA

अधिकार ही नहीं है। जो नियम है, नियम के हिसाब से वह काम होना चाहिए और जिस दौरान कैपिटल कास्ट के हिसाब से करारोपण किया उसी दौरान उन्होंने न्यूनतम किराया दर से भी टैक्स इम्पोज़ किए। मान लीजिए किसी एक व्यक्ति का तो न्यूनतम किराया दर से दस हजार टैक्स बना और दूसरे का उसी समय में कैपिटल कास्ट से दो लाख से चार लाख कर दिया। उसकी मैं जांच की मांग करता हूं और उसके विषय भी मेरे पास सबूत के साथ हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूं मेरे यहां डा0 अलका मित्तल का नर्सिंग होम है उनके ऊपर टैक्स का नोटिस दिया गया और 77,225 रुपये का टैक्स का नोटिस दिया गया। इन्होंने जवाब दिया कि इतना तो टैक्स हमारा है नहीं, और आपने जो नोटिस दिया है इसमें हमारे आवास के 201 मीटर का बेसमेण्ट दिखाया है। उन्होंने विनयपूर्वक कहा कि आप जांच कर लें 201 मीटर बेसमेण्ट की जो बात दूर है अगर एक मीटर का भी बेसमेण्ट होगा तो हम जिम्मेदार हैं। जब उनकी नहीं सुनी गयी, तो लिखित रूप से दिया गया। फिर नहीं सुना गया तो डी0एम0 साहब के पास व्यक्तिगत रूप से भी गए और लिखित रूप से भी दिया। केवल एक ही बात आयी कि पैसा दे दो। वह भी डटे रहे तो नतीजा यह हुआ कि उनकी रिकवरी निकल गयी और एक लाख एक हजार नौ सौ अट्ठाईस रुपये इसमें वसूल लिए गए और आज भी उनका घर जो बद्सतूर वहां पर है, वहां कोई भी जांच की जा सकती है। इसी तरह इमदाद पहलवान हैं उनका एक खाली प्लाट है छोटी सी दुकान है दो उनका 30 हजार 5 सौ का नोटिस दे दिया गया। हमने संबंधित अधिकारियों से कहा कि आप नोटिस ज्यादा क्यों दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि इन्होंने दे दिया है तो अपना जवाब दे दें। तो हर आदमी जवाब नहीं दे पाता है।

वहा पर इतने नोटिस देखकर वह घबरा जाता है और लेन–देन करने का मजबूर हो जाता है। मैं मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी से विनम्रतापूर्वक एक बात और कहूंगा कि मैं राजस्व के विरोध में नहीं हूं। नियमानुसार नगर निगम या नगर पालिकाओं को टैक्स नोटिस देना चाहिए और उनको टैक्स लेना भी चाहिए लेकिन जो गोरखधन्धा चल रहा है कि सुशीला देवी का 60 साल पुराना मकान है, क्षेत्रफल 3000 वर्ग फुट का है, 42,000 रुपये का नोटिस दे दिया। प्रेम नारायण का 2800 वर्ग फुट का मकान है, 40 साल पुराना है और 800 वर्ग फुट खाली भी है, उसका 43,590 रुपये का नोटिस दे दिया। इन सब नोटिस की कॉपी भी मैंने इकट्ठी करके रखी हैं। मैं आपके माध्यम से मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी से यह अनुरोध करता हूं कि यह जो सारा गोरखधन्धा चल रहा है जिसमें बुरी तरीके से नगर निगम के कर अधिकारियों द्वारा, कर्मचारियों द्वारा निर्दोष जनता का उत्पीड़न और शोषण किया जा रहा है तो आप एक निष्पक्ष जांच दल भेजकर जांच करा दें, मैं आपको इन सारे मामलों के कागज भी सौंप दूंगा। यदि ठीक पाए जाएं तो कोई बात नहीं है। मैं खुद जो सजा होगी भुगतने को तैयार हूं। जो मामले मैंने बताएं हैं अगर चार–चार, पांच–पांच गुना अगर इनके नोटिस दिए गए हैं अवैध वसूली के लिए तो इनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित कराएं। मैं यह अपेक्षा करता हूं और इस लोकमहत्व के तात्कालिक और सुनिश्चित अविलम्बनीय विषय पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराए जाने की मांग करता हूं।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 सदस्य ने जो प्रकरण रखा। ये पहली बार नहीं रखा है और ये बड़े खेद की बात है कि पहले भी आपने शिकायत की और दोबारा भी आपको शिकायत का मौका मिल रहा है। ये दोंनों प्रकरण आप मुझे भेज दीजिए और मैं इसके भी पक्ष में हूं कि अगर कोई सदन की समिति आप बना दें वह जांच कर ले। अच्छा, चलिए एक मौका हमें और दे दीजिए विभाग को। मैं विभाग को भी यह संदेश देना चाहता हूं कि इस तरह की बातें बुरी हैं। मैं कोशिश करूंगा कि किसी अच्छे अधिकारी से इसकी जांच कराऊं और जब पहले दिन सदन बैठेगा तभी मान्यवर, हम इस पर क्या कार्रवाई की, इसका उत्तर भी आपको देंगे।

श्री अध्यक्ष–

मैंने मा0 मनीष असीजा जी को सुना, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना। मैं इसे अग्राह्य करता हूं।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

मा0 अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी के शासन काल में इस देश में जन्मे तमाम सन्तों, गुरुओं और महापुरुषों के नाम पर बड़े पार्क, उद्यान, स्मारक, ईको गार्डेन, ग्रीन गार्डेन आदि का निर्माण कराया गया और उसी के तहत आपके लखनऊ में तथ नोएडा में डा0 भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिर्वतन स्थल, मान्यवर कांशीराम सामाजिक परिवर्तन स्थल एवं साथ ही साथ समता मूलक चौक, मान्यवर कांशीराम ईको गार्डेन, मान्यवर कांशीराम ग्रीन गार्डेन, बुद्धा विहार सहित अनेक स्मारक आज कहीं न कहीं उपेक्षा के शिकार हुए हैं। मान्यवर, चूंकि डा0 भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल के बगल से ही मैं जाता हूं। इत्तेफाक से कल साढ़े सात बजे सदन जब स्थगित हुआ तो मैं 8 बजे अपने कार्यालय से आवास की ओर निकला तो देखा कि डा0 अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल की सारी की सारी लाईट गुल थीं, पूरा का पूरा अंधेरा था। जब कि शाम 6 से लेकर रात 10–11 बजे तक लखनऊ शहर के ही हजारों लोग अपने परिवार और बच्चों के साथ अम्बेडकर स्मारक पार्क तथा उसके पास में बंधे पर बनी महापुरुषों की मूर्तियों के किनारे चहलकदमी करते नजर आते हैं, देखने के लिए आते हैं और साथ ही साथ अपने बच्चों के साथ वहां पर टहलते और घूमते हैं। लेकिन अंधेरे के नाते जिस तरीके से आज बड़े पैमाने पर अराजकता का दौर है लोग कभी–कभी चोर और उच्चकों के भी शिकार हो जाते हैं। यही नहीं मान्यवर, अंदर साफ–सफाई और रख–रखाव का भी बड़े पैमाने पर अभाव है जिसके नाते सारी व्यवस्थाएं होते हुए भी आज सारे–के–सारे वहां देख–रेख के लिए कर्मचारी हैं, सुरक्षा के लिए भी कर्मचारी हैं, सफाई के लिए भी कर्मचारी हैं, लेकिन इसके बावजूद उनको किसी अन्य जगह पर लगा करके उसको बिल्कुल उपेक्षा की नजर से देखा जा रहा है जिससे कि न केवल लखनऊ के बल्कि देश और प्रदेश से भी तमाम पर्यटक जो दिन में या शाम या सुबह आते हैं, उनको घोर अव्यवस्था का शिकार होना पड़ता है और घोर अव्यवस्था का सामना करना पड़ता है। यही नहीं मान्यवर, यहां तक की तमाम सुविधाओं जैसे पानी पीने के लिए नल लगाये गए हैं, उसमें समुचित रूप से पानी की व्यवस्था नहीं है और देख–रेख के अभाव में कूड़े का अम्बार भी लगा रहता है। मान्यवर, यह सामाजिक परिर्वतन स्थल हों या कोई भी पार्क या स्मारक हों, सरकारी उपेक्षा यदि किसी के साथ होती है तो घोर अन्याय है। साथ ही साथ मैं आपके माध्यम

से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इससे आने–जाने वाले जो तमाम दर्शक हैं, वहां इसको देखकर बहुत आक्रोशित भी हैं, गुस्से में हैं। मान्यवर, मैं चाहता हूं इस पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा करायें और इस पर सरकार भी गंभीरता से इसका संज्ञान लेते हुए जितनी भी समस्यायें हैं–बिजली, पानी, साफ–सफाई, रख–रखाव और वहां पर सारी की सारी सुव्यवस्थित तरीके अपनाकर सारी व्यवस्थायें बहाल की जायें। मान्यवर, आपके माध्यम से मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री से अपेक्षा करूंगा कि इसमें कोई सकारात्मक ही उत्तर आये तो ज्यादा अच्छा रहे।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, शिकायत कोई न कोई जरूर होगी तभी आपने डोर को इतना खींचा है। दिखवा लेंगे, अगर कोई भी कमी है सफाई वगैरह में तो उसको पूरा करेंगे। कोई नीयत नहीं हो सकती किसी महापुरुष का अपमान करने की, और बहुत ही घटिया व्यक्ति होगा जो महापुरुषों का अपमान करे। महापुरुष किस धर्म या जाति से नहीं जुड़े होते हैं, महापुरुष अपने कारनामों से अपनी अच्छाइयों से महापुरुष होते हैं। समाजवादी सोच ऐसी नहीं है, अगर कहीं भी कोई कमी हो रही है तो उसे दूर करेंगे।

(सदस्य अजय कुमार 'लल्लू' के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

ठीक है। अब लल्लू पहले सुनें हमने आपका सब नोटिस पढ़ा हैं, पहले तो आप यह समझ लें कि नियम–56 कैसे दिया जाता है, पांच घटनायें हैं। कहीं पुलिस के खिलाफ लिखे हैं कि चरस में रख के बंद कर दिया, कहीं लिखा है कि पुलिस ने चौकी में बुलाकर मारा, कहीं लिखा है कि गन्ना के खेत में ले जाकर बलात्कार कर दिया। इसमें पांच–छः घटनायें एक साथ नहीं दी जाती हैं। इसमें अलग से एक घटना दी जाती है, तब वह स्वीकार होता है, इसलिए अस्वीकार हो गया। अब आप 4 तारीख को एक घटना जो इसमें महत्वपूर्ण समझियेगा उसे दीजिएगा। अब आप किसी को भी पढ़ा लो, ये इतनी घटनायें आपने लिखीं है कि पुलिस पकड़ ले गई तो उनको चरस रखने में बंद कर दिया, फिर पुलिस चौकी में बुला लाई दूसरी घटना फिर तीसरी घटना इस तरह से पांच घटनाओं को लिखकर आप नियम–56 में दे रहे हैं तो किसी घटना में बात हो।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, इसमें एक बात तो समझ में आई कि ये जिसकी शिकायत कर रहे हैं कि पुलिस उनको ले गई और चरस में रख दिया। आमतौर पर मान्यवर, ऐसे सटोरिये जो मानते ही नहीं, सट्टे–जुए में चालान हुआ और मजिस्ट्रेट साहब ने पूछा क्यों तुम्हारा कोई जामिन है और जमानत मिल गई और 10 मिनट बाद वह ठेंगा दिखाते हुए आता है। देखिए ऐसे लोगों से ताल्लुकात भी मत रखिए।

श्री अध्यक्ष–

आप देखिए यह नियम–56 में नहीं लिया गया है, क्योंकि 6 घटनाओं का आपने अलग–अलग विवरण दिया है। नियम–56 एक घटना पर होता है, यह आप समझ लें, नियमावली पढ़ लें। इसको एक घटना पर आप अगले बार दीजिएगा तो उस पर हम विचार कर लेंगे। 6 घटनाएं पर एक साथ नहीं लिया जाता, ये नियम–56 में आता नहीं है, नियम तो पढ़ लें। बैठें।

अब चौथे नंबर पर अगयश रामसरन वर्मा जी की सूचना नियामक प्राधिकारी, इलाहाबाद द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा 2013 की परीक्षा के उपरांत नियुक्तियां न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, मैं इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर ले रहा हूं तथा डा0 आर0के0 वर्मा का प्रदेश में चल रही राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजनान्तर्गत बी0पी0एल0 परिवारों के स्मार्ट कार्ड धारकों का योजना से सम्बद्ध अस्पतालों के द्वारा ईलाज न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, इस पर भी ध्यान आकर्षित करता हूं।

वित्तीय वर्ष 2016–2017 के आय–व्ययक पर साधारण चर्चा

माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री विजय बहादुर पाल)–

माननीय अध्यक्ष जी, किसी सरकार का बजट मात्र एक आर्थिक लेखा नही होता वरन सत्तारूढ़ दल बहुमत दल का आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक चिन्तन भी होता है। बजट के माध्यम से समस्त जीवन दर्शन प्रस्तुत किया जाता है। इसमे मूल्यों और आदर्शों का भी वर्णन होता है। उत्तर प्रदेश का बजट एक ऐतिहासिक दस्तावेज है जिसमे भारत के विकास की कुजी छिपी हुई है, दुनिया के किसी व्यक्ति, किसी संस्था, किसी सरकार के पास इतने साधन नहीं होते कि सभी की इच्छाओं की पूर्ति और फलीभूत एक साथ एक बार मे हो सके। उत्तर प्रदेश एक विकासशील प्रदेश है। सरकार की आय अपेक्षित व्यय मे एक बाधा अथवा सीमा निर्धारित करती है। केन्द्र सरकार के अनुदान की महत्वपूर्ण भूमिका पिछले वर्षों से निरन्तर कम हुई है। उत्तर प्रदेश, जिसके विकास के बिना भारत के विकास की कल्पना भी असम्भव है। केन्द्र सरकार निरन्तर उपेक्षापूर्ण रवैया अपना रही है किन्तु इन सब बातों से यह तथ्य नहीं नकारा जा सकता कि कोई व्यक्ति उतना ही सबल और सफल होता है जो समस्त चुनौतियों को और बाधाओं को चुनौती दे सके।

संसदीय कार्य एवं नगर वकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, कुछ ऐसा सिस्टम करिये कि जब आपसे माननीय सदस्य बात करें तो माइक आफ हो जाये।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, हम भविष्य मे आपके सुझाव का ध्यान रखेंगे।

श्री विजय बहादुर पाल–

मान्यवर, इस बजट मे सभी मुख्य तथ्यों, सभी वर्गों, क्षेत्रों व वर्तमान भविष्य का सुन्दर समन्वय है। न्यूनतम व्यय अधिकतम लाभ के अर्थशास्त्री सिद्धांत का पालन किया गया है। यह बजट अल्पकालिक नहीं है। इसमे पहले जब बजट पर चर्चा की बात थी तो, वही गिने–चुने, रटे–रटाये शब्द कि बजट चुनावी है। जन आकांक्षाओं को जगाने वाला है। इसमे चुनावी रंग है। झूठ का पुलिंदा है लेकिन इस बजट से यह स्पष्ट है कि यह केवल चुनावी बजट नही है, लोक लुभावन नहीं है, यह बजट अल्पकालिक नहीं है। बजट अगले से 5 से 10 वर्षों के लिए बनाये गये नियोजन को प्रदर्शित करने वाला बजट है। चिन्ता इस बात की नही है कि हम इधर बैठेंगे या उधर बैठेंगे, कुर्सी हमे प्राप्त होगी

या नहीं चिन्ता इस बात की है कि उत्तर प्रदेश प्रगति पथ पर अग्रसर होगा या नही होगा। उत्तर प्रदेश की जनता किसान, मजदूर का भाग्य सितारा जगेगा कि नहीं

(इस समय 2 बजकर 12 मिनट पर श्री अधिष्ठाता श्री उदयराज पीठासीन हुए)

जगेगा, या अब तक उपेक्षित किये जाने वाली सरकारों जैसा ही रहेगा। इस बजट भाषण समाजवादी सरकार ने पिछले पांचो वर्ष की योजना नही बनाई, कोई प्रगति का सपना संजोया है, जिसका लाभ वर्तमान को ही न मिले, भविष्य को भी मिले। अब सरकार द्वारा जारी आकड़ो में सर्वाधिक पूंजीगत व्यय करने वाला प्रदेश, उत्तर प्रदेश बन गया है। वर्तमान वर्ष मे उत्तर प्रदेश सरकार के कुल 33 लाख 46 हजार नौ सौ पैंतिस करोड़ मे से 1 लाख 5 हजार करोड़ से अधिक पूंजी खाते का व्यय है। पूंजीगत का मतलब है आर्थिक व सामाजिक संरचना पर होने वाला व्यय, आर्थिक संरचना से मतलब है, सड़कें, परिवहन, बिजली, सिंचाई, सामाजिक संरचना से मतलब है शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा व बीमा सम्पूर्ण भारत मे उत्तर प्रदेश सरकार अपनी आय में जिन मदों पर सर्वाधिक व्यय करती है। वर्तमान पीढ़ी के लिए आवश्यक हैं लेकिन भविष्य के लिए भी। केवल काम करने मे हम लोग विश्वास करते हैं। कर्म करना हमारा कर्तव्य है, फल ईश्वाराधीन। हम काम मे विश्वास करते हैं। हम वाणीवीर नही है, हम वायदावीर नहीं है, हम कर्मवीर हैं, हम क्रान्तिवीर हैं। सड़क पर व पुल पर होने वाले व्यय को देख लीजिये। पिछले वर्षों से दो गुने से अधिक है। सड़क व पुल पर होने वाला व्यय लगभग 25 हजार करोड़ से अधिक है। आगरा से लखनऊ ग्रीन एक्सप्रेस अपने आपमें एक अनूठी कल्पना है। एक अनुकरणीय उदाहरण बन गया है। यह इलाहाबाद, जौनपुर, आजमगढ़ और बहराइच, श्रावस्ती, कालपी, छिबरामऊ सैरिख, विधूना आदि इतने चार मार्ग लेन स्थापित किये जायेंगे कि उत्तर प्रदेश परिवहन के मामले में श्रेष्ठता की ओर अग्रसर होगा। विद्युत को विकास का सूचकांक माना जाता है उत्तर प्रदेश में बिजली की किल्लत के कारण बड़े उद्योगपति आने से घबराते थे। अगले पांच वर्षों में बिजली का उत्पादन 11,000 मेगावाट से 21,000 मेगावाट किया जाना हैं। इसके ऊपर लगभग 60,000 करोड़ से अधिक पांच वर्षों में व्यय किया जाना है। उत्तर प्रदेश सरकार का व्यय पिछले वर्षों की तुलना में दुगना कर दिया गया है पिछले वर्ष जलवायु परिवर्तनों के कारण खेती और किसानों पर बड़ी जबरदस्त कठिनाइयां बीती और देश के कई भागों में किसानों को आत्महत्या को विवश होना पड़ा। उत्तर प्रदेश किसानों के लिये योजना बनाने व क्रियान्वयन में सदैव अग्रणी रहा है। नई सिंचाई योजनाओं के लिए 1574 करोड़ व लघु सिंचाई योजनाओं के लिये 550 करोड़ के आस पास का व्यय रखा गया है। अगले पांच वर्षों में उत्तर प्रदेश का सम्पूर्ण इलाका सिंचित क्षेत्र हो जायेगा। बुन्देलखण्ड भी पानी के अभाव में प्रगति के पथ से वंचित नहीं रह सकेगा। आर्थिक विकास के साथ–साथ सामाजिक संरचना का विकास आवश्यक है। जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार का कोई सानी नहीं है। स्वास्थ्य सुविधाओं में पिछले वर्ष की तुलना में किया जाने वाला व्यय 22 प्रतिशत अधिक है। उत्तर प्रदेश

सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत सभी नागरिकों को समस्त चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए कटिबद्ध है। बीमा के क्षेत्र मे भी उत्तर प्रदेश सरकार लगभग 1 करोड़ 10 लाख लोगों को आज भी बीमा उपलब्ध कराता है। वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन तथा विकलांग पेंशन लगभग 55 लाख लोगों को उपलब्ध करायी जाती है। यह आंकड़े बताते हैं कि 21 छोटे–मोटे देशों की जो जनसंख्या है उससे अधिक लोगों को हम बीमित करते हैं जिससे वह सभी गरीब व्यक्ति सम्मानपूर्ण जीवन जीने का अवसर प्राप्त कर सकें। जहां तक शिक्षा के कार्यक्रम हैं चाहे विश्वविद्यालय हों, चाहे महाविद्यालय हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा हो या बेसिक शिक्षा हो जितने काम, जितने विद्यालय प्रदेश सरकार द्वारा संचालित किये जाते हैं उतने और कहीं नहीं। उत्तर प्रदेश में जितने विद्यार्थियों क्रे माध्यमिक शिक्षा का सरकारी लाभ मिलता है उनकी संख्या लाखों में है। मान्यवर, आज मोदी जी एक डिजीटल इण्डिया की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार पिछले तीन वर्षों से माध्यमिक शिक्षा के उत्तीर्ण विद्यार्थियों को मुफ्त लैपटाप देती रही है डिजिटल इण्डिया तो तब सफल होगी जब विद्यार्थियों को संरचनात्मक सुविधायें उपलब्ध करायी जायेंगी।

मान्यवर, यह है किसान वर्ष। यह समर्पित है किसानों को, नौजवानों को। ये हैं राष्ट्र की रीढ़, यह है वर्तमान और युवा देश का भविष्य। इस बजट में युवाओं के लिए निश्चित नीतियां व कार्यक्रम है। किसान आत्मनिर्भर बने, गौरवपूर्ण जिन्दगी का अधिकार उसे प्राप्त हो सके। समाजवादी पार्टी ने यह वर्ष किसानों और नौजवानों के लिए घोषित किया है। किसान खुद अर्थव्यवस्था की बीमा है। सरकार चाहती है कि आगे ऐसा वक्त आये कि किसान को इसकी आवश्यकता ही न पड़े। समाजवादी किसान, सर्वहित बीमा योजना यह तो शुरुआत है। आगे आने वाले वक्त में किसान को इसकी आवश्यकता ही न पड़े किसान खुद अर्थव्यवस्था की बीमा है। उनके बीमें की आवश्यकता पड़ना ही दुखद है। जहां तक युवाओं का प्रश्न है यह बजट नौजवानों का है। उनके सुखद भविष्य के लिए है। ''जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है।'' इस तथ्य को हमारे यशस्वी ओजस्वी मुख्य मंत्री श्री अखिलेश यादव ने भलीभांति समझा है। वह चाहते हैं कि यह बजट उत्तर प्रदेश के युवाओं को खुले आसमान में उड़ने के लिए पंख उपलब्ध कराये। यह बजट उत्तर प्रदेश व सम्पूर्ण भारत के स्वर्णिम भविष्य हेतु मील का पत्थर साबित होगा। जय उत्तर प्रदेश, जय भारत।

श्री काली चरन सुमन–

मान्यवर, आपने 2016–17 के बजट पर बोलने का अवसर दिया मैं आपको बहुत– बहुत बधाई देना चाहता हूं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारे विपक्ष दल के नेता माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बजट चर्चा पर मैं अपने को सम्बद्ध करते हुए अपनी बात रखना चाहता हूं। मान्यवर, जनता के लिए जिसके मन में प्यार नहीं जनतंत्र में वह कुर्सी का हकदार नहीं यह कहावत बजट पुस्तिका में दर्ज है। अधिष्ठाता महोदय, यह कहावत वर्तमान सरकार समाजवादी पार्टी पर लागू होती है क्यों लागू होती है कानून–व्यवस्था ध्वस्त है, गुण्डे माफिया मस्त हैं। विकास कार्य ठप है, अखिलेश सरकार मस्त है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस बजट के अन्तर्गत ऐसा कोई प्राविधान नहीं है, जिसकी हम प्रशंसा करें। इस सरकार का यह पांचवा बजट है और चार साल तक इस

सरकार ने अपने बजट प्रस्तुत किये उनमें उत्तर प्रदेश की जनता को आस थी कि हमारे क्षेत्र में सड़कें बनेंगी, हमारे क्षेत्र में बिजली की 24 घण्टे व्यवस्था होगी, हमारे क्षेत्र में पानी की व्यवस्था होगी, इन तमाम मूलभूत समस्याओं को लेकर जनता की निगाहें माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ थी। परन्तु खेद के साथ कहना पड़ता है कि यह बजट जिस तरह से प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 2016 और 2017 का बजट मात्र प्रथम पंक्ति के जो उधर मंत्री बैठे हैं, या चार–पांच जिलों तक ही सीमित रह गया है।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य, आप अपनी बात कहें। क्या आप अपना पूरा समय इसी में ले लेंगे।

श्री काली चरन सुमन–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं इस बजट के बारे में जिक्र करना चाहूंगा। इस बजट में लोहिया ग्राम की बात रखी गई है। समाजवादी पार्टी के लोग लोहिया जी को तो मानते हैं, पर लोहिया जी की बात को नहीं मानते हैं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरे क्षेत्र के अन्तर्गत दो–तीन लोहिया ग्राम स्वीकृत हुये थे, लेकिन आज तक उनमें पूरी तरह से विकास कार्य नहीं हो सके हैं। उन गांवों में आज पूरी तरह से सी0सी0 रोड नहीं बन पाई हैं और इन गांवों में सड़कों की समुचित व्यवस्था नहीं की गई है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि मेरे यहां नगला नाथू को लोहिया ग्राम घोषित किया गया था, इस गांव में लोक निर्माण विभाग ने सड़क बनवाई थी। मण्डी समिति ने सड़क बनवाई थी और छह महीने के बाद ही सम्पर्क मार्ग धवस्त हो गया। माननीय अधिष्ठाता महोदय, सरकार के प्रति अधिकारियों की उदासीनता है। जब बहन कुमारी मायावती जी की सरकार थी तो उस समय अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत बहुत सारे काम किये जाते थे। एक मजरे को भी नहीं छोड़ा जाता है। बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में जो अम्बेडकर गांवों में काम हुये थे, आज भी लोग उसकी चर्चा करते हैं। कांग्रेस दल के नेता श्री प्रमोद तिवारी जी ने सार्वजनिक रूप से चर्चा प्रशंसा की थी कि यदि कहीं काम हुये थे तो बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में हुये थे। माननीय अधिष्ठाता महोदय, पेयजल के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि जब से बहन कुमारी मायावती जी की सरकार गई है तब से बड़ा बुरा हाल है। हमारे क्षेत्र में स्थाई टी0टी0एस0टी0 की टंकियां खराब पड़ी हैं, उनकी तरफ सरकार का ध्यान नहीं है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि स्थाई टी0टी0एस0टी0 की जो 241 टंकिया खराब पड़ी हैं, उनके लिए धन आवंटित किया जाये। माननीय अधिष्ठाता महोदय, 125 टी0टी0एस0टी0 की टंकियां हमारे यहां स्वीकृत हैं और उनका पैसा जिला स्तर पर है परन्तु जिला स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है और न ही टी0टी0एस0टी0 की टंकियां लगाई जा रही हैं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, लखनऊ–आगरा एक्सप्रेस–वे जो समाजवादी पार्टी की एक महत्वाकांक्षी योजना है, हम इसकी सराहना करते हैं। जिस तरह से बहन कुमारी मायावती जी ने ग्रेटर नोएडा–यमुना एक्सप्रेस–वे योजना का जो नमूना दिया था, उसी की नकल करते हुए

कार्य को आगे बढ़ाया है। लखनऊ–आगरा एक्सप्रेस–वे मेरी विधान सभा से शुरू होता है वहां के किसान, वहां के मजदूर, वहां के रास्तागीर जो लखनऊ एक्सप्रेस वे बनना है उससे सारी सड़कें प्रभावित हो रही हैं, ग्राम प्रभावित हो रहे हैं। रास्ता प्रभावित हो रहे हैं। मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि जो सम्पर्क मार्ग हैं, वह सही कराये जाये। इसके बाद मैं बसावट की ओर ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा। जैसे कि दो सौ–ढाई सौ की जो बसावटें हैं। मेरी विधान सभा के अन्तर्गत चार–पांच ग्राम ऐसे हैं, जो अभी तक सड़कों से नहीं जोड़े गये हैं। नगला आनन्दी गांव, टपरा गांव हैं, यह अभी तक सम्पर्क मार्ग से नहीं जोड़े गये हैं, घड़ी हरदपात है यह भी सम्पर्क मार्ग से नहीं जोड़ा गया है, घड़ी पीलिया है यह भी सम्पर्क मार्ग से नहीं जोड़ा गया है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि वर्ष 2013–14 में एक बसावट के अन्तर्गत एक ग्राम स्वीकृत हुआ था और उसके लिए 25–30 लाख रुपया स्वीकृत हुआ था। 10 लाख रूपया जिला स्तर पर पहुंच गया, परन्तु वर्ष 2013–14 से लेकर आज तक उस गांव को नहीं जोड़ा गया है। पता नहीं, पैसा कहां गया। माननीय अधिष्ठाता महोदय, प्राइमरी विद्यालयों की स्थिति बड़ी खराब है, उनमें बाउण्ड्रीवाल नहीं है तो कहीं पर पेयजल की व्यवस्था नहीं है, मेरे यहां बहुत सारे ऐसे ग्राम हैं जिनमें बाउण्ड्रीवाल की व्यवस्था की जाये, जैसे झील जाटव, विमई, इकतरा, देवरी, ककरारी, नगला आनन्दी, भुजगई, गुटिला आदि तमाम ऐसे गांव हैं जिनकी बाउण्ड्रीवाल नहीं हुई है। इसको बजट में जोड़ा जाये।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सुमन जी, कृपया समाप्त करें ।

श्री काली चरन सुमन–

जो किसान दुर्घटना बीमा योजना में सरकार की तरफ से 5 लाख की व्यवस्था की गयी है, वह बहुत सराहनीय काम है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो भूमिहीन मजदूर लोग होते हैं, उनको भी किसान बीमा की तरह दुर्घटना बीमा 5 लाख की व्यवस्था की जाय जिससे गरीब लोग अपना पालन पोषण कर सकें। माननीय अधिष्ठाता महोदय, यमुना नदी के किनारे पर हमारे यहां कई गांव बसे हुये हैं। जब बाढ़ आती है तो उन गांवों की भूमि नष्ट हो जाती है, गांव नष्ट हो जाते हैं। मेरे यहां कम से कम 5–6 गांव ऐसे हैं जो भूमि के कटान के कारण बरबाद हो जाते हैं और किसान बरबाद हो जाते हैं।

श्री अधिष्ठाता–

सुमन जी, कृपया समाप्त करिये ।

श्री काली चरन सुमन–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी दो ही मिनट हुये हैं। हमारे यहां समोगर गांव है, एक मेहरा नाहरगंज गांव है, तनोरा नूरपुर गांव है, बरोली गूजर गांव है, इन गांवो में कटान हो जाता है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, थोड़ी सी बात और रह गयी है कि इन गांवों को बाढ़ से बचाने के लिये चेक डैम या कटान बांध बनाये जायें। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरे यहां एक बहुत बड़ी समस्या है, हमारे यहां

अकोला विकास खण्ड एक बहुत बड़ा ब्लाक है। वहां पर क्षेत्रीय लोग बहुत दिनों से तहसील बनाने की मांग कर रहे हैं, माननीय राजस्व मंत्री जी बैठे हुये हैं लोग इसके लिये समय–समय पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, समय–समय पर जन आन्दोलन कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि अकोला विकास खण्ड को तहसील बनाया जाय।

श्री अधिष्ठाता–

बाकी सुमन जी आप मंत्री जी को लिखकर दे देना ।

श्री काली चरन सुमन–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारे यहां एक और बहुत बड़ा जन आन्दोलन चल रहा है, हमारे आगरा में एन0टी0पी0सी0 है, विभाग के लोगों ने तार और खंभे लगाने के नाम पर वहां के किसानों की जमीन को ले लिया है और जमीन का मुआवजा भी आज तक नहीं दिया गया है। वहां भारतीय किसान यूनियन के माध्यम से वहां के लोगों ने आन्दोलन किया है और हम लोगों के खिलाफ झूठी रिपोर्ट लिखाई जा रही है। मेरी आपके माध्यम से मांग है कि उन किसानों को जमीन का मुआवजा दिया जाय और आपको बहुत–बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

श्री शारदा प्रताप शुक्ला–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, विपक्ष के लोगों को सरकार के द्वारा राजधानी और प्रदेश में जो अच्छे कार्य किये जा रहे हैं वह इनको अच्छे नहीं लगते और इनको दिखाई भी नहीं पड़ते। लखनऊ शहर में मेट्रो जैसा साधन, जो कि मेरे क्षेत्र से शुरू होता है, माननीय मुख्य मंत्री जी ने दिया। जैसे कल बसपा के लोग कह रहे थे कि यह हमारी योजना थी अरे आपकी योजना थी तो आप बनवाये होते लेकिन काम हमारे नौजवान मुख्य मंत्री ने शुरू किया। साथ ही लखनऊ आगरा एक्सप्रेस–वे जब बनने की स्थिति आई तो मान्यवर, हमारे क्षेत्र के किसानों की जमीन की कीमत 4 लाख बीघे और मलिहाबाद क्षेत्र के किसानों की कीमत 12 लाख रुपये और मेढ़ से मेढ़ मिली हुयी, जब किसानों ने मुझको यह बताया तो हमने इस पर आपत्ति की, तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि हम इस प्रकरण को देखेंगे। सहगल साहब ने भी कहा, मैं लास्ट में जब मिला तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि न 4 लाख न 12 लाख बल्कि 50 लाख बीघे हम जमीन की कीमत देंगे। सारे के सारे काश्तकारों ने इसे स्वीकार कर लिया और किसानों ने अपनी जमीन स्वतः देना शुरू कर दिया। मान्यवर, समाजवादी बलिया एक्सप्रेस–वे, वह भी हमारे ही क्षेत्र से शुरू हो रहा है, जिसे माननीय मुख्य मंत्री जी ने समाजवादी बलिया एक्सप्रेस–वे का नाम दिया है। इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम मेरी कांस्टीट्एन्सी में बन रहा है। मेंदाता अस्पताल मेरी कांस्टीट्एन्सी सरोजनीनगर विधान सभा क्षेत्र में बन रहा है। मान्यवर, लोक बन्धु चिकित्सालय जिसे माननीय हमारे नेता मुलायम सिंह जी ने मेरे अनुरोध पर दिया था, वह जब बनकर तैयार हुआ तो बसपा की सरकार ने काफी समय तक उसे बंद रखा और जब 2010 में हमने आन्दोलन किया तब वह खुला और जिसे माननीय मुख्य मंत्री जी ने बढ़ाकर 300 बेड का कर दिया है। आज

वह अस्पताल पूरी तरह बनकर तैयार है और माननीय मुख्य मंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी का इंतजार कर रहा है कि उनके द्वारा कब इसका उद्घाटन होगा। मान्यवर, पकरी का पुल माननीय लोक निर्माण मंत्री, माननीय सिंचाई मंत्री जी ने मेरे अनुरोध को स्वीकार करते हुये बनवाया और उसको खुलवाया। उसके चौड़ीकरण का सवाल है वह भी माननीय मंत्री जी मान गये हैं क्योंकि वहां जाम लगता है। कैंट और सरोजनी नगर दोनों इलाके के बाशिन्दों को उसका लाभ मिलेगा। मान्यवर, आप भी वहीं रहते हैं, आपने भी देखा है, नई तहसील हमारे राजस्व मंत्री जी ने इसी सदन में सरोजनी नगर को बनाने की घोषणा की और आज वह तहसील अपना काम कर रही है और उससे वहां के किसानों, नौजवानों, वकीलों और सभी को लाभ है, इनको यह दिखाई नहीं दे रहा है। मा0 अधिष्ठाता जी, कुछ खामियां हैं उनका भी मैं जिक्र करना चाहता हूं, जब मैं 1989 में एम0एल0ए0 था तब मैंने एस0टी0पी0 बिजनौर बनाने के लिए अनुरोध किया था वह स्वीकार भी हुआ था परन्तु वह तब तक कम्प्लीट नहीं हो पाया था। हमारे आशियाना का, हमारे दक्षिणी लखनऊ का जो सीवर है वह शहर में ही टहल रहा है, अगर एस0टी0पी0 बिजनौर बन जाए तो वह सई नदी में चला जायेगा। पूरे शहर में, दक्षिणी लखनऊ में अगर इसका सिस्टम सही कर दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा। मान्यवर, सेक्टर–एम और सेक्टर–एन अंसल ने बनाया था जब मैं 1986 में एम0एल0ए0 था तो अंसल यहां आया था और अंसल ने इस कॉलोनी का डेवलपमेंट किया। खजाना मार्केट का शिलान्यास 1986 में हुआ था और तब से 26 साल तक खजाना मार्केट का जो अधिकार था जो व्यापारियों का हक था वह उनको नहीं मिल रहा था, उनकी रजिस्ट्री नहीं हो रही थी। मैं अपने मा0 मंत्री डा0 शिव प्रताप यादव को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने हमारे साथ दौरा करके और एल0डी0ए0 को बुला करके खजाना मार्केट के व्यापारियों को उनका मालिकाना हक दिलवाया और उनकी रजिस्ट्री कराई। मान्यवर, इतना ही नहीं सेक्टर–एम और सेक्टर–एन, 497 लाख रुपए अवस्थापना में एल0डी0ए0 के वी0सी0 ने रिकमेन्ड करके शासन को भेजा है अगर 497 लाख रुपया दे दिया जाए तो सेक्टर–एम और सेक्टर–एन के जो बासिन्दे हैं उनको सड़क मिल सकती है और पार्क मिल सकता है। मान्यवर, बड़ी स्थिति खराब है, सड़क बनी है परन्तु सड़क नहीं है, पार्क नहीं है, सांप और बिच्छू वहीं निवास करते हैं इसलिए मेरा अनुरोध है कि शासन उस 497 लाख रुपए को स्वीकार कर ले और साथ ही मेरा यह भी अनुरोध है मा0 नगर विकास मंत्री जी नहीं हैं, मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस आशियाना कॉलोनी को नगर निगम को ट्रांसफर कर दें क्योंकि अंसल पकड़ में आता नहीं, वह दिल्ली में रहता है अगर अंसल के खिलाफ मुकदमें कायम हुए तो उनका एक कारिन्दा बन्द हुआ और उसके बाद उसकी जमानत भी हो गई। अरे आप अंसल को पकड़ करके बन्द कर दीजिए तभी अंसल सही हो जायेगा। मान्यवर, आशियाना कालोनी की बड़ी दुर्दशा है जिसे आप स्वयं जानते हैं क्योंकि आप स्वयं भी वहीं से आते हैं इसलिए मैं चाहता हूं कि इस कॉलोनी को नगर विकास विभाग को हस्तान्तरित कर दिया जाए। मा0 अधिष्ठाता महोदय, हमारे मुख्य मंत्री और हमारी सरकार जलसंचयन के लिए जागरुक है, हमारे क्षेत्र

में तमाम तालाब थे उनमें लोगों ने कब्जा कर लिया और उसमें बड़ी–बड़ी अट्टालिकाएं बन गई हैं। मान्यवर, मैं बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं।

'श्री सतीश महाना –

मान्यवर, वैसे पड़ोसी का हाल आप अच्छा रख लेते हैं इसके लिए आपको धन्यवाद्। मान्यवर, बजट किसी भी सरकार का आइना होता है, लोकतन्त्र में पहले प्लानिंग उसके बाद एलोकेशन और उसके बाद उसकी मॉनीटरिंग। मान्यवर, एक व्यवस्था है बजट बनाने की, उसे बना देने के बाद सरकार भूल जाती है, पिछले चार सालों से ऐसा देखने में आ रहा है। बजट एलोकेशन के बाद कभी भी उसकी मॉनीटरिंग नहीं होती इसका यह प्रत्यक्ष प्रमाण है कि फरवरी, मार्च आ गया है और अधिकांश बजट की मदों में पैसा अभी तक जिलों को नहीं दिया गया है। हर चीज में राजनीति को जोड़ कर यह कह देना कि भारत सरकार नहीं कर रही है यह केवल इसलिए है क्योंकि ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आज भी जिन योजनाओं के बारे में ये कहते हैं कि हमने बहुत अच्छा किया है यदि भारत सरकार का उसमें सहयोग न हो तो ये उनमें भी शून्य हैं। मैं कुछ आंकड़े बजट के देना चाहता हूं जो आदरणीय मुख्य मंत्री श्रीमान अखिलेश यादव ने यहां पर चार सालों में प्रस्तुत किये हैं। वर्ष 2013–14 में 2 लाख 15 हजार करोड़ रुपए का बजट था जिसमें केन्द्रांश 68 हजार 458 करोड़ का था। अब जो 2016–17 में बजट पेश किया गया है, मैं बजट की किताब में जो लिखा है वही पढ़ रहा हूं इसके अतिरिक्त अन्यत्र से कोई आंकड़े प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं। 2016–17 में 3 लाख, 46 हजार करोड़ रुपये का बजट कहकर कि हमने 14 प्रतिशत बढ़ा दिया है, यह बात बड़े जोर–शोर से कही जा रही है तो 2013–14 से इन तीन सालों के अन्तर्गत जब भारत में एक नई सरकार बनी है जिसने कहा है कि प्रदेश तरक्की करेंगे तब देश तरक्की करेगा और हम सबको साथ ले करके चलेंगे। इस वर्ष 1,05637 करोड़ रुपये का एलोकेशन जो सेण्ट्रल टैक्सेस का था वो स्टेट गवर्नमेण्ट को मिला है। लगभग 40 हजार करोड़ रुपया पिछले तीन सालों में इनको बढ़ाकर मिला। यह जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसके आंकड़े के हिसाब से मैं बोल रहा हूं, एक भी अंतर हो तो आप खड़े होकर कह सकते हैं कि वो नहीं है। आपने कहा कि हमने 14 प्रतिशत पिछले वर्ष से बजट बढ़ा दिया। आपने 2015–16 में जो बजट 3,02,000 करोड़ रुपये का था और 2016–17 में 3,46,000 करोड़ रूपये का था आपने कहा कि हमने 14 प्रतिशत धनराशि बढ़ा दिया। भारत सरकार ने पिछले वर्ष जो केन्द्रांश दिया था वो 86 हजार करोड़ रुपये था जिसको 1,05,000 करोड़ कर दिया, लगभग 30 प्रतिशत बढ़ाया है। गवर्नमेण्ट ऑफ इण्डिया आपको 30 प्रतिशत बढ़ाकर दे रही है उसी को आप बढ़ाकर कह रहे हैं कि हमने बहुत काम कर दिया। मान्यवर, तेरहवें वित्त आयोग के अंतर्गत जिस विकास की आप बात करते हो, जिस विकास के बारे में मा0 नगर विकास मंत्री जी ने कहा कि हमने जितना पैसा अबकी बार स्थानीय निकायों को दिया इससे पहले कभी भी नहीं दिया गया। तो मान्यवर, दो मदों के अंतर्गत तेरहवें वित्त आयोग और चौदहवें वित्त आयोग में मैं अंतर बता देता हूं। नगरीय विकास के लिए तेरहवें वित्त आयोग में 3130.9 करोड़ रुपया दिया गया और

---

*oDrk us Hkk"k.k dk iquohZ{k.k ugha fd;kA

चौदहवें वित्त आयोग में जब हमारी सरकार बनी तो मैं नगरीय विकास की बात कर रहा हूं 3130.9 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10249.21 करोड़ रुपया कर दिया गया लगभग साढ़े तीन गुना उसको बढ़ा दिया गया, इसीलिए तो पैसे दे रहे हैं अपने पास से कहां दे रहे हैं और कहते हैं कि गवर्नमेण्ट ऑफ इण्डिया कुछ देती नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए तेरहवें वित्त आयोग के अंतर्गत जो ग्राम प्रधान के द्वारा विकास किया जाना है, जो सड़क बनानी है, पानी की व्यवस्था करनी है वहां के लिए मान्यवर, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए तेरहवें वित्त आयोग में 9824.08 करोड़ रुपया दिया जाता था वह भारत सरकार ने इस वर्ष बढ़ाकर 35,776 करोड़ रुपया कर दिया। तो लगभग साढ़े–तीन चार गुना ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के मद में बढ़ा दिया और लगभग साढ़े–तीन चार गुना शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए बढ़ा दिया। इतना पैसा बढ़ाने के बाद मिला क्या? अगर सारे बैठे हुए माननीय सदस्य यहां पर कह दें कि हमें 100 हैण्डपम्प दे दो तो उसका उत्तर मिलता है शून्य, अर्थात नहीं देंगे। विकास बहुत हो रहा है, ये सब लोग जानते हैं और यह सत्य है जैसा माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट में भी लिखा, मैं उस बात को पढ़ना चाहता हूं। उन्होंने लिखा कि इस वर्ष प्राकृतिक कारणों के कारण समस्या हुई, किसानों को भी समस्या हुई। सूखे के कारण यह स्वभाविक है कि जब सूखा पड़ा तो भू–गर्भ जल नीचे चला गया, हैण्ड पम्प नये लगाने की बात करते हैं तो सरकार कहती है कि मानक के अनुरुप हैण्डपम्प लगे हुए हैं 100 मीटर, 50 मीटर, 75 मीटर के ऊपर जो भी उनका मानक है उसको गिना देते हैं। मैं माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि भू–गर्भ जल ही नीचे चला गया, अण्डर ग्राउण्ड वाटर की सतह नीचे हो गयी तो जो हैण्डपम्प लगे हुए थे वो सारे के सारे टूट हो गये। आप नये हैण्डपम्प नहीं दे सकते हो तो कम से कम दो–दो सौ हैण्डपम्प रि–बोर के लिए आप घोषणा जरूर कर देते, वह भी आपने नहीं किया है, कहां और कौन से मद में किया है, कौन से पेज पर किया है ? पीने का पानी आप देंगे नहीं, पानी के ऊपर आप राजनीतिक बात करेंगे। पिछले चार सालों से कहा जा रहा है कि नगरीय क्षेत्रों के अंतर्गत हम हैण्डपम्प तो नहीं देंगे हम पानी की लाइन बिछा देंगे, ओवरहेड टैंक दे देंगे। पता नहीं कहां पर ओवर हैड टैंक दिये ? आपने कहा था कि जो आपसे पहले वाली सरकार बहुजन समाज पार्टी की थी उन्होंने ऐसे ओवरहेड टैंक खड़े कर दिये जो हवा चलती है तो हिलते हैं, उनको गिरा दिया जायेगा। चार साल हो गये आपने उनको गिराया भी नहीं और उनको चालू भी नहीं किया या तो आप उनको चालू कर देते या आप उनको गिराकर नये बनाते। अगर इन्होंने गलती की थी तो आपने उसके ऊपर पर्दा डालने का काम किया लेकिन ठीक करने का काम नहीं किया। ठीक आप करेंगे नहीं, पानी आप देंगे नहीं। इण्डस्ट्री को बढ़ाने की आप बात करेंगे और इण्डिस्ट्रलिस्ट को चोर कहेंगे, आप कैसे इण्डस्ट्री बढ़ायेंगे ? इण्डस्ट्री को बढ़ाने की बात करेंगे आप लॉ–एण्ड–ऑर्डर ठीक नहीं कर पायेंगे इन्डस्ट्री को बढ़ाने की बात करेंगे आप इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं दे पायेंगे। मैं आपके माध्यम से माननीय अधिष्ठाता महोदय सरकार को यह जो पानी वाली समस्या है, उससे सब लोग सहमत होंगे। (सत्ता पक्ष से किसी सदस्य के बोलने पर) मेरा ख्याल है यह शुरू में नहीं थे मान्यवर, जब मैंने

भाषण शुरू किया या सो रहे होंगे। मैंने शुरूआत ही वहां से करी थी। (सत्ता पक्ष से टिप्पणी करने पर)

श्री अधिष्ठाता–

शांत रहिये भाई। महाना जी खत्म करिये। महाना जी बहुत सारे मेम्बर्स हैं।

श्री सतीश महाना–

मैं मना थोड़ी कर रहा हूं। उनको अवसर दीजियेगा। वैसे जब यह लोग बोलते हैं तो इधर वाले लोग कहते हैं कि मत बोलो। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज विकास की बात हो रही है। आपने कहा था कि हम लोहिया ग्राम के अन्तर्गत सारे माननीय विधायकों की संस्तुति से 5–5 गांव करेंगे। हां यह हुआ जरूर होगा मुझे नहीं लगता कि यहां पर हुआ है। मान्यवर, जिस समय विकास की बात हो आप वोट को ध्यान में रखकर विकास करेंगे। जब भी कोई भी सरकार (शोर) आप लोग बोलिये। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी सरकार हो, जो भी से मतलब जो भी सरकार हो अगर वोट को ध्यान में रखकर विकास करेगी तो न प्रदेश का भला कर पायेंगें न प्रदेश की जनता का।

श्री अधिष्ठाता–

चलिये अब समाप्त करिये महाना जी।

श्री सतीश महाना–

अधिष्ठाता जी, समाप्त तो इन्होंने कर ही दिया।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त नहीं, आप भाषण बंद करिये।

श्री सतीश महाना–

वैसे समाप्त तो हो ही रहे हैं। मन की बात वहां बैठकर नहीं करनी चाहिए मान्यवर, अलग कर लिया करिये।

श्री अधिष्ठाता–

चलिये भाषण क्यों कर रहे हैं बाद में बात कर लीजियेगा।

श्री सतीश महाना–

आपकी बात को मानते हुए जैसा हमारे माननीय सदस्यों ने बोला कि कानपुर महानगर के लिये जिस इन्फ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है जिस मेट्रो को आपने सिर्फ शिलान्यास करने के लिये 50 करोड़ रूपये दिये हैं। 13 हजार करोड़ में अगर सिर्फ 50 करोड़ दिये जायं तो उससे मंशा स्पष्ट नहीं होती। कानपुर महानगर के लिये मान्यवर, कम से कम पीने के पानी की व्यवस्था करायें। गंगा के तट के ऊपर प्यासे महानगर को आप अगर पानी दे देंगे तो हम सरकार को धन्यवाद देंगें।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करिये।

श्री सतीश महाना–

समाप्त तो होना ही होना है मान्यवर।

'श्री फेरन लाल–

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे माननीय मुख्य मंत्री जी के बजट पर अपनी बात रखने का मौका दिया है उसके लिये आपको धन्यवाद देता हूं। मैं अपने आप को नेता विरोधी दल माननीय स्वामी प्रसाद मौर्या जी से सम्बद्ध करते हुए अपनी बात रखना चाहता हूं। माननीय अधिष्ठाता जी, अभी इस बजट पर हमारे तमाम माननीय साथियों ने हिस्सा लिया। जहां विपक्ष के सदस्यों ने इस बजट को जन विरोधी और चुनावी बजट बताया वहीं सत्ता पक्ष के लोगों ने जन कल्याणकारी और वृहत बजट बताकर इसकी तारीफ की है। माननीय अधिष्ठाता जी, बात महत्वपूर्ण यह नहीं है कि बजट कितना बड़ा है या बजट कितना छोटा है। बात महत्वपूर्ण यह है कि बजट में मूलभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया है कि नहीं रखा गया है। माननीय अधिष्ठाता जी, मैं सरकार की आलोचना करने के लिये नहीं खड़ा हुआ हूं। मेरा उद्देश्य है कि बजट में जो भी कुछ खामियां हैं, खामियां बजट कोई भी बनाये उसमें खामियां हो सकती हैं। सर्वज्ञाता कोई नहीं है दुनिया में, तो यह लोकतंत्र की स्वस्थ परम्परा भी है कि सत्ता पक्ष विपक्ष के कुछ सुझावों को समझे और गम्भीरतापूर्वक उनको सुन करके आवश्यकता हो तो उसमें सुधार भी करे। माननीय अधिष्ठाता जी, कृषक दुर्घटना बीमा, देश के जो अन्नदाता हैं जो हमारा किसान है, जो देश की 80 प्रतिशत हमारी आबादी खेती करके जीवन यापन करती है और खेती से उसकी आजीविका चलती है। मान्यवर, किसान के बेटा के साथ यह दोहरा मापदंड अपनाया जाता है। यह बड़े दुख की बात है कि जब किसी किसान का बेटा जब भूमि प्रबन्धक समिति गांव में पट्टे डालती है तो वह आवेदन करता है कि हमें पट्टा आवंटित किया जाए तो लेखपाल लिखकर देता है कि तुम्हारे पिताजी के नाम दस एकड़ जमीन है और तुम दो भाई हो तो तुम्हारे हिस्से में पांच एकड़ होती है तुम पास नहीं हो, तुम्हें पट्टा आवंटित नहीं होगा, जब वही किसान का बेटा खेत में पानी लगाते समय कीड़ा काट लेता है मर जाता है एक्सीडेंट हो जाता है मर जाता है तो वही लेखपाल किसान की विधवा से कहता है कि तुम्हारे पति के नाम कोई जमीन नहीं थी तुम कृषक दुर्घटना बीमा की हकदार नहीं हो। माननीय अध्यक्ष जी, यह कैसा दोहरा मापदंड है जब वह पट्टा मांगता है तो सरकार कहती है कि तुम्हारे पिताजी के नाम जमीन है जब उस किसान के बेटे की मृत्यु हो जाती है तो सरकार कहती है कि तुम्हारे नाम कोई जमीन नहीं है तो मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि जिस भी किसान के पिताजी के नाम भूमि है तो उसको भी कृषक दुर्घटना बीमा का लाभ दिया जाए यह मेरा सरकार से अनुरोध है। माननीय अधिष्ठाता जी, माध्यमिक शिक्षा का जो बजट है इसमें 9.168 करोड़ का प्राविधान किया गया है और यह अत्यन्त महत्वपूर्ण विभाग है। चूंकि हमारी भावी पीढ़ी इससे प्रभावित होती है माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस बजट में नये विद्यालय खोलने का कहीं कोई जिक्र नहीं है तीन सैनिक स्कूल और 18 नये विद्यालय खोलने का जिक्र किया गया है। नये विद्यालय इण्टर कालेज, हाई स्कूल खोलने का कहीं कोई जिक्र नहीं है जबकि माननीय अधिष्ठाता जी, पूरे प्रदेश की स्थिति यह है कि

---

*oDrk us Hkk"k.k dk iquohZ{k.k ugha fd;kA

जब भी बच्चे कक्षा आठ पास करके निकलते हैं उन्हें नाइन्थ में एडमीशन के लिए विद्यालय नहीं मिलता है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं मुझे पूरे प्रदेश की जानकारी नहीं है मैं अपनी विधान सभा क्षेत्र की बात बताना चाहता हूं मेरी विधान सभा क्षेत्र में 240 के लगभग जूनियर हाई स्कूल हैं जिससे लगभग 17000 बच्चे जूनियर हाई स्कूल पास करके निकलते हैं और केवल 15 शासकीय अशासकीय हाई स्कूल इण्टर कालेज हैं जिनमें अधिकतम 1500 बच्चे नाइन्थ में एडमीशन ले पाते हैं और लगभग पन्द्रह सोलह हजार बच्चे या तो प्राइवेट पद्धति पर शिक्षा अध्ययन करते है या फिर घर बैठ जाते हैं मेरा सरकार से अनुरोध है आपके माध्यम से इस बजट में मेरे विधान सभा क्षेत्र महरौनी में ग्राम तेलगवॉ विकास खण्ड में एक राजकीय इण्टर कालेज और ग्राम भानपुर विकास खण्ड बाढ़ में एक राजकीय बालिका इण्टर कालेज ग्राम कालीटोला विकास खण्ड मरौरा में एक राजकीय इण्टर कालेज ग्राम बालारोड ब्लाक दुगधा में एक राजकीय इण्टर कालेज, ग्राम धौरवां में एक राजकीय इण्टर कालेज खोला जाए क्योंकि यह ग्राम पांच से दस हजार की आबादी के हैं। पचास गांव का एक सेन्टर प्वाइन्ट है इन गांव के आस–पास बीस किलोमीटर की दूरी में कोई सरकारी राजकीय इण्टर कालेज नहीं है। दूसरी बात माननीय अधिष्ठाता जी मेरा क्षेत्र मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है और 80 प्रतिशत या तो पथरीला एरिया है या जंगली क्षेत्र है आज तक सरकार ने चार साल के दौरान एक भी रोड नहीं बनाई है। मैंने कई बार निवेदन भी किया और लिखा भी है बुंदेलखण्ड से पता नहीं क्यों नाराज हैं, बुन्देलखण्ड से इनके कितने विधायक जीते इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। चूंकि जनता आपकी भी है और हमारी भी है,आपकी सरकार है आपको सम दृष्टि से देखना चाहिए। मैं अनुरोध करना हूं कि वाल से ...

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें।

श्री फेरन लाल–

बानपुर तक रोड बना दिया जाए महरौनी मुख्यालय से बाया सेंगुआ मरौहड़ा तक रोड बना दिया जाए नाला से महरौनी तक रोड बना दिया जाए और पेयजल की जो समस्या है, मुझे याद है कि कभी भी ऐसा समय नहीं आया कभी भी बुन्देलखण्ड के लोगों को रोटी के लिए तो पलायन करना पड़ा लेकिन अध्यक्ष जी यह ऐसा काला वर्ष है कि इस बार पीने के पानी के लिए लोगों को गांव से पलायन करना पड़ा और वह या तो जिला मुख्यालय जा रहे हैं या लखनऊ जा रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें।

श्री फेरनलाल–

मेरा आपसे आग्रह है कि कम से कम जो महाना जी ने हैण्ड पम्प की मांग की थी 200–200 हैण्ड पम्प प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में विधायकों को दिए जाएं ताकि जनता के पीने की समस्या हल हो सके। धन्यवाद।

महिला कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा)–

अधिष्ठाता महोदय आपने मुझे वित्तीय वर्ष 2016–17 के बजट के पक्ष में बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपकी आभारी हूं। मैं बधाई देना चाहती हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को जिन्होंने प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा बजट 3,46,935 करोड़ का बजट प्रस्तुत किया जो पिछले वित्तीय वर्ष से लगभग 14.6 प्रतिशत अधिक था लेकिन मैं बधाई केवल इसलिए नहीं दे रही हूं कि यह सबसे बड़ा बजट है बल्कि बधाई इसलिए दी जा रही है कि समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चला गया है और सभी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया है चाहे वह किसान हों, युवा हों, नौजवान हों, महिलाएं हों या कोई भी व्यक्ति हो समाज के अन्तिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा था उसकी जरूरतों का पूरा पूरा ध्यान इस बजट में रखा गया है। बजट सिर्फ एक सरकारी दस्तावेज नहीं होता बल्कि बजट किसी भी सरकार की जो नीतियां होती हैं उसका वह आइना होता है इस बात का परिचायक होता है कि वह सरकार क्या सोचती है और इस नजरिए से हम अगर देखते हैं तो यह बजट वास्तव में समाजवादी सोच का आइना है विकासोन्मुखी है जनोन्मुखी है हालांकि बहुत से लोगों को इसमें कुछ नजर नहीं आया हम यही कह सकते हैं कि उन लोगों ने शायद ध्यान से इस बजट को नहीं देखा होगा। वरना इस बजट ने किसानों का भी ध्यान रखा है और सिर्फ कहने के लिए नहीं बल्कि करके दिखाया है कि समाजवादियों का यकीन इस बात पर रहता है कि हम सबको साथ लेकर चलें। चाहे वह किसी भी वर्ग के लोग हों हमारा यकीन इसमें है कि, ''हयात लेकर चलो, कायनात लेकर चलो, और चलो तो सारे जमाने को साथ लेकर चलो''–चलो तो सारे जमाने को साथ लेकर चलो इस जज्बे के साथ में वर्ष 2016–17 का बजट रखा गया है यह मैं इसलिए कह रही हूं कि सबसे अच्छी बात इस बजट की थी कि हमारी सरकार ने वर्ष 2016–17 को किसान एवं युवा वर्ष के रूप में घोषित किया है किसान और युवा वर्ष के रूप में मनाया जाएगा और यह इसलिए भी हम लोगों ने दिखाया कि जब पिछली बार सूखा पड़ा था और ओलावृष्टि हुई थी तो प्रदेश की सरकार ने सिर्फ ऐसा नहीं किया कि संसाधनों की कमी का रोना रोया हो बल्कि हमारे पास जो भी संसाधन थे उनसे किसानों की मदद की गई मैं बधाई देना चाहती हूं माननीय राजस्व मंत्री जी को माननीय मुख्य मंत्री जी को कि केन्द्र से हमें कोई सहायता नहीं मिली थी इसके बावजूद अपने संसाधनों से लगभग साढ़े चार हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद किसानों को पहुंचाकर दिखा दिया कि देने का जज्बा होना चाहिए अगर दे देनी की नीयत हो तो कभी भी संसाधनों की कमी आड़े नहीं आती है। इसके लिए मैं बधाई देना चाहती हूं अपने राजस्व मंत्री जी को इस सरकार में अभी सामने विपक्ष के लोग कह रहे थे बीमे की बात कर रहे थे मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहती हूं किसान बीमा दुर्घटना योजना जो थी उसके लिए 240 करोड़ रुपए का बजट में प्राविधान तो किया ही इसके साथ में आम आदमी बजट योजना भी रखी गई जिसके लिए 50 करोड़ रुपए थे और ग्रामीण अंचलों के वह लोग जो भूमिहीन हैं और 18 से 59 वर्ष की आयु वर्ग में आते हैं और परिवार के मुखिया हैं यदि उनकी मृत्यु हो जाए तो उनके परिवार को इस बीमे

का लाभ मिलेगा इसके लिए व्यवस्था इस सरकार ने की थी। इसी तरह से समाजवादी सर्वहित बीमा योजना चली जिसके लिए 897 करोड़ रुपए की व्यवस्था वर्तमान बजट में की गई और इसलिए यह व्यवस्था की गई कि सबको उसका लाभ मिल सके। पहले जब किसान बीमा योजना थी तो पांच लाख रुपया लोगों को मिलता था इस बार यह व्यवस्था की गई कि जिनकी मृत्यु हो जाती है। उनको पांच लाख रूपये मिलेंगे और जो गंभीर रूप से विकलांग हो जाते हैं, उनको भी पांच लाख रुपये मिलेंगे, जो दुर्घटना में घायल हो जाते हैं उनके लिये ढाई लाख रुपये की व्यवस्था थी और यदि कृत्रिम अंग लगवायेंगे तो एक लाख रुपये की व्यवस्था इस सरकार ने की है। सवाल यह है कि अगर कोई देखना न चाहे तो उसके लिये क्या कहा जा सकता है ? समाजवादी पेंशन योजना अत्यन्त सुन्दर व्यवस्था है और महिला सशक्तीकरण की दिशा में एक मजबूत कदम हैं, क्योंकि जो परिवार की महिला मुखिया हैं, उसको अधिकार दिये गये और पिछले वर्ष 45 लाख लाभार्थी इसमें शामिल हुये थे, जिसके लिये वित्तीय वर्ष 2015–16 में 2727 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी थी। हम लोग गर्व के साथ कह सकते हैं कि इस वर्ष में 45 के बजाय 55 लाख महिला लाभार्थी इससे लाभान्वित होंगी और जो बजट था उसको इस वर्ष बढ़ाकर 3327 करोड़ करके मा0 मुख्य मंत्री जी ने यह साबित कर दिया है कि अगर कोई वास्तव में किसानों का, युवाओं का, महिलाओं का हितैषी है तो वह समाजवादी सरकार है, क्योंकि यह वह सरकार है जो गांधी और लोहिया के सपनों को साकार करने का दम रखती है। मा0 अधिष्ठाता जी, मैं कुछ बातें कहकर अपनी बातें समाप्त कर देना चाहती हूं। ग्रामीण अवस्थापना के क्षेत्र में भी लगभग 2000 करोड़ रुपये खर्च करने की बात की गयी है। पानी की जो बात हो रही थी तो हम गर्व के साथ बता सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्था के लिये इस बजट में 2300 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। अगर 2300 करोड़ रुपये पेयजल के लिये रखे जा रहे हैं तो क्या विपक्ष एक छोटा सा धन्यवाद भी नहीं कर सकता है, लेकिन वहां का किस्सा यह है कि हम कुछ कहना ही नहीं चाहते। बात हो रही थी रोजगार की, तीन लाख से ज्यादा नौजवानों को कौशल विकास कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित किया गया और केवल इतना ही नहीं, औद्योगिक नीति की बात थी, जरा अपने गिरेबां में झांककर देखियेगा कि जब आपकी सरकार थी तो आप लोगों ने औद्योगिक विकास के लिये क्या किया ? एम0ओ0यू0 तो बहुत साईन हुये थे, बहुत हस्ताक्षरित हुये थे, लेकिन क्या एक भी पैसे का पूंजी निवेश हुआ ? हमारी सरकार ने न केवल एम0ओ0यू0 साईन किये हैं, आज हमारे प्रदेश में चाहे रिलायंस हो, एस्सेल हो, गेल हो, आई0टी0सी0 हो या फोर्टिस हो, यह सभी प्रतिष्ठित समूह यहॉ पर निवेश करना चाह रहे हैं। इस वजह से आज की तारीख में साढ़े बयालीस हजार करोड़ का निवेश औद्योगिक क्षेत्र में हुआ है, लेकिन देखने के लिये नजरें होनी चाहियें। मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं अपनी बात सिर्फ एक बात कहकर समाप्त कर दूंगी कि जो लोग अक्लियतों की बात करते थे, बातें तो बहुत हुईं, लेकिन अल्पसंख्यकों के हक के लिये आपने क्या किया था, इसका हिसाब कभी फुर्सत में बैठकर कर लीजियेगा, लेकिन हम लोगों ने जरूर किया है और छात्रों की छात्रवृत्ति जो

पूर्वदशम हैं उनके लिये 537 करोड़ रुपये की व्यवस्था इस बजट में की गयी है। इतना ही नहीं, दशमोत्तर छात्रों के लिये 153 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है और शुल्क प्रतिपूर्ति के रूप में 150 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। मदरसों के आधुनिकीकरण के लिये 394 करोड़ रूपये की व्यवस्था इस सरकार के द्वारा की गयी है।

'श्री रविन्द्र जायसवाल–

मा0 अधिष्ठाता महोदय जी, बौद्ध विद्यालय के लिये कुछ नहीं किया गया है, केवल मदरसों के लिये ही किया गया है। वाराणसी पर्यटन क्षेत्र हैं, वहां पर हजारों की संख्या में पर्यटक आते हैं, सारनाथ बौद्ध पर्यटन का क्षेत्र है।

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा–

हमें अपनी पूरी बात कह लेने दीजिये। आप अपराधों में बढ़ोत्तरी की बात करते हैं, हमारी सरकार ने 1090 हेल्पलाईन शुरू की है जिसके द्वारा साढ़े तीन लाख शिकायतों का निस्तारण हुआ है। इतना ही नहीं, आशा ज्योति केन्द्रों की स्थापना की जा रही है, जहां एक छत के नीचे सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसके अलावा 181 की शुरुआत की जायेगी ताकि महिलाओं को न्याय मिल सके। आशा ज्योति केन्द्र 11 जनपदों में चलाए जा रहे हैं। सरकार ने तो बहुत प्रयास किये हैं, हां यह जरूर है कि हमनें कभी मौसम की मार भी देखी है, कभी सूखा पड़ा, कभी ओला पड़ा, लेकिन उससे हम कभी घबराये नहीं हैं। चाहे खिजा का मौसम रहा हो या बहार का मौसम रहा हो, मजबूत इरादों के साथ समाजवादी सोच की सरकार आगे बढ़ती रही है, क्योंकि हमारा लक्ष्य आगे बढ़ने का था। हम आगे बढ़ते रहे हैं, कभी उससे घबराये नहीं हैं। उधर से बहुत तंज हुये पतवारों के ऊपर, कभी कहा गया पतवारें कमजोर, कभी कहा गया कि नाव डूब गयी तो कभी इंतजार था कि सरकार की नाव बीच भंवर में डूब जायेगी तो किसी ने साहिल पर डुबो दी। तो किसी ने साहिल पर डुबा दी, हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि 'हम डूब कर भी खैर से साहिल तक आ गए', तुम्हें लगा कि हम डूब रहे हैं लेकिन हुआ क्या वह तो देखो। 'हम डूब कर भी खैर से साहिल तक आ गए, मौजे बला ने देख लिया हौसले मेरे'। बहुत–बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।

श्री रविन्द्र जायसवाल–

मान्यवर, वाराणसी पर्यटन का बड़ा केन्द्र है। सारनाथ है, सारनाथ में लगभग 22 देशों के अलग–अलग मन्दिर बने हुए हैं। जान करके आश्चर्य होगा कि सारनाथ, वाराणसी नगर निगम सीमा के अन्दर है, वहां पर सीवर ही नहीं है। वाराणसी नगर निगम के अन्दर तीन ऐसे वार्ड हैं, 40 साल हो गए हैं, नगर निगम की सीमा में आए हुए, वहां पर सीवर नहीं है। सारनाथ, बौद्ध का जो बड़ा क्षेत्र है, वहां 22 देशों के मन्दिर बनाये गए हैं, वहां पर सीवर नहीं है, वहां आज भी मन्दिरों के अन्दर सोख्ता का इस्तेमाल किया जाता है। मेरी मांग है कि सारनाथ, तरना और लहरतारा में सीवर डाला जाए, वहां पर सोख्ता का इस्तेमाल होता है। देश–विदेश के तमाम वहां पर्यटक आते हैं, 22 देशों के वहां मन्दिर हैं। मान्यवर, वहां वरूना नदी है, गोमती नदी की तर्ज पर

---

*oDrk us Hkk"k.k dk iquohZ{k.k ugha fd;kA

उसकी लम्बाई भी लगभग 11 कि0मी0 है। मेरा सुझाव है कि इस बजट में चौका घाट, पुराना पुल, उर्दली बाजार, शास्त्री घाट, उन पर लगभग 11 कि0मी0 का पाथ–वे बनाया जाए, गोमती की तर्ज पर उसकी लम्बाई है और लखनऊ से अधिक वहां पर्यटक आते हैं। उन घाटों पर पक्का घाट नहीं है तो मेरी मांग है कि इस बजट में वरूना नदी पर, पुराना पुल पर, चौका घाट पर, पंचकोशी पर, इन चारों जगहों पर पक्के घाट बनाये जायें। मान्यवर, पूरा उत्तर प्रदेश हायर एजूकेशन में पिछड़ा है। आज लगभग 90 प्रतिशत पालिटीशियन, ब्यूरोक्रेट, व्यापारी इनके बच्चे उत्तर प्रदेश से बाहर पढ़ रहे हैं, बंग्लौर में, पूना में, हैदराबाद में। मान्यवर, उत्तर प्रदेश की यूनीवर्सिटीज में 12–12 लाख बच्चे पढ़ते हैं, वर्ल्ड रैंकिंग में उत्तर प्रदेश की कोई भी यूनीवर्सिटी 100 में नहीं आयी, 200 में नहीं आयी, 300 में नहीं आयी, 400 में नहीं आयी, 500 के अन्दर में उत्तर प्रदेश की यूनीवर्सिटीज की रैंकिंग आयी है। एक–एक यूनीवर्सिटी में 10–10 लाख विद्यार्थी हैं, उन यूनीवर्सिटीज में केवल प्रिंटिंग मशीन की तरह से सर्टीफिकेट बॉटे जा रहे हैं। मेरी मांग है, उत्तर प्रदेश की किसी भी यूनीवर्सिटी के अन्दर 100 से अधिक कालेज न हों और 01 लाख से ऊपर विद्यार्थी न हों, तब जा करके हम वर्ल्ड रैंकिंग में आ सकते हैं, वरना हमारी 500 की रैंक में भी कोई यूनीवर्सिटी नहीं आ रही है। मान्यवर, राजस्थान के अन्दर महिला यूनीवर्सिटीज भी हैं, सरकार की भी हैं और प्राइवेट भी हैं लेकिन उत्तर प्रदेश में एक भी महिला विश्वविद्यालय नहीं है। डिग्री कालेज के लिए इन्होंने मान्यता में छूट दे रखा है, 50 परसेण्ट, अगर महिलाओं का कालेज खुलेगा तो भूमि में 50 परसेण्ट की छूट है। मेरी मांग है कि प्राइवेट यूनीवर्सिटीज यदि बाहर से आती हैं, विदेश से आती हैं और महिला यूनीवर्सिटीज खोलते हैं तो भूमि में उनको छूट देना चाहिए। उत्तर प्रदेश में इस समय मात्र 22 प्राइवेट यूनीवर्सिटी हैं, जबकि महाराष्ट्र में 115 हैं, कर्नाटक में 48 से ऊपर हैं, कहीं न कहीं हमें मानक में भी ढील देना चाहिए ताकि वह यहां पर खुल सकें। हमारे यहां 22 यूनीवर्सिटी हैं लेकिन उनमें से पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक भी नहीं है। सारी यूनीवर्सिटियां पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हैं। मेरी मांग है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में इसको बढ़ावा देने के लिए भूमि में छूट देनी चाहिए कि 100 एकड़ की जगह इसको 10 एकड़ रखा जाए। मान्यवर, वाराणसी पर्यटक का बड़ा केन्द्र है, स्मार्ट सिटी के लिए भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ रुपया प्रति स्मार्ट सिटी, 24 करोड़ रुपया एक सितम्बर को जारी किया ताकि वहां पर एवेयरनेश हो सके। अलग–अलग कम्पनियों ने अलग–अलग विट लिया था, बिल्ड कॉम कम्पनी ने लिया था बनारस के लिए, 24 करोड़ रुपया भारत सरकार ने दिया था, एक सितम्बर को लेकिन प्रदेश सरकार ने वह पैसा जिले को भेजा ही नहीं। अगर स्मार्ट सिटी में उत्तर प्रदेश नहीं आया है तो उसके पीछे प्रदेश सरकार रही है क्योंकि इनकी नीति थी, सिद्धान्त था कि 500 करोड़ रुपया भारत सरकार देगी और 500 करोड़ रुपया प्रदेश सरकार देगी, लेकिन इनके बजट में स्मार्ट सिटी के लिए रखा गया केवल 168 करोड़ रुपया, जबकि 12 सिटी में होता है, 06 हजार करोड़ रूपया। इनकी नीयत स्मार्ट सिटी के लिए ही नहीं थी। 02 करोड़ रुपया प्रति सिटी अर्वेनेस के लिए, वह पैसा 01 सितम्बर को जारी किया गया था, वह पैसा

प्रदेश सरकार ने जिलों को भेजा ही नहीं, इसलिए पूरे उत्तर प्रदेश में स्मार्ट सिटी गायब हो गया। जब यह दिया पैसा नहीं देंगे तो 500 रुपया प्रति शहर यह क्या देंगे। मा0 अधिष्ठाता जी, इसके अलावा हमारे मा0 आजम खां जी यह बयान देते हैं कि बनारस में क्या किया गया है, मैं बताना चाहता हूं केवल रोड के लिए परिवहन मंत्रालय ने 4880 करोड़ रूपये दिया, बनारस से सुल्तानपुर, बनारस से गाजीपुर, बनारस से आजमगढ़, बनारस से गोरखपुर फोर लेन दिया था, फिर उसके बाद बनारस में कचहरी से सारनाथ 1600 करोड़ रुपया उसके अलावा रिंग रोड के लिए 6200 करोड़ रुपया, फिर उसके अलावा आई0पी0जे0एफ0 ऊर्जा मंत्रालय ने दिया था 6048 करोड़ रुपया, इसमें 2/8 पूरी अण्डर ग्राउण्ड पार्क करनी थी, पैसा देख कर खाली काम शुरू नहीं किया उत्तर प्रदेश के विभाग के लोगों ने, उसी प्रकार से एल0ई0डी0 36070 शहर के अन्दर एल0ई0डी0 लाइट दिया गया, जो नगर निगम की सोडियम लाइट थी उनको हटा कर के लाईट लगाई जा रही है, मेरी मांग है कि जो 36 हजार लाइट वहां से हटाई जा रही हैं सोडियम वाली उनको वहां लगाया जाय जहां अभी तक लाइट नहीं लगाई गई हैं।

श्री अधिष्ठाता–

मा0 जायसवाल जी समाप्त करिये।

श्री रवीन्द्र जायसवाल–

मा0 अधिष्ठाता जी, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, मान्यवर मेरी मांग है, पूरे बनारस के अन्दर कई ऐसी कालोनियां हैं जहां अभी भी नगर निगम के अन्दर होने के बावजूद न सीवर है, न पानी है, न वहां पर नाली है ऐसे तमाम कालोनी के नाम शास्त्री घाट पर है, दुर्गा बिहार है, नवल नगर है, बसई है इन तमाम जगहों पर अभी भी सुविधा नहीं है। मान्यवर, बनारस में लकड़ी खिलौना बनता है, उसके अलावा हमारे यहां साड़ी वाले बुनकर हैं, साड़ियों के बुनकर के लिए आपने योजना दिया है फिक्स रेट पर बिजली 50 रुपये महीने पर, उसी प्रकार से लकड़ी कारीगर हैं उनको भी यह सुविधा मिलनी चाहिए, 50 रुपये प्रति महीने पर उनको मिलना चाहिए क्योंकि वह खराब को मशीन पर साफ करते हैं, जबकि आप केवल साड़ी वाले कारीगरों को दे रहे हैं। मान्यवर, मेरी मांग है कि बनारस के अन्दर पानी के लिए सुविधा नहीं है, वहां पर तीन ट्यूब्वेल पाण्डेयपुर के अन्दर हुकुलगंज के अन्दर सारनाथ में लगाये जांय क्योंकि 01 अरब 91 करोड़ रूपये में जे0एल0एन0यू0आर0एम0 की योजना के तहत 16 पानी टंकी बनाई गई थीं, उसमें एक बूंद पानी वहां नहीं मिल पा रहा है, जो टंकियां हैं वह चू रही हैं, जो पाईप है वह लीकेज है, 2009 की योजना थी, ये और ये मिलकर के एक ये यू0पी0ए0 सरकार इन तीनों लोगों ने मिल कर के पूरी की पूरी योजना का बंटाधार कर दिया है, एक बूंद पानी वहां पर नहीं मिला है, इसलिए मांग करता हूं कि वहां पर सप्लाई के लिए 03 ट्यूबवेल वहां पर तत्काल लगाये जाने चाहिए।

श्री अधिष्ठाता–

मा0 जायसवाल जी कृपया अब समाप्त करें।

श्री रवीन्द्र जायसवाल–

मान्यवर, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक ऐप चला है मेडिकल टूरिज्म मेरी मांग है कि सरकार ने अच्छा काम किया है कि पहली बार वह पर्यटन को उद्योग नीति में ले आये हैं, इसके लिए सरकार को मेरी ओर से बधाई है, साथ ही एक सुझाव भी है कि मेडिकल टूरिज्म और कल्चर टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाय, ताकि गांवों का जो हमारा कल्चर है, जो हमारे तीज–त्योहार हैं उनको भी देखने के लिए पर्यटक आयें, बहुत–बहुत धन्यवाद।

'श्री रामलाल अकेला–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मा0 मुख्य मंत्री जी ने वर्ष 2016–17 का जो बजट सदन के अन्दर प्रस्तुत किया है, उसके समर्थन में आपने बोलने का अवसर दिया, मैं इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं, मान्यवर सामने के साथी हमारे तमाम किसानों के बारे में, प्रदेश के विकास के बारे में, तमाम चर्चा कर रहे थे, मैं इनको सिर्फ एक बात बताना चाहता हूं कि चाहे हमारे बसपा के साथी हों या भाजपा के साथी हों, दोनों भाई–भाई हैं और आप लोगों ने जब उत्तर प्रदेश में सरकार चलाई थी, तो किसानों की जो दुर्दशा किया था, उसको भी किसान याद कर लेता है तो रूह कांप जाती है। आपने खाद के नाम पर, आपने एक–एक बोरी खाद के लिए किसानों के ऊपर लाठियां चलाने का काम किया और हमारी सरकार ने हमारे मंत्री हमारे सहकारिता मंत्री जी ने शपथ लेने के बाद सबसे पहले यह ऐलान कर के कहा ऐ उत्तर प्रदेश के किसानों, पिछली सरकार में खाद के नाम पर जो तुम्हारी दुर्दशा हुई थी, अब सत्ता समाजवादियों के हाथ में है और खाद के लिए किसानों को कभी लाइन नहीं लगानी पड़ेगी। इतना स्टोरेज किया है हमारी सरकार ने, कि किसानों को कहीं पर भी खाद के लिए लाइन नहीं लगानी पड़ी। मान्यवर, आपकी सरकार ने सिंचाई वसूली के नाम पर अमीन, तहसीलदार, लेखपाल किसानों को दौड़ाता था। तहसील की जेलों में बंद करने का काम करता था। उनका उत्पीड़न करने का काम करता था। तब आपको किसानों का दर्द याद नहीं आया। अगर किसान का यह दर्द किसी ने पहचाना है तो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने पहचाना है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के किसानों को, चाहे वह नहर से खेतों को सींचने का काम करें, चाहे सरकारी नलकूप से सींचने का काम करें, एक नया पैसा किसी किसान से नहीं वसूला जायेगा। पूरी की पूरी सिंचाई हमारी सरकार ने मुफ्त में करने का काम किया है, और आज पूरा किसान फ्री में खेतों को सींचने का काम करता है। मान्यवर, यही नहीं आप किसान बीमा की बात करते हो, हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव ने अपने नेतृत्व में, अपने मुख्य–मंत्रित्वकाल में किसानों का बीमा एक लाख रुपया किया था। आपने इतने दिन सरकार चलायी, आपने दस रूपया बढ़ाने का काम नहीं किया। जब दोबारा हमारी सरकार आयी तो हमने एक लाख को बढ़ा करके, पांच लाख करने का काम किया है। आज पूरे उत्तर प्रदेश का किसान इस बात को महसूस करता है कि किसानों की हमदर्द सरकार कौन है। मान्यवर, गरीबों के बारे में, आपने रिक्शा चालकों के बारे में कभी सोचा था ? हमारी सरकार ने

---

*oDrk us Hkk"k.k dk iquohZ{k.k ugha fd;kA

रिक्शा चालकों को बैट्रीयुक्त रिक्शा दे करके एक ऐतिहासिक काम किया है। आपने आवास के नाम पर गरीबों को, हमने लोहिया आवास तीन लाख की लागत के ऊपर का आवास दिया और वह आवास नहीं दिया, आवास के नाम पर हमने लोगों को घर देने का काम किया है। आपने एक कमरा दिया था, हमने तीन लाख का आवास गरीबों को देने का काम किया है। समाजवादी पेंशन योजना, यह तमाम सारे कार्यक्रम हमारी सरकार ने चलाने का काम किया है। आपको पता है, आपके जमाने में नहरों में धूल उड़ा करती थी। नहर में पानी नहीं दिखायी पड़ता था। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपनी सरकार को, अपने सिंचाई मंत्री जी को, कि आपके इस सरकार में आने के बाद दो–दो बार, चाहे रबी की फसल हो, चाहे खरीफ की फसल हो, दोनों बार नहरों में आपने सिल्ट की सफाई करा करके और हेड से टेल तक पानी पहुंचा करके आपने ऐतिहासिक काम करने का काम किया है। यही नहीं किया, गांव में जिन सड़कों का हाल आपने छोड़ा था, पूरे प्रदेश की सड़कें खस्ताहाल हो गयी थीं, पूरे प्रदेश की सड़कें गड्ढों में तब्दील हो गयी थी। वह पैसा जो सड़क में लगना चाहिए था, जो बिजली में लगना चाहिए था, जो किसान बीमा में लगना चाहिए था, जो कालोनी में लगना चाहिए था, वह पैसा आपने कहां लगाया है ? आप यह नहीं बताएंगे कि वह पैसा पत्थर में लगा दिया। वह पैसा आपने कहां लगा दिया, आप जरा बेहतर जानते हो, लेकिन आपको सच्चाई दिखायी नहीं पड़ती। सरकार आने के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में अभियान चला कर, हमारी सरकार ने, हमारे मुख्य मंत्री जी ने हमारे लोक निर्माण मंत्री जी ने एक अभियान चला कर अधिकारियों को निर्देश दिया कि अगर किसी सड़क में गड्ढा मिलेगा तो उस अधिकारी की खैर नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश में कितने बड़े–बड़े पुलों का निर्माण कराया, छोटे पुलों का निर्माण कराया, सड़कों का जाल बिछाने का काम किया और जो ग्रामीण सड़कें थीं, उन सारी सड़कों को गड्ढामुक्त करने का काम हमारी सरकार ने किया है। आपको किसानों के बारे में पता नहीं है, गांव की सड़क ठीक नहीं होगी।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय अकेला जी, समाप्त करिए।

श्री रामलाल अकेला–

मान्यवर, अभी तो हमने शुरू नहीं किया है।

श्री अधिष्ठाता–

शुरू नहीं, आप समाप्त करें। बहुत लोग हैं। अध्यक्ष जी, लम्बी लिस्ट दे गए हैं।

श्री रामलाल अकेला–

मान्यवर, ठीक है, समाप्त कर रहा हूं। एक बात शायद आपको याद नहीं है, जब गांव का रास्ता ठीक नहीं होगा, गांव की सड़क ठीक नहीं होगी तो किसान की पैदावार की लूट होगी। यह सोच केवल हमारी सरकार, हमारे नेताओं के पास है। इसीलिए सरकार बनने के बाद सबसे पहले हमने गांव के रास्तों को ठीक करने का काम किया है। ताकि किसान अपनी पैदावार, अपने अनाज को लेकर मण्डी तक आसानी से जा सके। इसके अलावा व्यापारी गांव तक जा सके और इसलिए कि किसान को उसकी

उपज का उचित मूल्य मिल सके। समाजवादी एम्बुलेंस, 1090 अस्पतालों में मुफ्त में दवाईयां मुफ्त में किताबें कभी आपने सोचा था क्या। गरीब आदमी एक–एक टिकिया के लिए लाइन लगाता था लेकिन सरकार बनने के बाद हमारी सरकार ने इलाज के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में जो बेहतर काम किया है उसके लिए आज सारे उत्तर प्रदेश की जनता अखिलेश यादव जिन्दाबाद के नारे लगा रही है और आप मुगालते में न रहिए, 2017 आ रहा है, 2017 में आप ख्वाब देखते रहिएगा और समाजवादी पार्टी के लोग अखिलेश यादव के नेतृत्व में फिर से दो तिहाई बहुमत की सरकार बनाकर उत्तर प्रदेश की बेहतरी और विकास का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपने बोलने का मौका दिया इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं और मा0 मुख्य मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसका पुरजोर समर्थन करता हूं।

'श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य–

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपको धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मा0 मुख्य मंत्री जी के द्वारा रखे गए 2016–17 के बजट की सामान्य चर्चा में मा0 नेता विरोधी दल, मौर्य जी ने जो अपनी बात रखी, मैं उससे अपने को सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, पूरे सत्ता पक्ष की तरफ से बराबर यह बात आ रही है कि बहुत बड़ा बजट रखा गया है। मान्यवर, इसके पहले भी बजट आए लेकिन इस बजट को पढ़ने के बाद यह लगा कि वाकई में मुख्य मंत्री जी ने भी इस बात को स्वीकार किया कि जिस तरह से प्रदेश का चौमुखी विकास चार साल में होना चाहिए था वह नहीं करा पाए और उन्होंने बजट की शुरुआत की कि जब से पतवारों ने मेरी नाव को धोखा दिया। जब पतवारों ने धोखा दिया तो इसका मतलब प्रदेश में चार साल सही काम नहीं हो पाए। मान्यवर, अब मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं।

(सत्ता पक्ष से बात आई कि सही–सही बोलिए)

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य–

हम सही–सही बोल रहे हैं, इसमें जो लिखा हुआ है वही बोल रहे हैं। मा0 मुख्य मंत्री जी ने अब यह भरोसा दिलाया है कि अब हमने धोखा देने वालों से सबक ले लिया है, हमने सीख लिया है और अब हम प्रदेश को आगे ले जाएंगे। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक सुझाव मा0 मुख्य मंत्री जी को देना चाहता हूं और शेर है निदा फाज़ली जी का।

हर आदमी में होते हैं दस–बीस आदमी,
जिसको भी देखना, कई बार देखना।

मा0 मुख्य मंत्री जी, आगे होशियार रहिएगा, पता नहीं और धोखेबाज लोग न आ जाएं। मान्यवर, पूरा प्रदेश दैवीय आपदा की मार से पीड़ित है। दैवीय आपदा की मार ओलावृष्टि से हुई। उसके बाद हमारे प्रदेश के अन्दर 50 जनपद सूखाग्रस्त घोषित किए गए। मान्यवर, दैवीय आपदा पर किसी का बस नहीं है लेकिन दैवीय आपदाओं से हम किसानों को कैसे राहत दे सकें, ये काम सरकार की जिम्मेदारी है। मान्यवर, दैवीय

---

*oDrk us Hkk"k.k dk iquohZ{k.k ugha fd;kA

आपदा में जो भी नुकसान हुआ उसका अभी भी मुआवजा अच्छी तरह से बंट नहीं पाया और सरकार पिछले वर्ष से यह चिल्ला रही है कि हम किसान वर्ष मना रहे हैं। आज अगर प्रदेश के अन्दर सबसे बुरी हालत में कोई है तो वे हमारे किसान भाई हैं। आज किसानों की जो दुर्दशा है उस पर अगर एक कोई महत्वपूर्ण योजना नहीं बनाई गई तो हमारे किसान कैसे आगे बढ़ेंगे, यह सबके लिए चिन्ता का सबक है। आज हमारे उत्तर प्रदेश के अन्दर 65 फीसदी खेती की जमीन है और कई ऐसे देश हैं जहां पर मात्र 15 फीसदी जमीनों पर खेती हो रही है लेकिन वहॉ के किसान समृद्ध हैं और हमारे यहां के किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं। मान्यवर, इस पर भी सरकार को विचार करके योजना बनाने की आवश्यकता है और मा0 सिंचाई मंत्री जी बैठे हैं। सिंचाई को लेकर हमारे यहॉ आज भी बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां सिंचाई की सुविधाएं नहीं हैं। हमारे ही क्षेत्र में केवल एक माइनर है इसके अलावा हमारे वहां कोई भी नहर नहीं है। जो तमाम ट्यूबवेल हैं वे बन्द पड़े हुए हैं। ट्यूबवेल चालू नहीं हो रहे हैं। मान्यवर, शुरुआत में जब यह सरकार बनी थी तो मा0 मंत्री जी इज़राइल गए थे और कहा जाता है कि एशिया ही नहीं विश्व में इज़राइल ऐसा देश है जिसने सिंचाई के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य किया है। मा0 मंत्री जी ने सदन को यह भरोसा दिलाया था कि हम उत्तर प्रदेश में भी सिंचाई की व्यवस्था ऐसी करेंगे जैसी इज़राइल में है। लेकिन मान्यवर, यह अंतिम बजट है सरकार का सिंचाई के साधन नहीं हो पा रहे हैं दैवीय आपदायें आ रही हैं इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि सिंचाई की व्यवस्था को सुदृढ़ कराया जाए। मान्यवर, दैवीय आपदाओं में एक और बड़ी आपदा अभी भू–कम्प आया। नेपाल में भूकम्प आया उसके झटकें यहॉ उत्तर प्रदेश के लोगों ने भी महसूस किये। आज भू–कम्प के झटके को तो हम लोग नहीं रोक सकते, सरकार नहीं रोक सकती लेकिन भू–कम्प से कैसे बचा जाए, कैसे लोगों को जागरुक किया जाए। इस पर भी एक योजना बनाने की जरूरत है। मान्यवर, हमारे जो नगरीय क्षेत्र में लोग आते हैं, जो महानगरों में रहते हैं, वह लोग तो इंजीनियरों से मिलकर, आर्किटेक्ट से मिलकर भू–कम्परोधी मकान बना लेते हैं लेकिन हमारे प्रदेश की जो 70 फीसदी आबादी गांव में रहती है, उनके पास कोई ऐसी टैक्नोलाजी नहीं है। मैं आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि अभी हमारे जनपद शाहजहांपुर में दैनिक जागरण अखबार के द्वारा और एक मारिया डे कम्पनी है उन्होंने गांव के मिस्त्रियों के लिए भू–कम्परोधी मकान बनाना सिखाने का एक ट्रेनिंग कैम्प चलाया। लगभग एक महीने कैम्प चला और उस कैम्प में रोजाना 50 से 60 राजमिस्त्री आते थे, उनको तीन दिन की ट्रेनिंग दी जाती थी और मारिया डे कम्पनी ने जो राजमिस्त्री वहां ट्रेनिंग करने आते थे उनको नुकसान न हो, क्योंकि वह गरीब लोग है तो उनके महनताने के लिए जो भुगतान है वह भी देने का काम कर रहे थे। दैनिक जागरण ने बड़ा सराहनीय यह काम किया। मैं आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि सरकार दैनिक जागरण या ऐसी जो और संस्थायें हैं उनसे मिलकर पूरे प्रदेश के हर जनपद में गांव के जो राजमिस्त्री हैं उनको भूकम्परोधी मकान बनाने के लिए ट्रेनिंग देने की व्यवस्था की जाए, क्योंकि भू–कम्परोधी

मकान अगर नहीं बने और कभी ऐसी दैवीय आपदा आती है तो आप जानते हैं कि क्या त्रासदी हो सकती है इसलिए हमको इसमें सजग होने की जरूरत है, जागरूक होने की जरूरत है।

श्री अधिष्ठाता–

नीरज जी अब समाप्त करिए।

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अध्यक्ष जी ने आठ मिनट का समय तय किया था अभी तो मेरे तीन मिनट हुए हैं। मान्यवर, मैंने घड़ी देखकर बोलना शुरू किया था, वैसे आप कहेंगे तो मैं बैठ जाऊंगा।

श्री अधिष्ठाता–

अब 6 मिनट हो गए हैं।

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य–

मान्यवर, आठ मिनट तो बोलने दीजिए इतनी बड़ी किताब है अभी तो तीसरे पेज पर पहुंचे हैं। मान्यवर, जो भी सुझाव हैं, मैं चाह रहा हूं कि हम लोग यहां चुनकर आते हैं, इन सुझावों पर अमल किया जाए। मान्यवर, अभी सुबह यहां पर पंचायतीराज का एक प्रश्न लगा था जो कि शौचालयों के सम्बन्ध में था। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार ने जो भी यह बजट रखा है यह आप भी जानते हैं और सब लोग जानते हैं कि जो शौचालयों का निर्माण हो रहा है, वह गुणवत्तापरक नहीं है। उसको कैसे दुरूस्थ किया जाए ताकि वाकई में जो कार्य हो रहा है वह अच्छा कार्य हो। मान्यवर, सरकार ने एक और अच्छा काम भी किया है अभी ग्रामीण क्षेत्रों में अन्तेष्टि स्थल बनाने की योजना चलाई है। अच्छी योजना है और यह अन्त्येष्टि स्थल बनने भी शुरू हो गए, लेकिन इसमें हम लोगों की अभी कोई सहभागिता नहीं है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी जो वरिष्ठ मंत्री हम लोगों के बैठे हैं कि कम से कम जिले में निर्देश जाए कि हम लोगों से प्रस्ताव लिये जायें। हम लोगों से पूछा नहीं जाता है और अधिकारी मनमाने तरीके से कहां बना देते हैं, प्रधान से और सेक्रेटरी से मिलकर तो कम से कम इसमें हम लोगों की भी सहभागिता हो, हम लोगों से प्रस्ताव लिये जाएं। यह सरकार का सराहनीय काम है। मान्यवर, अभी बराबर यह बात सदन में उठ रही है अंतिम वर्ष है हैण्डपम्प दिये जाएं। हैण्डपम्प चार साल से नहीं मिले हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करूंगा कि सरकार द्वारा सभी विधायकों को हैण्डपम्प दिये जाएं और जिस तरह सरकार यह ढिंढोरा पीट रही है कि हम उत्तर प्रदेश का सर्वांगीण विकास करना चाहते हैं तो हम लोग भी चाहते हैं कि विकास हो इसलिए कम से कम माननीय लोक निर्माण मंत्री जी कृपा करें कि विधायकों से 5–5, 7–7, 8–8 किलोमीटर सड़क के प्रस्ताव ले लें, वैसे मैंने एक प्रस्ताव आज आपको दिया है। आप कृपा करेंगे तो इससे पूरे प्रदेश का विकास होगा और सड़क तो आपको बनानी ही है, हम लोगों के कहने से बना देंगे तो और अच्छा होगा।

श्री अधिष्ठाता–

नीरज जी समाप्त करिये।

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य–

मान्यवर, अभी पांच मिनट भी नहीं हुआ। हमने घड़ी देख ली थी।

श्री अधिष्ठाता–

पांच मिनट से ज्यादा हो गए हैं। घड़ी हम भी देख चुके हैं।

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य–

मान्यवर, दो–चार बातें हैं। केवल दो बातें और करके आप का बिल्कुल आदर करते हुए अपनी बात समाप्त कर दूंगा। मान्यवर, आज बोर्ड की परीक्षायें चल रही हैं। बोर्ड की परीक्षाओं के समय में बिजली की उपलब्धता समय से नहीं मिल पा रही है। मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि कहीं पर भी कटौती करके उन गांवों में जहां शाम को बिजली नहीं जाती है, कम से कम चार–छः घंटे शाम को, जो पीक आवर्स हैं वहां पर बिजली देने की व्यवस्था की जाए, क्योंकि बोर्ड के एक्जॉम में हमारे इस प्रदेश के नौजवान परीक्षाएं दे रहे हैं, उनके पढ़ने के लिए बिजली की व्यवस्था करायी जाए। क्योंकि यह परीक्षायें साल मे और इनका एक टाइम–टेबल बना हुआ है उतने दिन बिजली की व्यवस्था सरकार जरूर पूरी कराये और मान्यवर, आज मै यहां देख रहा हूं कि हमारे बनारस के भारतीय जनता पार्टी के साथी बहुत परेशान हैं। यह बनारस के साथी जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, ये लोग कह रहे थे कि सरकार बनाने पर हम अच्छे दिन आयेंगे, आज दो साल होने जा रहे हैं सरकार को और अभी बनारस की समस्या, बनारस नही डेवलेप हुआ तो ये देश कैसे डेवलेप करेंगे। यह देश को कैसे आगे बढ़ायेंगे, मान्यवर भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे थे कि अच्छे दिन लायेंगे और मैंने देखा कि जो भी बनारस के विधायक हैं, वो रो रहे हैं, कि हमारे यहां काम ही नही हो रहा है। मान्यवर, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने चुनाव के पहले पूर्वान्चल में एक सभा की थी, वहां पर उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश वह प्रदेश है जो पूरे यूरोप को खाना खिला सकता है और सभा करने के बाद उनके उत्तर प्रदेश में 73 सांसद दिया, प्रधानमंत्री बन गये और वह आज इस प्रदेश को भूल गये। मैं सरकार के साथियों से कहना चाहता हूं कि आप इनके सहारे मत रहिये, आप अपने संसाधनों से सारे विधायकों की बात सुनकर विकास कराने का काम करिये क्योंकि यह धोखेबाज लोग हैं इन्होंने छल–कपट करके सरकार बना ली है, अब इनका हर जगह सूपड़ा साफ हो रहा है और अगर सरकार ने हमारे सुझाव नहीं माने तो इनका भी सूपड़ा साफ हो जायेगा। मैं यह अपील करते हुए कि सरकार इन बातों पर ध्यान देगी, बहुत–बहुत धन्यवाद देता हूं।

'श्रीमती रूबी प्रसाद–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने माननीय मुख्य मंत्री जी के 2016–17 के बजट के अभिभाषण के समर्थन मे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। मान्यवर मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारी सरकार चुनावी वादों को पूरा

---

*oDrk us Hkk"k.k dk iquohZ{k.k ugha fd;kA

करने के साथ–साथ तरक्की का भी शुभारम्भ किया और नई–नई दिशाओं में काम करना शुरू किया ताकि प्रदेशवासियों का खुशहाल हो सके। साथ ही साथ जो यह 2016–17 का बजट है, यह बढ़ा हुआ बजट समाज के उस गरीब पीढ़ी, किसान, मजदूर, अल्पसंख्यक, कमजोर महिला वर्गों को आगे बढ़ाने के लिए यह बढ़ा हुआ बजट 2016–17 में लाया गया। साथ ही साथ हम महिलाओं की बात हमेशा करते हैं और जब भी सदन मे हम 2012 से चुनकर आये हमेशा सिर्फ महिला सुरक्षा की बात सुनाई दी किसी दल ने यह नही उठाया कि हम महिलाओं को सशक्त और मजबूत, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक रूप से कैसे कर सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम महिलाओं का सम्मान बढ़ाने के लिए इनको सशक्त करने के लिए आशाज्योति केन्द्र जो महिलायें उत्पीड़ित होती हैं, जिनके साथ कोई घटना घटती हैं, उनके उपचार से लेकर सारा खर्च आशाज्योति केन्द्र द्वारा उठाया जाता है। साथ ही साथ हम यह भी कहेंगे कि 102, 108 एम्बुलेन्स आज के समय में प्रतिदिन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तीन हजार पांच सौ प्रत्येक दिन एम्बुलेन्स उत्तर प्रदेश में चलती है। साथ ही साथ हमारी महिला बहनों को जो परिवार की मुखिया होती हैं और जो गरीब जिनके पास न लाल कार्ड, न पीला कार्ड, न सफेद कार्ड उनके लिए 47 लाख समाजवादी पेंशन देकर उनको आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम किया। साथ ही साथ हमारे बहुत सारे नौजवान कृषि स्नातक जो कृषि के क्षेत्र में स्नातक की डिग्री लिये हों उनको प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए एग्री जंकशन योजना की शुरूआत का उन्होंने इस बजट में जिक्र किया। मैं इस सदन के माध्यम से धन्यवाद देना चाहती हूं कि इतने बड़े प्रदेश में उन्होंने नौजवान युवाओं के बारे में, रोजगार के बारे में इस बजट से उन्होंने अपनी संस्तुति दी। साथ ही साथ माननीय सिचांई मंत्री जी को हम इस सदन के माध्यम से कोटिशः धन्यवाद देना चाहते हैं कि हम जनपद सोनभद्र के सबसे अन्तिम विधान सभा 403 जो पांच राज्यों की सीमाओं से घिरा हुआ अति नक्सल प्रभावी क्षेत्र है और झारखण्ड छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार की सीमाओं से घिरा हुआ है। आजादी के बाद 1976 में हमारे यहां करहल परियोजना की शुरुआत हुई थी और वहां पर माननीय नारायण दत्त तिवारी, माननीय मुख्य मंत्री के नाम का शिलापट लगा। जब भी विपक्ष की सरकार बनी बसपा की सरकार बनी अभी अभी एक भाई कह रहे थे कि हम बहुत किसानों के हितैषी हैं यदि किसानों के इतने हितैषी थे तो आपके भी माननीय मुख्य मंत्री सुश्री मायावती जी का शिलापट वहां लगा हुआ है लेकिन दुःख की बात है कि आपके समय में भी यह परियोजना शुरूवात नहीं की गयी। मान्यवर, माननीय सिंचाई मंत्री जी की सहायता से जो हमारे पूर्वान्चल की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना करहल बांध वाह्य सड़क परियोजना उसका उन्होंने धन देकर शुरुआत करवाने का काम किया और 38 साल बाद यह परियोजना शुरू हुई। बहुत इसमें रुकावटें आई विपक्ष के लोगों ने भाजपा, बसपा, कांग्रेस के लोगों ने काफी विरोध किया, गोलिया तक वहां चली लेकिन हमारी सरकार हमारे मंत्री जी ने बहुत संयम से काम करके 11 विस्थापित गांव जो भारत का इतिहास है कि विस्थापितों को कभी भी 3 पुश्तों का मुआवजा वहां नहीं दिया गया, वहां करहल परियोजना के 11 गांव के लोगों को विस्थापित गांवों को 3–3 पुश्तों को मुआवजा देकर

और 4000 लोहिया आवास देकर आच्छादित करने का काम माननीय शिवपाल जी ने किया है इसलिए मैं उन्हें धन्यवाद देती हूं। हमारा आदिवासी पथरीला क्षेत्र होने के कारण वहां के किसान भगवान भरोसे खेती करते थे। इस परियोजना के बन जाने से दो दो तीन तीन राज्यों के अलावा उत्तर प्रदेश के किसान भी लाभान्वित होंगे। साथ ही साथ हम यह भी बताना चाहते हैं कि हमारी सरकार मजदूरों की सरकार है, किसानों की सरकार है, गरीबों की सरकार है। हमारी सरकार ने एक ओर हिन्दुओं के लिए अन्त्येष्ठि स्थल देने का काम किया, शमशान घाट देने का काम किया तो दूसरी ओर मुसलमानों के लिए उन्होंने कब्रिस्तान की बाउण्ड्रीवाल देने का काम किया। उन्होंने सभी जातियों, सभी धर्मो का हमेशा सम्मान किया। हमारी बेटी उसकी कल योजना, पढ़ो बेटी बढ़ो बेटी बहुत सारी योजनाओं का माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बजट में सेक्शन करने का काम किया। साथ ही साथ हाईटेक टाउनशिप नीति के अन्तर्गत 5427 करोड़ रूपये का पूंजीनिवेश, 33 इन्टीग्रेटेड टाउनशिप 7587 करोड़ रुपये का पूंजीनिवेश इसमें हुआ है। इंटीग्रेटेड टाउनशिप में बहुत सारी बाते आती है। ग्रामीण क्षेत्रों में माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय सिंचाई मंत्री जी जिस वाराणसी क्षेत्र की बात कर रहे हैं वह हमारे जनपद से मात्र 65 किमी0 की दूरी पर वाराणसी है। गंगा के घाटों की सफाई वर्षो से लम्बित पड़ी थी। सिंचाई मंत्री जी ने पैसा देकर के गंगा घाटों की सफाई कराने का काम किया। आप बखूबी वाकिफ हैं कि यह गंगा और साथ ही साथ बनारस शहर जो हमारा अध्यात्मिक शहर है बहुत ही कंजेस्टेड है पर माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय सिंचाई मंत्री जी चाहते हैं कि बनारस को पर्यटन के रूप में और भी खुबसूरत बनाने का काम किया जाय। साथ ही साथ हम यह भी कहेंगे कि हमारे यहां गांव में बसवटों को सड़कों से जोड़ने के लिए 19 करोड़ 23 लाख की बजट में व्यवस्था की गयी है, जो छोटी छोटी सड़क जो गांव से बसावटों को जोड़ने का काम करती हैं उसके लिए दिया गया है। साथ ही साथ कौशल प्रशिक्षण योजना के तहत जो लाखों युवक युवती इण्टरमीडिएट करके ग्रेजुएशन करके और चाहते हैं कि कोई टेक्निकल कम्प्यूटर, सिलाई और भी चीजे हैं जो यह कौशल विकास परियोजना के अन्तर्गत यह प्रशिक्षित होकर प्लेसमेन्ट के रूप में कहीं न कहीं इनको 5 से लेकर के 6–7–8 हजार तक की नौकरी प्राप्त होती है। यह माननीय मुख्य मंत्री जी की देन है। उन्होंने मिनी कामधेनु जैसी योजना की शुरूआत कर किसानों को बहुत बड़ा तोहफा दिया और आज उत्तर प्रदेश में कई छोटे मोटे किसान जो हैं सब्सिडी मुफ्त है, पैसा लेकर वह मिनी कामधेनु और कामधेनु योजना का लाभ ले रहे हैं। मैं यह भी बताना चाहूंगी कि एक 1090 जो वीमेन पावर लाइन है उसकी सहायता से जिन बहनों की सुनवाई पुलिस थानों में नहीं हो पाती उनकी सुनवाई 1090 के माध्यम से होकर उनको सहायता मिलती है। यह माननीय मुख्य मंत्री जी की देन है इसके लिए मैं उन्हें बहुत–बहुत धन्यवाद देती हूं कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए ठीक इंतजाम किया है। भारत में उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जहॉ 1090 की शुरुआत हुई है। निश्चित तौर पर हम यह भी कहेंगे कि हमेशा हमारा प्रदेश इतनी बड़ी जनसंख्या के दष्टिकोण से पूरे भारत में सबसे बड़ा प्रदेश है, इसकी वजह से कहीं न कही छोटी–मोटी घटनायें होती है और इन घटनाओं से हमें भी

दुख होता है, हमारी पार्टी के चाहे नेतागण हों, विधायकगण हों, सभी दुखी होते हैं। पर हम सभी चाहे पक्ष के विधायक हों अथवा विपक्ष के विधायक हों, सभी की नैतिक जिम्मेदारी होती है कि आप लोग सभी को जानते हैं कि धीरे–धीरे पाश्चात्य सभ्यता को अपनाने की वजह से लोंगो का नैतिक पतन होने के कारण यह सब घटनायें होने लगी हैं। हम चाहते हैं कि हम लोग उत्तर प्रदेश की परिकल्पना करते हैं और हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए बहुत काम भी किया है और हम चाहते हैं कि हम सभी विधायकगण जो सदन में बैठे हैं, हम सभी मिलकर उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश और खुशहाली के रास्ते पर मिलकर लायें। सिर्फ आरोप–प्रत्यारोप से उत्तम प्रदेश नहीं बन सकेगा, उत्तर प्रदेश का विकास नहीं हो सकेगा। सभी को मिलकर उत्तर प्रदेश के विकास में योगदान देने से ही उत्तम प्रदेश बनेगा। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए बहुत–बहुत धन्यवाद।

'श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने हमें बजट में बोलने का अवसर दिया, मैं आपको बहुत–बहुत धन्यवाद देता हूं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की जो सदन अपने मन में इच्छा रखता है तो उस इच्छा के संबंध में कहना चाहता हूं कि सब चाहते हैं कि मेरा प्रदेश अच्छा बने, लेकिन सरकार की इच्छा भी होनी चाहिये कि अगर उनके विधायकों के विधान सभा क्षेत्र अच्छे बनें, तो विपक्ष के विधायकों के भी क्षेत्र अच्छे बनें, तभी तो अपना प्रदेश उत्तम प्रदेश बनेगा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे यहां माननीय मुख्य मंत्री जी ने मेट्रो के लिए 50 करोड़ रुपये और मिल्क पावडर फैक्ट्री के लिए 80 करोड़ रूपये तथा चिड़ियाघर के तितलीवाले पार्क के लिए एक करोड़ रूपये दिये हैं। इस प्रकार कानपुर के लिए मात्र 131 करोड़ रुपये दिये गये हैं। 50 करोड़ रूपया तो मैट्रो की खुदाई में ही चला जायेगा। हालांकि यह पैसा ऊंट के मुंह में जीरा है, फिर भी मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं क्योंकि थोड़ा ही सही पर कानपुर के लिए कुछ दिया तो। हम तो यहां अपने क्षेत्र के विकास के लिए आपसे लेने आये हैं, जो भी मिले अच्छा है। कानपुर नगर सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला जनपद है, कानपुर उत्तर प्रदेश का उत्तम जिला है, जो सबसे ज्यादा माल देता है, उसी को आप सबसे कम देंगे, उसको सबसे छोटा समझकर चलेंगे, उसको सबसे पीछे रखकर चलेंगे, तो फिर कैसे चलेगा। मैं कहना चाहता हूॅ कि हमारे कानपुर नगर में एयरपोर्ट की व्यवस्था नहीं है, लेकिन अगर माननीय मुख्य मंत्री जी चाहें तो हमारे कानपुर के छावनी क्षेत्र जाजमऊ से लखनऊ के एयरपोर्ट तक एयरपोर्ट मेट्रो ट्रेन चलायें, जैसे कि दिल्ली में चलती है। इस मेट्रो ट्रेन से 40 मिनट में लोग कानपुर से लखनऊ तक आ सकेंगे और इसका लाभ सीधे–सीधे कानपुर नगर के व्यापारियों को मिलेगा, उसका लाभ पूरे उत्तर प्रदेश तथा देश के व्यापारियों को मिलेगा तथा विदेश से आने वाले व्यापारियों को मिलेगा। चूंकि कानपुर में

---

*oDrk us Hkk"k.k dk iquohZ{k.k ugha fd;kA

एयरपोर्ट न होने के कारण कानपुर के व्यापारियों का बड़ा नुकसान हो रहा है और खासकर जैसे टेनरी व फैक्ट्री तथा बड़े–बड़े उद्योगपतियों के यहां विदेशी लोग नहीं आ पा रहे हैं, जिससे विदेशी मुद्रा का भी नुकसान हो रहा है।

(कुछ सदस्यों द्वारा बीच में टोंका टाकी करने पर)

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय सतीश निगम जी की वजह से मेरे दो मिनट चले गये हैं, आप यह समय श्री सतीश निगम जी के कोटे से काट लीजियेगा।

श्री अधिष्ठाता–

श्री भदौरिया जी, आपने केवल दो मिनट मांगे थे, इसलिये उनसे काटने की कोई बात ही नहीं है।

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं कानपुर का छोटा सा विधायक हूं। मुझे श्री शेर बहादुर सिंह 'शेरू' और श्री सतीश कुमार निगम दोनों 'स' नाम वाले डिस्टर्ब कर रहे हैं, 'र' वाला आ रहा है, अब यह पीछे हट जायेंगे, क्योंकि बगैर 'र' के कुछ होना नहीं है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे विधान सभा क्षेत्र में सोसाइटी क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश के सारे जिलों में ऐसे क्षेत्र हैं जो सोसाइटी में आते हैं। पहले इन हाथीवालों की सरकार ने सोसाइटियों का काम नहीं किया और अब वही काम समाजवादी पार्टी की सरकार कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि इन सोसाइटियों में रहने वाले लोग क्या उत्तर प्रदेश में नहीं रहते हैं। आप क्या चाहते हो कि यह सोसाइटी के लोग पलायन कर जाये, आप क्या चाहते हो कि सोसाइटी के लोग प्रदेश छोड़कर चले जाये। इनमें किसानों के बच्चे पढ़ते हैं, किसानों ने अपनी जमीनें बेंचकर किसी तरह 100 गज जमीन ले ली है, वहां हमारे खोमचेवाले, ठेलेवाले गरीब लोगों ने थोड़ी–थोड़ी जमीन ले रखी है। वहां पर छोटे–छोटे नौकरीपेशा लोग रहते हैं। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि यह उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि यहां पर नाली नहीं है, पानी निकासी के लिए नाला नहीं है, सड़कें टूटी हुई हैं, बिजली के खम्भों की जगह बल्लिओं पर तार लेकर गये हैं। हमारे विधान सभा क्षेत्र न्यू आजाद नगर, कोयला नगर, बंगला बाजार–८ एवं ५, तिस्तीनगर, जगईपुरवा, ओमपुरवा, तुलसीनगर, चाणक्यपुरी, सिंघाटटिया, भल्लाटटिया, भगवनटटिया, देहली सुजानपुर आदि के लोग इससे पीड़ित हैं। आपको वर्ष 2017 के चुनाव में यहां का वोटर हैसियत दिखायेगा, तब आपकी समझ में आ जायेगा, क्योंकि आप सोसाइटी के लोगों की पीड़ा को नहीं समझ रहे हो। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह कानपुर है, कानपुर व्यापारियों का क्षेत्र है, कानपुर में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, व्यापारी लूटा जा रहा है, औरतों की इज्जत जा रही है, पुलिस रिपोर्ट नहीं लिख रही है। मैं कैसे कहूं माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह जो हमारे सामने और बगल में बैठे हैं, समय–समय पर एक हो जाते हैं, धन्य हो वोट, धन्य हो तुम्हारा ईमान और धन्य हो तुम सब, लेकिन मैं तो जनता की बात करता हूं। मैं आपसे बताना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

श्री भदौरिया जी, अब समाप्त करिये।

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया–

मान्यवर, अभी दो ही मिनट हुये। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि अगर इनके मुख्य मंत्री को धन्यवाद दो तब भी इन्हें बुरा लगता है। ऊंट के मुंह में जीरा डाल रहे हैं तब भी कह रहे हैं कि सब कुछ दे रहे हैं। हाथी खा गये गन्ना ई खा गये जीरा। यह ऊंट के मुंह में जीरा। देना कुछ नहीं चाहते हैं और 2017 में सरकार बनाना चाहते हैं। अरे कम से कम हर विधायक के लिये काम कीजिये, हर विधायक का साथ दीजिये। माननीय अधिष्ठाता महोदय, एक बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि कानपुर के अस्पतालों को अलग से पैसा देना चाहिये, कानपुर की गंगा मां को अलग से पैसा देना चाहिये, कानपुर के व्यापारियों को अलग से सहयोग करना चाहिये। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारे छावनी क्षेत्र में अल्पसंख्यक लोग रहते हैं, काफी गरीब लोग रहते हैं, यहां पर डूडा द्वारा नाप होनी थी वह अभी तक नहीं हुयी है। माननीय मंत्री जी इसकी नाप कराने का कष्ट करें जिससे कि वहां अल्पसंख्यक और हरिजन बस्ती खुश हो जायेगी और आपको भी बहुत–बहुत धन्यवाद देगी। हमारे माननीय आजम खां जी नहीं हैं, हमारे माननीय आजम खां जी 24 तारीख को गुस्सा हो गये थे, पता नहीं किस मूड में बैठे थे। हम बात कर रहे थे उन गरीब कालोनियों की, वहां की सफाई की, माननीय आजम खां सोचें कि सोसाइटी की बात कर रहे हैं मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि कभी–कभी हम छोटे विधायकों की बात भी सुना करें और गुस्से में न बैठा करें। सदन में आवें तो सदन की बात रखें, घर का गुस्सा यहां न उतारें। चूंकि हम तो बात जनता की कर रहे हैं जिस जनता से हमने भीख मांगी है, हाथ जोड़े हैं और मैं तो उन देवी देवताओं के लिये मांगता हूं और इस सदन से चाहता हूं कि मेरी विधान सभा क्षेत्र में आपके माध्यम से सोसाइटी में काम हो, कालोनी की सफाई हो, सीवर पड़े, गंगा मां की सफाई हो और टेनरियों को अलग से पैसा दें और जो नगर निगम मनमानी कर रहा है, उस पर तत्काल कार्यवाही करें वहां का नगर आयुक्त बेईमान है और सफाई के नाम पर वह डाका डाल रहा है, ऐसे नगर आयुक्त को तत्काल बर्खास्त करवाने का काम करें। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, आपको बहुत–बहुत धन्यवाद।

'वन राज्य मंत्री (श्री तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय)–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत 2016–2017 के बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया, इसके लिये आपको बहुत–बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्य मंत्री जी के द्वारा जो यह उत्तर प्रदेश का 2016–2017 का बजट प्रस्तुत किया गया है, यह बजट गरीबों का, किसानों का, मजदूरों का, मजलूमों का, उत्तर प्रदेश के किसानों का, उत्तर प्रदेश के नौजवानों का और उत्तर प्रदेश को तरक्की, उन्नति के पथ पर ले जाने वाला बजट है। अभी हमारे साथी रघुनन्दन सिंह भदौरिया जो कानपुर के विधायक है, अपनी बात को रख रहे थे। मुझे लगता है कि इनका जो जमीर है इनका जो ईमान है वह पूरी तरह से मर चुका है। मैं सदन में इस बात को इसलिये कह रहा हूं कि कोई भी दिन नागा नहीं जाता, अगर

मुख्य मंत्री जी सदन में बैठे हों तो यह अपनी सीट से उठकर कम से कम 50 पन्ने अपने पैड के लेकर उनके पास काम के लिये न जाते हों ...

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया–

अगर मुख्य मंत्री जी काम करते हैं तो मैं बधाई देता हूं लेकिन मैं अपने व्यक्तिगत काम नहीं बल्कि जनता के लिए भीख मांगता हूं और जनता के काम लेकर जाता हूं।

(सदस्य श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया के खड़े होकर अपनी बात कहने पर)

श्री अधिष्ठाता–

मा0 सदस्य, आप बैठ जाएं, जब आप बोल रहे थे तो सब लोग चुप थे।

श्री तेज नारायण उर्फ पवन पाण्डेय–

अच्छा ठीक है, आप बैठिये, जब आप बोल रहे थे तो मैं तो नहीं उठा। जब–जब मा0 मुख्य मंत्री जी सदन में होते हैं तो ये पैड अपने क्षेत्र के विकास के लिए देते हैं, हमें बहुत खुशी है कि आज जो हमारे मा0 मुख्य मंत्री जी हैं उनके पास सभी दलों के विधायक जाते हैं और अपने काम कराते हैं आप भी करा रहे हैं लेकिन जिस तरह से आप बात बोल रहे थे, जिस तरह से आप भाषण दे रहे थे कि सरकार कोई काम नहीं कर रही है, मुख्य मंत्री कोई काम नहीं कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश तरक्की के पथ पर नहीं जा रहा है। आप पत्र भी देते हैं चिठ्ठी भी कर रहे हैं, काम भी करा रहे हैं और बुराई भी कर रहे हैं तो कम से कम आपका इमान जिन्दा रहना चाहिए। सदन में जो बात आप कहते हैं उस पर आपको कायम रहना चाहिए। आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, आज हम आपके समक्ष कहना चाहते हैं कि आज मा0 मुख्य मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, वर्ष 2012 से लेकर 2016–17 तक यह बजट उत्तर प्रदेश को तरक्की और उन्नति के पथ पर ले जाने वाला है। आज आप देख लीजिए चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे पढ़ने वाले विद्यार्थी हों, चाहे गरीब वर्ग के लोग हों और चाहे जिस तबके के लोग हों आज हमारे मुख्य मंत्री जी की सरकार उनको तरक्की के पथ पर ले जाने का काम कर रही है। आप लोक निर्माण विभाग को देख लीजिए, मा0 लोक निर्माण मंत्री जी ने इस प्रदेश में जितनी सड़कें और पुल बनवाये हैं, आजादी के 68 सालों में उतने पुल और उतनी सड़कें कभी नहीं बनी होंगी। आप कानपुर देख लीजिए, इलाहाबाद और बनारस देख लीजिए, मैं जिस विधान सभा अयोध्या से चुन करके आता हूँ मैं वहां की बात करना चाहता हूं। हमारे अयोध्या में 14 कोसी, पचकोसी परिक्रमा मार्ग है लाखों श्रद्धालु आते हैं और परिक्रमा करते हैं। आज उस परिक्रमा मार्ग को सुन्दर और बहुत अच्छा बनाने का काम मा0 मुख्य मंत्री और मा0 लोक निर्माण मंत्री जी ने किया हम उनको ढेर सारी बधाई देना चाहते हैं। अयोध्या में जो सड़कें आजादी के 70 सालों में नहीं बनी थीं, ये भाजपा के लोग बैठे हैं हमें इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है, राम का नाम ले करके केन्द्र में सरकार बनाई और राम का नाम लेकर प्रदेश में कई बार सरकार बनाई, इनके मुख्य मंत्री बने लेकिन अयोध्या में सबसे ज्यादा काम, सबसे ज्यादा सम्मान और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की धरती का अगर सबसे ज्यादा किसी ने विकास किया है चाहे

वह पर्यटन के रूप में हो, चाहे वहॉ सड़कों के रूप में हो, चाहे शैक्षिक रूप से हो, अगर सबसे ज्यादा किसी ने काम किया तो हमारे नेता मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव जी ने अयोध्या की गरिमा, परम्परा और सम्मान को बढ़ाने का काम किया है। भाजपा के लोग कभी 14 कोसी परिक्रमा के नाम पर कभी राम के नाम पर अयोध्या के सम्मान को गिराने का काम करते हैं, वहां के व्यवसाय को चौपट करने का काम करते हैं, वहां की पढ़ाई–लिखाई और व्यवसाय को चौपट करने का काम करते हैं। आज अयोध्या अगर पर्यटन के रूप में पिछड़ा है तो मैं सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह भारतीय जनता पार्टी की देन है। हमारे नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव और हमारे मुख्य मंत्री मा0 अखिलेश यादव जी का कहना है कि ''हिन्दू का नहीं मुस्लिम का नहीं, यह लहू है हिन्दुस्तान का, जब लहू टपकता गीता का तो बहता लहू कुरान का''। आज हम इस विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, आज मैं इस सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर गरीबों के दुःख–दर्द को पोछने का अगर कोई काम कर रहा है तो वह हमारे मुख्य मंत्री जी हैं, उसके घर में खाने पीने की व्यवस्था नहीं है तो आज समाजवादी पेंशन के माध्यम से हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री उसके परिवार की जीविका को चलाने का काम कर रहे हैं। आपको सोचना होगा, आज हमारे नेता प्रतिपक्ष बोल रहे थे, कानून–व्यवस्था की धज्जी उड़ा रहे थे बता रहे थे कि जंगलराज है, यहां पर कोई कानून–व्यवस्था नहीं है, मा0 मुख्य मंत्री जी की सरकार ठीक से नहीं चल रही है। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मा0 नेता प्रतिपक्ष अपनी सरकार के बारे में बयान दे रहे थे या आज के बारे में बात कर रहे थे। वह शायद इस बात को भूल गये जब उत्तर प्रदेश की सड़कों पर जनता यह नारा लगा रही थी कि ''माया तेरे जमाने में बलात्कार है थाने में'', आज अखिलेश यादव जी की सरकार में इस तरह का नारा कहीं नहीं लग रहा है। आपकी सरकारों में थानों में बलात्कार होते थे और उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति थी उस समय आपके जेल में सी0एम0ओ0 की हत्या होती थी, आपके विधायक अधिकारियों से वसूली करते थे और उसके बाद जेल भेजे जाते थे। आज समाजवादी पार्टी की सरकार और मा0 मुख्य मंत्री श्री अखिलेश यादव जी की सरकार में ऐसा कहीं नहीं हो रहा है। अभी हमारे साथी स्मार्ट सिटी के बारे में बता रहे थे जो हमारे फैजाबाद के सांसद हैं उन्होंने मोदी जी के मुंह में लड्डू खिलाते हुए फोटो पूरे अयोध्या, फैजाबाद में लगवा दिया कि नरेन्द्र मोदी जी को ढेर सारी बधाई, अयोध्या, फैजाबाद स्मार्ट सिटी घोषित हो गया और जब भारत सरकार ने स्मार्ट सिटी की सूची घोषित की तो पूरे प्रदेश में कोई भी शहर नहीं था। मैं उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्य मंत्री अखिलेश यादव जी को बधाई देना चाहता हूं कि जब उन्होंने मॉर्डन सिटी घोषित की तो हमारे अयोध्या और फैजाबाद से, फैजाबाद व अयोध्या नगर पालिका को मॉर्डन सिटी घोषित किया। मैं अपने को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि मा0 मुख्य मंत्री जी ने 07 मार्डन सिटी घोषित किये उसमें दो फैजाबाद जनपद में मेरी विधान सभा में घोषित किये। इसलिए मैं अपने मा0 मुख्य मंत्री जी का स्वागत करता हूं और उनको बधाई देना चाहता हूं। आज हमारा श्रम विभाग है, श्रम विभाग में जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है आज उनके यहां अगर

बच्चा पैदा होता है तो बच्चा पैदा होने से लेकर उसकी पढ़ाई–लिखाई, नौकरी तक की व्यवस्था मा0 मुख्य मंत्री जी ने की है। आज गरीबों, मजदूरों को साइकिल देने की व्यवस्था, 40 तरह के काम करने वालों को रोजगार देने की व्यवस्था उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री अखिलेश यादव जी ने की है। अगर किसी मजदूर की दुर्घटना में मृत्यु हो जाए तो उसको 05 लाख रुपया, उसके दाह–संस्कार के लिए 15 हजार रुपया, आज ऐसी व्यवस्था समाजवादी पार्टी की सरकार ने की है। अभी किसान दुर्घटना बीमा के बारे में बोल रहे थे बहुजन समाज पार्टी के विधायक, हम कहना चाहते हैं कि हमारे नेता मुलायम सिंह यादव जी मुख्य मंत्री थे तब 01 लाख रुपया देते थे, आज उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री अखिलेश यादव जी अगर कोई किसान दुर्घटना में मर जाए तो उसको 05 लाख रुपया देने का काम करते हैं। आज समाजवादी पार्टी की सरकार हर क्षेत्र में काम कर रही है। माध्यमिक शिक्षा में जो नया संशोधन हुआ है उसमें जो हमारी बहिनें हैं उनको दुबारा 30–30 हजार रुपया कन्या विद्याधन के रूप में देने की व्यवस्था हमारी सरकार ने की है।

श्री अधिष्ठाता–

पवन पाण्डेय जी, अब समाप्त करिये।

श्री तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय–

मान्यवर, मैं ज्यादा भाषण न देते हुए अपनी बात को खत्म करते हुए अधिष्ठाता महोदय मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आज चाहे 108 या 102 एम्बुलेंस हो, आज गरीब किसान परिवार में कहीं दुर्घटना हो जाए तो नातेदार, रिश्तेदार बाद में पहुंचते हैं पहले 108 एम्बुलेंस पहुंचकर उसको अस्पताल पहुंचाने का काम करती है। यह व्यवस्था समाजवादी पार्टी की सरकार ने चालू की है। (मेजें थपथपायी गयी।) आज पर्यटन के क्षेत्र में आप देख लीजिए जो भारत सरकार का सर्वे आया है, भारत में तो पर्यटन की दृष्टि से आने वाले पर्यटक कम हुये हैं लेकिन मा0 मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के प्रयास से उत्तर प्रदेश में पर्यटक बढ़े हैं, पर्यटन की दृष्टि से आने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है। मा0 मुख्य मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा दिया है। मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से आज इस बात को सदन में कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश को तरक्की, उन्नति, प्रगति के पथ पर ले जाने का काम मा0 मुख्य मंत्री श्री अखिलेश यादव कर रहे हैं और दो लाइनें कहते हुए अपनी बात को खत्म करूंगा कि–

बहते दरियाओं की मानिन्द बहकते जांए,
अखिलेश यादव कमजर्फ नहीं हैं जो छलकते जाएं।
इन्हें थानों में कोई कैद नहीं कर सकता,
ये तो खुशबू हैं जिधर जाएं, महकते जाएं।

मैं अपनी बात को खत्म करते हुए सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आज गरीब, किसान, मजदूर, मजलूम, नौजवान उत्तर प्रदेश का हर एक तबका अखिलेश यादव जी के विकास के कामों से खुश है और आज यह उत्तर प्रदेश नई इबारत लिख रहा है। 2017 में दोबारा सरकार बनेगी, श्री अखिलेश यादव मुख्य मंत्री बनेंगे। तरक्की का,

उन्नति का, प्रगति का श्रीगणेश किया है श्री अखिलेश यादव जी ने और जनता बोल रही है जय अखिलेश, जय अखिलेश, जय अखिलेश। धन्यवाद।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बजट के सामान्य चर्चा पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। महोदय, मैं बजट भाषण पढ़ रहा था बजट में कुछ अच्छाईयॉ भी हैं तो ढ़ेर सारी कमियां भी हैं। अच्छाईयों के सिलसिले में प्रदेश की सरकार ने तीन बड़े विकास के काम किये हैं। पहला, मेट्रो रेल चलाने का काम, दूसरा, इन्होंने 108 और 102 एम्बुलेंस जो अच्छी स्वास्थ्य सेवा में देने का काम है और तीसरा आगरा से लेकर लखनऊ तक फोर लेन बनाने का काम जो एक्सप्रेस–वे के रूप में विकसित करने का काम किया है। लेकिन शायद इन तीन चीजों से ही पूरे प्रदेश में खुशहाली नहीं आ सकती। बहुत सारे और भी आयाम हैं उन पहलुओं पर विचार करना शायद मा0 मुख्य मंत्री जी भूल गये। उन्होंने बजट के क्षेत्र में जिला मुख्यालय से तहसील मुख्यालय तक की सड़क को जोड़ने की बात की। मैं पिछले 2012 से लगातार इसी विधान सभा में अपने जनपद मुख्यालय पडरोनासे तहसील तमकुहीराज मुख्यालय को हाई–वे से हाई वे से जोड़ने की मांग मैं करता रहा और वह सड़क गोंडरिया तक 2009 से लम्बित पड़ी है। आज 2016 हो गया और पिछली बार लगातार नियम–301, नियम–51 और तमाम बार उस मुददे को उठाने के बाद भी आज तक उन सड़कों का निर्माण नहीं पूरा हो सका और वह अधूरी पड़ी हैं। मान्यवर, हमारे क्षेत्र में पूर्वांचल में इन्सेफेलाइटिस एक बहुत बड़ी समस्या है और संयोग की बात है कि जब–जब मैं सवाल लगाता हूं तब–तब वह सवाल आता जरूर है लेकिन किसी न किसी विवाद के कारण वह पूरा नहीं हो पाता। इन्सेफेलाइटिस से अगर आप देखें वर्ष 2010 में 3540 केस आये जिसमें 494 की मत्यु हुई, वर्ष 2011 में 3492 केस आये जिसमें 579 की मत्यु हुई, वर्ष 2012 में 3484 केस आये और 557 की मत्यु हुई। वर्ष 2013 में 3096 केस आये और उसमें 609 की मत्यु हुई। वर्ष 2014 में 3264 केस आये और 599 की मत्यु हुई और इस बार 2015 का भी रिकार्ड आया है जिसमें करीब 3600 केसेज आए और लगभग 625 लोगों की मौत हुई। मान्यवर, परिस्थितियां यह हैं कि अगर आप देखें तो कुशीनगर जनपद में जे0ई0 और ए0ई0एस0 से जो सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र है इन्सेफेलाइटिस से 132 मौतें 2015 में हो चुकी हैं जहॉ तक इसे महामारी घोषित करना चाहिए, सरकार को इसके लिये कड़े कदम उठाने चाहिए। लेकिन इस बजट में इन्सेफेलाइटिस बीमारी से लड़ने का, इसे रोकथाम करने का कोई उपाय नहीं किया गया। कोई ऐसे बजट का प्राविधान नहीं किया गया जिससे कम से कम उन नौनिहाल बच्चों को जो बच्चा पैदा होने के बाद काल के गाल में समा जाता है, इस बीमारी के नाते, उसको राहत की सांस मिल सके। मान्यवर, आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि जे0ई0 ए0ई0एस0 से लगभग विकलांग को 50 हजार और जो मृत्यू प्राप्त करता है उसको एक लाख रुपये का अनुदान सरकार के द्वारा दिया जाता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह मांग करना चाहूंगा कि यह धनराशि बहुत कम है, इस धनराशि को बढ़ाने की भी व्यवस्था की

जाय। मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा कि बेसिक शिक्षा प्रणाली में एक व्यवस्था है, जिसके अन्तर्गत दो तरह की व्यवस्था है जो पिछड़े विद्यालय हैं उसमें टीचर नियुक्त करने की और जो अगड़े विद्यालय हैं उसमें अगर कम भी टीचर रहे तो उसके अनुपात में पिछड़े क्षेत्रों में टीचर नियुक्त करके उस विद्यालय को चलाने की व्यवस्था संचालित की जाती है। ठीक उसी तर्ज पर शायद अगर आप देखें 1988–89 में भारत सरकार ने भारत की जनसंख्या परियोजना चलाई थी जिसमें स्वास्थ्य की सुविधा को निरन्तर बढ़ाने के लिये संकल्प लिया गया था और उसमें उन्होंने 30 हजार पर नया पी0एच0सी0 बनाने का और 5 हजार पर उपकेन्द्र का निर्माण कराने की बात कही थी। लेकिन आज यह 30 हजार पर जो नये पी0एच0सी0 तो बन गई, 5 हजार पर उपकेन्द्र तो बन गये लेकिन उपकेन्द्रों और इन पी0एच0सी0 का क्या हाल है अगर आप देख लें तो प्रदेश के तमाम उपकेन्द्र जो डाक्टर्स से विहीन हैं, ए0एन0एम0 से विहीन हैं और मैं अपने क्षेत्र में बताऊं अगर दुधही के पी0एच0सी0 को देखें तो 9 सेण्टर हैं जिसमें आज तक कोई ए0एन0एम0 नहीं है। 9 सेन्टर हैं तरया का जिसमें आज तक कोई ए0एन0एम0 नहीं है। यानि ए0एन0एम0 और डाक्टरों की भारी कमी शायद उस क्षेत्र में जो इन्सेफेलाइटिस से पीड़ित है अगर डाक्टरों और ए0एन0एम0 की भर्ती की व्यवस्था की जाय तो शायद उससे लड़ने में एक आसानी हो सकती है।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

मान्यवर, 8 मिनट का समय मिला था। आप चाहें तो अध्यक्ष जी आयेंगें तो उनसे पूछ लीजियेगा। एक विधायक को आठ मिनट का समय दिया था। अधिष्ठाता महोदय, सरकार ने एक बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया, 1 लाख 72 हजार शिक्षामित्रों को भर्ती किया। मैं बधाई देना चाहूंगा लेकिन उसके साथ साथ वर्ष 2011 की परीक्षा में टी0ई0टी0 में 2 लाख 65 हजार लड़के पास हुए। सुप्रीम कोर्ट ने लगातार इस बात को कहा कि जो 72,825 मूल पद हैं उसकी भर्ती करने की व्यवस्था तो की लेकिन उसने सरकार से मांगा कि पूरे उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा में कितने शिक्षक हैं जिनको लिया जा सकता है और जो खाली पड़े हुए है उस समय सरकार ने जो अपना एस0एल0पी0 दाखिल किया उसमें उन्होंने बताया कि पांच लाख बेसिक शिक्षक के पद खाली हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार आपने एक लाख 72 हजार शिक्षामित्रों की भर्ती कर ली, और 72 हजार 800 टी0ई0टी0 और लोगों का आपने भर्ती किया। जो आज दो लाख 65 हजार लड़के पास थे 72000 की आपने भर्ती कर ली तो बाकी के जो शेष बचे हुए छात्र हैं जो टी0ई0टी0 अर्ह हैं उनको भी बेसिक शिक्षा में समायोजन कर उनको भी शिक्षक बनाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। मान्यवर, आपके माध्यम से, अभी हमारे सिंचाई मंत्री जी नहीं हैं, मैं कहना चाहूंगा कि नहरों की सफाई के लिए मुख्य पश्चिमी गण्डक नहर में 256 करोड़ का प्राविधान करके 2013 में नहरों की सफाई की व्यवस्था संचालित की गई पांच डिवीजन थे सिल्ट

और सफाई के, सिल्ट सारे निकालकर जगह–जगह रख दिए गए और नहरों के पास वह सिल्ट बार–बार गिरकर उसी नहर में आ जाता है और फिर वही स्थिति होगी आने वाले दिनों में नहरों में, फिर सिल्ट जमा हो जाएगा जो मेन कैनाल है जो पानी पहुंच जाना चाहिए, किसानों के खेतों तक वह नहीं पहुंच पाएगा। तमाम माइनर और तमाम रजवाहों की अभी भी सफाई नहीं हो पाई है गेट, सड़क और नई पुलिया का निर्माण होना था जो नहीं हो पाया माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे पूर्वांचल में कृषि का बहुत महत्व है।आपके संज्ञान में मैं लाना चाहूंगा अधिष्ठाता महोदय कृषि के क्षेत्र में हमारे यहां एक कृषि गन्ना अनुसंधान क्षेत्र है जो बाबू गेंदा सिंह जी के नाम पर है साढ़े तीन सौ एकड़ जमीन, और साढ़े तीन सौ एकड़ जमीन किसी जगह के लिए बड़ी पर्याप्त होती है। मैंने पूर्व में भी मांग किया था कि पूर्वांचल में कृषि विश्वविद्यालय मात्र एक है और उसकी संख्या बढ़नी चाहिए। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से यह मांग करना चाहूंगा कि उस गेंदासिंह अनुसंधान में कृषि विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया जाए तो शायद उस इलाके का विकास होगा। अधिष्ठाता महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने मैत्रेय परियोजना की शुरुवात की, मैट्रो परियोजना का उद्घाटन किया 2013 में और माननीय अधिष्ठाता महोदय यह बड़े अफसोस की बात है कि कुशीनगर में मैत्रेय परियोजना का उद्घाटन तो हुआ लेकिन आज तक एक ईंट नहीं रखी गई। यह बताया जाता है कि मुख्य मंत्री जी की बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है और उस मैत्रेय परियोजना में तमाम विकास के संसाधन होंगे। कुशीनगर जो बौद्ध स्थली है उसका सर्वांगीण विकास होगा। लेकिन जिस प्रदेश के मुखिया के उद्घाटन करने के बाद भी,अगर एक ईंट आज तक न रखी गई हो तो यह बड़ा चिन्तनीय विषय है।

श्री अधिष्ठाता–

आठ मिनट से ज्यादा हो गया है।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

माननीय अधिष्ठाता महोदय आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि बाढ़ के नाते हमारे क्षेत्र में भारी तबाही हुई। मैंने हर बार सदन में उठाया, बाढ़ के नाते कई गांव नदी के चपेट में आ गए। वह लोग आज तक पुनर्वासित नहीं हो पाए। बार–बार सरकार का यह कहना कि हमारे पास जमीन नहीं है। सरकार से पैसा आएगा तो जमीन खरीदकर देंगे। माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहूंगा जो पिपरा घाट और अरौली..

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

के जो लोग हैं जो लगातार बाढ़ की विभीषिका को झेले हैं उनका घर और आशियाना पूरी तरह नदी में समाहित हो गया है। उन्हें जमीन आवंटित कर कहीं न कहीं बसाने की व्यवस्था की जाए। मैं चर्चा कर रहा था कानून व्यवस्था की, तमाम लोग इसकी वकालत कर रहे थे कि कानून–व्यवस्था बड़ी अच्छी है मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा

हमारे जनपद कुशीनगर में तरया थाने में एक महिला जिसका नाम सुगान्ती देवी है पत्नी श्री बृज किशोर पटेल बहुत गरीब महिला उस महिला को प्रेमजाल में एक विनोद राय व्यक्ति फंसाता है और फंसाने के बाद वह शादी शुदा औरत है..

श्री अधिष्ठाता–

यह बजट पर बोलने वाली बात नहीं है। बजट में, जो बजट प्रस्तुत हुआ है आप उस पर चर्चा कर रहे हैं।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

अधिष्ठता महोदय उस महिला की जमीन रजिस्ट्री करा लिया गया। अधिष्ठाता महोदय उस महिला की जमीन रजिस्ट्री करा लिया गया। रजिस्ट्री कराने के बाद उस महिला से लोन निकलवा लिया गया और लोन निकलवाने के बाद उस महिला को मारने की नीयत से उसके शरीर पर तेजाब फेंककर जला दिया गया।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

उसमें जो मुल्जिम थे उनको पकड़ने का काम पुलिस ने नहीं किया। इसी तरह से कसया में दरोगा ने एक आदमी को छोटे से मामले में बुलाने का काम किया और दरोगा ने चौकी में उसे पीटते पीटते मार डाला। यह मामला 251/2015 2015 के फर्स्ट महीने का है। फरवरी का मामला है अब तक वह दरोगा गिरफ्तार नहीं हो सका है। यह कानून–व्यवस्था की बात है।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

अध्यक्ष महोदय इसी तरह से एक लास्ट मामला बताकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। एक लड़की जो गुरूवलिया थाना तुरपट्टी की थी, पढ़ने जा रही थी कुछ मनबढ़ लोगों द्वारा उसे ले जाकर उसके साथ बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई। अध्यक्ष महोदय यह तुरपट्टी थाने का मामला है स्थिति यह होती है कि जब जनता उसके खिलाफ सड़क पर उतरती है तो जनता पर लाठी बरसाई जाती है उन लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। जब सारे लोग दबाव बनाते हैं तो एक व्यक्ति जो मुसहर जाति का था उसको लीपापोती करने के नाम पर उस आदमी को जेल भेज दिया जाता है और पूरी घटना का पर्दाफास कर दिया जाता है।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

अध्यक्ष महोदय मैं अन्तिम बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा अध्यक्ष महोदय आप जानते हैं कि होमगार्ड कितना महत्वपूर्ण काम करते हैं वह थाने से लेकर तमाम वी0आई0पी0 ड्यूटी करने लगते हैं लेकिन होमगार्डों का नियमितीकरण नहीं हो पाया

आपके माध्यम से मैं मांग करना चाहूंगा कि होमगार्डों का नियमितीकरण किया जाय। अन्त में आपको धन्यवाद अर्पित करते हुए कहना चाहता हूं कि चौकीदारों का भी विनियमितीकरण करके उनके वेतन भत्ता दिया जाए यह इस बजट में नहीं रखा गया है इसको रखा जाय आपने मुझे इस बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपको बहुत–बहुत धन्यवाद देता हूं।

'वाह्य सहायतित, परियोजना समग्र ग्राम विकास, खेल व युवा कल्याण, राज्य मंत्री (श्री रामकरन आर्य)–

माननीय अधिष्ठाता महोदय यह 2016–17 का लोकप्रिय और जनप्रिय बजट मुख्य मंत्री जी ने रखा है। यह बजट 3,86,935 करोड़ का है। यह बजट पिछली सरकार में जो बजट था उसका 14.6 प्रतिशत अधिक है। अधिष्ठाता महोदय यह ठीक है कि विपक्ष के लोगों को तो बात रखनी ही चाहिए जो अपने जिले की समस्याएं हैं अपने क्षेत्र की समस्याएं हैं हम लोग भी रखते हैं। मगर सरकार की अच्छी बातों का भी जिक्र करना चाहिए। कुछ साथियों ने किए हैं पिछले चार साल में हमारी सरकार ने जितने काम किए हैं वह चारों तरफ दिखाई पड़ता है। चाहे वह विकास का हो शिक्षा हो समाज का हो किसी भी क्षेत्र का देखिएगा काम दिखाई पड़ रहे हैं। जहां तक सड़कों का सवाल है आज पूरे उत्तर प्रदेश में जो सभी जिलों को 4 लेन से जोड़ने का प्रोग्राम हुआ किसी भी प्रदेश के लिए यह अति महत्वपूर्ण हो सकता है। हमारे साथी कह रहे थे कि वहॉ इतना विकास है। हमारा प्रदेश लगभग 22 करोड़ का है हम तीन चार करोड़ वाले नहीं हैं यह मध्य प्रदेश है राजस्थान नहीं है जहां प्रति वर्ग कि0मी0 में जिनकी जनसंख्या 200–250, 221 है हमारे उत्तर प्रदेश में प्रति वर्ग कि0मी0 जनसंख्या 900–1000 के बीच में है। वहां की समस्या और हमारे यहां की समस्या में बहुत फर्क है एक बात मेरी शिकायत है क्योंकि मैं खेल विभाग से हूं। आज भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग यहां नहीं हैं। दो सालों में इन्होंने एक नया पैसा खेल विभाग को नहीं दिया। हमारे उत्तर प्रदेश का जो 25 प्रतिशत हमारा पैसा है, वह खाते में जमा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक नया पैसा नहीं दिया है। मा0 अधिष्ठाता जी, जब तक 22 करोड़ की आबादी वाला प्रदेश खेल में तरक्की नहीं करेगा तब तक मैं नहीं समझता हूं कि देश तरक्की कर सकेगा। इसीलिये मा0 मुख्य मंत्री जी ने खेलों को इतना प्रोत्साहन दिया है कि अगर कुश्ती में कोई खिलाड़ी ओलम्पिक में स्वर्ण पदक प्राप्त करता है तो उसे 6 करोड़ रूपये देंगे और अगर कोई खिलाड़ी रजत पदक प्राप्त करता है तो उसे 4 करोड़ रुपये देंगे और अगर कोई खिलाड़ी कांस्य पदक भी प्राप्त करता है तो उसे 2 करोड़ रूपये देंगे। हम 20 लाख रुपये उन खिलाड़ियों को दे रहे हैं जो वहां केवल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमने खिलाड़ियों की खुराक में वृद्धि की है, खेल के मैदानों का सुन्दरीकरण किया है और यही कारण है आज सैफई, लखनऊ, गोरखपुर, रामपुर, बनारस और कानपुर आपको चारों तरफ दिखायी दे रहे हैं, जहां आज अन्तर्राष्ट्रीय खेल के मैदान तैयार हो रहे हैं। मा0 अधिष्ठाता जी, मैं जब 11वीं का विद्यार्थी था तो मैंने 19 महीना

---

*oDrk us Hkk"k.k dk iquohZ{k.k ugha fd;kA

जेल की जिन्दगी गुजारी। मैं मा0 मुख्य मंत्री अखिलेश यादव जी को, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को, मा0 नेता विपक्ष को भी बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने मिलकर लोकतंत्र सेनानियों की पेंशन को 10000 रुपये से बढ़ाकर 15000 रुपये कर दिया और इसके साथ ही साथ स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की पेंशन को 12000 रुपये से बढ़ाकर 15176 रुपये कर दिया है। हमारी सरकार कितनी संवेदनशील है, सबसे बड़ी बात यही है। हमारी सरकार ने लोहिया आवास बनवाये। अभी तक जो भारत सरकार से पैसा आता है, 70–80 हजार रुपया आता है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने तीन लाख पांच हजार रूपये लोहिया आवास के लिये दिये हैं। हमनें समाजवादी पेंशन दी, यही नहीं हमनें भूमि सेना बनाई। जो बड़े–बड़े बीहड़ हैं हम उनको तोड़कर उसे गरीबों–मजदूरों में बांटना चाहते हैं। इसके साथ ही साथ आज हम किसान ऋण तीन परसेन्ट पर दे रहे हैं। सरकार जो काम कर रही है इसकी कोई भी तारीफ नहीं कर रहा है। हर 100 किलोमीटर के रेडियस में, हर 100 किलोमीटर की दूरी पर हम मण्डी बना रहे हैं, जहां किसानों का सामान आयेगा, उनका सामान सड़ने नहीं पायेगा, वहां हमारी व्यवस्था होगी, यह हमारी सरकार की अपनी व्यवस्था है। इसी तरीके से सड़कों और पुलों के लिये इस साल बजट में हमनें 14721 करोड़ रूपये का प्राविधान किया है। यह बहुत बड़ा बजट है। मैं जानता हूं कि अगर गंगा पर पुल नहीं बनेगा, यमुना पर पुल नहीं बनेगा, गोमती पर पुल नहीं बनेगा, अगर मनोरमा पर पुल नहीं बनेगा, अगर राप्ती नदी पर पुल नहीं बनेगा तो निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता है। हमारी सड़के नहीं बनेंगी तो विकास नहीं हो सकता है। हम एक टाईम भोजन कम खा लेंगे तो चल जायेगा, बाकी सारी चीजें चल जायेंगी, लेकिन यदि हमारी सड़कों का विकास नहीं होगा, हमारी ऊर्जा का विकास नहीं होगा, हमारे स्कूलों का विकास नहीं होगा तो यह नहीं चल पायेगा। मैं इस सरकार को बहुत–बहुत बधाई देना चाहता हूं कि सिद्धार्थ विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी है, उसमें इस साल पढ़ाई शुरू हो गयी है। जहां भगवान बुद्ध की जन्मस्थली है, वहां सिद्धार्थ विश्वविद्यालय बनाया गया है, जहां श्रीलंका और हिन्दुस्तान के विद्यार्थी पढ़ेंगे। आज भी नेपाल में 51 परसेन्ट मूल के भारतीय लोग हैं तथा 49 परसेन्ट केवल पहाड़ के लोग हैं। इसलिये हमारे सिद्धार्थ विश्वविद्यालय से जो तराई का इलाका है वह शिक्षा ग्रहण करेगा, श्रीलंका के विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करेंगे, जापान के विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करेंगे, क्योंकि भगवान बुद्ध की जन्मस्थली पर स्थित होने के कारण सिद्धार्थ विश्वविद्यालय बहुत महत्वपूर्ण है। मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं इस सरकार का और मा0 मुख्य मंत्री जी का बहुत आभारी हूं कि हमारे बस्ती जिले को इन्होंने एक इंजीनियरिंग कालेज दिया है, गोण्डा को इंजीनियरिंग कालेज दिया है, गोरखपुर में इंजीनियरिंग कालेज डेवलॅप किया है और अब बलिया में बनने जा रहा है और आप क्या लेंगे, भाई ? हम तो विकास करना चाहते हैं, प्रदेश का चहुमुंखी विकास चाहते हैं। हम दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, गरीबों के लिए, मुसलमानों के लिए, गरीब बड़ी जातियों के लिए, सब के लिए हम विकास की बात करते हैं और जब ये आते हैं तो यह हिन्दु–मुसलमान की बात करते हैं और इनके पास

कुछ नहीं है। मैंने एक दिन कहा था, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई एजेण्डा नहीं है, न इस बजट से इनका मतलब है, न प्रदेश के विकास से इनका मतलब है, इनका मतलब है, हिन्दू–मुसलमान कैसे लड़ें, इनका मतलब है, हिन्दुस्तान–पाकिस्तान के नाम पर भिडंत हो, इनका यह है, बाबरी मस्जिद, राम जन्म भूमि, काशी विश्वनाथ, मथुरा की जो पवित्रता है, इस सवाल पर कैसे विवाद बढ़े और वह लड़ें और लाशों की होली खेलें। माननीय अधिष्ठाता जी, हम समाजवादी लोग हैं, मैं जानता हूं, अगर मुसलमान मरेगा तो ईरान का नहीं मरेगा, अगर हिन्दू मरेगा तो नेपाल का नहीं मरेगा। हिन्दू और मुसलमान, सिख और ईसाई, इस भारत माता के, इस धरती के हम लोग हैं, इस धरती ने पैदा किया है, इसलिए एक–एक व्यक्ति से हमारा सम्बन्ध है। मैं नहीं चाहता हूं कि किसी की झोपड़ी चले, मैं नहीं चाहता हूं कि मन्दिर गिरे, मैं नहीं चाहता हूं कि मस्जिद गिरे, हम लोग तो समाजवादी लोग हैं, समरस विचारधारा के लोग, लेकिन कुछ मेरे साथी बहस करते हैं, ऐसी बहस करते हैं, अभी बहस चल रही थी, मैं सवाल करना चाहता हूं, कल हमारे एक साथी इस बात पर वेल में आ गए थे कि मुझे कुर्सी नहीं मिली। तब तो बड़ा अच्छा लग रहा था, मुझे भी तकलीफ हो रही थी कि क्यों नहीं एक विधायक को कुर्सी मिली और कल उनको नहीं मिली और आने वाले दिनों में हमको भी नहीं मिलेगी। आज जब एक सवाल आया, एक मेम्बर के सवाल पर तो सारे के सारे लोग बहिष्कार किए माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य, नेता, विरोधी दल की मैं तारीफ करना चाहता हूं कि जनतंत्र में कहीं न कहीं यह चीज है कि आज उन पर हमला बोला। जब उत्तर प्रदेश रहेगा, देश रहेगा, तभी हम रहेंगे, जब देश नहीं रहेगा, तो नहीं रहेंगे। जब मन्दिर होगा, तभी पुजारी पूजा करेगा, मस्जिद रहेगा, तभी अजान होगा, मन्दिर और मस्जिद टूट जायेंगे तो न अजान होगा, न घण्टी बजेगी। मैं चाहता हूं कि इस मुल्क में बराबरी हो, समरसता हो, हिन्दू और मुसलमान की एकता हो, ईद और होली में हम एक दूसरे के यहॉ जायें क्योंकि तभी हमारा प्रदेश विकास करेगा तभी देश विकास करेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ जिन हमारे साथियों ने, विपक्ष के लोगों ने हमारे इस बजट का समर्थन किया है, उनको बहुत–बहुत धन्यवाद और जिन लोगों ने आलोचना भी किया है, सुझाव के रूप में उसका भी स्वागत है। मैं इस बजट का समर्थन करते हुए, अपनी बात समाप्त करता हूं, बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री राजेश त्रिपाठी–

धन्यवाद, माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर अपनी बात रखने का मौका दिया है। मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं, अपने नेता विरोधी दल, माननीय श्री स्वामी प्रसाद मौर्या जी के वक्तव्यों से और वहां से शुरू करना चाहता हूं, जहां से माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट की जो पहली लाइन थी कि 'जनता के लिए जिसके मन में प्यार नहीं है, जनतंत्र में वह कुर्सी का हकदार नहीं।' बहुत अच्छी लाइन थी, वह। मैं इस बात पर यह कहना चाहता हूं, माननीय मुख्य मंत्री जी के लिए, इस लाइन पर मेरी यह लाइन समर्पित है कि 'गमों की आंच पर आंसू उबाल कर देखो, खिलेंगे रंग किसी पर भी डाल कर देखो। तुम्हारे भी

दिल की चुभन, जरूर होगी कम, किसी के पांव से कांटा निकाल कर देखो।' उधर पीड़ा थी, जनता की और जवाब में भी यह पीड़ा है और जनता की यह पीड़ा तभी कम होगी, जब हम गरीब के पांव से उसकी समस्याओं का कांटा निकालेंगे। मान्यवर, बहुत लम्बा–चौड़ा बजट आया है, तीन लाख छियालिस हजार करोड़ का, इस साल का। मैं देख रहा था, यह पाँचवा बजट है, पाँच साल का बजट मैंने देखा, लगभग 13 लाख हजार करोड़ पाँच वर्षों में आया है और जब मैं 13 लाख हजार करोड़ को देखता हूं या इस बार के 03 लाख 46 हजार करोड़ रुपये के बजट को देखता हूं तो अपनी विधान सभा क्षेत्र चिल्लूपार की तरफ देखता हूं कि चिल्लूपार उसमें कहाँ खड़ा है ? मैं चिल्लूपार से आता हूँ और चुल्लू भर भी आता तो संतोष होता, नाम के अनुसार भी नहीं आप मान्यवर, फिर वह लाईन याद आती है कि–

''बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर,
पथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर।''

मान्यवर, फल बहुत दूर दिखाई दे रहा है। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि पिछला बजट जो आया था वह भी 03 लाख के आस–पास था, मा0 मुख्य मंत्री जी समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, मा0 मुख्य मंत्री जी के पूज्य पिता जी आदरणीय नेता जी, आजमगढ़ क्षेत्र से आते हैं, लगभग छः महीने हो गये, भाई संग्राम सिंह जी बैठे है जो हमारे मित्र हैं, इनकी मौजूदगी में मा0 नेता जी और मा0 पी0डब्ल्यू0डी0 मिनिस्टर सबकी मौजूदगी में रौनापार और चिल्लूपार दोनों को जोड़ने के लिए एक बहुत ही महत्वाकाँक्षी घाघरा नदी पर पुल का शिलान्यास मा0 नेता जी ने किया था, लगभग छः महीने होने जा रहे हैं, स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा किये गये शिलान्यास पर अगर अब तक एक ईंट भी नहीं रखा गया, कैसे कहूं कि बहुत बड़ा बजट है ये, अपनी ही सरकार के मुखिया के द्वारा रखे गये शिलान्यास पर अगर काम शुरू न हो पाया हो, तो प्रश्नचिन्ह लगाना स्वाभाविक होता है। मान्यवर, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, लोहिया ग्राम की चर्चा करना चाहूँगा मा0 प्रभारी मंत्री जी हमारे यहां बैठे हुए हैं, आपको अवगत कराना चाहता हूं मा0 मंत्री जी, 2013–14 में आपने जिन पांच गांवों का चयन किया था, उसमें एक गांव है मटिहानी, यह 2013–14 का चयनित लोहिया गांव है, दो वर्ष हो गये, इस गांव में अब तक कार्य शुरू ही नहीं हुआ, इस सत्र में आपके पास आठ से नौ महीने का समय है, मुझे आप बतायें कि जब इस साल में लाहिया ग्राम का आप चयन करेंगे तो अगर 2013–14 का कार्य अब तक शुरू ही नहीं हुआ मटिहानी जैसे गांव का जो लम्बे सड़क से जुड़ा हुआ गांव हुआ है, जब वह गांव नहीं जुड़ पाया तो इस साल का गांव आपके अधिकारी कैसे संतृप्त करेंगे, मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि आप चाहे जितना लम्बा–चौड़ा बजट ले आयें, मगर आपके अधीनस्थ शिथिल हो तो कैसे कार्य होगा ? अगर दिमाग आपका कह रहा हो यह काम होना चाहिए और हाथ को लकवा मारा हुआ है, पैर को लकवा मारा हुआ है, तो आप कार्य नहीं कर पायेंगे यही हाल यहां है और आप इस बात को स्वीकार करिये कि चाहे जो कुछ आप कहते हों, आप जितनी अच्छी बातें करते हो सदन में या जितना सख्त आदेश पारित करते हों आप लेकिन

निचले स्तर पर आपका कोई अधिकारी सुनने–करने को तैयार नहीं, अगर है तो प्रभारी मंत्री हैं आप, आपने चयन किया था गांव, आपके प्रभार जनपद गोरखपुर से जुड़ा हुआ है उस गांव का कार्य अब तक शुरू क्यों नहीं हुआ पता कराइये, एक बानगी केवल मैं देना चाहता था, इसका जरूर आप संज्ञान लेंगे। मान्यवर, कार्य का जहां तक सवाल है, मैंने पूछा कि इतने बड़े बजट में चिल्लूपार कहां दिखता है, पांच साल से वहां पर एक राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज बन रहा है, मान्यवर मुझे आश्चर्य हुआ कि मा0 मुख्य मंत्री जी ने जो बजट पेश किया, उसमें उसका कहीं जिक्र तक नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार आयुष के प्रति गम्भीर है या नहीं है, आयुष मंत्री, आयुर्वेदा, होम्योपैथ, सिद्धा या यूनानी यह सारी विधा मिलकर के एक पैरलल एलोपैथ के चलती है, बहुत करोड़ो लोगों का यह पैथी भला करती है, उस पैथी का आपके बजट में जिक्र तक नहीं, यहां तक मा0 महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में भी उसका जिक्र नहीं, यह इस बात को साबित करती है कि अधिकारी या सरकार में बैठे लोग आयुष जैसी गम्भीर पद्धति के बारे में पूरी तरह से चिन्तित नहीं हैं, केन्द्र सरकार इस पर भारी कालम बजट देने की घोषणा कर चुकी है। उस पर मैंने सुना है, उनकी कथनी–करनी का अन्तर तो रोज दिखाई देता है, मगर मैं जानना चाहता हूं अगर दिल्ली कुछ कह रही हैं तो आयुष पर अगर उनका इतना बड़ा बजट है तो प्रदेश सरकार गम्भीर होकर के उस पैसे को यहाँ लाना क्यों नहीं चाहती पांच साल से राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज बन रहा है, 2014–15 में मा0 मुख्य मंत्री जी ने एक सवाल के जवाब में यहां सदन में लिखित उत्तर दिया था कि 2015 में वहां पढ़ाई शुरू करा दी जायेगी, मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा लिखे गये जवाब के बावजूद अगर आज एक जवाब आया है और लिखा गया है कि हम यह नहीं बता सकते कि वहां पढ़ाई कब शुरू होगी, यह दुर्भाग्यपूर्ण है, यह कार्य करने का सरकार का और अधिकारियों का तरीका है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं इस बड़े बजट में कहीं आई0टी0आई0 कालेज का भी जिक्र है क्या। चिल्लूपार में पिछले पांच वर्ष से राजकीय आई0टी0आई0 कालेज का कार्य ठप पड़ा हुआ है, पांच वर्षों में इतने 3 लाख हजार करोड़ में चिल्लूपार के आई0टी0आई0 कालेज के लिए कोई धन न जाना या वहां का कार्य शून्य कराना, कैसे कहूं कि आपकी मंशा सही है ?

मान्यवर, हमारे यहां पिछले पांच वर्षों से फायर स्टेशन का कार्य चल रहा है। बिल्डिंग तैयार है और उसमें कुत्ते, बिल्ली, जानवर रहते हैं, उस पर फायर स्टेशन का कोई अधिकारी नहीं है, कुछ भी नहीं है। यह जवाब आता है कि कमेटी गठित कर दी गयी है, जैसे ही कमेटी का जवाब आएगा तो वहां पर फायर स्टेशन शुरू होगा। पिछले पांच वर्षों से फायर स्टेशन का कार्य चल रहा है। अधिष्ठाता महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि सरकार इस पर ध्यान दे। हमारे यहां दो गांव में खरवाईजखोर और रतनपुरा पांच वर्षों से यहां सब–स्टेशन का अधूरा निर्मित है। बीस से ज्यादा एप्लीकेशन दी गयी, अधिकारियों से मिला गया। माननीय मंत्री जी तक अपनी बात पहुँचायी गयी, लेकिन उस खरवाजईजखोर और रतनपुरा गांव का सब स्टेशन कार्य अब तक ज्यों का

त्यों ठप पड़ा हुआ है। मैं आपके माध्यम से यह चाहूंगा कि सरकार इसको संज्ञान में ले और इन दोनों सब–स्टेशनों को शीघ्र पूरा कराए ताकि उस क्षेत्र की विद्युत की समस्या दूर हो सके। सरकार ने यह वायदा सत्ता में आने के पहले किया था, कि और सरकारें चीनी मिलों को बेचा करती थी, इन्होंने कहा था कि हम आएंगे तो बन्द चीनी मिलों को चलाएंगे। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आपको, कि सठियांव की चीनी मिल को आपने चलाने का कार्य किया। जब आपने सठियांव के चीनी मिल को चलाया तो हमें लगा कि बगल की धुरियापार चीनी मिल, जो एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल है, आप उसे भी चलाएंगे। लेकिन वह चीनी मिल ऐसे ही पड़ी हुई है, वह बाट देख रही है कि कब सठियांव जैसे उसके भी दिन पलटेंगे, और धुरियापार चीनी मिल भी चलेगी। लगातार हाउस में सवाल दिए जा रहे हैं, लगातार अधिकारियों से बातें की जा रही हैं। मगर इस चीनी मिल को चलाने की कोई व्यवस्था अभी तक नहीं की गयी।

श्री अधिष्ठाता–

त्रिपाठी जी, समाप्त करिए।

श्री राजेश त्रिपाठी–

मान्यवर, मैं आठ मिनट के अंदर ही समाप्त कर दूंगा।

श्री अधिष्ठाता–

आठ मिनट नहीं, कुछ कम कर दीजिए।

श्री राजेश त्रिपाठी–

मान्यवर, आठ मिनट से कम में ही खत्म कर दूंगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि धुरियापार चीनी मिल को चलाया जाये। किसान वर्ष आप मना रहे हैं, युवा वर्ष आप मना रहे हैं अगर यह मिल आप चलाते हैं, तो किसान वर्ष भी सार्थक होगा और युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। तो युवा वर्ष भी सार्थक होगा। सचमुच आप अगर अपने इस नारे को सार्थक करना चाहते हैं तो धुरियापार चीनी मिल को आप चलाएं। माननीय खेलकूद मंत्री जी बैठे हुए हैं, अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं, हमने आपको लिख कर भी दिया था। एक राजकीय मिनी स्टेडियम चिल्लूपार में है और उसकी यह हालत है कि वह खण्डहर बना हुआ है। न वहां पर कोई फुटबाल खेल सकता है, न वहां कोई क्रिकेट खेल सकता है, न वहां कोई बैडमिंटन खेल सकता है। शीशे टूटे हुए हैं, सब कुछ जर्जर है। मैंने लिखा था कि कृपया आप उस पर ध्यान दें। मुझे आपकी तरफ से जवाब मिला है कि 2014–15 के बजट में व्यवस्था कर दी है। 2016–17 आ गया, कब वह काम शुरू होगा ? एक साल का बजट हो और वह कहीं धरातल पर दिखायी न दे तो आपकी कार्यशैली पर संदेह होता है। हमारे यहां राप्ती नदी पर दो बड़े पुल बन रहे हैं, जो देवरिया और गोरखपुर को जोड़ते हैं, यह दोनों पुल अधूरे पड़े हुए हैं, आप जितना विलंब करेंगे उतना ही आपका अधिक खजाना खाली होगा। जनता में आक्रोश बढ़ेगा, नुकसान सरकार का है, और खजाना अलग खाली होगा, आप आक्रोश अलग झेलेंगे। उचित होगा कि जितनी जल्दी हो सके, आप उन पुलों को बनाने की कृपा करें। मेरा एक निवेदन संस्कृति मंत्री

जी से भी है, वह अभी यहां बैठी नहीं हैं, शायद वह चली गयी हैं। मैं आपके माध्यम से संस्कृति विभाग तक यह बात पहुंचाना चाहता हूं कि सरकार यशभारती पुरस्कार दे रही है दे, कलाकारों का सम्मान कर रही है, करे, आप महीने में 50 हजार का उनका पेंशन देना चाहते हैं, स्वागत है बिल्कुल दिया जाना, मगर अकादमी एवार्ड वालों ने आपका क्या बिगाड़ा है संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2014 में आपने घोषणा की, कलाकारों को चिट्ठी आपने भेज दी, कि आप आइए हम आपका स्वागत सम्मान करना चाहते हैं, जब वह सम्मान लेने के लिए अपना बैग तैयार कर रहे थे तो आपका एस0एम0एस0 चला गया, अभी मत आना, बाद में बताऊंगा। वह पिछले दो साल से इंतजार कर रहे हैं कि कब सरकार उन्हें बुलायेगी, एकेडमी अवार्ड देगी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार एकेडमी अवार्ड देगी ? सरकार एकेडमी एवार्ड को देते समय यह भी ध्यान रखे कि जैसे सरकार यशभारती पुरस्कार प्राप्त करने वाले कलाकारों को पेंशन देती है, उसी तरह एकेडमी अवार्ड जो कलाकार प्राप्त कर रहे हैं 47 किये हैं उन्हें भी सरकार मासिक पेंशन दे ताकि वह कलाकार अपने परिवार का जीवन–यापन कर सके।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि सूखा पड़ा है, ओला पड़ा है। आपने ओलावृष्टि के नाम पर जो पैसा जिले पर भेजा था, एक तो आपने चयन कम किया जिन गांवों में ओला पड़ा वे सभी गांव नहीं लिए गए। मगर जो गांव आपने लिया वहां आपके अधिकारी वह पैसा नहीं बांट रहे हैं, वह जिले में पड़ा है। प्रभारी मंत्री जी, मैं आपसे चाहूंगा कि आप इसका संज्ञान लीजिए, वह पैसा उन तक पहुंचना चाहिए। जो सूखाग्रस्त किसान हैं और सूखे की जो राहत आप देना चाहते हैं उसे तत्काल दें क्योंकि अगर आप बहुत बाद में देंगे तो उस राहत का कोई मतलब नहीं होगा। एक निवेदन आखिरी और करना चाहता हूं कि किसान दुर्घटना बीमा आपने दिया, आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने एक लाख से पांच लाख कर दिया। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने विकलांगों के लिए ढाई लाख रुपये की व्यवस्था की। मैं बधाई इस बात के लिए भी आपको देना चाहता हूं कि आपने विकलांगों के कृत्रिम अंगों के लिए एक लाख रुपये की व्यवस्था की। मगर एक व्यवहारिक कठिनाई भी आप समझिए कि अगर एक बुजुर्ग जिसके नाम से खेती है वह वृद्ध है, वह 80 साल, 90 साल का व्यक्ति है वह खेत में नहीं जा सकता। खेत में उसका नाती, उसका पोता, उसका बेटा जाता है। काम वह करता है, किसानी तो असली वह करता है, कागज में भले ही वह बुजुर्ग है। खेती का काम जो किसान करता है दुर्घटना में मौत उसकी होती है और हम कहते हैं कि उसका खतौनी में नाम नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि इस बात को चिन्हित कराईए कि अगर वह बुजुर्ग व्यक्ति है, वह खेतों पर नहीं जा सकता और उसका बेटा अगर किसान है, अगर वह खेती का काम करता है और उसकी मौत हुई है तो उसके परिवार को लोगों को मदद मिलनी चाहिए।

श्री अधिष्ठाता–

राजेश जी, यह बात पहले आ गई है उसी चीज को रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई मेम्बर यह बात पहले कह चुका है।

श्री राजेश त्रिपाठी–

मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं। एक बधाई सरकार को देना चाहूंगा कि सरकार ने हमारे निवेदन को स्वीकार किया और सरकार बड़हलगंज कोतवाली का नया भवन बनवा रही है, बधाई आपको। उरूवा थाने को आपने नया भवन दिया जो छप्पर में चलता था आपने धन दिया, बधाई आपको। आपने हमारे विधान सभा क्षेत्र गोला को सी0ओ0 सर्किल बनाया, इसके लिए बधाई आपको। लेकिन हालात ये हैं कि इन थानों को और सी0ओ0 को देकर क्या करेंगे क्योंकि एक भी सड़क हमारे यहां की ऐसी नहीं है जिस पर आपकी पुलिस जल्दी से भाग करके चोर को या बदमाश को पकड़ पाए। सारी सड़कें जर्जर पड़ी हैं सी0ओ0 को गोला में बैठाकर क्या करेंगे, जब वह 15 कि0मी0 3 घण्टे बाद अगर पहुंचेगा। अगर टूटी, जर्जर सड़कों की हालत आप ठीक नहीं कराएंगे तो केवल पुलिस के थाने बनाने से काम नहीं चलेगा, पुलिस की जीप को भागने वाला रास्ता भी दीजिए ताकि वह अपराधियों को दौड़ाकर पकड़ सके। रास्ते जर्जर हैं, हमारे यहां की सारी जर्जर सड़कों की स्थिति ठीक कराई जाए। एक आखिरी बात कहकर के अपनी बात समाप्त करता हूं। एक सड़क हमारे यहां है मैं आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं। धुरियापार और उरुवा बाजार सड़क पिछले चार वर्षों से खोदकर के छोड़ दी गई है। वहां लगातार धरना–प्रदर्शन हो रहा है, आमरण–अनशन हो रहा है। यह सरकार के संज्ञान में है कृपया उस सड़क को अविलम्ब बनाया जाए वरना वहां लॉ ऐण्ड ऑर्डर की स्थिति खराब हो सकती है, पब्लिक बहुत आक्रोश में है। मेरा निवेदन है कि उस सड़क को जल्दी ठीक कराया जाए और बड़हलगंज को नगर पालिका बनाने की मुख्य मंत्री जी ने गोरखपुर में घोषण की थी। मा0 आजम खां साहब भी बड़हलगंज गए थे चिल्लूपार उन्होंने भी कहा था कि बड़हलगंज को नगर पालिका बनाएंगे। मेरा निवेदन है कि बड़हलगंज को नगर पालिका, उरुवा को टाउन एरिया और हाटा को टाउन एरिया सरकार बनवाए, अतिशीघ्र बनवाए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

'श्री आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी'–

मा0 अधिष्ठाता जी, मैं आपको बहुत–बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे वर्ष 2016–17 के बजट पर बोलने का अवसर दिया। आदरणीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत इस बजट में कहा गया है कि यह किसान वर्ष और युवा वर्ष है। मुझे नहीं लगता कि किसानों के लिए क्या किया गया, इस सदन में अनेकों बार किसानों की बदहाली की बात तमाम मा0 विधायकों ने उठाई है। न तो समर्थन मूल्य बढ़ा, न ओलावृष्टि से पीड़ित किसानों को मुआवजा भी उचित रूप में मिला। समय सीमित है मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता हूं। युवा वर्ष में युवाओं के लिए क्या योजना है बजट में कोई सामने नहीं आई है। कैसे युवाओं को ये सरकार रोजगार देगी, बड़े उद्योगों की छोड़ दीजिए, कुटीर उद्योग, लघु उद्योगों की जो बदहाली है इस बजट में बनारस का साड़ी उद्योग, मुरादाबाद का बर्तन उद्योग, मिर्जापुर का कालीन उद्योग, सीतापुर का दरी उद्योग,

* oDrk us Ò"k.k dk iquohZ{k.k ugha fd;kA

अलीगढ़ का ताला और डोर फिटिंग्स का उद्योग, लखनऊ का चिकन और जरी का उद्योग उसके लिए कोई किसी तरह की कार्य योजना सामने नहीं आई है। क्या सरकार इसकी बेहतरी के लिए कोई कार्य योजना बनाएगी। इन उद्योगों के जरिए लघु और कुटीर उद्योगों के जरिये, कैसे लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिलेगा इसका कोई विवरण इस बजट में नहीं है। अगर बड़े उद्योगों की बात की जाए तो इस बजट में कहा गया है कि तमाम औद्योगिक समूहों ने सहमति–पत्र जारी किये हैं, तमाम एम0ओ0यू0 साइन हुये हैं। ये हम तीन–चार बजटों से सुनते चले आ रहे हैं लेकिन कहां पर कोई परियोजना लगी, कितने लोगों को रोजगार मिला, कहां पर निवेश हुआ इसका कोई विवरण नहीं। अब कोई उद्योग लगाने के लिए आये कैसे बड़े उद्योगों के लिए दो बातें जो अनिवार्य हैं, उसमें से एक है दुरुस्थ कानून–व्यवस्था और दूसरा बिजली की उपलब्धता। कानून–व्यवस्था के मामले में सारा प्रदेश त्रस्त है, अनेक बार माननीय विधायकों ने यह बात रखी आज भी इसके ऊपर बहुत–सी बातें आई हैं कि कानून–व्यवस्था के क्या हाल हैं। राजधानी लखनऊ में विधान भवन से थोड़ी दूर मुख्य मंत्री के आवास के पास एक छात्रा का शव मिलता है। एक सप्ताह के अंदर पुनः दूसरा शव मिलता है। अपराधियों के हौसले इतने बुलन्द हैं कि कल भी एक शव मिला है। कल आगरा में एक दलित सामाजिक कार्यकर्ता की हत्या हुई है, पूरे प्रदेश में कानून–व्यवस्था ध्वस्त है, कैसे कोई उद्योग यहां पर आएगा। अगर बिजली की बात करें तो बजट में माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में 16 घंटे और शहरी क्षेत्रों को 22 घंटे बिजली देने पर सरकार काम कर रही है। चार साल से सरकार काम कर रही है परिणाम क्या है ग्रामीण क्षेत्र में कहीं 7 घंटे, कहीं 8 घंटे बिजली आ रही है। गांवों में 16 और शहरों में 22 घंटे बिजली देने के लिए 22000, 24000 मेगावाट की बिजली की आवश्यकता होगी उसके लिए क्या योजना है, क्या प्लान है? आज क्या प्रदेश का उत्पादन है मुझे लगता है कि 3500 मेगावाट के आस–पास बिजली का उत्पादन होगा और यह 22000, 24000 मेगावाट बिजली कहां से आयेगी ? सौर ऊर्जा इसमें बड़ी सहायक हो सकती है लेकिन सौर ऊर्जा के लिए इस बजट भाषण में कहा गया कि कई गुना सौर ऊर्जा बढ़ी है, लेकिन यह है कि प्रदेश की सौर ऊर्जा सिर्फ 140 मेगावाट है, हो सकता है कि पिछले साल 50–60 या 70–80 मेगावाट हो और आप कह रहे हो कि हमने बहुत बढ़ा दी है लेकिन राजस्थान में 1264 मेगावाट है, गुजरात में 1024 मेगावाट है और 9 राज्य ऐसे हैं जहां सौर ऊर्जा का उत्पादन उत्तर प्रदेश से अधिक है। सौर ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि विद्युत की उपलब्धता बढ़ायेगी और पर्यावरण संतुलन के लिए भी सौर ऊर्जा सहायक है।

(इस समय 4 बजकर 38 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये)

पर्यावरण के सम्बन्ध में कहना है कि इतनी भयावह स्थिति हो रही है कि देश के सर्वाधिक वायु प्रदूषित शहरों में चार शहर उत्तर प्रदेश के हैं और पिछले दिसम्बर और जनवरी का जो आंकड़ा है उसमें हिन्दुस्तान का सबसे अधिक वायु प्रदूषित महानगर आगरा है और उसके बाद कानपुर, लखनऊ और वाराणसी हैं। इसके लिए कोई कार्य

योजना सामने नहीं है। पर्यटन के क्षेत्र में मुझे कोई विशेष योजना सामने नहीं दिखी। पर्यटन आज विश्व में एक बहुत बड़ा उद्योग है। टूरिज्म इण्डस्ट्री जो तमाम रोजगार सृजन कर सकती है लेकिन प्रदेश में पता नहीं क्या स्थिति है कि वर्ष 2013 में 32 लाख विदेशी पर्यटक उत्तर प्रदेश में आये थे और 2015 के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं लेकिन 2014 में यह संख्या घटकर 29 लाख हो गयी और घरेलू पर्यटक भी घटे हैं ऐसा क्यों हुआ है ? क्या पर्यटकों का उत्तर प्रदेश के लिए आकर्षण खत्म हो रहा है या हम सुविधायें नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं....

श्री अध्यक्ष–

जल्दी करिये, पांच बजे बन्द हो जायेगा।

श्री आशुतोष टण्डन (गोपाल जी)–

अब बजट मे तमाम चीजे ऐसी हैं जिसमे साम्प्रदायिक तुष्टीकरण सामने दिखता है कि अंत्येष्टि स्थलों के लिए 100 करोड़ और कब्रिस्तान की चार दीवारी के लिए 400 करोड़, कितना भेद–भाव है। मान्यवर मुख्य मंत्री जी के प्रोजेक्ट साईकल ट्रैक, अगर आप देखें, मान्यवर सरकार जो अच्छे काम भी कर रही है, उसका परिणाम क्या है, मुख्य मंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट साईकल ट्रैक लेकिन मै तो जहां जहां जाता हूं, गौर से देखता रहता हूं एक भी साईकल उस ट्रैक पर चलती हुई नही दिखती है। इसका क्या कारण है। मुझे लगता है साईकल ट्रैक बनवाकर आपने अच्छा काम तो किया लेकिन चुनाव आयोग के लिए भी एक और काम आ गया जैसे इनके हाथी वह ढकवाते हैं वैसे आपके साईकल के बोर्ड ढ़कवायेंगे चुनाव में। मान्यवर, स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैं लखनऊ में बता रहा हूं कि पी0जी0आई0 में बेड की बहुत कमी है जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। उसके लिए भी कोई योजना सामने नहीं है। हमारे राजनैतिक कार्यकर्ताओं के लोग आकर सिफारिशें करते हैं कि साहब वहां पर एडमिट करा दीजिये, पी0जी0आई0 में बेड नहीं होते, अस्पतालों की यह हालत है कि लखनऊ में मेडिकल कालेज और लोहिया अस्पताल वैन्टिलेटर की कमी है सरकार को स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए। लखनऊ में बहुत बड़ा ऐसा एरिया है जो जल भराव से पीड़ित है, उसके लिए कोई कार्य योजना नहीं है, लखनऊ में जे0एन0एनआर0एम0 योजना में सीवर पड़ चुका है लेकिन कहीं भी कनेक्ट नहीं हुआ है, उसके लिए भी कार्य योजना नहीं है और लखनऊ के साथ–साथ सारे महानगरों में जाम की बहुत समस्या है, उसके लिए कोई कार्य योजना नहीं है। अनियोजित विकास के लिए कोई कार्य योजना नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

पांच बजे तक ही है 20 मिनट शेष है। पांच–पांच मिनट के लिए बोल लीजिये।

श्री सन्तराम कुशवाहा–

मान्यवर, आपने बजट चर्चा पर बोलने का मौका दिया उसके लिए मैं आभारी हूं। अध्यक्ष जी, हमारे पी0डब्लू0डी0 मंत्री माननीय शिवपाल जी माधौगढ़ विधान सभा में यमुना नदी के ऊपर उद्घाटन करने गये थे, वहां माननीय मंत्री जी का बहुत स्वागत किया गया था तथा उन्होंने वादे भी किये थे लेकिन अध्यक्ष जी चार साल गुजर गये हैं, जो

वादे किये थे खास तौर से माननीय मंत्री जी से बिजली के बारे में कहा गया था लेकिन उस गांव की बिजली आज तक पूर्ण नही हुई है। अध्यक्ष जी, अभी–अभी बुन्देलखण्ड को सूखा घोषित किया गया है और हमारी सरकार कह रही है कि हम किसानों के हितैषी हैं लेकिन हमें पानी नहीं देगी। बुन्देलखण्ड में जो डैम है उनके अधिकारियों ने साफ कह दिया है कि अब हम पानी नहीं देंगे। अध्यक्ष जी, इसके पहले की सरकार में भी यह परिस्थितियां आई है लेकिन हमेशा मध्य प्रदेश से पानी खरीदा जाता रहा है हमारे यहां के जिलाधिकारी ने पूरे जनपद के सभी जनप्रतिनिधियों ने माननीय सिचांई मंत्री जी को लिख कर दिया कि जब तक मध्य प्रदेश से पानी नहीं खरीदेंगे तब तक जनपद जालौन मे सिचाई नहीं हो सकती है। अध्यक्ष जी हमारे कहने का एक ही उद्देश्य है कि अगर अब सिंचाई का पानी न मिला तो जो फसल बची है वह भी बर्बाद हो जायेगी और बुन्देलखण्ड किस जगह जायेगा यह सोचने की बात है। माननीय अध्यक्ष जी आपसे अनुरोध करना है कि बुन्देलखण्ड में एकल पेय योजना, पेयजल योजना के अन्तर्गत कम से कम उन गांव में लागू करा दी जाये जो चार–पांच हजार आबादी के हैं।

जनपद में पिछली सरकार के बाद तार फेनसिंग योजना बन्द कर दी गयी है। किसान के खेतों में तार फेनसिंग कराई जाय क्योंकि इस समय गो–रक्षा कानून अधिनियम लागू होने कारण और बुन्देलखण्ड में सूखा के कारण अन्ना पशु घूम रहे हैं। जो गाय है उनसे जो बछड़े पैदा होते थे उनको किसान खेती की जुताई के लिए लेते थे लेकिन अब ट्रैक्टर आदि की व्यवस्था हो गयी है सारे बछड़े खेती के काम में नहीं आते हैं और वह सड़कों पर घूम रहे हैं। किसान दिन रात लाठी लेकर के अपने खेतों की रखवाली कर रहा है जो किसान जिस दिन गैरहाजिर अपने खेत से हो जायेगा उसी दिन उसकी फसल नष्ट हो जाती है इसीलिए हम आपसे मांग करते हैं कि इस बजट में पिछली सरकार में तार फेनसिंग योजना किसानों की थी उसको भी जोड़ दिया जाय। माननीय अध्यक्ष जी, इस बजट में जैविक खाद के लिए हमीरपुर को लिया गया है, बुन्देलखण्ड बुरी स्थिति में गुजर रहा है इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि जैविक खाद योजना के लिए जिस तरह से हमीरपुर को चिन्हित किया गया है उसी तरह से जनपद जालौन को भी जोड़ दिया जाय। मान्यवर, माधोगढ़ विधान सभा, माधोगढ़ तहसील लगभग 15 वर्ष हो गये हैं और माधोगढ़ विधान सभा की आबादी कम से कम 15 लाख की है परन्तु वहां पर कोई मुन्सिफी नहीं है वहां पर मुन्सिफी की स्थापना कराई जाय।

श्री अध्यक्ष–

अब आपका खत्म हो गया।

श्री सन्त राम कुशवाहा–

नहीं अध्यक्ष जी।

श्री अध्यक्ष– आप लिखकर दो, हम सब जुड़वा देंगे।

(वार्तालाप से व्यवधान) जासमीन अंसारी जी, लिखकर दे दीजिए, आपका जोड़ दिया जायेगा।

श्री सन्त राम कुशवाहा–

मान्यवर, सरकार कोई काम कर नहीं रही है, आप बोलने का मौका दे नहीं रहे हैं आखिर क्या होगा विधान सभा का। हम आपसे कहते हैं कि 4 साल गुजर गये हैं 100 रुपये का काम माधोगढ़ विधान सभा में सरकार ने अभी तक नहीं किया है। अध्यक्ष जी, आपने हमारे नियम–51, 301 में जो लगभग 10 काम पास किये हैं उसमें से एक पर भी काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है। केवल एक बात आ जाती है वित्तीय, केवल वित्तीय। मान्यवर, माधोगढ़ विधान सभा के लिए केवल वित्त नहीं है ऐसी स्थिति में हम कैसे कह दें कि यह बजट बहुत अच्छा है। यह बजट केवल इसी लाइन सत्ता पक्ष के लिए है जो कहते हैं कि बजट अच्छा है। हम 4 वर्ष से सुन रहे हैं कि बजट जानदार है, शानदार है लेकिन है किसके लिए। यह बजट न गरीबों के लिए है न किसानों के लिए है केवल समाजवादी पार्टी के लोगों के लिए है। इसलिए हम अपनी बात को नेता विरोधी दल के साथ जोड़ते हुए खत्म करते हैं। अध्यक्ष जी, एक समस्या और है। जनपद जालौन का उरई जो जनपद का हेडक्वार्टर है उरई नगर में उक्त मच्छर चौराहा था उसको सरकारी अभिलेखों में शहीद भगत सिंह चौराहे के नाम से दर्ज कर दिया गया है। सारे नगरपालिका, पूरे जनपद जालौन की जनभावना है कि वहां पर शहीद भगत सिंह को मूर्ति स्थापित कर दी जाय। अध्यक्ष जी, डेढ़ वर्ष से मूर्ति रखी है जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सारे सभी लोगों स्वीकृत हो करके फाइल आकर के सरकार में पड़ी है।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें। डा0 मुस्लिम जी आपकी आवाज बुलन्द है आप बोलें। कुशवाहा जी आप बैठ जायें।

'डा0 मो0 मुस्लिम–

मान्यवर, आभारी हं कि आपने मुझे मौका दिया 2016–17 के बजट में रूबरू होने के लिए। एक तो आपने तवज्जह दिया मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए बहुत–बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बजट जो 2016–17 का माननीय मुख्य मंत्री जी ने पेश किया। यह विचार सदन का है कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा था कुछ कहते हैं खराब था लेकिन जो बजट है बजट में बहुत अच्छी चीजें आई हैं। जो उत्तर प्रदेश के विकास के लिए आगे के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। इस बजट में कुछ कमियां हैं, जिसके लिए बजट में पैसा तो दे दिया जाता है, लेकिन बजट का पैसा इस्तेमाल नहीं हो पाता है कुछ अधिकारियों की कमियों की वजह से। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से अपने विधान सभा क्षेत्र तिलोई, जनपद अमेठी की कुछ समस्याओं की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। जब चुनाव की शुरुआत हुई थी तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने तिलोई की जनता से एक वायदा किया था कि अगर हमारी उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी तो तिलोई को हम रायबरेली में जुड़वा देंगे, लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी ने वायदा खिलाफी किया है। सलवन को तो जोड़ दिया गया, लेकिन तिलोई को नहीं जोड़ा गया। तिलोई में आंदोलन चल रहा है, आंदोलन में सैकड़ों–हजारों लोग भूख

---

* oDrk us Òk"k.k dk iquohZ{k.k ugha fd;kA

हड़ताल पर बैठ रहे हैं, जनता परेशान है कि तिलोई को रायबरेली में जोड़ दिया जाये। आपने गौरीगंज हेडक्वार्टर बना दिया, जिला बना दिया, लेकिन वहां पर न कोई अस्पताल है, न कोई रखरखाव है, वहां पर जाने का कोई रास्ता नहीं है, मार्ग खराब हैं, इसलिये मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कराते हुए अनुरोध करना चाहता हूं कि जो हैदरगढ़ से समरौता मार्ग है, जो गौरीगंज को जोड़ता है, जिसकी हालत बहुत जर्जर है, कृपया उसे बनवा दिया जाये। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे यहां जायस नगर पालिका है। जायस नगर पालिका की आबादी एक लाख की है, यहां कोई बड़ा अस्पताल नहीं है, सरकार ने घोषणा की थी कि हम यहां पर बड़ा अस्पताल बनायेंगे, लेकिन बदकिस्मती है कि आज तक वहां पर किसी अस्पताल की बुनियाद भी नहीं रखी गई है। माननीय मुख्य मंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अमेठी जिले में सैनिक स्कूल बनाने की घोषणा की है। जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझसे पूछा कि भई सैनिक स्कूल का क्या हो रहा है। जायस में माननीय राहुल गांधी जी ने एक केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव पास करा दिया था और माननीय मुख्य मंत्री जी ने उसके लिए जमीन भी दे दी थी, लेकिन अमेठी और जायस की बदकिस्मती यह है कि हमारे देश की मानव संसाधन विकास मंत्री श्रीमती स्मति ईरानी जी, जो हमारे यहां चुनाव भी लड़ी थी, वह पता नहीं उस स्कूल को कहां ले गई, वह आज तक खुला ही नहीं। मैं आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट कराते हुए अनुरोध करना चाहता हूं कि वहां पर स्कूल की सिफारिश की जाये और वहां पर केन्द्रीय विद्यालय खोला जाये। मेरी आपसे दरख्वाश्त है कि जायस नगर पालिका में शहरी बिजली मिलनी चाहिये। वहां पर शहर की बिजली का शिड्यूल निर्धारित है, लेकिन वहां पर गांव की बिजली मिलती है और पैसा हमसे शहर का वसूल किया जाता है। बिजली हमसे 12 घण्टे वसूल की जाती है, पैसा शहर के शिड्यूल के हिसाब से लिया जाता है। इसके लिए भी व्यवस्था की जाये। मैंने कई बार इसकी मांग की है, लेकिन आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपने यहां की सिंचाई की समस्या के बारे में भी अवगत कराना चाहता हूं। हमारे यहां हैदरगढ़ ब्रान्च है, हैदरगढ़ ब्रान्च में दो तीन नहरें जैसे सिंहपुर माइनर है, बस्तामऊ रजबहा है, उनमें पानी बिल्कुल नहीं जा रहा है, किसानों के खेत बिल्कुल बर्बाद हो रहे हैं, बगैर सिंचाई के वहां का किसान पूरी ताकत से खेती में पैदावार नहीं कर पा रहा है। ओला वृष्टि के लिए इस सरकार ने एलान किया, ओलावृष्टि में सरकार ने पैसा दिया, लेकिन कुछ चिन्हित गांवों में पैसा बांटा गया और वह पैसा उन्हीं गांव में दिया गया, जहां सत्तापक्ष के लोग थे। लोहिया गांव की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। हमारे यहां 31 गांवों को इसमें चयनित किया गया। पता चला कि माननीय मंत्री जी अमेठी के हैं उन्होंने 16 गांव ले लिये, और दूसरे विधायक जी ने 10 गांव ले लिये और मेरे जो बगल में हैं उनको दो गांव दिये गये और मुझको दो गांव दिये गये। आगे जो चयन हो रहा है पता नहीं क्या होगा भगवान जाने। लेकिन सरकार जो कह रही है कि हमने कुछ काम किये हैं, काम यह करते हैं लेकिन निष्पक्ष तरीके से काम नहीं हो रहे हैं, मुझे इस बात का

बड़ा दुख है। अध्यक्ष जी, सरकार से बड़ी उम्मीद होती है, वह काम निष्पक्ष करे, इसीलिये सरकार बनाई गयी है, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है, अगर यही हालात रहा तो इसका खामियाजा आगे अच्छा साबित नहीं होगा। जहां तक हमारे यहां केरोसिन आयल की बात है, हमारे अमेठी में उसके लिये एक जगह चिन्हित कर दिया गया है और हमारी विधान सभा है, वहां से 18 किमी0 दूर जाकर तेल मिलता है, किसानों को, वहां के लोगों को केरासिन आयल नहीं मिलता है, मेरी आपसे गुजारिश है कि कम से कम हमारे यहां बच्चों के पढ़ने के लिये, किसानों को दिया जलाने के लिये तेल तो मिल जाय। एक जगह पूरा तेल चला जाता है और वहीं से पूरा ब्लैक हो जाता है और जनता को तेल भी नहीं दिया जाता। आपने मुझे बोलने के लिये वक्त दिया, उसके लिये बहुत–बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।

'श्री वीरपाल राठी–

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। यहां पर माननीय मंत्री फातिमा जी, पवन पाण्डेय जी, राम करन जी ने बजट पर अपना जो पक्ष रखा उससे ऐसा लगता है कि अमेरिका का कोई व्यक्ति अगर इस सदन में होता तो वह यह उम्मीद करता कि तू भी इस उत्तर प्रदेश में बस जाये। मान्यवर, मैं एक बात के लिये तो उत्तर प्रदेश सरकार को धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने जो बजट में प्रस्ताव रखा, किसान दुर्घटना बीमा योजना, समाजवादी किसान हित योजना, इसके लिये मैं धन्यवाद दूंगा और साथ ही साथ यह भी निवेदन करूंगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर कोई ऐसी परियोजना इस बजट में नहीं रखी गयी, पांचवा बजट यह है और पांचवे बजट में अब तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिये कोई ऐसी परियोजना नहीं रखी गयी जिससे कि हम यहां पर सरकार को धन्यवाद दें। बहुत उपेक्षा की गयी है हमेशा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि इन्होंने बजट में कहा कि किसान वर्ष मना रहे हैं, युवा वर्ष मना रहे हैं और यह बात इन्होंने घोषणा–पत्र में भी कही थी कि हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे और भी बहुत सी ऐसी बांते कही थीं और कह रहे हैं कि हमने सारे वायदे पूरे किये और नये इरादे लेकर हम आये हैं। यह उत्तम प्रदेश की भी बात करते हैं लेकिन मान्यवर, बजट तो आखिर रखना ही पड़ेगा। सरकार चाहे यह रही हो चाहे वह रही हो, जो पैसा मिलेगा, बजट तो रखना ही पड़ेगा। लेकिन हमें यह भी देखना चाहिये कि कितने पैसे का बजट था और उसमें कितना लगा, इस पर सदन में कोई चर्चा नहीं हुयी। आप देखिये, मैं एक उदाहरण आपके सामने दूंगा। एक पी0डब्लू0डी0 मंत्री थे हमारे प्रदेश के, वह अमेरिका में चले गये । वहॉ के पी0डब्लू0डी0 मंत्री के पास रुके। रुकने के बाद में पी0डब्लू0डी0 मंत्री ...

श्री अध्यक्ष–

वह कौन थे, उनका नाम बताइये ।

श्री वीरपाल राठी–

मैं उनका नाम तो नहीं लूंगा। वह पी0डब्लू0डी0 मंत्री वहां रुके और वह उनको महल की छत पर लेकर गये, छत पर जब देखा तो छत से कुछ दूरी पर बहुत सुंदर

---

* oDrk us Òk"k.k dk iquohZ{k.k ugha fd;kA

लाइटें लगी हुयी थीं तो पी0डब्लू0डी0 मंत्री उत्तर प्रदेश बोले कि माननीय मंत्री जी यह क्या बात है, बहुत जानना है तो उन्होंने बताया कि यह पुल बनाया है और पुल बनाने का ही कमाल है कि राजमहल इतना बड़ा है। उसके बाद अमेरिका का पी0डब्लू0डी0 मंत्री जब उत्तर प्रदेश में आया तो आकर वह भी उसके महल पर चढ़ा, चढ़ने के बाद में देखा।

श्री अध्यक्ष–

अरे लन्तड़ानी मत सुनाइये, आप बजट पर बोलिये। आप बजट पर बोल ही नहीं रहे हैं और पूरा टाइम बरबाद कर रहे हो।

श्री वीरपाल राठी–

और वहां के पी0डब्लू0डी0 मंत्री ने कहा कि आपके यहां तो कोई लाइट ही नहीं है, आपके यहां तो कोई जानना ही नहीं है आपके यहां तो लाइट ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

यही सुनाना था तो क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, कोई अच्छा आदमी बोल लेता।

श्री वीरपाल राठी–

मान्यवर, उन्होंने कहा कि इसी का तो कमाल है कि मेरा महल इतना ऊंचा है। मान्यवर, मैं एक बात कहूंगा कि यह कृषि का बजट है मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आज किसान को प्रताड़ित किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष–

अब बैठो आप, इतनी देर से तो आप लन्तड़ानी सुना रहे थे, अब बैठो समाप्त, इतनी देर में तो अपनी बात कही नहीं आपने।

श्री वीरपाल राठी–

मान्यवर, मैं एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा, बहुत लम्बा समय है, मैं गन्ने पर एक बात कहूंगा कि मा0 अध्यक्ष जी सरकार से मेरा आग्रह है, जितना बड़ा बजट है और इस बजट में मा0 मुख्य मंत्री जी को अधिकार है कि वह पूल फण्ड बना करके गन्ने को दे सकते हैं और गन्ना किसानों का भला हो सकता है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

'श्रीमती विमला बाथम–

बहुत–बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी मैं नोएडा क्षेत्र से आती हूं।

[05.02] कार्य–मंत्रणा समिति द्वारा सदन में कार्यक्रम निर्धारण के सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

आप थोड़ा सा रूक जाएं, मुझे सदन को एक सूचना देनी है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य–मन्त्रणा समिति ने अपने दिनांक 26 फरवरी, 2016 की बैठक में विधान सभा की दिनांक 27 फरवरी, 2016 से दिनांक 11 मार्च, 2016 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप से रखे जाने की सिफारिशें की हैंः–

---

* oDrk us Òk"k.k dk iquohZ{k.k ugha fd;kA

1–दिनांक 04, 05, 06 व 08 मार्च, 2016 को नियम–300 व 301 की सूचनाएं न ली जाएं तथा नियम–56 के अन्तर्गत सूचनाएं ली जाएं।

2–दिनांक 04 मार्च, 2016 को अपराह्न में आय–व्ययक पर साधारण चर्चा पर मा0 मुख्य मंत्री का उत्तर भाषण हो।

3–दिनांक 27 फरवरी, 2016 से 11 मार्च, 2016 तक का शेष कार्यक्रम यथावत् रखा जाए।

लोक निर्माण एवं सिंचाई राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह पटेल)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गई, सहमत है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव जो मा0 संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

[05.04] वित्तीय वर्ष 2016–2017 के आय–व्ययक पर साधारण चर्चा (क्रमागत)

श्रीमती विमला बाथम–

मान्यवर, नौएडा यूपी की नाक है, यूपी की शान है नोएडा। नौएडा को हम कई भागों में बांट सकते हैं जिसमें रेजीडेंशियल, इण्डस्ट्रियल, कामर्शियल और इंस्टीट्यूशनल, इस तरह से हम चार भागों में नोएडा को बांटकर उसकी संरचना कर सकते हैं, जैसी संरचना हुई है। रेजीडेंशियल सेक्टर में कच्ची कॉलोनी, गांव, सोसायटी और प्राईवेट घर यह चार तरह की व्यवस्थाएं वहां पर हैं। इसमें जो कच्ची कॉलोनियां हैं उनमें लाखों लोग रहते हैं परन्तु वहां पर ना तो पानी है ना सीवर है और न ही किसी तरह की व्यवस्था है। सरकार का ध्यान मैंने कई बार दिलाया है परन्तु अभी तक जरा भी वहां परिवर्तन नहीं हुआ है। वह भी इंसान हैं वह अलग बात है कि वह इल्लीगल कॉलोनियां हैं लेकिन या तो उनको बसने ना दिया जाए और अगर बस गई हैं तो उनके रहने–सहने की व्यवस्था की जाए।

(इस समय 5 बजकर 2 मिनट पर अधिष्ठाता श्री राजबली जैसल पीठासीन हुये)

मान्यवर, नौएडा औद्योगिक सिटी है मैं उद्योगों के बारे में कुछ बातें रखूंगी, 2012 की औद्योगिक नीति के अन्तर्गत इलेक्ट्रानिक्स इंडस्ट्री के लिए प्लॉट लेने वालों को स्टैम्प ड्यूटी माफ करने की व्यवस्था की गई थी जो कि आज तक लागू नहीं हुई यह मा0 मुख्य मंत्री जी के संज्ञान में भी है। इसके अलावा आई0टी0 इण्डस्ट्री को जो प्लॉट आवंटित हुए थे चूंकि आई0टी0 इण्डस्ट्री बिल्कुल अलग तरह का बिजनेस है। वहां पर जो प्लॉट एलॉट हुए थे, उसमें जो लोग समय से नहीं बना पाये थे तो उन्होंने उस प्लॉट का लैण्ड यूज बदलने की बात कही थी, जिसे शासन से मान भी लिया था। आज मुझे क्षेत्र से पता चला कि 10 माह से आपके अधिकारी महेश गुप्ता, आई0डी0सी0 के पास वह फाइल पड़ी हुई है परन्तु उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। इससे लोगों को

बहुत परेशानी हो रही है। जो आई0टी0 इण्डस्ट्री लगाना चाहते थे परन्तु किसी कारणवश नहीं लगा पाये वह अपने प्लाट को कन्वर्ट कराना चाहते हैं एक सामान्य इण्डस्ट्री के लिए। इसी तरह नोएडा में जो लीज रेण्ट है, हम सभी लोग चाहते हैं कि वह जमीन फ्री–होल्ड हो जाए परन्तु वहां 99 साल की लीज है। लीज का मतलब आप किरायेदार हैं, मालिक नहीं हैं। जबकि करोड़ों रुपया हम लोग वहां इन्वेस्ट करते हैं परन्तु 99 साल के बाद में हम उसके मालिक नहीं रह जायेंगे जिसका खामियाजा हमारी आने वाली पीढ़ियां भुगतेंगी। तो इसको तुरन्त फ्री–होल्ड किया जाय। लीज रेण्ट में भी शुरू में जो वहां की कीमत थी वो बहुत कम थी ढाई–ढाई, तीन–तीन रुपये का मुआवजा मिला था गांव वालों को। सबसे पहली जो शुरुआत थी वह 40 रुपये मीटर की थी, मैं भी उसी वक्त के एलाटमेंट का एक हिस्सा हूं। उस समय में 40 रुपये में 2.5 प्रतिशत देना बहुत आसान था परन्तु मान्यवर, अब वहां दस हजार, पन्द्रह हजार, बीस हजार, 50 हजार का रेट है और ऐसे में 2.5 प्रतिशत बहुत ज्यादा है एक इण्डस्ट्री लगाने के लिए। तो इस लीज रेंट को या तो खत्म किया जाए या कम करके 01 प्रतिशत किया जाय, यह 01 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए क्योंकि जमीनों की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। मैं मेक इन इण्डिया की बात करूंगी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है। आपको ध्यान होगा जब नरसिम्हा राव की गवर्मेन्ट थी डब्ल्यू0टी0ओ0 की बात मैं जरूर करना चाहूंगी जिससे हमारा एक समझौता हुआ था उस समय विदेश नीति के तहत जिसमें हमें एक खास परसेण्ट के तहत विदेशी माल खरीदना पड़ता था। जिस वजह से हमारे यहां के जो नवयुवक थे वो बेरोजगार हुए और बेरोजगारी उस समय से आज तक बढ़ती गयी, कांग्रेस सरकार ने इसमें कुछ भी नहीं किया कि हमारे देश का क्या होगा ? अगर हम चीन जैसे देशों से माल लेते रहेंगे, उसका नतीजा यह हुआ कि चाइना के माल से मार्केट पूरा पट गया, यहां के बेरोजगार युवक घूमते रहे, रोजी रोटी को तरसते रहे। आज हमारी दीवाली की लड़ियां और गणेश लक्ष्मी भी चाइना से आते हैं, आप सब सदन में बैठे हुए लोग इस बात को जानते होंगे। इसको रोकने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो मेक इन इण्डिया का नारा दिया है, हमारे मुख्य मंत्री जी ने भी मेक इन यू0पी0 का नारा दिया है। प्रधानमंत्री और मुख्य मंत्री दोनों चाहते हैं कि यहां मैन्युफैक्चरिंग बढ़े। मेक इन यू0पी0, मेक इन इंडिया का मतलब है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में प्रगति हो। अगर जिस भी देश में मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कम है वहां एक लिमिटेड तरीके से उसका विकास हो सकता है अधिक विकास नहीं हो सकता। चूंकि 125 करोड़ की आबादी हमारे देश की है इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना इण्डिया को बहुत जरूरी है। हम अपने यू0पी0 की बात करते हैं, यू0पी0 में नोएडा जैसा एक इण्डिस्ट्रयल टाउनशिप डेवलप हुआ परन्तु सुविधाओं के अभाव में वहां जितना होना चाहिए वह नहीं हो रहा है। मेरी इस सरकार से प्रार्थना है कि नोएडा की तरफ विशेष ध्यान दें क्योंकि रेवन्यु का बहुत बड़ा हिस्सा जो पूरे प्रदेश में खर्च होता है वह नोएडा से आता है। नोएडा में इण्डस्ट्री को नो पॉवर कट जोन घोषित किया गया था, जो आज तक कभी भी नहीं लागू हुआ क्योंकि मुझे भी नोएडा में लगभग 30 साल हो

गये हैं इण्डस्ट्री चलाते हुए लेकिन आज तक मैंने नहीं देखा एक दिन ऐसा हो जब लाइट न गयी हो। उस नो पॉवर कट जोन का क्या अर्थ है, जो आपकी सरकार ने घोषित किया था। इसी के रिफरेंस में जब तक आप इण्डस्ट्री को सहूलियत नहीं देंगे तब तक इण्डस्ट्री नहीं चल पायेगी और इण्डस्ट्री नहीं चलेगी तो आप समझ सकते हैं कि सरकार का नुकसान है किसी और का नहीं क्योंकि रेवेन्यु सरकार को मिलेगा। नोएडा हाईटेक सिटी है, वर्ल्ड मैप पर है। मेरी एक प्रार्थना है कि मेरी विधान सभा नोएडा को औद्योगिक क्षेत्र में, रेजीडेंसियल क्षेत्र में विशेष सहूलियतें दी जाए ताकि नोएडा का विकास हो सके और नोएडा आगे बढ़ सके। उत्तर प्रदेश सरकार उसमें भागीदारी करेगी, फायदा जो भी सरकार आयेगी उसका होगा। इसके अलावा जिन किसानों की जमीन गयी है मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि उन किसानों को जिनकी जमीन पर नोएडा बसा है या ऐसी जहां–जहां जिनकी जमीन अधिग्रहीत की गयी है और बड़े बड़े शहर बस गये हैं उन किसानों को क्या मिला ? कई बार हमने इस सदन से भी प्रश्न उठाया, नोएडा एथारिटी को भी लिखा है, डेलीगेशन लेकर मिले कि उस परिवार के एक बच्चे को, जिसकी जमीन गई है सरकारी नौकरी मिल जाय तो उस परिवार का कल्याण हो जायेगा। आज उनके बच्चे भटक रहे हैं। इकट्ठा मुआवजा मिल गया करोड़ों में और वह खर्च कर डाला लोगों ने और आज उनकी बहुत दयनीय स्थिति है। तो एक बच्चे को सरकारी नौकरी मिलना अति आवश्यक है जिनकी जमीन अधिगृहीत की गई है। मान्यवर, शुद्ध पानी जो बेसिक नीड है, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगी कि अभी तीन–चार दिन पहले अखबारों में इतनी चर्चा हुई टाइम्स आफ इंडिया, हिन्दुस्तान टाइम्स, दैनिक जागरण हर अखबार में बड़े बड़े मोटे शब्दों में लिखा है वाई सेक्टर–53 जहां चार दिन से पानी बिल्कुल कीचड़ जैसा आ रहा है। हम तो खुद भुक्तभोगी हैं, जब नल खोलते हैं तो 3/4 बाल्टी पानी जो है वह कीचड़ निकलता है। छोटे–छोटे शहरों में भी मैं जाती हूं वहॉ पर भी जब भी नल खोलो शुद्ध पानी निकलता है। लखनऊ में भी मैंने देखा शुद्ध पानी नहाने जाते हैं नल खोलो तो शुद्ध पानी निकलता है। लेकिन नोएडा में ऐसा क्या है ? हाई टेक सिटी है, इतना फंड है वहां पर, इतने पैसे हैं वहां पर एथारिटी के पास, फिर भी वह पानी को शुद्ध नहीं कर पा रहे हैं। पेयजल जो हमारी बेसिक जरूरत है और सरकार का कर्तव्य है कि पेयजल की व्यवस्था करना, वह नहीं हो पा रही है। आपके माध्यम से मैं सरकार को अवगत कराना चाहूंगी।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य विमला जी अब आप समाप्त करें।

श्रीमती विमला बाथम–

मान्यवर, बस मैं अभी एक मिनट में खत्म कर रही हूं। मैं कहना चाहूंगी कि सरकार पेयजल की समस्या तुरन्त दूर करे और नोएडा को शुद्ध जल मुहैया कराये। गंगाजल की भी बात थी लेकिन वह लगता है सपना बन गया है या तो वहां की लाइनें जर्जर हैं या जो भी समस्या है उसकी तह तक जायं और उस समस्या को तुरन्त हल कराकर शुद्ध पानी की व्यवस्था करें। एक अंतिम बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त

करूंगी। नोएडा में सारे आई0ए0एस0 अधिकारी वहीं बैठकर सारी चर्चाए करते हैं। बोर्ड बैठक में जो भी डिसीजन लेना होता है वो ले लेते हैं। जो नोएडा के जन प्रतिनिधि हैं जो वहां की समस्या जानते हैं कि समस्या है क्या ? रूट लेविल पर समस्या है क्या, उसकी कोई भागीदारी नहीं है। न तो वह अपनी बात कह सकता है, न सुन सकता है न अपनी बात मनवा सकता है। ऐसे माहौल में नोएडा की जो बेसिक जरूरते हैं जो बेसिक समस्याएं हैं, वह दूर होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मान्यवर, मेरी आपके माध्यम से गुजारिश है इस सरकार से कि एथारिटी में जनप्रतिनिधियों की भागीदारी बहुत आवश्यक है। कोई सरकार हो, कोई जनप्रतिनिधि हो, उसको वहां रहना जरूरी है, अगर वो हीं रहता तो सरकार को समस्याएं कौन रखेगा क्षेत्र की, क्योंकि आई0ए0एस0 अधिकारी तो मेहमानों की तरह होते हैं आये और चले आये, आये और चले गये उनको नहीं मालूम कि समस्याएं वाकई में क्या हैं। दूसरी अंतिम बात यह कि यहां सरकार से जितनी ग्रान्ट मिलती है, जो भी नोएडा एथारिटी काम कराती है उसमें पता नहीं चलता कि क्या काम करा रहे हैं? कितना फंड आया है ? इसकी व्यवस्था की जाय कि जो वहां जनप्रतिनिधि हैं उनको जरूर अवगत कराया जाय अगर एथारिटी कोई काम करने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य कोई सत्ता पक्ष से है बोलने वाला ?

'श्री अब्दुल मशहूद खां–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने बजट पर चर्चा में हिस्सा लेने का मुझे दोबारा मौका दिया, इसके लिये मैं आपका बहुत आभारी हूं।

(विपक्ष की तरफ से एक माननीय सदस्य एक बार बोल चुके हैं)

श्री अधिष्ठाता–

आप बोल चुके हैं क्या ?

श्री अब्दुल मशहूद खां–

मान्यवर, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। मान्यवर, आज दुनिया ग्लोबल वार्मिंग से झेल रही है इस ओर किसी का ध्यान नहीं जाता।

श्री अधिष्ठाता–

आप बोल चुके हैं, बैठ जाइये।

'श्री पंकज कुमार मलिक–

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिये आपका धन्यवाद करता हूं। अधिष्ठाता जी, मैं कहना चाहता हूं कि मैंने बजट का पेज नम्बर–16 देखा जिसमें लिखा हुआ है कि किसानों के गन्ना अवशेष भुगतान मूल्य के लिये इतने करोड़ रुपये की बजट में व्यवस्था की गई। हृदय कांपता है यह धनराशि देख करके। नजर पड़ती है माननीय अधिष्ठाता जी, उन लोगों की तरफ जो लोग भूखे मर रहे हैं

---

* oDrk us Òk"k.k dk iquohZ{k.k ugha fd;kA

जिनको आज भी 240 रुपये के हिसाब से 240 रुपये के हिसाब से, 240 का भी बाकी है और जो नया सिस्टम आपने बनाया है 230, उसका भी बाकी है। गन्ना किसान का 496 करोड़ बाकी है। बात करते हैं किसान वर्ष की और किसान भूखों मर रहा है। अधिष्ठाता जी, बार–बार मा0 न्यायालयों की बात आती है कि उनके संदर्भ में जो आदेश आते हैं तो उनका पालन सरकार करती है कहां करती है, सरकार को आदेश था कि ब्याज सहित भुगतान किया जाएगा, अधिष्ठाता जी, अकेले पिछले वर्ष का 600 करोड़ रुपया ब्याज बैठता है 496 के ऊपर जो किसानों को अनदेखा सरकार कर रही है। मैं बताना चाहता हूं इस सरकार को, कि 230 रुपये करोड़ के हिसाब से लगभग नौ हजार करोड़ बकाया है इस वर्ष का, और 280 के हिसाब से लगभग 12 हजार करोड़। एक चीज और मेरी समझ में नहीं आती है बात करते हैं किसान की खुशहाली की, और जब मैं देखता हूं तो हिन्दुस्तान की जो सरकार है वह साम्प्रदायिकता की आग में हिन्दुस्तान को झोंककर सरकार बनी है। उस सरकार को, उस सरकार के कामों को समर्थन करते हो, चुप्पी से समर्थन करते हो, समर्थन की बात इसलिए कहता हूं 230 रुपये की आपने बात की, केन्द्र सरकार का गन्ने का समर्थन मूल्य 230 रुपये है। क्या आप 230 और 50 के हिसाब से जो पैसा दे रहे हैं क्या चुपचाप कहीं गन्ना किसान के विरोध में, कहीं केन्द्र सरकार को समर्थन देने का काम तो नहीं कर रहे हैं। स्पष्ट किया जाना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले हमारे सम्मानित साथी और मंत्री पवन पाण्डेय जी एक बात कह रहे थे, देखिए इसके लिए मैं मुख्य मंत्री जी को बधाई दूंगा मैं पिछली बार भी सदन में था। वास्तव में हम लोग कभी जो उस समय की आदरणीय मुख्य मंत्री जी थीं उनसे नहीं मिल पाए। आज हौसले के साथ एक नौजवान मुख्य मंत्री है मिलकर के अपना पत्र तो दे देते हैं उनका व्यवहार अच्छा है वह एक राजनैतिक परिवार से हैं। इसीलिए हमारा हौसला बढ़ता है और इसलिए हम वहां जाते हैं। लेकिन इसका भी इन्होंने हमें उलाहना दे दिया हमारी भाषा में उलाहना कहते हैं कह दिया कि विपक्ष के विधायक वहां जाते है। यहां जो दल बैठता है जो लोगों का खून बहाकर राजनीति करता है मैं उनका समर्थन नहीं करता हूं एक सदस्य के नाते कहना चाहता हूं बड़ा दर्द हुआ हम सदन के सदस्य हैं मुख्य मंत्री जी के पास जाएंगे मैं भी जाता हूं मैं पत्र लेकर के जाता हूं लेकिन मेरे पत्रों का जो हाल होता है उस संबंध में एक लाइन कहना चाहता हूं–

हीरों की बस्ती में हमने कांच ही कांच बटोरे हैं,
कितने लिखे फसाने फिर भी सारे कागज कोरे हैं।।

आज शामली को विकास से अछूता रखा गया है वहां पर राजस्व उठाकर देखें सरकार को कितना फायदा होता है। अछूता रखा गया है विकास से, चाहे पीने के पानी की समस्या हो, आज पूरे जनपद का सर्वे करा लीजिएगा। पीने का पानी खराब होने की वजह से लोग कैंसर जैसी गम्भीर बीमारियों से ग्रस्त हैं। सम्मानित सदस्य राणा जी कह रहे थे इनके क्षेत्र में भी यही हाल है। बुरा हाल है कहते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश बड़ा सम्पन्न प्रदेश है हरियाली का क्षेत्र है सम्पन्नता कहां रही वहां पर, किसान भूखे मरने की कगार पर है। अधिष्ठाता जी, अकेले शामली में पांच हजार से ज्यादा हैण्डपम्प खराब हैं।

दुर्भाग्य की बात है मैं आपके माध्यम से सरकार को सुझाव देना चाहूंगा पुराने हैण्डपम्प ही ठीक करा दो, नये तो मिल नहीं रहे हैं नये मिल जाते तो अच्छी बात, लेकिन पुराने हैण्डपम्प ठीक कराकर बीमारी से तो बचा ही जा सकता है। दूसरी बात आज उत्तर प्रदेश के जितने भी बड़े शहर हैं एक गम्भीर समस्या से ग्रसित हैं जाम की समस्या। मैं चाहता हूं कि सरकार विशेष रूप से जाम की तरफ ध्यान दे। आप शामली जनपद को देख लीजिएगा या मुजफ्फरनगर जनपद को देख लीजिएगा। मुख्यालय पर अगर आपको एक किलोमीटर चलना है तो कई बार ऐसा हो जाता है कि एक घंटे का सफर तय करके एक किलोमीटर जाया जाता है। मैं तो कई बार गाड़ी छोड़कर पैदल गया हूं या स्कूटर से गया हूं या मोटरसाइकिल से गया हूं। इतनी खराब स्थिति है मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि शामली में एक तरफ का बाईपास प्रस्तावित है जो बलत को होकर निकलता है, वलवा से वाल्दा को होकर निकलता है दिल्ली यमुनोत्री मार्ग का हिस्सा जलालाबाद होते हुए सहारनपुर जाता है वहां जाकर मिलता है मैं कहना चाहता हूं कि इस समस्या को देखते हुए आज आवश्यकता है दूसरी तरफ भी शहर को बाईपास से जोड़ा जाए।जो मेरठ करनाल रोड को मिलता है गांव पिटोली की तरफ सरकार उसका संज्ञान ले बड़ी गम्भीर समस्या है जो जिले का मुख्यालय जनपद पिछली सरकार ने बनाया था अब इसे आगे बढ़ाना विकास को गति देना आपका काम है आपकी जिम्मेदारी बनती है। आज मेरे क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र की बात आप करते हैं और मैंने भी पढ़ा और सुना है। मेरे पिताजी चार बार एम0एल0ए0 रहे जानता हूं कि मुलायम सिंह जी ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए बड़ा काम करते थे अगर आपका ध्यान उधर न गया हो तो कम से कम मैं अपने क्षेत्र की बात कहना चाहता हूं मेरे क्षेत्र में कांधला से गंगेरू मार्ग कांधला से कैराना मार्ग, कांधला से बुढ़ाना मार्ग, कांधला से शामली मार्ग और करीब शत–प्रतिशत गांव को जो रास्ता जोड़ता है उन रास्तों पर बसें नहीं चलतीं। बसों की भारी कमी है। शामली से थाना भवन के लिए कमी है शामली आपने नई तहसील बनाई है ऊन की तरफ नहीं जाया जा सकता बड़ी खराब स्थिति है सड़कें तो हैं नहीं परिवहन की स्थिति भी खराब है। परिवहन में सुधार किया जा सकता है यह आवश्यकता है। दूसरा बड़े लम्बे समय से पिछली जो केन्द्र में सरकार थी उस सरकार के समय में इस सरकार ने काम किया था पानीपत खटीमा मार्ग दिल्ली यमुनोत्री मार्ग का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए उसका चौड़ीकरण होना था नए स्तर से मार्ग बनना था वह मार्ग आज भी खटाई में पड़ा है। सुना है उसे पी0डब्लू0डी0 बना रही है मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि उस पर जल्द से जल्द काम किया जाए। तो दिल्ली से जो आने वाले लोग हैं चाहे वह हरिद्वार जाते हों सहारनपुर जाते हों देहरादून जाते हों, उत्तरांचल जाते हों बड़ा लोगों को लाभ मिलेगा जनहित की बात होगी। दूसरा कुटीर उद्योगों की बात आती है। अधिष्ठाता जी आज हम एक तरफ बात करते हैं युवाओं की नौजवानों की उन्हें रोजगार देने की बात करते हैं लेकिन अगर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा तो रोजगार देने के अवसर सरकार ज्यादा प्राप्त करा सकती है। सरकार ने जो चुनाव में वायदा किया था उसे पूरा कर सकती है। दूसरी बात मेरा पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश मेरा

जिला पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आता है वहां पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में मैं तो कहूंगा पूरे उत्तर प्रदेश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है खेल के क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का काम उत्तर प्रदेश के लोगों ने किया मैं उसमें शामली की बात जोड़ना चाहूंगा खेल मंत्री जी यहां बैठे थे वह होंगे तो मेरी बात सुन ही लेंगे।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें।

श्री पंकज कुमार मलिक–

अधिष्ठता जी जनता की बात थोड़ा समय बढ़ा दीजिए। वहां स्टेडियम के नाम पर कुछ नहीं है नौजवान ऐसे ही सड़कों पर रेस लगाते हैं भर्ती की तैयारी करते हैं, खेल की तैयारी करते हैं। वहां स्टेडियम की अति आवश्यकता है स्टेडियम होना चाहिए खासतौर पर कबड्डी और कुश्ती के खिलाड़ियों के लिए नई व्यवस्था होनी चाहिए आज की तकनीक के हिसाब से वहां सुविधाओं का अभाव है। हमारे क्षेत्र में शूटिंग के बहुत खिलाड़ी हैं जो शूटिंग करते हैं और कई बार राष्ट्रीय स्तर पर नाम किया है उनके लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए। जो गांव पहले जनेश्वर मिश्र योजना और लोहिया योजना में हुए थे कम से कम इस सदन के सम्मानित सदस्यों की एक समिति बनाकर जांच जिले के अधिकारियों के सामने करवा दीजिएगा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हम भी देखते हैं मुख्य मंत्री जी अच्छी बात करते हैं उनकी बातों को सुनकर लगता है कि कुछ करना चाहते हैं पर पता नहीं खामियां कहां रह जाती हैं मैं नहीं जानता लेकिन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। गन्ना भुगतान की बात मैंने कही किसान के लिए बात आती है, नौजवान के लिए बात आती है सरकार से बहुत अच्छा जवाब आता है लेकिन जब समय दाखिलों का आता है तो हजारों हजार बच्चे एडमीशन से वंचित रह जाते हैं। अधिष्ठाता जी बातें तो और भी हैं लेकिन समय देखकर मैं यहीं पर अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री कपिल देव अग्रवाल–

अधिष्ठाता महोदय बहुत बहुत धन्यवाद। प्रथम बार मुझे इस सदन में अपनी बात कहने का अवसर मिल रहा है मान्यवर, अभी हम निर्वाचित होकर आए हैं पूर्व में चार वर्ष तक हमारे राज्यमंत्री रहे हैं लेकिन बहुत बड़ी समस्या मुजफ्फरनगर शहर की है। वहां जाम की समस्या है वहां पर तीन सर्किल में बाईपास बना हुआ है लेकिन शामली करनाल रोड से लेकर एन0एच058 तक उसका प्रस्ताव मैंने नगर पालिका अध्यक्ष रहते हुए चार वर्ष पूर्व भी दिया था उसका इस्टीमेट भी बनकर शासन के पास आया है लेकिन अभी तक उसके अन्दर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। शामली रोड से लेकर सहारनपुर रोड होते हुए एन0एच058 तक बाईपास का निर्माण होना बहुत आवश्यक है। उसके कारण से सरवर चौक के सामने जाम की हमेशा समस्या रहती है और घण्टों घण्टों तक पूरा शहर जाम रहता है जनहित में यह कार्य बहुत आवश्यक है। मान्यवर, मेरा अगला निवेदन यह है। अभी डिग्री कालेज में एडमिशन होने वाले हैं। वहां पर जितने भी डिग्री कालेज हैं उनमें पहले सांध्यकालीन कक्षाएं चलती थीं। इण्टरमीडिएट में जिन बच्चों के

70 प्रतिशत तक मार्क्स आते हैं, उनके एडमिशन मैरिट के आधार पर डिग्री कालेज में नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण छात्रों को धरना–प्रदर्शन और आंदोलन करना पड़ता है फिर समझौते होते हैं, वी0सी0 का घेराव होता है, लेकिन वी0सी0 और प्राईवेट डिग्री कालेज आपस में मिले हुये हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ यह बात कह सकता हूं कि जब से प्राईवेट डिग्री कालेज की व्यवस्था हुई है तब से सांध्यकालीन कक्षाएं चलनी बंद हो गयी हैं, इस कारण से छात्रों को बहुत अधिक पैसा देकर एडमिशन लेना पड़ता है। गरीब, निर्धन और असहाय बच्चों को एडमिशन लेने का मौका नहीं मिलता है जिससे वह बहुत परेशान रहते हैं। प्रदेश भर की यूनिवर्सिटियों की जो समस्या है वह मुझे नहीं मालूम हैं, परन्तु मुझे अपने क्षेत्र की समस्या मालूम है। इसलिये मैं चाहूंगा कि मेरठ में जो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है, वहां छात्र–छात्राओं को एडमिशन दिलवाने का काम करें।

(इस समय 5 बजकर 27 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

मा0 अधिष्ठाता जी, बिजली की समस्या बहुत गंभीर है। कल मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी ने आपत्ति की थी, जिससे मुझे और मेरे क्षेत्र के लोगों को भी बड़ा कष्ट हुआ, मेरे क्षेत्र से मेरे पास कई फोन आये। उन्होंने कहा कि उद्यमी बिजली चोरी करते हैं। इस बात का मुझे बेहद कष्ट है। यदि आज वहां उपस्थित होते तो शायद मेरी बात का उत्तर देते। मुजफ्फरनगर को स्टील उद्योग के लिये पूरे उत्तर प्रदेश में जाना जाता है। इस सरकार ने बिजली के 40 से 50 प्रतिशत रेट दो वर्ष पूर्व बढ़ाये थे। हमारे क्षेत्र में स्टील की 70 यूनिटें थीं, जिनमें से 60 यूनिटें बंद हो चुकी हैं और 10 यूनिटें जो वर्तमान में चल रही हैं वह भी बंदी की कगार पर हैं। जब उद्यमी बिजली की चोरी करते हैं तो फैक्ट्रियां कहां से बंद हो गयीं? सच्चाई यह है कि बिजली के रेट इतने अधिक बढ़ गये हैं कि उद्यम की कमर टूट गयी है। अभी जो पेपर मिल चल रही हैं और कुछ स्टील उद्योग चल रहे हैं, उन पर इन्ट्री टैक्स लगाया गया है, इन्ट्री टैक्स लगाये जाने के कारण से वह उद्योग भी लगातार बंदी के कगार पर हैं, उनका बहुत अधिक शोषण हो रहा है। इस इन्ट्री टैक्स की डिटेल मैं अलग से दे दूंगा। मैं चाहूंगा कि वह इन्ट्री टैक्स समाप्त किया जाये। मान्यवर, मेरा निवेदन यह है कि अभी चुनाव के समय तक शहर की बिजली 22 घंटे तक आ रही थी, जिस दिन चुनाव परिणाम आया, उस दिन से बिजली 16 घंटे से भी कम होकर 12–14 घंटे रह गयी है। छात्रों की परीक्षाएं चल रही हैं। सुबह 5 बजे तक बिजली आती है और 5 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक बिजली कट जाती है जिससे बच्चों को स्नान करने में, माताओं को पूजा करने तथा बच्चों को तैयार करने में परेशानी होती है।

मा0 अध्यक्ष महोदय जी, यह मेरे लिये प्रसन्नता की बात है कि मुझे आपके सामने भी अपनी बात कहने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं बिजली की बात कर रहा था कि जो बिजली अभी 22 घंटे आ रही थी, चुनावों के परिणाम के बाद वह बिजली 14 घंटे ही रह गयी। बच्चों की इंटरमीडिएट, हाईस्कूल की परीक्षाएं चल रही हैं। मान्यवर, सुबह 5 बजे तक बिजली आती है और 5 बजे से 9 बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित

रहती है, जिससे बच्चों को नहाने–धोने, पढ़ने–लिखने, स्कूल जाने की तैयारी करने में बहुत दिक्कत होती है। मैं चाहूंगा कि बिजली की कटौती को कम करके विद्युत आपूर्ति बढाई जाये। मान्यवर, वहां पर 25 वर्ष पूर्व सीवर लाईन बिछाई गयी थी, आज तक उन सीवर लाईनों की सफाई न होने से वह सभी चोक पड़ी हैं, जिस कारण से वहॉ पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। अतः सीवर लाईन की सफाई होना जनहित में बहुत आवश्यक है। अंत में मैं कहना चाहूंगा कि एक जनकपुरी कालोनी है, जिसमें बहुत गरीब लोग रहते हैं, वह लकड़ी बीनने का काम करते हैं। मेरा निवेदन यह है कि वह कालोनी नियमित की जाये। उसमें पानी की व्यवस्था नहीं है, सीवर की व्यवस्था नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है। उनके राशन कार्ड बने हुये हैं, वोटर कार्ड बने हुये हैं, लेकिन उस तरफ नगर पालिका की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उन लोगों को भी उनका अधिकार दिलाकर संवैधानिक व्यवस्था को कायम किया जाये। मान्यवर, गांधी कालोनी में भी सीवर की आवश्यकता है, सीवर न होने की वजह से लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे प्रथम बार बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपका बहुत–बहुत आभारी हूं।

'श्री सुरेश राणा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस विषय पर बजट की चर्चा का मुझे अवसर दिया। माननीय अध्यक्ष जी, किसान वर्ष की बात थी और लगातार किसानों की चर्चा यह सरकार करती है लेकिन बड़े कष्ट के साथ कहना पड़ता है कि जब हम प्रदेश के बराबर के राज्यों को देखते हैं और उनकी कृषि दर के बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है कि 2.3 प्रतिशत पर कृषि दर पर हम खड़े कहां हैं ? हम किसानों की बात करते हैं और 2.3 प्रतिशत जहां कृषि दर है, मुख्य मंत्री जी भी डबल डिजिट की बात लगातार कर रहे हैं कि हम डबल डिजिट में विकास दर को ले जाना चाहते हैं। जब कृषि दर में आप इतने पिछड़े हुए हो तो डबल डिजिट में कहां जाओगे और कृषि दर में भी हम लोग लगातार यहां गन्ने की बात करते हैं। लगातार मांग करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, तीन साल से तो मैं लगातार देख रहा हूं। अध्यक्ष जी, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, आपकी तो बड़ी कृपा पश्चिम पर रहती है, मुझे लगता था कि यह सरकार 02 महीने में जितने भी लोगों ने गड़बड़ किया है, सब के खिलाफ कार्रवाई कर देगी। कितने सारे शुगर मिल बेंच लिए, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुझे तो कई बार यह लगता है कि इन दोनों दलों का एक अच्छा–खासा गठबन्धन है। कई सारे विषय हैं, जो इस ओर इशारा करते हैं, यह दोनों दलों का गठबन्धन है। इन्होंने गन्ने के मिल बेंचे, इनका समय आया, लगता था कि कार्रवाई करेंगे, आज हालत क्या है, 09 हजार करोड़ रूपया बकाया है और पहली बार ऐसा हुआ है कि दो किश्तों में भुगतान की परम्परा इस सरकार ने शुरू की है और आप थे तो साढ़े तीन सौ मांगते थे, आज 280 है, उसमें भी आप दो किश्तों में भुगतान कर रहे हैं और अध्यक्ष जी, यह हालत तब है, आप विशेषज्ञ हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं, यह हालत जब है कि इस वर्ष सवा परसेण्ट

* oDrk us Òk"k.k dk iquohZ{k.k ugha fd;kA

रिकवरी बढ़ी है। सवा परसेण्ट रिकवरी इस बार चीनी की बढ़ी है और सवा परसेण्ट का मतलब मान करके चलिए कि कम से कम एक कुन्तल पर 50 रुपये का सीधा फायदा हो रहा है, तब यह हालत है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तो 'नसीब में जिसके जो लिखा था, वह तेरी महफिल में काम आया, किसी के हिस्से में प्यास आयी, किसी के हिस्से में जाम आया।' हमारे हिस्से में दंगा आया। कल भी संसदीय कार्य मंत्री जी आरक्षण पर बोल रहे थे, अरे, हमने तो प्रदेश में आरक्षण दिया था, आपने मुकदमें दिए, सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में नौजवान झूठे मुकदमों में जेल में हैं। हमने प्रदेश के अन्दर आरक्षण दिया था, आपने झूठे मुकदमें दिए हैं, आपने झूठे रासुका दिए हैं, आपने गॉवों को बर्बादी दी है, आपने गांव को दो हिस्सों में बांट करके रख दिया। अध्यक्ष जी, हमने पिछले बजट में भी सुझाव दिया था, आगरा में कई कार्यक्रम आपके हुए हैं, दिल्ली से ले करके जो यमुना की पटरी है, वह थाना मोड़ शामली से हो करके सहारनपुर का एक ऐसा पैरलल मार्ग हो सकता है, लेकिन उसकी चिन्ता बजट में नहीं की गयी है। दिल्ली–यमुनोत्री पर लगातार पहले दिन से माननीय मुख्य मंत्री जी गंभीर हैं। हम लोग कई बार सोचते हैं, नौजवान मुख्य मंत्री हैं, पढ़े–लिखे हैं, सकारात्मक भी है, फिर कारण क्या है, विकास कहां रुका हुआ है ? वह कहते भी है कि विकास का पहिया प्रदेश के अन्दर घूम रहा है, पहिया तो घूम रहा है, परन्तु अध्यक्ष जी मुझे लगता है कि साइकिल खड़ी हुई है, खड़ी हुई साइकिल का पहिया घूम रहा है। उसका स्पष्ट उदाहरण है कि चार साल से लगातार बात हो रही है, दिल्ली–यमुनोत्री की, मैं तो उस सड़क पर रहता हूं, चार साल में आज तक अध्यक्ष जी, उस सड़क पर काम शुरू नहीं हुआ। पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश डेंगू के कहर से तड़प रहा है। एक–एक गांव के अन्दर 20–20 मौंते डेंगू से हुई हैं। हमने पिछले वर्ष भी निवेदन किया था कि आप हर जिला मुख्यालय पर, हर जिला चिकित्सालय पर एक ब्लड कम्पोनेंट मशीन दे दो, कम से कम जो गरीब आदमी तड़पते हैं, उनके इलाज की सुविधा हो जायेगी। लेकिन कोई व्यवस्था नहीं हुई। अध्यक्ष जी, मुझे लगता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश षड्यन्त्र का शिकार है। अरे, तड़प तो हम रहे हैं लेकिन व्यवस्था हो रही है कन्नौज के अन्दर, व्यवस्था कन्नौज में और तड़प हम रहे हैं। बिजली का कनेक्शन नहीं, कैसे करेंगे सिंचाई ? 04 साल में एक भी सिंचाई योजना न शामली को है, न बागपत को है, न मेरठ को है, न मुजफ्फरनगर को है, न सहारनपुर को है और जिन नहरों में 02 हजार क्यूसेक पानी होना चाहिए, यमुना नहर में 02 हजार क्यूसेक पानी होना चाहिए, आज मात्र 800 क्यूसेक पानी चल रहा है, 1200 क्यूसेक पानी गायब है। न नहरों में पानी है, न सड़क है, न बिजली है। बिजली की बात अभी हमारे साथी भी कह रहे थे। संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी कहा था बिजली चोरी उद्यमी करते है, मैं पूरे दावे के साथ सदन में कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता के खिलाफ अभी पिछले साल 02 करोड़ की बिजली चोरी का आरोप मुजफ्फरनगर के अन्दर लगा, जिस अधिकारी ने पकड़ा पहले उसका तबादला कर दिया गया और बाद में उसे सस्पेण्ड कर दिया गया। जो बिजली चोरी कर रहे हैं, उन्हें उजागर करने के

लिए आप सांस नहीं लेते और उद्यमियों के बारे में आप कह रहो हो कि आप बिजली चोरी कर रहे हो।

श्री अध्यक्ष–

कृपया अब समाप्त करें।

श्री सुरेश राणा–

मा0 अध्यक्ष जी, बस थोड़ा सा बचा है, अभी समय ही कितना हुआ है। मान्यवर, आपसे निवेदन है कई बार विषय आता है तो संसदीय कार्य मंत्री जी कह देते हैं कि देश जाने, प्रधानमंत्री जाने, अरे मैं बधाई देना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री को, आज यदि देश के प्रधानमंत्री गन्ना किसानों के लिए योजना न बनाते, चीनी की इम्पोर्ट ड्यूटी को 10 से 40 परसेण्ट न करते, तो दावे से कहता हूं मैं अध्यक्ष जी, अबकी बार शुगर मिलें न चलती। 10 से लेकर के 40 परसेण्ट इम्पोर्ट ड्यूटी कर दी, अभी सुबह ही सदन में बवाल उठा और आज समाजवादी के वंशज मैं लोहिया जी को देखता हूं तो याद करता हूं कि उन्हें लगता होगा, वह क्या सोंचते होंगे,

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें। दीपक पटेल जी बोलना है ? या लिखकर देंगे ?

श्री सुरेश राणा–

मा0 अध्यक्ष जी एक मिनट, मेरा आपसे अनुरोध है कि कोई व्यवस्था चाहे तहसील हो, चाहे ब्लाक हो, चाहे थाना हो, इनकी सरकार थी तो 50 रुपये में प्रमाण–पत्र बनता था, आज 100 रुपये में प्रमाण–पत्र बनता है, थाने में आप जा नहीं सकते, ब्लाक में न कोई सचिव है, न गांव की कोई व्यवस्था है, सारी व्यवस्था अध्यक्ष जी चरमरा गई है, किसी प्रकार की व्यवस्था इस सरकार में नहीं है। मान्यवर, पिछले बजट में आपने कहा था एक लाख की आबादी के शहरों को बाईपास देंगे, थानाभवन की आबादी एक लाख, शामली की आबादी एक लाख कोई बाईपास नहीं, चार–चार घण्टे हम शामली में जाम में खड़े रहते हैं, एक–एक घण्टे का थानाभवन में जाम लगता है, मुजफ्फरनगर में जाम लगता है, यदि मेरठ से होकर आना–जाना हो दिल्ली तो मुरादनगर की हालत ऐसी है कि मुरादनगर में आज भी हम लोग दो–दो घण्टे जाम में खड़े होते हैं। पूरी तरह से नक्शे से ऐसी–ऐसी योजना हैं जिससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान पलायन कर जाय और वहां की सारी भूमि उद्योगपतियों के हवाले कर दी जाय।

श्री अध्यक्ष–

राणा साहब बहुत बोल लिये, अब समाप्त करें।

श्री सुरेश राणा–

मा0 अध्यक्ष जी, अन्त में मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि किसान रो रहा है, किसान तड़प रहा है और लोहिया जी का नारा अन्त में सुना कर के अपनी बात समाप्त करूंगा, लोहिया जी बालते थे कि ''इस देश में जो 16 आना पैसा है, उस 16 आने में से 13 आने एक परिवार पर खर्च होता है और 03 आने में पूरा देश चलता है।'' मैं आज लोहिया के अनुयायियों से कहना चाहता हूं आज वही स्थिति है

अध्यक्ष जी, 16 आने में से 13 आने कन्नौज, इटावा, एटा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, आजमगढ़ पर खर्च होता है और 03 आने में पूरा प्रदेश चलता है। मा0 अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत–बहुत धन्यवाद।

'डा0 संग्राम यादव–

माननीय अध्यक्ष जी, हम आपके प्रति बहुत–बहुत आभार प्रकट करते हैं कि आपने मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा 2016–17 के बजट के धन्यवाद् प्रस्ताव पर हमें बोलने का अवसर दिया। मा0 अध्यक्ष जी, मा0 मुख्य मंत्री जी जब बजट प्रस्तुत कर रहे थे, तो उन्होंने अपने बजट भाषण के शुरुआत में ही कहा कि ''जनता के लिए जिसके मन में प्यार नहीं, वह कुर्सी का हकदार नहीं'', हम कहना चाहते हैं अपने भारतीय जनता पार्टी के साथी से हमारे मुख्य मंत्री जी तो स्पष्ट रूप से अपनी शुरुआत ही बजट भाषण में किसानों के लिए जनता के लिए और बड़ी बात उन्होंने कहा कि जिसके मन में जनता के प्रति प्यार नहीं है, वह उन कुर्सियों पर बैठने का हकदार नहीं है, आप कहां से उठाये किसान, आपने युवा ला–लाकर साम्प्रदायिक एजेण्डे पर आप खड़े हो गये। आप बांट कर उत्तर प्रदेश को देखने लगे, आप शामली–शामली–शामली, अगर आपका भाषण निकाल लिया जाय तो क्या आपने उन सुदूर क्षेत्रों, सोनभद्र की आपने बात की, आपने मिर्जापुर की बात की, चन्दौली की बात की, मऊ, अम्बेडकरनगर की बात की, आप कहते हैं राष्ट्रीय नेता भारतीय जनता, आप नहीं चाहते हैं, आपकी सोंच न तो गरीब के प्रति है, न तो किसान के प्रति है, अगर आपके अन्दर सम्वेदनशीलता होती तो आप इस बात का धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करते कि जब ओलावृष्टि या अतिवृष्टि के कारण उत्तर प्रदेश का किसान प्रभावित हुआ था, उत्तर प्रदेश का किसान तबाह था तो बार–बार मुख्य मंत्री जी के अनुरोध के बावजूद भी भारत सरकार ने आर्थिक सहायता देने में विलंब किया। आज भी माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, उस हिसाब से आज भी नहीं मिल पाया। हमारे मुख्य मंत्री जी ने आकस्मिक निधि की सीमा को बढ़ा करके सीधे–सीधे किसानों को लाभ पहुंचाने का काम किया है। जहां तक किसान का सवाल है, आपने कहा हमने चीनी मिलें पहले बढ़ा दिया या घटा दिया। पूर्वांचल के अंदर आजमगढ़ समाजवादी आंदोलन का केन्द्र रहा है। आजमगढ़ मण्डल बलिया, देश की आजादी के आंदोलन की अलख जगाने वाला जनपद बलिया, आप पूर्वांचल में, पश्चिम में बुन्देलखण्ड को बांट करके उत्तर प्रदेश को कमजोर करनी की बात करते हैं। आज आजमगढ़ में पूर्वांचल के अंदर चीनी मिल को लगाने का काम हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी, श्री अखिलेश यादव जी ने किया है। वह चीनी मिल सिर्फ आजमगढ़ के किसानों के लिए नहीं, देवरिया कुशीनगर से लेकर के मऊ, आजमगढ़, अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर से लेकर के जौनपुर के सारे के सारे किसानों को वहां पर गन्ने के लिए सुविधा देने का काम कर रहे हैं। आपने देश के अंदर बहुत सरकारें चलाईं, आज किसान दुर्घटना का शिकार होता था। हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो खेतों में काम करते–करते बुड्ढे हो जाते थे, मर जाते थे, बीमारी से ग्रसित हो

---

* oDrk us Òk"k.k dk iquohZ{k.k ugha fd;kA

जाते थे, उनके लिए क्या जगह बनायी। हमने और हमारी सरकार ने ऐसे किसान जो दुर्घटना के शिकार होते हैं उनको एक लाख से बढ़ा करके पांच लाख देने का काम किया। हम अपने साथी से कहना चाहते हैं कि आज आपने कहा कि पानी के कारण बीमारियां फैल रही हैं, हमारे मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा और बजट भाषण में एक व्यवस्था दी, आज विधायक निधि से आप 25 लाख रुपया ऐसे असाध्य रोग से पीड़ित व्यक्ति की मदद कर सकते हैं। यह हमारे मुख्य मंत्री जी की संवेदनशीलता है। भारत सरकार बड़ी–बड़ी बातें करती है, किसान की बात, गरीब की बात, न जाने क्या–क्या बात, आज तक भारत के प्रधानमंत्री जी, एक्स पार्लियामेण्ट का मेम्बर अपने पांच विधान सभाओं से जो उसका लोकसभा क्षेत्र है, केवल दो लोगों की मदद कर सकता है वह भी उसकी सीमा सिर्फ 50 हजार है। जब तक गांव के अंदर अवस्थापना सुविधाओं को आप बढ़ावा नहीं देंगे तब तक आप देश को खुशहाली के रास्ते पर नहीं ले जा सकते हैं। आप कहते हैं, वही बाईपास शामली नहीं बना, कैराना नहीं बना, भड़ाना नहीं बना, हम देश को जोड़ना चाहते हैं। हम बलिया से दिल्ली को जोड़ना चाहते हैं, हम पूर्वांचल समाजवादी एक्सप्रेस–वे बनाने की बात करते हैं। हम बलिया से लेकर के लखनऊ आजमगढ़, अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर को जोड़ते हुए लखनऊ से लेकर आगरा एक्सप्रेस–वे से हम दिल्ली को जोड़ना चाहते हैं। हम दिल से दिल को मिलाना चाहते हैं, हम मोहब्बत का रास्ता देना चाहते हैं और आप कभी हिन्दू, कभी मुसलमान। आप किसान की क्यों बात करते हैं किसान तो आपके एजेंडे में है ही नहीं। हम स्वागत करते हैं अपने मुख्य मंत्री जी का कि उन्होंने बड़ी मजबूती के साथ कहा कि हमारा जो किसान वर्ष है वह युवा वर्ष भी रहेगा। माननीय राणा साहब, हमें अफसोस भी होता है और तकलीफ भी होती है। अब बड़ी बातें बंद हो गयी हैं। किसान का बेटा ही जवान होता है, जो सीमाओं की हिफाजत करता है। कहां गई आपकी बड़ी–बड़ी बातें, कब तक आप सबक लेंगे। पठानकोट एयरबेस पर, जो रिपोर्ट आ रही है कि सबसे ज्यादा देश की सीमाएं आपके समय में असुरक्षित हैं। सबसे ज्यादा किसान का बेटा मारा जा रहा है। क्या योजनाएं आपने उन्हें दी हैं ? हमें तो फक्र है, हमें नाज है अपने नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव पर। आपके जमाने में वर्दी भेज दी जाती थी, एक महीने का वेतन भेज दिया जाता था और टोपी भेज दी जाती थी और कह दिया जाता था कि इसी को अपने बेटे की शहादत मानकर के इनका क्रियाक्रम कर देना। मुझे फक्र है, इस सदन में बोलते हुए हमारे नेता ने कहा कि यह शहीद की शहादत का अपमान है, शहीद को उसके घर पर बाईज्जत भेजा जायेगा और उसके भेजने के बाद जब उसका शव गांव की तरफ जायेगा, तो लोगों के मन में, ऐसे किसान परिवार का जवान जो सीमा पर शहीद हुआ उसके प्रति सहानुभूति जगेगी, महोब्बत जगेगी और जज्बा पैदा होगा। हमने उनके लिए पेट्रोल पम्प, गैस एजेंसी।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप सुनिए न। बैठिए।

डॉ0 संग्राम यादव–

मान्यवर, सुनने की क्षमता रखिए।.....

(भाजपा की ओर से मा0 अटल बिहारी बाजपेई जी ने किया था)

आज उनका सम्मान सब लोग करते हैं जिनकी बात आप कर रहे हैं। जब आपने राष्ट्र धर्म का पालन नहीं किया था तो देश के सामने उन्होंने हिम्मत रखी थी कि हम कौन सा मुंह लेकर के दुनिया के सामने जाएंगे। ये मा0 अटल बिहारी बाजपेई जी ने कहा था। हम देश के प्रजातंत्र को मजबूत करना चाहते हैं। आज क्या हालत है आपकी, कैसे लोगों के साथ आप खड़े हो गए। जो लोग अपने चैनलों के माध्यम से देश को तोड़ने की बात करते हैं। जो राजनीति में प्रजातंत्र को कमजोर करना चाहते हैं। लोकतंत्र के जो चार मजबूत स्तम्भ हैं, अगर ये ईमानदारी के साथ काम करेंगे तब जाकर के देश का कल्याण होगा। अध्यक्ष महोदय, मा0 मुख्य मंत्री जी ने सबसे बड़ी बात जो की कि तमाम लोग जो वित्त विहीन माध्यमिक कालेजों में पढ़ाने का काम करते हैं जिन्हें बहुत कम पारिश्रमिक मिलता है। मुख्य मंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के अन्दर जो वित्त विहीन माध्यमिक स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं तो उनको भी मुख्य मंत्री जी ने मानदेय देने की घोषणा की है और बजट में उसके लिए व्यवस्था की है। मैं मा0 मुख्य मंत्री जी का स्वागत करता हूं। हम इनसे कहना चाहते हैं कि –

तुमने समझा नहीं ये हालात बदल सकते थे
तेरे आंसू मेरी ऑखों से निकल सकते थे
अरे, तुम तो ठहरे झील के पानी की तरह
दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे।

मा0 अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के मा0 मुख्य मंत्री जी जो बजट लाए हैं इससे किसान तरक्की करेगा, जवान तरक्की करेगा। गांव के अन्दर खुशहाली आएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मा0 मुख्य मंत्री जी के द्वारा रखे गए बजट का समर्थन करता हूं। अध्यक्ष जी आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री रामचन्द्र यादव–

मा0 अध्यक्ष जी, वित्तीय वर्ष 2016–17 के आय–व्ययक की चर्चा पर बोलने के लिए आपने मुझे अनुमति दी है, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मा0 अध्यक्ष जी, आज उत्तर प्रदेश के किसानों की जिस तरह से स्थिति बिगड़ी है, लगातार दैवीय आपदा, ओला और आज पूरे प्रदेश में सूखे की भयंकर समस्या है। उत्तर प्रदेश की सरकार किसान वर्ष के रूप में और इस बजट में भी किसान वर्ष का जो बहुत बड़ा नारा आया है। जनपद फैजाबाद के किसानों को सूखाग्रस्त घोषित करने की श्रेणी में शामिल होने के बाद में भी एक पैसे की मदद की व्यवस्था इस बजट में नहीं की गई। श्रीमन्, आज जनपद फैजाबाद के वे किसान जिन किसानों के बच्चे डा0 राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, आचार्य नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं। प्रदेश के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में पढ़ते हैं, आज उनकी फीस नहीं जमा हो पा रही है। मान्यवर, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में किसानों की स्थिति को भारत सरकार ने सुधारने

के लिए दैवीय आपदा की मद में 18 अप्रैल, 2015 को डेढ़ गुना वृद्धि करके उत्तर प्रदेश के किसानों को मदद करने के नाम पर एक बड़ी उपलब्धि दी है। आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपनी तरफ से एक पैसे की बढ़ोतरी नहीं की है। केवल घोषणा करके कह दिया कि जनपद फैजाबाद को हम सूखाग्रस्त घोषित करते हैं लेकिन बजट में फैजाबाद जनपद के किसानों को एक पैसे की व्यवस्था नहीं की गई। हुआ क्या, जनपद फैजाबाद के किसानों को 60 रुपये, 70 रुपये का चेक बांटा गया और 60 रुपये का, 70 रुपये का चेक बांटने वाले वे अधिकारी जिनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, केवल एक लेखपाल को निलम्बित किया गया। मैं प्रदेश की सरकार के उन बड़े अफसरों से और मा0 मुख्य मंत्री जी के जो सलाहकार हैं, उनसे कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जिस तरह से फैजाबाद जनपद में सूखे के पैसे का, ओलावृष्टि की राहत के पैसे का बंदर बांट हुआ और केवल एक लेखपाल सस्पेण्ड किया गया। आखिर ये क्या हो रहा है, किसानों का मजाक हो रहा है, 60 रुपये–70 रुपये का चेक बांटा जा रहा है और उत्तर प्रदेश की सरकार कहती है कि किसान वर्ष है। काहे का किसान वर्ष है।

फैजाबाद जनपद के रजवाहे, फैजाबाद जनपद के सभी नहरों में आज कहीं न कहीं पानी नहीं है, सफाई नहीं हो पायी, काहे का किसान वर्ष। आज किसानों की रहनुमाई की बात करने वाली उत्तर प्रदेश की सरकार के जो भी माननीय मंत्रीगण हैं और फैजाबाद जनपद में जिनका काम है। मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं कि आज जितने समग्र गांव हैं, उन समग्र गांवों में काम करने वाले जितने ठेकेदार हैं, उसको तय करते हैं, जनपद फैजाबाद के उस क्षेत्र के मंत्री और उस क्षेत्र के सत्ताधारी दल के नेता। यह आज प्रदेश की सरकार कहती है कि हम हर हाल में विकास और तरक्की के रास्ते में प्रदेश को ले चलेंगे आज सड़कों को बनाने के नाम पर फैजाबाद जनपद में पूरा का पूरा माफियाराज है। आज मेरे रूदौली विधान सभा क्षेत्र में राजकीय इण्टर कालेज सुन्दा है, आज सत्ता बल के ठेकेदारों के द्वारा वहां पर गोलियां चलाई गईं। वह कौन सी कानून–व्यवस्था है जिस कानून–व्यवस्था के चलते केवल काम के नाम पर सत्तादल के लोग आपस में गोलियां चला रहे हैं। जांच हो जायेगी, मैं दावा करता हूं मैं सदन के सामने इस तथ्य को रख रहा हूं। अगर कहीं से भी एक पैसे की इसमें कमी निकलेगी तो मैं इस बात को वापस लूंगा।

श्री अध्यक्ष–

अब आप खत्म करें।

श्री राम चन्द्र यादव–

नहीं मान्यवर, मेरी बात पूरी हो जाए।

श्री अध्यक्ष–

आप कितना बोलेंगे अब पूरा तो एक घंटे में करेंगे तब हम क्या करेंगे।

श्री राम चन्द्र यादव–

मान्यवर, हम तो कितनी बार आपसे कह रहे हैं कि बोलने का मौका नहीं मिलता।

श्री अध्यक्ष–

इसमें मैं क्या करूं आप अपने पार्टी को कहें।

श्री राम चन्द्र यादव–

यह सरकार कहती है कि हम समग्र विकास करेंगे। हर जनपद में जिला योजनाओं की बैठक होती है, जिला योजनाओं की बैठक में हम तय करते हैं। हम सभी विभागों को बराबर पैसा देने की बात करते हैं। मान्यवर, 44 विभाग ऐसे हैं फैजाबाद के जिनको एक पैसा अभी तक नहीं मिला है और इस वित्तीय वर्ष का एक माह बचा है। ये कौन–सा समग्र विकास है। एक महीने के अंदर विभागों को पैसा देकर क्या सरकार उस सरकारी खजाने पर लूट करना चाहती है क्या ? यह कौन सी व्यवस्था है और आज प्रदेश की सरकार कह रही है कि हम समग्र विकास करेंगे। मान्यवर, बहुत महत्वपूर्ण बात है, हमारे जनपद में माननीय मुख्य मंत्री जी ने दो साल पहले मेरे तहसील में निर्वाध बिजली की आपूर्ति हो उसके लिए बिजलीघर का शिलान्यास किया। दो–तीन–चार साल बीत गए और अभी तक बिजलीघर रूदौली का शुभारम्भ नहीं हो पाया, अभी तक वह ऊर्जीकृत नहीं हो पाया। आर0ए0पी0डी0आर0पी0 की योजना पूरे ग्रामीण इलाके का विद्युतीकरण, 424 बस्तियों का विद्युतीकरण, इतनी जबरदस्त लूट इतना बड़ा भ्रष्टाचार और अभी तक 4 सालों में एक नगरपालिका का आर0ए0पी0डी0आर0पी0 का काम न हो पाये, मैं श्रीमन् आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार यह कहती है कि हमारी एजेन्सी काम कर रही है। रूदौली विधान सभा क्षेत्र में चलने वाली जो बिजली विभाग के काम हैं चाहे आर0ए0पी0डी0आर0पी0 हो, चाहे ग्रामीण विद्युतीकरण का काम हो और चाहे वह बिजलीघर जिसका आपने स्वयं जिसका शिलान्यास किया उसकी जांच करा लें निश्चित रूप से सत्तादल के बहुत–सारे करीबी आफिसर उसमें दोषी पाये जाएंगे। मान्यवर, पेयजल संकट के बारे में कहना चाहता हूं बहुत गंभीर बात है। अपने क्षेत्र की पेयजल समस्या जिस पेयजल समस्या पर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने एम0एस0डी0पी0 प्लान में हमारे विधान सभा क्षेत्र के 17 गांवों का प्रस्ताव भेजा है, पेयजल संकट को दूर करने के लिए। एक आई0टी0आई0 की स्थापना के लिए भेजा है। मैं बधाई देना चाहता हूं भारत सरकार के माननीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जी जो उन्होंने आई0टी0आई0 मऊ की स्थापना के लिए अपना अंश तो स्वीकृत करके 250 लाख रुपये भेज दिया लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी तक एक पैसा नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष–

अब समाप्त करें।

श्री रामचन्द्र यादव–

माननीय अध्यक्ष जी, एक मिनट में अपनी बात कहता हूं। मान्यवर, अभी 16 फरवरी को थाना मऊ क्षेत्रान्तर्गत में एक ऐसी घटना हुई 15 वर्षीय बच्ची के साथ जिस तरीके से कृत्य हुआ।

श्री अध्यक्ष–

वह तो आपने दिया है कि नियम–51 में।

श्री रामचन्द्र यादव–

मान्यवर, अभी कल फैजाबाद जनपद के व्यापारी का मुंह दबाकर सरेआम 4.00 बजे उसको लूट लिया गया। कन्हैया ज्वैलर्स को खदेड़कर, गोलियों से मारकर उसकी हत्या कर दी गयी। मान्यवर, इस तरीके से खुले आम फैजाबाद जनपद में अपराधियों का साम्राज्य स्थापित हो गया है।

मान्यवर इस तरीके से खुले आम फैजाबाद जनपद में अपराधियों का साम्राज्य स्थापित हो गया है। अपराधी खुले आम लूट कर रहे हैं, डकैती डाल रहे हैं, हत्या कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

अब आप बैठिये, अब आपका लिखा नहीं जायेगा, दीपक पटेल जी का लिखा जायेगा। यह हमारे नेता प्रतिपक्ष के सहयोगी हैं, यह उसी तरह बोलते हैं। ये हमारे साथ हमारे दल में रहे हैं।

'श्री दीपक पटेल–

आपने 2016–17 के बजट भाषण पर बोलने का अवसर दिया उसके लिए आपका बहुत–बहुत आभार। हमारे बहुत ही पुराने विश्वविद्यालय के साथी रहे हैं बड़े भाई संग्राम जी, बड़ी अच्छी पंक्तियों के साथ उन्होंने अपनी बात खत्म की। आपकी अनुमति हो तो सुना दूं–

''कि वह इतने सलीके से झूठ बोल रहा था, कि मै एतबार न करता तो और क्या करता''

मान्यवर, बहुत बड़ा प्रदेश है हमारा और अब तक के इतिहास का सबसे भारी–भरकम बजट इस सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया। मैं कह रहा था कि आबादी के लिहाज से देश का सबसे बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश और पूरी दुनिया में बहुत सारे देश ऐसे हैं जो हमसे आबादी की संख्या में बहुत पीछे हैं। बहुत लम्बी–चौड़ी फौज है हमारे पास किसानो की, मजदूरों की, लेकिन मान्यवर, मुझे बड़ा दुख है, मुझे बड़ा अफसोस है कि सारे लोग उत्तर प्रदेश के जिनका मैंने जिक्र किया, इनकी उम्मीदों पर पानी फेरने वाला यह बजट है। मान्यवर इस पुस्तिका को मैंने पढ़ा यह बहुमत की सरकार है, उसी का अहंकार है और उसी का अत्याचार है। चार साल से यह बजट भाषण पढ़ रहे हैं। बड़ी उपयोगी बातें हम कहते हैं जो प्रदेश की जनता के हित की होती हैं। मानना तो दूर सिर्फ रिकार्ड में पन्नों के कैद होकर रह जा रहा है। हमतो कहते हैं सुझाव आप हमारे मानिये और सराहना आपकी होगी, ताली आपके लिए बजेगी लेकिन जनता के हित की बात हम कर रहे हैं, कम से कम सुनने और मानने का काम करिये। लेकिन जैसा मैंने कहा कि कुछ भी नहीं यह औपचारिकता है यह दायित्वों का निर्वहन है, सदन में बैठने के कारण करना पड़ रहा है और मान्यवर बड़े दुख के साथ कह रहा हूं बहुत सारे कटमोशन में बहुत सारे बजट और माननीय राज्यपाल के अभिभाषण में कई बार बोलने का मौका दिया लेकिन एक भी सुझाव को मानने का काम, विपक्ष के शायद किसी भी

---

* oDrk us Hkk"k.k dk iquohZ{k.k ugha fd;kA

विधायक के एक भी सुझाव को मानने का काम इन्होंने नहीं किया। मान्यवर, इस पुस्तिका को मैंने पढ़ा, चुनावी साल है हमें लगता है कि यह बजट पुस्तिका नहीं है यह समाजवादी पार्टी का चुनावी घोषणा–पत्र है और मेरा दावा है कि जो हश्र जो हाल इनके घोषणा–पत्र का हुआ है वही इस बजट का भी होने वाला है। मान्यवर, इसकी शब्दावली मैं पढ़ रहा था।

श्री अध्यक्ष–

क्या किसी का मोबाइल बज रहा है ?

'श्री दीपक पटेल–

जी अध्यक्ष जी, मेरा ही है, हमें लगा जैमर काम कर रहा होगा लेकिन पूरे प्रदेश की व्यवस्था फेल है तो यह सदन उससे अलग नहीं है। मान्यवर, इसकी शब्दावली की मैं बात कर रहा हूं कि इसको किसने लिखा ? योजनायें पूरी करायी जा रही हैं, व्यवस्था प्रस्तावित है, सुविधायें उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया जा रहा है, यह सब तो हम लोग भाषण में बोलते हैं चुनाव के पहले। यह कराने वाले हैं, यह कराने जा रहे हैं, अरे साहब कब तक करेंगे आप ? प्रदेश की किसी भी योजना को चार साल में अभी तक इस सरकार ने पूरा करने का काम नहीं किया। बड़ी गम्भीर बात है लोहिया की बात अभी हो रही थी हम सब लोग उनकी आइडियोलोजी के, उनकी विचारधारा के समर्थक रहे हैं इन्होंने बड़े जोर शोर से डा0 लोहिया समग्र गांव की बात कही। लोहिया जी बड़े महान शख्सियत थे और समाज के दबे कुचले मजलूम को समाज की मुख्यधारा में जोड़ना चाहते थे और समाज को मुख्यधारा में जोड़ना चाहते थे। लेकिन इन्होंने साथियों, भेदभाव को इस सदन के अन्दर उनके नाम के साथ जोड़कर, उनकी आत्मा कराह रही होगी लोहिया गांव माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि विधायकों के प्रस्ताव पर होंगे। मान्यवर, रिकार्ड उठाकर देख लें, मैं चार साल से विधायक हूं हर बार प्रभारी मंत्री जी को दिया वहां की जिला योजना में इसकी बात कही लेकिन मेरा एक भी गांव इन 4
वर्षो में चयनित नहीं किया गया और एक आश्चर्य की बात जिस शख्स को मैने पराजित करने का काम किया जिस व्यक्ति को मैंने चुनाव में हराने का काम किया उसके बताये हुए गांव को लोहिया गांव में चयन किया जा रहा है। कितना बड़ा अत्याचार है इस सरकार का और लोकतंत्र का मान्यवर। एक महत्वपूर्ण बात और है लोहिया जी की विचारधारा की बात कर रहे हैं हमारी विधान सभा से जुड़ा हुआ तत्कालिक मामला है। हमारे यहां कचरी पावर प्लांट इलाहाबाद में है, उसका निर्माण कराया जाना 7–8 सालों से विवादों में रहा है हाईकोर्ट सुप्रीमकोर्ट तक कई बार यह मामला गये हैं और अभी भी स्थिति स्पष्ट नहीं है 20 प्रतिशत किसानों ने उसका मुआवजा नहीं लिया है। उसके बावजूद 15 हजार पुलिस कांस्टेबिल लगाकर संगीनों के साये में उन लोगों को जिन लोगों ने मुआवजा नहीं लिया है उनको घर में कैद करके जबरदस्ती उस पावर प्लांट का निर्माण कराया जा रहा है। आप इसकी तस्दीक कर सकते हैं। मान्यवर, बहुत सारी बाते हैं। मैं कभी कभी आश्चर्य करता हूं सारे लोग चुनाव लड़ते हैं क्षेत्र में जाते हैं इतनी बड़ी समस्या पानी की है पूरे प्रदेश के अन्दर। हम लोग जाते हैं तो पहला प्रश्न गांव का

---

* oDrk us Hkk"k.k dk iquohZ{k.k ugha fd;kA

व्यक्ति जो नहीं बोल पाता है वह इशारे में कहता है साहब पानी की व्यवस्था कर दो। पांचवां साल है सरकार का मान्यवर, एक बार सौ हैण्डपम्प की व्यवस्था सरकार ने करी थी स्थिति आप देख रहे हैं पानी बरस रहा नहीं है पूरे प्रदेश में पिछले डेढ़ दो सालों से और वाटर लेबिल नीचे ही होता जा रहा है 80 फीसदी हैण्डपम्प काम करने बन्द कर चुके हैं। नये हैण्डपम्प का कोई जिक्र नहीं है और पता नहीं है सत्ता पक्ष के आदरणीय ग्राम विकास मंत्री जी बैठे हैं पुराने नेता हैं, जमीनी नेता हैं हम आपके माध्यम से इनका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। आपने प्रस्तावित किया है 200 हैण्डपम्पों का प्राविधान था पहले के जमाने में आज 80 प्रतिशत हैण्डपम्प काम नहीं कर रहे हैं हम आपके माध्यम से इस बजट के डिसकशन के माध्यम से कहना चाहेंगे कि पांच वर्षो में 1000 हैण्डपम्प का बकाया आपके ऊपर है आप एक हजार नहीं दे सकते हैं तो कम से कम 500 हैण्डपम्प की व्यवस्था सुनिश्चित करा दें। 3 लाख 40 हजार करोड़ का बजट है। सारे विधायक लोगों की बहुत बड़ी समस्या है चुनांव में सबको जाना है। जहां जाते हैं सिर्फ एक प्रश्न हैण्डपम्प का खड़ा होता है तो इसके लिए आप प्राविधानित करें। आपने 2200 करोड़ रूपये दिये हैं यह पेयजल के लिए बहुत ही नाकाफी है 22–24 करोड़ की आबादी में एक व्यक्ति के हिस्से में 100 रुपये 10 रुपये भी नहीं आ रहे हैं। इस बजट को बढ़ाने का काम करें बहुत कुछ कहना है आपका आदेश मैं हमेशा मानता हूं। मैं यह कहूंगा जाते–जाते कि यह जो आपकी बजट पुस्तिका है इसको अगर क्षेत्र में बटवा दिया जाय तो समाजवादी पार्टी के कोई विधायक क्षेत्र में घुस नहीं पायेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसमें सुधार करिये विपक्ष के सारे माननीय सदस्यों के सुझावों को सम्मिलित करिये, जनहित की बात कर रहे हैं हम हैण्ड पम्प मांग रहे हैं, सड़क मांग रहे हैं, बिजली मांग रहे हैं, संग्राम जी, आवश्यकता है जो आप हाइवेज बना रहे हैं बड़े हाइवे बना रहे हैं, जरूरत है।

डा0 संग्राम यादव–

जेपी एक्सप्रेस वे को आपने कौड़ियों के भाव अगल–बगल के बिल्डरों को बेच दिया था। हम तो बना रहे हैं हम तो मण्डी भी बना रहे हैं। अब उस पर मत ले जाइये कि आपने उत्तर प्रदेश को कहां ले जाकर खड़ा कर दिया। अब आप बैठ जाइये।

श्री दीपक पटेल–

मान्यवर, बहुत–बहुत आभार आपका। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष–

अब तक इस बजट भाषण में सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलाकर कुल 64 माननीय सदस्यों ने हिस्सा लिया है। 19 माननीय सदस्य सत्तापक्ष के हैं और 45 माननीय सदस्य विपक्ष के हैं। इस प्रकार कुल 64 माननीय सदस्यों के इस पर विचार आ चुके हैं। अब दिनांक 04 मार्च, 2016 को माननीय मुख्य मंत्री जी इस बजट भाषण पर अपना उत्तर देंगे।

[06.06 बजे, नियम–51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 26–02–2016 को नियम–51 के अन्तर्गत कुल 67 सूचनायें प्राप्त हुई।

क्र0	नाम	विषय
1	श्रीमती रूबी प्रसाद (वक्तव्य हेतु स्वीकृत)	जनपद सोनभद्र की तहसील दुद्धी को नया जनपद बनाये जाने के सम्बन्ध में।
2	श्रीमती श्रद्धा यादव (वक्तव्य हेतु स्वीकृत)	जनपद जौनपुर अन्तर्गत लुम्बिनी–दुद्धी मार्ग के एक निश्चित क्षेत्र की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में।
3	श्री शिवचरन प्रजापति (केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत)	जनपद उन्नाव की नगर महापालिका के कतिपय क्षेत्रों में इन्टरलाकिंग टाइल्स सहित कई अन्य व्यवस्थायें किये जाने के सम्बन्ध में।
4	श्री गुलाबचन्द सरोज (केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत)	जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र केराकत के अन्तर्गत गोमती नदी पर सरोज बड़ेवर घाट पर सेतु का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
5	श्री मो0 जासमीर असांरी (केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत)	उ0प्र0 के धार्मिक क्षेत्र नैमिषारण्य का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में।
6	श्री तेजपाल सिंह (केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत)	जनपद मथुरा की सहकारी चीनी मिल छाता को पुनः चालू कराये जाने के सम्बन्ध में।
7	श्री संजय कपूर (केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत)	जनपद रामपुर की तहसील विलासपुर में उत्तराखण्ड द्वारा विद्युत आपूर्ति रोके जाने के कारण नये उपकेन्द्र की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में।
8	श्री रामचन्द्र यादव (केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत)	जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रूदौली व मिल्कीपुर को जोड़ने वाले मार्ग के अधूरे निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में।
9	सुश्री शकुन्तला देवी (केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत)	मुख्य चिकित्साधिकारी, हरदोई द्वारा की जा रही अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में।
10	श्री सिबगतुल्ला अंसारी (केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत)	जनपद गाजीपुर की तह0 मोहम्मदाबाद के अन्तर्गत अतिवृष्टि एवं ओलावृष्टि से किसानों की बर्बाद फसलों के मुआवजा दिये जाने में की गई धांधली की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में।
11	डा0 आर0 के0 वर्मा (केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत)	जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा विश्वनाथगंज की कतिपय टूटी जर्जर गड्ढायुक्त मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में।
12	श्री इन्दल रावत (केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत)	लखनऊ स्थित राज्य सम्पत्ति विभाग के अधीन राजकीय लालबाग आफिसर्स कालोनी की बाउण्ड्री ऊंची कराये जाने के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गई :–

क्र0	नाम
1	श्री विवेक कुमार सिंह
2	श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा
3	श्री राजकुमार रावत
4	श्री प्रदीप माथुर
5	श्री मो0 इरफान
6	श्री जय प्रकाश निषाद
7	श्री उमेश पाण्डेय
8	डा0 रमेश चन्द्र बिन्द
9	श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भईया
10	श्री राधेलाल रावत
11	श्री कपिलदेव अग्रवाल
12	श्री संजय प्रताप जायसवाल
13	श्री ललितेशपति त्रिपाठी
14	श्री मुकुट बिहारी वर्मा
15	श्रीमती बिमला बाथम
16	श्री रविन्द्र जायसवाल
17	श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी
18	श्रीमती सीमा
19	श्री मनीष असीजा
20	श्री राजीव गुम्बर
21	श्री सुरेश राणा
22	श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया
23	श्री योगेन्द्र उपाध्याय
24	श्री सुरेश कुमार खन्ना
25	श्री रविन्द्र भड़ाना
26	श्री जगन प्रसाद गर्ग
27	श्री सत्यवीर मुन्ना
28	श्री नदीम जावेद
29	श्री रामहेत भारती
30	श्री काली चरन सुमन
31	श्री सतीश महाना
32	श्री जय प्रकाश अंचल
33	श्री अगयश रामसरन वर्मा

34	श्री उपेन्द्र तिवारी
35	श्री दीपक पटेल
36	श्री आरिफ अनवर हाशमी
37	श्री पंकज गुप्ता
38	श्री गेंदा लाल चौधरी
39	श्री सुरेश बंसल
40	श्री उमाशंकर
41	श्री भीम प्रसाद सोनकर
42	श्री राधेश्याम जायसवाल
43	श्री सुधाकर सिंह
44	श्री लोकेश दीक्षित
45	श्री जितेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी
46	श्री कुं0 कौशल सिंह
47	श्रीमती अराधना मिश्रा 'मोना'
48	श्री ओम कुमार
49	श्री सन्त राम कुशवाहा
50	श्री रोशन लाल वर्मा
51	श्री बब्बन सिंह चौहान
52	श्री चन्द्रभान सिंह पटेल
53	श्री राज नारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज
54	श्री भगवान सिंह कुशवाहा
55	श्री शारदा प्रताप शुक्ल

जनपद बागपत के ग्राम खिंछौड़ा के निवासी सुश्री साक्षी चौहान का दिनांक 30 जनवरी, 2016 को अपहरण होने के उपरान्त दुष्कर्म/हत्या किये जाने के बाद पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में श्री लोकेश दीक्षित द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

लोक निर्माण राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह पटेल)–

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण में....

श्री कुलदीप सिंह सेंगर–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है। इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य लोक निर्माण राज्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री सुरेन्द्र सिंह पटेल–

ख्पुलिस अधीक्षक, बागपत से आख्या प्राप्त की गयी। प्राप्त आख्यानुसार यह अवगत कराना है कि उक्त घटना के सम्बन्ध में वादी श्री राजेन्द्र सिंह द्वारा दिनांक 31–12–2015 को थाना सिंहावली अहीर पर लिखित तहरीर देते हुये मु0अ0सं0–411/2015 धारा–363 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत कराया गया। जिसकी विवेचना उ0नि0 श्री रामबीर शर्मा द्वारा प्रारम्भ की गयी। विवेचना के दौरान दिनांक 10–01–2016 को अपहृता कु0 साक्षी का शव ग्राम पूठड़ के जंगल में ईख के खेत से बरामद हुआ। अभियोग में धारा–302/201 भादवि की वृद्धि की गयी। मृतका के पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं अन्य साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियोग में धारा–376 डी भादवि व 3/4 पोक्सो अधिनियम की वृद्धि की गयी। दिनांक 11–01–2016 को अभियोग की विवेचना श्री राजेन्द्र सिंह प्रभारी निरीक्षक, सिंधावली अहीर को स्थानान्तरित की गयी। विवेचनात्मक कार्रवाई के दौरान उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियोग की घटना में अभियुक्तगण 1–बिजेन्द्र उर्फ उन्नू पुत्र श्री अभयराम उर्फ अतरे यादव, 2–मोनू पुत्र श्री सुनील यादव, 3–सौरभ पुत्र श्री धर्मपाल, 4–बिट्टू उर्फ विनय पुत्र श्री हरबीर समस्त निवासीगण ग्राम सैडभर थाना सिंघावली अहरी, जनपद बागपत के नाम प्रकाश में आये। दिनांक 15–01–2016 को उक्त चारों अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया, जिनके द्वारा जुर्म का इकबाल करते हुये सम्पूर्ण घटनाक्रम के सम्बन्ध में बताया गया। दिनांक 15–01–2016 को अभियुक्तों से गहन पूछताछ हेतु पुलिस अभिरक्षा में 03 दिन का रिमाण्ड प्राप्त हुआ। पुनः पूछताछ कर दिनांक 19–01–2016 को अभियुक्तगण की निशानदेही पर मृतका का स्कूल बैग, किताबें, कापियां आदि बरामद की गयीं। घटना में प्रयुक्त एक मोटर साइकिल बजाज सीटी0–100 नं0 एच0आर0–51 जेड–4523 व एक मारुति कार नं0 यू0पी0–17सी–9567 बरामद हुई। विवेचना प्रचलित है।

3–गांव में शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु पुलिस/पी0ए0सी0 तथा अन्य पुलिस अधिकारियों द्वारा ग्राम खिन्दौड़ा में मौजूद रहकर निरन्तर सतर्क दृष्टि रखी गयी तथा गहन पूछताछ एवं वैज्ञानिक ढंग से साक्ष्य संकलन व कॉल डीटेल के आधार पर घटना का अनावरण किया गया है। गहन पूछताछ से यह भी तथ्य संज्ञान में आया कि अभियुक्तगण अपराधिक प्रवृत्ति के हैं और वर्ष का अन्तिम दिन होने के कारण कु0 साक्षी का अपहरण किया गया और घटनाक्रम को छिपाने के उद्देश्य से कु0 साक्षी की हत्या कर उसके शव को ईख के जंगल में फेंक दिया गया। शान्ति एवं कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य बनी हुई है। विवेचक एवं पर्यवेक्षण अधिकारी को उक्त अभियोग की विवेचना का गुण–दोष के आधार पर त्वरित सफल निस्तारण हेतु आवश्यक निर्देश निर्गत किये जा चुके हैं। गैंगस्टर एक्ट जैसी निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है तथा पुलिस एवं स्थानीय अभिसूचना इकाई द्वारा निरन्तर सतर्क दृष्टि रखी जा रही है।,

जनपद बलिया की तहसील सिकन्दरपुर में वर्ष 2015–2016 में सूखा एवं ओलावृष्टि से पीड़ित किसानों को मुआवजा राशि दिलाये जाने हेतु धनराशि अवमुक्त कराये जाने के

---

uksV %& [ ];g va'k i<+k gqvk eku x;kA

सम्बन्ध में श्री जियाउद्दीन रिजवी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर बेसिक शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य

लोक निर्माण राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह पटेल)–

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि ओलावृष्टि..

श्री कुलदीप सिंह सेंगर–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है। इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य लोक निर्माण राज्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री सुरेन्द्र सिंह पटेल–

ख्2015 से कृषि फसलों को हुयी क्षति के सापेक्ष भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार जिलाधिकारी, बलिया द्वारा रु0 45.89 करोड़ की धनराशि की मांग की गयी थी। शासन द्वारा अद्यतन ओलावृष्टि से किसानों को राहत प्रदान किये जाने के लिये रु0 33.03 करोड़ कीी धनराशि स्वीकृत की गयी थी। स्वीकृत धनराशि का 1,41,080 (एक लाख इकतालिस हजार अस्सी) किसानों के मध्य वितरण भी कराया जा चुका है।

3–जहाँ तक जनपद बलिया के तहसील सिकन्दरपुर का प्रश्न है शासन द्वारा आवंटित धनराशि में से जिलाधिकारी, बलिया द्वारा तहसील सिकन्दरपुर के लिये रु0 6. 60 करोड़ की धनराशि आवंटित की गयी थी, और उक्त आवंटित धनराशि में से ग्राम सिवानकलां, उसरैला, रक्शा, खटमा, खटमी, नवानगर, नरहनी, लिलकर के 31,457 (इकतीस हजार चार सो सत्तावन) किसानों को कृषि निवेश अनुदान वितरित किया जा चुका है।

4–उक्त के अतिरिक्त यह उल्लेख करना है कि भारत सरकार को ओलावृष्टि से हुयी कृषि फसलों की क्षति के सापेक्ष रु0 7543.14 करोड़ की मेमोरेण्डम भारत सरकार को प्रेषित किया गया था। भारत सरकार से रु0 2801.59 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुयी थी। मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा अवशेष धनराशि रु0 4741.55 करोड़ की स्वीकृति किये जाने का अनुरोध मा0 प्रधान मंत्री जी से दिनांक 08–02–2016 को किया गया है। भारत सरकार से धनराशि प्राप्त होने पर स्वीकृत की जा सकेगी।

5–शासनादेश संख्या–453/1–11–2014–7(जी)/2015, दिनांक 19–11–2015 द्वारा 50 जनपदों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है, जिसमें जनपद बलिया भी सम्मिलित है परन्तु सूखे के कारण जनपद में भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार कृषि फसलों को 33 प्रतिशत या उससे अधिक फसलों की क्षति नहीं हुयी है। अतः सूखे के लिये कोई धनराशि जनपद बलिया को नहीं स्वीकृत की गयी है।,

जनपद अम्बेडकर नगर में एस0एम0आई0 रामनगर द्वारा बड़े पैमाने पर की गयी अनियमितताओं के सम्बन्ध में श्री भीम प्रसाद सोनकर द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर खाद्य रसद मंत्री का वक्तव्य

---

uksV %& [ ] ;g va'k i<+k gqvk eku x;kA

लोक निर्माण राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह पटेल)–

इसके सम्बन्ध में अवगत कराना है कि श्री लालधर राम, विपणन निरीक्षक कीी..

श्री कुलदीप सिंह सेंगर–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है। इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य लोक निर्माण राज्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री सुरेन्द्र सिंह पटेल–

ख्तैनाती केन्द्र रामनगर जनपद अम्बेडकरनगर पर सम्भागीय खाद्य नियंत्रक कार्यालय फैजाबाद संभाग, फैजाबाद के आदेश सं0–1225/सं0खा0नि0/अधि0/2015, दिनांक 02–06–2015 के द्वारा की गयी है। इसके अनुपालन में इनके द्वारा केन्द्र रामनगर पर दिनांक 03–06–2015 (पूर्वाह्न) को योगदान किया गया है। इस प्रकार श्री लालधर राम, विपणन निरीक्षक केन्द्र रामनगर पर लगभग 09 महीनों से कार्यरत है। इससे स्पष्ट है कि श्री लालधर राम, विपणन निरीक्षक केन्द्र रामनगर जनपद अम्बेडकरनगर में लम्बे समय से तैनात नहीं है।

क्रय केन्द्रों पर घटतौली व मानकों के विरुद्ध बिचौलियों से धान खरीद किये जाने की शिकायत तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली में उठान व वितरण में घटतौली एवं चोरी व भ्रष्टाचार आदि शिकायतों की गहनता से विस्तृत जांच हेतु वरिष्ठ संभागीय वित्त एवं लेखाधिकारी (खाद्य), फैजाबाद संभाग, संभागीय खाद्य विपणन अधिकारी, फैजाबाद संभाग एवं जिला खाद्य विपणन अधिकारी, अम्बेडकरनगर की कमेटी बना दी गयी है। जांचोपरान्त निष्कर्षों का सम्यक् विवेचन करते हुये इस पर कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी।,

जनपद सन्तकबीरनगर के टेमा सेमरियावां मार्ग का नवीनीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 मो0 अयूब द्वारा नियम––51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण राज्य मंत्री का वक्तव्य

लोक निर्माण राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह पटेल)–

प्रश्नगत मार्ग जनपद सन्तकबीरनगर में बस्ती कांटे मार्ग...

श्री कुलदीप सिंह सेंगर–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है। इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य लोक निर्माण राज्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री सुरेन्द्र सिंह पटेल–

ख(अन्य जिला मार्ग) के कि0मी0 22.00 में स्थित जगदीशपुर से निकलकर लखनऊ–फैजाबाद गोरखपुर (राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–28) के कि0मी0 216 में स्थित टेमा

---

uksV %& [ ] ;g va'k i<+k gqvk eku x;kA

से होकर बस्ती मेंहदावल–तमकुही राजमार्ग (राजमार्ग सं0–64) के कि0मी0 23 पर स्थित सेमरियावां में मिलता है। प्रश्नगत अन्य जिला मार्ग की कुल लम्बाई 13.00 कि0मी0 व वर्तमान चौड़ाई 3.50 मी0 है। मार्ग के 3.50 से 5.50 मी0 चौड़ीकरण व पूरे मार्ग के सुदृढ़ीकरण हेतु रु0 1898.53 लाख की लागत विभागीय व्यय वित्त समिति से अनुमोदित है, जिसकी स्वीकृति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।,

जनपद शामली को तहसील शामली अन्तर्गत ग्राम सभा लिलौन में राजकीय बालिका इण्टर कालेज की स्थापना हेतु धन आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में श्री पंकज मलिक द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर माध्यमिक शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य

लोक निर्माण राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह पटेल)–

माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा दिनांक 19–02–2015 को जनपद...

श्री कुलदीप सिंह सेंगर–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है। इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य लोक निर्माण राज्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री सुरेन्द्र सिंह पटेल–

ख्शामली के ग्राम–लिलौन, ब्लाक व तहसील शामली में राजकीय इण्टर कालेज की स्थापना की जायेगी विषयक, घोषणा की गयी है। मा0 मुख्य मंत्री जी की घोषणा के अनुपालन में जनपद–शामली के विकास खण्ड/तहसील शामली के अन्तर्गत ग्राम सभा–लिलौन में राजकीय इण्टर कालेज, लिलौन शामली की स्थापना हेतु शासनादेश संख्या–254/पन्द्रह–10–2016–10(6)/2015, दिनांक 24–02–2016 द्वारा विद्यालय के भवन निर्माण हेतु नामित राजकीय कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 द्वारा प्रस्तुत प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन रु0 316.52 लाख के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 में प्रथम किश्त के रूप में आगणन की 50 प्रतिशत धनराशि रु0 158.26 लाख की वित्तीय स्वीकृति के आदेश निर्गत कर दिये गये हैं।,

प्रदेश के अनुसूचित जाति एवं जनजाति व पिछड़ा वर्ग के छात्र–छात्राओं के छात्रावास शुल्क समेत अन्य शुल्कों का भुगतान किये जाने हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में श्री पूरन प्रकाश द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर समाज कल्याण मंत्री का केवल वक्तव्य

लोक निर्माण राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह पटेल)–

मा0 सदस्य द्वारा दी गई उपरोक्त सूचना....

श्री कुलदीप सिंह सेंगर–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है। इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

---

uksV %& [ ] ;g va'k i<+k gqvk eku x;kA

(वक्तव्य लोक निर्माण राज्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

ख्के सम्बन्ध में निदेशक, समाज कल्याण की आख्या प्राप्त की गयी। निदेशक, समाज कल्याण के पत्र दिनांक 23–02–2016 द्वारा शासन को उपलब्ध करायी गयी आख्या में यह अवगत कराया गया है कि अनुसूचित जाति के रुपया 2.00 लाख तक की अय–सीमा वाले माता–पिता के बच्चे जो उ0प्र0 के मूल निवासी हों, को देश के अन्दर अध्ययनरत होने पर दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति दिये जाने की व्यवस्था है। समाज कल्याण विभाग द्वारा देश के बाहर अध्ययनरत छात्रों को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति दिये जाने की कोई भी योजना संचालित नहीं है।,

जनपद मथुरा के कतिपय ग्रामसभाओं स्थित नेशनल हाई–वे–2 व गोवर्धन रोड के दोनों तरफ बसी आबादी से उत्सर्जित जल को समुचित निकासी हेतु गहरे नालों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रदीप माथुर द्वारा दी गयी सूचना पर पंचायती राज मंत्री का केवल वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी ने इसे स्थगित रखने का अनुरोध किया है। इसलिये यह स्थगित रहेगा।

जनपद आजमगढ़ के नगर पालिका मुबारकपुर में अधिशाषी अधिकारी की नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में श्री शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

लोक निर्माण राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह पटेल)–

उक्त सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि नगर पालिका ...

श्री कुलदीप सिंह सेंगर–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है। इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य लोक निर्माण राज्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री सुरेन्द्र सिंह पटेल–

ख्परिषद्, मुबारकपुर में अधिशासी अधिकारी श्रेणी–3 संवर्ग के अधिशासी अधिकारियों की तैनाती की जाती है। अधिशासी अधिकारी श्रेणी–3 संवर्ग में कुल 118 पर सृजित हैं, जिसके सापेक्ष मात्र 51 अधिशासी अधिकारी ही कार्यरत हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि विभाग में अधिशासी अधिकारियों की कमी होने के कारण नगर पालिका परिषद्, मुबारकपुर (आजमगढ़) में नियमित अधिशासी अधिकारी की तैनाती किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। रिट याचिका संख्या–47309/2013 गिरधारी लाल स्वर्णकार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 27–11–13 के क्रम में ए0डी0एम0 (प्रशासन) आजमगढ़ से प्रभार वापस लेते हुये शासन के कार्यालय–ज्ञाप दिनांक 24–02–16 द्वारा अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, आजमगढ़ को नगर पालिका परिषद्, मुबारकपुर के अधिशासी अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

---

uksV %& [ ] ;g va'k i<+k gqvk eku x;kA

अधिशासी अधिकारियों की पर्याप्त उपलब्धता होने पर उक्त पालिका में अधिशासी अधिकारी की नियमित तैनाती कर दी जायेगी।,

जनपद बुलन्दशहर के लोक निर्माण विभाग के प्रान्तीय खण्ड में ठेकेदार की मिलीभगत से सरकारी धन का दुरुपयोग किये जाने के सम्बन्ध में श्री दिलनवाज खां द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य

लोक निर्माण राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह पटेल)–

उक्त के सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता...

श्री कुलदीप सिंह सेंगर–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है। इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य लोक निर्माण राज्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री सुरेन्द्र सिंह पटेल–

ख(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ से प्राप्त आख्या के अनुसार बी0बी0 नगर–स्याना–बुगरासी मार्ग (प्रमुख जिला मार्ग सं0–50 डब्ल्यू) जनपद–बुलन्दशहर का अतिमहत्वपूर्ण मार्ग है। प्रश्नगत मार्ग बुलन्दशहर–स्यान–गढ़ मार्ग (राज्य मार्ग सं0–65) तथा हामिदपुर–सिकन्दराबाद–कुचेसर मार्ग (राज्य मार्ग सं0–100) को परस्पर जोड़ता है। मार्ग के 16 कि0मी0 लम्बाई के चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण हेतु शासनादेश सं0–258(1)/23–11–2015–1/2 (66)/14, दिनांक 17–08–15 द्वारा रु0 3695.58 लाख की स्वीकृति निर्गत की गयी है। कार्य का सम्पादन कराने हेतु अनुबन्ध सं0–25/एस0ई0–बु0 शहर वृत्त/2015–16, दिनांक 07–09–2015 को गठित किया गया है। मार्ग के स्वीकृत आगणन में चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण हेत निम्नलिखित प्राविधान किये गये हैं :–

(1) चैनेज 0.00 से 10.550 तक (10.550 कि0मी0)– मार्ग के इस भाग में लेपित सतह की चौड़ाई 5.50 मी0 थी, जिसकी मार्ग के दोनों ओर 75–75 से0मी0 बढ़ाकर 7.00 मी0 किया गय है, जिसमें 25 से0मी0 काम्पेक्टिड जी0एस0बी0, 7.50 से0मी0 काम्पेक्टिड जी–2 तथा 7.5 से0मी0 काम्पेक्टिड जी–3 का प्राविधान है। सुदृढ़ीकरण हेतु मार्ग की पूर्ण 7.00 मी0 चौड़ाई में 12.00 से0मी0 काम्पेक्टिड डब्ल्यू0एम0एम0 6.50 से0मी0 काम्पेक्टिड डी0बी0एम0 तथा 4.00 से0मी0 काम्पेक्टिड बी0सी0 का प्राविधान है।

(2) चैनेज 11.920 से 16.00 तथा चैनेज 18.00 से 19.37 तक (5.450 कि0मी0)–मार्ग के इस भाग में लेपित सतह की चौड़ाई 3.70 थी, जिसको मार्ग के दोनों ओर 1.65–1.65 मी0 बढ़ाकर 7.00 मी0 किया गया है, जिसमें 18 से0मी0 काम्पेक्टिड जी0एस0बी0, 7.50 से0मी0 काम्पेक्टिड जी–2 तथा 7.5 से0मी0 काम्पेक्टिड जी–3 का प्राविधान है। सुदृढ़ीकरण हेतु मार्ग की

---

uksV %& [ ] ;g va'k i<+k gqvk eku x;kA

पूर्ण 7.00 मी0 चौड़ाई में 19.0 से0मी0 काम्पेक्टिड डब्ल्यू0एम0एम0, 6.50 से0मी0 काम्पेक्टिड डी0बी0एम0 तथा 4.0 से0मी0 काम्पेक्टिड बी0सी0 का प्राविधान है।

3–मार्ग के चैनेज 10.550 से 11.920 तक का भाग बुलन्दशहर–स्याना–गढ़ मार्ग से कॉमन है। मार्ग के चैनेज 16.000 कि0मी0 से चैनेज 18.000 कि0मी0 तक मार्ग की दशा ठीक होने के कारण यह भाग स्वीकृति में सम्मिलित नहीं है। वर्तमान में चौड़ीकरण का कार्य पूर्ण है तथा सुदृढ़ीकरण का कार्य प्रगति में है। जी0एस0बी0 का कार्य एम0ओ0आर0टी0एच0 की विशिष्टियों के अनुसार कराया जाना प्रस्तावित था एवं तद्नुसार ही कार्य कराया गया है। जी0एस0बी0 की मोटाई आगणन में किये गये प्राविधानों के अनुरूप है तथा ग्रेडेशन विशिष्टियों के अनुरूप है। विभागीय अभियन्ताओं द्वारा कार्य का निरीक्षण व गुणवत्ता की जांच नियमित रूप से की जा रही है। कार्यस्थल पर किये गये जी0एस0बी0 के ग्रेडेशन परीक्षण की प्रविष्टि निर्धारित पंजिका में की जाती है।,

जनपद बुलन्दशहर के विकास खण्ड सिकन्दराबाद के अन्तर्गत गाँव सरायघासी व आढा के बीच करों नदी पर पड़ने वाले पुल के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री का केवल वक्तव्य

लोक निर्माण राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह पटेल)–

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत सिकन्दराबाद ...

श्री कुलदीप सिंह सेंगर–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है। इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य लोक निर्माण राज्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री सुरेन्द्र सिंह पटेल–

ख्जनपद बुलन्दशहर के विकास खण्ड सिकन्दराबाद के अन्तर्गत आने वाले गांव सरायघासी तथा आढा के बीच करों नदी पर पड़ने वाला पुल अत्यधिक पुराना हो जाने के कारण वर्तमान में क्षतिग्रस्त हो गया है। इस पुल क्षेत्र में स्थानीय लोग करबन नदी को ही करों नदी कहते हैं।

करबन नदी एवं काली नदी के बीच पड़ने वाले नालों की क्षमता पुनर्स्थापना की परियोजना तैयार की गई जिसमें उक्त पुल का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। परियोजना दिनांक 06–02–2013 को सम्पन्न उत्तर प्रदेश राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद् की स्थायी संचालन समिति की 45वीं बैठक में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत अनुमोदित है, तत्पश्चात् राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना के अन्तर्गत वित्त पोषण का प्रस्ताव प्रेषित किया गया परन्तु राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत वित्त पोषण में विलम्ब होने के कारण परियोजना राज्य सेक्टर के अन्तर्गत वित्त पोषण हेतु पुनः उत्तर

---

uksV %& [ ] ;g va'k i<+k gqvk eku x;kA

प्रदेश राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद् की स्थायी संचालन समिति की दिनांक 08–04–2015 को सम्पन्न 47वीं बैठक में प्रस्तुत की गयी। जिसमें समिति द्वारा विचारोपरान्त परियोजना को स्थगित करने का निर्णय लिया गया है।

अतः सक्षम स्तर से वित्त पोषण की स्वीकृति हो जाने एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर कार्रवाई की जायेगी।,

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर में प्राथमिक विद्यालय प्रथम निगोही में कार्यरत रसोइयों को मानदेय दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री रोशन लाल वर्मा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर बेसिक शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य

लोक निर्माण राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह पटेल)–

मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत....

श्री कुलदीप सिंह सेंगर–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है। इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य लोक निर्माण राज्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री सुरेन्द्र सिंह पटेल–

ख्दी गयी सूचना के सम्बन्ध में निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया है कि वित्तीय वर्ष 2015–16 में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जनपद–शाहजहांपुर द्वारा दी गयी सूचना के आधार पर भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015–16 हेतु वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट में अनुमोदित 9299 रसोइयां स्वीकृत हैं, जिनके सापेक्ष कुल 8311 रसोइया कार्यरत हैं, जिनका वित्तीय वर्ष 2015–16 में 100 माह का मानदेय (भारत सरकार द्वारा अनुमोदित प्रतिमाह प्रति रसोइयां मानदेय रु0 1000/–) कुल रुपये 831.10 लाख आगणित होता है। जिसके सापेक्ष रसोइयां मानदेय मद में केन्द्रांश के रूप में रु0 396.18 लाख तथा राज्यांश के रूप में 264.12 लाख कुल धनराशि 660.30 लाख जनपद–शाहजहांपुर को प्रेषित किया जा चुका है, जबकि जनपद शाहजहांपुर में रसोइयों की अनुमोदित संख्या के सापेक्ष कार्यरत रसोइयों की संख्या के आधार पर माह दिसम्बर, 2015 तक कुल रु0 581.77 लाख (07 माह हेतु–ग्रीष्मावकाश छोड़कर) की आवश्यकता होती है। अतः माह दिसम्बर, 2015 तक की मानदेय की राशि के भुगतान करने के पश्चात् रुपये 78.53 लाख शेष रहेंगे।

यह भी अवगत कराया गया है कि जनपद–शाहजहांपुर से प्राप्त वित्तीय वर्ष 2014–15 का उपभोग प्रमाण जो, जिलाधिकारी, शाहजहांपुर से प्राप्त है, के अनुसार जनपद–शाहजहांपुर में कुल कार्यरत 8804 रसोइयां हैं, के सापेक्ष आवंटित धनराशि रुपये 926.00 लाख दर्शायी गयी है, जबकि कार्यरत 8804 रसोइयों हेतु 10 माह का मानदेय रु0 880.40 लाख आगणित होता है। शेष धनराशि रु0 45.60 लाख वित्तीय वर्ष 2014–15 का अवशेष जनपद स्तर पर विद्यमान होना चाहिये। अतः वित्तीय वर्ष 2014–15 का अवशेष रु0 45.60 लाख तथा वित्तीय वर्ष 2015–16 का अवशेष रु0

---

uksV %& [ ] ;g va'k i<+k gqvk eku x;kA

78.53 लाख, इस प्रकार कुल रु0 124.13 लाख जनपद स्तर पर दिसम्बर, 2015 के मानदेय के भुगतान करने के पश्चात् भी शेष है जिससे आगामी माहों का भुगतान सम्भव हो सकता है।

विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विद्यालयों में कार्यरत रसोइयों को माह मई, 2015 तक भुगतान किया जा चुका है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शाहजहांपुर को जनपद में उपलब्ध अवशेष धनराशि को कोषागार के माध्यम से तत्काल आहरित कर रसोइयों के अवशेष मानदेय का भुगतान किये जाने के कड़े आदेश निर्गत कर दिये गये हैं।,

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं। दिनांक 04 मार्च, 2016 को पूर्वाह्न 11.00 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 07 बजकर 03 मिनट पर शुक्रवार, दिनांक 04 मार्च, 2016 को अगले के दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
दिनांक 26 फरवरी, 2016 ई0

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

पी0एस0यू0पी0–एल0 109 विधान सभा (170) 17–08–2016–813 प्रतियां (कम्प्यूटर)।